विषय-सूची

दशम माला, खंड 3, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 28, मंगलवार, 20 अगस्त, 1991/29 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
* तारांकित प्रश्न संख्या : 467 470 से 474 और 478.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—184
* तारांकित प्रश्न संख्या : 468, 469 475 से 477 और 479 से 486	24—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3421 से 3650	31—184
मंत्री द्वारा वक्तव्य	185—210
(एक) सोवियत संघ की राजनीतिक स्थिति श्री माधव सिंह सोलंकी	185
(दो) आयातित अखबारी कागज का मूल्य श्री अजीत कुमार पांजा	209
सभा पटल पर रखे गए पत्र	208
सभापति तालिका के सदस्य के नाम-निर्देशन के बारे में घोषणा	210
नियम 377 के अधीन मामले	210—214
(एक) हरियाणा के महेन्द्र-गढ़ जिले में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की और इस क्षेत्र में खनिजों का पता लगाने के लिए धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता राव राम सिंह	210

* किसी सदस्य के नाम अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रयोग की जाने वाली मुद्रण स्याही का उचित रिकार्ड रखने की आवश्यकता श्री फूलचन्द्र वर्मा	211
(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश के अठारह जिलों को मिलाकर "पूर्वांचल प्रदेश" बनाने की आवश्यकता श्री हरि केवल प्रसाद	212
(चार) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उड़ीसा में भुवनेश्वर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार आदि की अपनी योजना पर कार्य शुरू कपने के निदेश देने की आवश्यकता श्री शिवाजी पटनायक	212
(पांच) मेघालय के जैंतिया हिल्स जिले के गांवों में सुपारी के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली रहस्यमयी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तुरन्त उपचारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता श्री पीटर जी० मरबनिआंग	212
(छः) ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता श्री संतोष कुमार गंगवार	213
(सात) केरल के कोट्टायम जिले में इराट्टूपेट्टा टेलीफोन केन्द्र में उपभोक्ता ट्रंक डाइलिंग सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता श्री पी० सी० थामस	213
(आठ) नागपुर में नरखेड़ा रेलवे स्टेशन के कामगारों को वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता श्री तेजसिंह राव भोंसले	213

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92, उद्योग मंत्रालय	214—278
श्री शंकरसिंह वघेला	215
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	236
श्री अजय मुखोपाध्याय	241
श्री ए० चार्ल्स	253
श्री चन्द्रजीत यादव	261
श्री प्रफुल पटेल	268
श्री मोहन विष्णु रावले	274

लोक सभा

मंगलवार, 20 अगस्त, 1991/29 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री दिग्विजय नारायण सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री दिग्विजय नारायण सिंह लम्बे समय तक संसद में रहे। वह 1952-79 तक पहली लोक सभा से लेकर छठी लोक सभा तक के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार राज्य से 5 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया ।

श्री सिंह एक कृषक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता तथा एक योग्य और सक्रिय सांसद थे। उन्होंने सभा की कार्यवाही, विशेष रूप से विदेशी और रक्षा सम्बन्धी मामलों में गहरी रूचि ली ।

श्री सिंह ने देश विदेश का भ्रमण किया था। वह 1955 में सोवियत संघ तथा युगोस्लाविया गए संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्य थे तथा 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय शिष्टमंडल के भी सदस्य थे ।

श्री दिग्विजय नारायण सिंह का निधन 2 अगस्त, 1991 को पटना में हुआ। वह 67 वर्ष के थे ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और सभा की ओर से संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं ।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर तक मौन खड़े रहेंगे ।

(तत्पश्चात् सदस्य कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विमान किरायों में वृद्धि

*467. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्रीमती सुमित्रा महाजन } : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान किरायों में वृद्धि करने सम्बन्धी

कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बढ़े हुए किराये कब से लागू होंगे; और

(ग) इस वृद्धि का पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारुक) : (क) से (ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्य में वृद्धि तथा मुद्रा विनियम पर समायोजन के प्रभाव से निपटने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया है, जिनमें से एक किरायों में संशोधन है। इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि गल्फ सरचार्ज अभी भी लिया जा रहा है तथा इन्डियन एयरलायन्स के प्रवक्ता की 9 अगस्त को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 18 ए-320 विमानों में से केवल 12 ही चालू हालत में हैं। यह घाटा इन्डियन एयरलायन्स की अकुशलता के कारण हो रहा है तथा यात्रियों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। यह अनुचित है। क्या नागर विमानन मंत्रालय सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखेगा कि विमान ईंधन पर छूट की दर पुनः 30 प्रतिशत कर दी जाये जो कि घटा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : नहीं, महोदय। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय वह बोल्ड हो गए हैं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या इन्डियन एयरलायन्स द्वारा रात्रि उड़ानों में बढ़ौतरी करने का कोई प्रस्ताव है जिनका वर्तमान किराया कम है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु इन सभी सम्भावनाओं पर समय-समय पर विचार होता रहता है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : दिल्ली-बम्बई-दिल्ली के बीच चलने वाली उड़ान काफी सफल रही है। तथा इस उड़ान में बढ़ौतरी करने की मांग है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप दो पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री राम नाईक : विशेष मामला समझते हुए एक और प्रश्न पूछने की अनुमति दे दीजिए। एक अतिरिक्त गेंद की तरह एक अतिरिक्त प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : यह 'नो बाल' था। (**व्यवधान**)

श्री चेतन पी० एस० चौहान : अब जब कि मुझे अवसर मिला है तथा मंत्री महोदय भी

उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं। क्या विदेशी पर्यटकों तथा अनिवासी भारतीयों को कोई विशेष छूट देने का प्रस्ताव है ताकि आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटायी जा सके।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : क्या आप क्रिकेट खेलने गई थीं जिसकी वजह से ये सब हुआ ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : कम से कम इनसे लड़ाई नहीं लड़ी।

श्री अन्ना जोशी : क्या यह एयर-क्रैश से हुआ है ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह न तो एयर क्रैश से हुआ है और न ही सिंधिया जी से लड़ाई हुई है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप सिंधिया जी के निवास पर थीं ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : नहीं, **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। उनका उत्तर न दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी जैसा कि उन्होंने कहा कि किराया वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, मतलब कि आप इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यात्रियों को सुविधाएं अधिक प्रदान करने के लिए और हवाई-अड्डों का सुधार करने पर विचार कर रहे हैं ? कई ऐसे हवाई-अड्डे हैं जहां पर हवाई जहाजों की लैंडिंग के लिए आई० एल० एस० की सुविधा नहीं है जिसका जीता जागता उदाहरण अभी जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें देखने को मिला। इन्दौर के हवाई-अड्डे में भी आई० एल० एस० की सुविधा नहीं है। वहां कनवेयर बैल्ट तक नहीं है। यात्रियों को प्लेन में जो भोजन मिलता है, उसमें क्या सुधार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? आप किराया वृद्धि के साथ-साथ क्या ये सब सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : प्रश्न कनवेयर बेल्ट के बारे में नहीं है। यह हवाई-अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी नहीं है।

माननीय सदस्य श्री चेतन चौहान को दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कुछ एक उड़ानें ऐसी हैं जिनमें छूट दी जाती है जैसे कि 'डिस्कवर इन्डिया' उड़ान का किराया। एक ऐसी योजना भी है जिसके अन्तर्गत उन विदेशी पर्यटकों को छूट दी जाती है जो किराये का भुगतान डालरों में करते हैं। इस सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं

है। इसलिए उनको इस सम्बन्ध में नोटिस मिलना चाहिए।

श्री अन्ना जोशी : 'एविएशन टरबाईन फ्यूल' की कीमतों में वृद्धि तथा विनिमय दर में सामन्जस्य स्थापित करने के कारण कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या वास्तविकता यह नहीं है कि आपने कीमतों में केवल इसलिए वृद्धि नहीं की क्योंकि अहमदाबाद न्यायालय में आपके विरुद्ध अहमदाबाद उपभोक्ता परिषद द्वारा दायर एक मामला लम्बित पड़ा है ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : ए० टी० एफ० की कीमतों में वृद्धि से 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह सत्य है कि अहमदाबाद न्यायालय में एक मामला लम्बित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आपने केवल इसी कारण से ही किराए में वृद्धि नहीं की।

श्री माधवराव सिंधिया : नहीं महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री माधवराव सिंधिया : पहले तो 'एविसेशन टरबाईन फ्यूल' के मूल्यों में वृद्धि से लगभग 103 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा।

रुपए के अवमूल्यन से लगभग 85 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। ये सब आकलन हैं तथा मार्ग निर्देशन और रात्रि में वायुयानों के उतरने की सुविधा इत्यादि पर लगभग 15 करोड़ रुपए व्यय होने वाला है। जहां तक कुल अतिरिक्त भार का प्रश्न है, यह लगभग 200 करोड़ रुपए होगा। जहां तक अहमदाबाद में लम्बित मामले का प्रश्न है, जो भी किराया वृद्धि पिछले दिनों हुई तथा भविष्य में होगी उसके लिए उच्च न्यायालय की अनुमति ली जाएगी।

श्री अन्ना जोशी : क्या उच्च न्यायालय में मामला लम्बित होने के कारण इसमें देरी हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न का उचित उत्तर दिया है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा त्रिपुरा में 17.50 प्रतिशत की दर से किराए में छूट दी जाती है। अगर ऐसा है, तो इसके लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह राज सहायता उन यात्रियों को भी दी जाएगी जो कि कलकत्ता और मद्रास से पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : किराए में छूट देश के उन हिस्सों के लिए, इस मापदण्ड के आधार पर दी जाती है कि वे दूसरे संचार साधनों के संदर्भ में देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल कटे होते हैं। मेरे विचार में पोर्ट ब्लेयर इस श्रेणी में आता है तथा इस मामले पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां वह, इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में किराया वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है, किराया बढ़ाने की सोच रहे है तो यात्रियों की सुरक्षा के बारे में और विमान दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करें ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में नहीं आता ।

डा० बी० जी० जावाली : कुल निवल राजस्व लगभग 103 करोड़ रुपए है। अब इस राजस्व को एकत्रित करने के दो पहलू हैं—जैसे कि मंत्री, संसद सदस्य, उच्चाधिकारी तथा व्यापारी वर्ग जिन्हें प्रतिपूर्ति मिलती है। इस प्रकार के किताबी समायोजन के अतिरिक्त, वास्तव में लोगों से कितना राजस्व मिलता है।

श्री माधवराव सिंधिया : वर्ष 1990-91 में इन्डियन ने कुल 1100 करोड़ रुपये अर्जित किए। पहले यह राशि 1125 करोड़ रुपये थी। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान यह राशि 1435 करोड़ रुपये होने की आशा है।

श्री राम नाईक : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस समय निकट भविष्य में भाड़ा वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेलवे में आपने उत्पादन लागत तथा ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण 20 प्रतिशत भाड़ा वृद्धि की तथा उपनगरीय यात्रियों को 25 प्रतिशत अधिक भाड़ा देना पड़ रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है जबकि आम आदमी पर इतना अधिक बोझ डाला जा रहा है तो एयरलायन्स के यात्रियों को किराया वृद्धि में विलम्ब करके इस मामले में छूट क्यों दी जा रही है क्या भाड़ा वृद्धि न करने का कोई विशेष कारण है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाड़ा वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है बल्कि मैंने यह कहा है कि इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। परन्तु मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अगर भविष्य में यह निर्णय लेता हूं तो मुझे श्री राम नाईक तथा उनके वरिष्ठ सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा।

एयर इन्डिया के लिए बोइंग विमानों की खरीद

***470. श्री भगवान शंकर रावत**
श्री महेश कुमार कनोडिया } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के लिए चार बोइंग विमान खरीदने का निर्णय लिया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या एयर इंडिया ने बोइंग विमान खरीद लिए हैं,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या इनकी दो वर्ष पूर्व की अनुमानित लागत अब बढ़ गई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) विमान शीघ्र खरीदने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ताकि उनकी लागत में आगे होने वाली वृद्धि से बचा जा सके ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) से (ङ) सरकार ने 1962.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चार बोइंग 747-400 यात्री विमानों को प्राप्ति के लिए एयर इंडिया का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। विनिमय दर समायोजन के कारण, परियोजना लागत में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है; तथापि विदेशी मुद्रा अंश 667.09 मिलियन अमरीकी डालर ही है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, एयर इंडिया के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कब किया था ? अनुमोदन के पश्चात् इसमें विलम्ब क्यों किया गया ? विलम्ब के कारण खरीद मूल्यों में छः सौ करोड़ रुपये की वृद्धि से देश को होने वाली हानि का दायित्व किसका है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव था, पी० आई० बी० ने 14 मार्च को इसकी स्वीकृति दी और फिर यह केबिनेट के सामने प्रस्तुत करना था और केयर-टेकर गवर्नमेंट को होने के कारण जो महत्वपूर्ण निर्णय थे, उनको केयर-टेकर गवर्नमेंट लेने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए मामला स्थगित रखा गया।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, क्या अन्य प्रकार के विभिन्न विमान या बोइंग खरीदने के लिए एयर इंडिया ने कोई निर्णय लिया गया है ?

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, अभी कोई ऐसा प्रस्ताव हमारे समक्ष नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार उन 747 नए विमानों को खरीद रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इन विमानों को खरीदते समय वे बीमे की कौन-सी पद्धति अपनाते हैं। दो मुख्य विमान दुर्घटनाएं हुई है—एक जनवरी, 1978 में मुम्बई के पास और दूसरी कनाड़ा के मार्ग पर। क्या इन दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान की राशि वापस मिल गई है ? हम किस प्रकार का बीमा करवाते है ? क्या यह तोड़-फोड़ जैसे सभी खतरों पर मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, इसके लिए मुझे अलग नोटिस चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न जानना चाहता हूं। वैसे तो मंत्री महोदय ने बताया है कि पी० आई० वी० से एप्रूवल मार्च के महीने में मिली। यह प्रपोजल एयर इंडिया की तरफ से कब शुरू हुई थी, यह बात कब सरकार के सामने लाई गई थी ? दूसरे—क्या इसमें विलम्ब होने के पीछे यह भी एक कारण है कि हम लोगों की तरफ से कहा गया था, इसमें रोल्स-रॉयसी इंजन होने चाहिए थे ? इसकी निर्माता अमेरिकी कंपनी है, उनकी तरक से रोल्स रॉयसी इंजन नहीं बल्कि अमरीका में बने हुए किसी इंजन को रखने का आग्रह है ?

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया के बोर्ड ने 13 सितम्बर, 1989 को इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया। जहां तक इंजन का सवाल है, इसके कारण इस प्रोजेक्ट में कोई विलम्ब नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में ग्रामीणों को रियायती दर पर भोजन

*471. **प्रो० राम कापसे :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में ग्रामीणों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने की कोई योजना शुरू की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत पर्यटन विकास निगम के उन होटलों के नाम क्या हैं जहां यह योजना लागू की गई है,

(ग) इस रियायत का ब्यौरा क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं,

(घ) इस योजना के कार्यकरण से अब तक क्या अनुभव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) क्या इस योजना पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने दिनांक 25.1.1991 से एक स्कीम शुरू की थी जिसके अंतर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक होटल के एक विनिर्दिष्ट रेस्तरां में सप्ताह में दो दिन, अर्थात् बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ग्रामीण अतिथियों को भोजन पर 50% छूट दी जाती है। यह रियायत उन ग्रामीण व्यक्तियों को उपलब्ध है जो भारत पर्यटन विकास निगम के सम्बन्धित होटल/रेस्तरां के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हों। उन्हें यह

सुविधा इलाके के ग्राम प्रधान द्वारा जारी और सरपंच द्वारा प्रमाणित पहचान-पत्र/ प्रमाण-पत्र, बेहतर होगा यदि उस पर फोटो चिपका हो, या उस इलाके के खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जहां से वह अतिथि आया है, के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करने पर मिलेगी। तथापि, संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में स्थित होटलों के मामले में, 50 किलोमीटर दूरी की सीमा लागू नहीं होती और भारत के किसी भी भाग में रहने वाला कोई भी वास्तविक ग्रामीण अतिथि इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। एक परिवार के मामले में, इस सुविधा का लाभ उठा सकने वाले आश्रितों की संख्या 6 तक सीमित की गई है जिनमें परिवार का मुखिया शामिल है। भारत पर्यटन विकास निगम के उन होटलों की एक सूची अनुबंध में दी गई है जहां इस स्कीम को लागू किया गया है।

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत, 15.7.1991 तक 38 ग्रामीण व्यक्तियों ने सुविधा का लाभ उठाया है।

(ङ) जी, हां।

अनुबंध

20.8.1891 को पूछे जाने वाले लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 471 के उत्तर में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे उन होटलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जहां पर 25.1.1991 से ग्रामीण व्यक्तियों को भोजन पर 50% रियायत की स्कीम लागू की गई है।

क्रम नं०	एकक का नाम
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली
2:	होटल सम्राट, नई दिल्ली
3.	कुतुब होटल, नई दिल्ली
4.	अशोक रेडिसन होटल, बंगलौर
5.	अशोक रेडिसन ललित पैलेस होटल, मैसूर
6.	अशोक रेडिसन बीच रिसॉर्ट, कोवलम
7.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता
8.	होटल आगरा अशोक, आगरा
9.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली
10.	होटल जनपथ, नई दिल्ली
11.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी
12.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर
13.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर

14.	होटल रणजीत, नई दिल्ली
15.	लोदी होटल, नई दिल्ली
16.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू
17.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो
18.	होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना
19.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै
20.	टेम्पल बे अशोक बीच रिजॉर्ट, मामल्लापुरम
21.	होटल बोधगया अशोक, बोधगया
22.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर
23.	होटल हसन अशोक, हसन
24.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली
25.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : छः महीनों के समय में सिर्फ 38 ग्रामीण मेहमानों ने 25 आई० टी० डी० सी० होटलों में इस सुविधा का उपभोग किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसका पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : मेरे विचार से पर्याप्त प्रचार किया गया था—सिर्फ आई० टी० डी० सी० की ओर से किया गया प्रचार ही नहीं अपितु आई० टी० डी० सी० के प्रयासों से भिन्न भी इस मामले का सारे देश में पर्याप्त प्रचार हुआ है। निश्चय रूप से आई० टी० डी० सी० की ओर से प्रयासों में कोई कमी नहीं की गई या इस योजना से संबंधित अन्य लोगों की ओर से भरपूर प्रयास किया गया।

श्री राम कापसे : अपने प्रश्न के खंड (घ) में मैंने इस योजना के कार्यकरण में अभी तक हुए अनुभव के बारे में पूछा है। किन्तु इस पहलू पर मंत्री जी मौन हैं। उन्होंने सिर्फ 38 की संख्या दी है। अनुभव क्या रहा?

श्री माधवराव सिंधिया : संख्या 38 हमारे अनुभव का कुल योग है।

श्री राम कापसे : अगर संख्या इतनी कम है, तो इस पर पुनर्विचार क्यों हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह आपका तीसरा पूरक प्रश्न है।

श्री राम कापसे : मैं एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। कोई खंड क, ख आदि नहीं है। हांलाकि मैं एक अध्यापक हूं, फिर भी कोई खण्ड क, ख, ग आदि नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार क्यों किया जा रहा है। जब सिर्फ 38 लोगों ने इसका लाभ उठाया है, तो आप इसे बंद क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई नुकसान नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : हम प्रत्येक पहलू पर लगातार पुनर्विचार करते रहते हैं। होटलों की यही प्रकृति है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर नहीं उठाया गया है क्योंकि 38 की संख्या बहुत कम है और 6 का परिवार माना जाता है, तो कितने परिवार आए इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके साथ जो शर्तें लगी हैं कि होटल में जाकर गांव वाले को यह सबूत करना है कि वह गांव वाला है। इन बड़े-बड़े होटलों और बड़े-बड़े शहरों में गांव से अगर कोई आदमी आता है तो क्या वह ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसर से प्रमाण-पत्र लाएगा, क्या वह अपना फोटो लाएगा, क्या वह यह पुष्टि करा कर लाएगा कि वह गांव वाला है ? क्या मंत्री महोदय इसे स्वीकार नहीं करते कि सचमुच में इसके कारण लोग कम आए और अगर इन बन्धनों को हटा दें और गांव वालों को सचमुच में प्रोत्साहन देना चाहें, तो ऐसी प्रक्रिया बनाएं जिसको गांव वाले स्वीकार कर सकते हैं और अमल में ला सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अटल बिहारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं जिस पर निश्चित रूप से हम गम्भीरता से चिन्तन कर सकते हैं और उनके विचारों को पूरी तरह से नोट कर सकते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैं जानना चाहता हूं कि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जो सामान आया, फर्नीचर आया या और जो भी खर्चा हुआ, पब्लिसिटी पर जो खर्च किया गया, विज्ञापन दिए गए, यह सारा कितना खर्च इसके ऊपर हुआ। जैसा कि अभी आपने बताया कि इसके कारण 38 ग्रामीण लोगों को फायदा मिला है। उस पर खर्चा कितना किया गया, इस स्कीम पर लोगों को एटरेक्ट करने के लिए और फिजिकली कुछ चीजों को, जैसे गांव की कुछ चीजों को लाया गया या जो भी खर्चा किया गया, ये सारा कितना खर्च हुआ ? इस बारे में बताएं।

श्री माधवराव सिंधिया : श्रीमन्, होटलों के अलग-अलग विभाग होते हैं, अलग-अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, अलग-अलग सर्विसेज और सेवाएं होती हैं उन सबके एकाउंट्स अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं, एक सामूहिक रूप से उनके एकाउंट्स प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर इसके बारे में माननीय सदस्य बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर विशेष अभ्यास करने के पश्चात् मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत करूंगा।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : अध्यक्ष महोदय, पांच तारा होटलों में ग्रामीणों को रियायती दर पर भोजन देने की यह योजना शायद ग्रामीणों को होटलों में आने का प्रोत्साहन देने के लिए है कि वे देखें कि पांच सरा होटलों में क्या हो रहा है।

अब, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा—क्योंकि ग्रामीण योजना का आधार व्यापक होना चाहिए और इसका बिस्तार गांवों तक होना चाहिए—क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों

को राज्य सहायता देने पर विचार करेगी ताकि ऐसी योजनाएं विभिन्न राज्यों में शुरू की जा सकें।

श्री माधवराव सिंधिया : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राम नाईक : इस योजना के प्रमुख प्रनेता भूतपूर्व-उपप्रधानमंत्री थे। अब जबकि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है, तो क्या सरकार उन्हें विश्वास में लेगी ताकि इस योजना को उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके ?

श्री माधवराव सिंधिया : शायद भूतपूर्व उपप्रधानमंत्री ने ही इस योजना को तैयार किया था। हम भी उनकी भावनाओं का उचित सम्मान करना चाहते हैं। मूलतः, हम भी विश्वास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को और ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसीलिए हम इस योजना को जारी रख रहे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम इसे बन्द क्यों नहीं कर रहे। इसका कारण यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का आदर करते हैं। हम इस योजना को सफल सिद्ध करने के लिए थोड़ा और समय देना चाहेंगे। वह एक भयंकर कार्य हो जाएगा। किन्तु मैं निश्चय ही अनुमान कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में सभा में कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जो व्यक्ति धोती-कुर्ते में चला जाएगा, उसको ग्रामीण मानकर रियायती दर पर भोजन कराया जाएगा। धोती-कुर्ते में जाने के बाद ब्लाक के किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है, धोती-कुर्त्ता अपने आप में गांव का द्योतक है। तो क्या धोती-कुर्ते वाले व्यक्ति को रियायती दर दर पर भोजन करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री माधव राव सिंधिया : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

बुरहानपुर को पर्यटन केन्द्र घोषित करना

*472. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुरहानपुर को पर्यटन केन्द्र घोषित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऐतिहासिक स्थल के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक : (क) जी नहीं। किसी स्थान को पर्यटक केन्द्र घोषित करने की कोई नीति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री पूछिए ।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : बस, मुझे नहीं पूछना है ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि बुरहानपुर के बारे में तो कहा गया है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अच्छे पर्यटन स्थय बन सकते हैं, तो क्या मंत्री महोदय मध्य प्रदेश का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की दृष्टि से कुछ और योजनाएं बनाने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, अगर राज्य सरकार आगे आकर कहती है कि ऐसे स्थानों का विकास करना है, तो हमें इन्हें विकसित करने का प्रयास करना है । जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, मेरे पास कई योजनाएं हैं । किन्तु मैं जान नहीं पा रहा कि माननीय सदस्य किसके बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री अरविन्द नेताम : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है 'नहीं' किन्तु क्या मैं माननीय मंत्री से जा सकता हूं कि एक स्थान को पर्यटक केन्द्र घोषित करने का क्या मापदण्ड हैं ?

नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मेरे विचार से, माननीय सदस्य उत्तर को समझ नहीं पाए हैं । हमनेकहा हैं, नहीं, किसी स्थान को पर्यटक केन्द्र घोषित करने की कोई नीति नहीं है । ऐसी कोई नीति नहीं है । पर्यटक सर्किल आदि तो हैं । राज्य सरकार के अनुरोध पर हम वित्तीय सहायता भी देते हैं जब वे कुछ परियोजनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं । किन्तु, पर्यटक जैसी कोई चीज नहीं है ।

श्री अरविन्द नेताम : मैं मापदण्ड जानना चाहता हूं ।

श्री माधव राव सिंधिया : ऐसी कोई नीति नहीं है । ऐसा कोई पर्यटक केन्द्र नहीं हैं ।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में कई ऐसे स्थान है, जिनको पर्यटन केन्द्र माना जाता है । इन स्थानों के विकास की दृष्टि से और सुविधायुक्त बताने की दृष्टि से आर्थिक सहायता देने की सरकार की कोई योजना है या नहीं तथा सहायता देने का मापदण्ड क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मंत्री जी ने "हां" कह दिया है ।

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : कौन-कौन से ऐसे स्थान मध्यप्रदेश में हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बता दिया है, कई स्थान हैं ।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का लाभ उठाते हुए यह जानकारी

देना चाहता हूं, हालांकि इस प्रश्न के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न बुरहानपुर के बारे में है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को काफी आर्थिक सहायता और अनुदान दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ 30 लाख रुपया 5 वर्ष में दिया गया था और इस वर्ष उतनी ही धनराशि 2 करोड़ 34 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है, जबकि पहले सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता दी गई थी।

श्री कड़िया मुंडा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र......।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न बिहार के बारे में नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, संसार में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्थान खुशी नगर है, जो देवरिया के पास है। यहां पर श्रीलंका, चीन और बर्मा आदि जगहों से यात्री आते हैं लेकिन इस स्थान का विकास नहीं हुआ है और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मध्यप्रदेश से सम्बन्धित है, यदि बिहार के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहेंगे तो मंत्री महोदय कहेंगे कि नोटिस चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र : यदि मंत्री जी नोटिस देने के लिए कहेंगे तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कह दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की दृष्टि से विदिशा, सांची महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। मुझे थोड़े दिन विदिशा का भ्रमण करने का मौका मिला। मुझे वहां लगा कि विदेशी पर्यटकों के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिएं अभी तक वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय विदिशा का विशेष विचार कर के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकृष्ट करने की दृष्टि से कुछ सुधार करेंगे ?

श्री माधव राव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बुरहानपुर के बारे में है। विदिशा और सांची एरिया में काफी प्रोजेक्टस आगे बढ़े हैं मध्य प्रदेश सरकार से सलाह मश्विरा करके। विदिशा जो एक स्वीकृत ट्राईब्ल सर्कट है उसमें भोपाल, सांची, उदयगिरि सर्कट भी आता है। उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की तरफ हम विशेष ध्यान निश्चित रूप से देंगे।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों को रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

*473. **श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम पंचायतों को रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) उत्पाद की उपलब्धता, व्यवहार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए एल० पी० जी० की एजेंसियां 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में स्थापित की जा रही हैं।

श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन् : अध्यक्ष महोदय, उत्तर सिर्फ असंतोष जनक ही नहीं है अपितु बेतुका और अपूर्ण भी है। मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में एल०पी०जी० एजेंसी स्थापित करेगी ताकि शहरी और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर के अंतर को कम किया जा सके, आज भी ग्रामीण लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से वन नष्ट हो रहे हैं। और वनों को नष्ट होने से रोकना इस सरकार की एक नीति है। मेरे मूल प्रश्न का यही तात्पर्य है। किन्तु यह सिर्फ ग्राम पंचायत के तौर पर उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में एल० पी० जी० गैस एजेंसी स्थापित करेगी अथवा नहीं। यह करने से, जनसंख्या जो एक लाख से अधिक है, वह भी संतुष्ट होगी और समय धन की बचत होगी और गांवों में भी स्वास्थ्यकर व्यवस्था का पालन होगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सरकार का सतत प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक एल० पी० जी० उपलब्ध कराई जाएं। किन्तु इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में एल० पी० जी० देने पर विचार करना भी संभव नहीं है क्योंकि उपलब्ध उत्पाद समिति है और वर्तमान में अलाभकर वितरण व्यवस्था की बड़ी संख्या है। देश के लगभग 40 प्रतिशत वितरक घाटे में चल रहे हैं। इन कारणों से यह आश्वासन देना संभव नहीं होगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वितरक एजेंसी दी जाएगी।

श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन : महोदय, माननीय मंत्री गैस की उपलब्धता की बात कर रहे हैं और कई बार संसद में यह कहा गया है कि बम्बई हाई में प्रतिदिन गैस निकाली जा रही है। कावेरी बेसिन में भी गैस निकालने की गति धीमी है। इसलिए सरकार जो गैस की उपलब्धता के बारे में उत्तर दे रही है, वह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इतनी अधिक गैस फालतू जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन : महोदय, सरकार ने गैस की उपलब्धता के बारे में बताया है। और मैं उस भाग की व्याख्या कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको भाषण नहीं देना है। आपको सिर्फ प्रश्न पूछना है।

श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन : महोदय, आग से निकलने वाले धुएं की वजह से आज भी ग्रामीण महिलाएं आंसू बहा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न है ? क्या आप मंत्री से पूछना चाहते हैं कि वे उनके आंसू पोंछेंगे या नहीं।

(व्यवधान)

श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन : यह प्रश्न ग्रामीण लोगों के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे तो आपको स्पष्ट उत्तर प्राप्त होगा।

श्री एम० आर० कादम्बर जनार्दनन : लेकिन उत्तर नकारात्मक दिया गया है। उत्तर से यह लगता है कि ऐसा सम्भव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम आठवीं योजनावधि के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालयों को अधिक से अधिक गैस एजेंसियां दी जानी चाहिए ताकि शहरी और ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर के बीच का अन्तर कम हो। ग्राम कल्याण इस सरकार की मुख्य नीति है। जब सरकार कहती है कि ऐसा सम्भव नहीं है तो यह ग्रामीण लोगों की भावनाओं के विपरीत है। यही कारण है कि मैं प्रासंगिक प्रश्न पूछ रहा हूं। नकारात्मक उत्तर दिए बगैर क्या सरकार आगे आकर कहेगी कि वे कम से कम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर विचार करेंगे ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : हमने नकारात्मक रूप में उत्तर नहीं दिया है। हमने कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य उत्पादित गैस और गैस के एक अंश को, जो तेल क्षेत्रों में जल रही है, को एक साथ पेश कर रहे हैं जैसे कि बॉम्बे हाई की रसोई गैस के साथ जो एक संघटक है और इसका उत्पादन अलग होना चाहिए। हमारे पास रसोई गैस अधिक उत्पादित करने के लिए एक योजना है। हमारे पास तैयार योजना है और मेरे पास उसके आंकड़े उपलब्ध हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनायें लागू की गई हैं और हमारा यह प्रयत्न है कि रसोई गैस के लिए बकाया सूची में पड़े लगभग 70 लाख आवेदन-पत्र शीघ्रता से निपट जाएं। रसोई गैस का प्रश्न व्यर्थ जल रही गैस से अलग है। जहां तक इस गैस का सम्बन्ध है, उसके लिए हमारे पास एक अलग परियोजना है और विश्व बैंक परियोजना पहले ही मंजूर हो चुकी है। रसोई गैस के उत्पादन के लिए हमारे पास एक अलग कार्यक्रम है और मेरे पास उस कार्यक्रम का विवरण मौजूद है…

अध्यक्ष महोदय : अगर प्रश्न लम्बा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर भी विस्तृत हो।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मेरा उत्तर यह है कि बाजार मांग के अध्याधीन हमारा यह प्रयत्न होगा कि जितना जल्दी हो सके बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों को रसोई गैस प्राप्त कराई जाए।

श्री प्रफुल पटेल : सरकार समय-समय पर गैस के सिलैण्डरों की कमी के बारे में शिकायत करती रही है। इस कमी के कारण ही वितरण में भी देरी होती है। कुछ समय पहले बाम्बे हाई

के पास बम्बई गैस कम्पनी की विद्यमान पाइप लाइनों के माध्यम से गैस की आपूर्ति करने का प्रस्ताव था।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह एक अलग मुद्दा है। यह रसोई गैस के बारे में है।

श्री प्रफुल पटेल : अगर कुछ क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति पाइप लाइनों के माध्यम से की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए और अधिक सिलेण्डर उपलब्ध होंगे। बार-बार यह प्रस्ताव आता है परन्तु सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें केवल "गैस" शब्द ही समान है। कोई और बात समान नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसे स्थानों के लिए जहां की जनसंख्या 20,000 है, गैस एजेंसियों कीं मंजूरी देने के लिए कदम उठा रही है। क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक है और वहां रसोई गैस एजेंसी तक नहीं है जिसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत अधिक परेशानी हो रही है ? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि निकट भविष्य में सरकार ऐसे स्थानों को जो आपके सामान्य मानदंडों के अंतर्गत आते हैं, गैस एजेंसियां देने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य का अनुमान ठीक है। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले बहुत से क्षेत्र होंगे जहां कोई एजेंसी नहीं है। मैंने सरकार के सामने आने वाली रुकावटों के बारे में उत्तर दिया है। जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है 14 लाख उपभोक्ता पहले ही विद्यमान हैं और 3.2 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में हैं। मैंने सभी राज्यों की उपभोक्ता सूची और प्रतीक्षा-सूची के आंकड़े प्राप्त किए हैं। रसोई गैस के आवेदकों की संतुष्टि मुख्य रूप से मांग और पूर्ति स्थिति तथा तेल कंपनियों की परियोजित विपणन योजना पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : माननीय मंत्री जी ने कहा कि एल० पी० जी० की अनुपलब्धता की वजह से हम पंचायतों को एजेंसी नहीं दे सकते, यह भी कहा कि 20 हजार की आबादी के ऊपर हम एल० पी० जी० एजेंसी देते हैं। देश में कोई भी ऐसा प्रखण्ड नहीं है जिसकी आबादी 20 हजार से कम हो। क्या प्रखण्ड स्तर पर यह गैस एजेंसी देने का आप विचार रखते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय मैं पहले ही उस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं। देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां कोई गैस एजेंसी नहीं है जबकि उस क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 है। रसोई गैस की सीमित उपलब्धता और निश्चित समयावधि में उपलब्धता बढ़ाने में रुकावटों के कारण, हमारे पास प्रत्येक राज्य में विपणन योजना है। रसोई गैस डीलरों की संख्या तेजी से प्रत्येक

तेल कम्पनी द्वारा बढ़ाई जा रही है। जब वे विपणन योजना बनाते योजना हैं तो प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा माननीय सदस्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि गैस पूरी उपलब्ध न होने के कारण पंचायतों को नहीं दे सकते, लेकिन चार महीने पहले ऐसे आदेश दिए गए थे कि गांवों में सिलेंडर दिए जाएं। प्रत्येक गांव में दो से ज्यादा उपभोक्ता नहीं होते। जबकि एजेंसी वाले देने को तैयार नहीं हैं और वहां जाते नहीं हैं। क्या आप यह छूट देने को तैयार हैं कि वे खुद आकर वहां से ले जायें ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से बनता है। यदि आप जवाब देना चाहते हैं, तो मुझे आपत्ति नहीं है। वे पूछ रहे हैं कि क्या आप गांव से आने वाले लोगों को कुछ विशेष रियायत दे रहे हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, संसद सदस्यों की सिफारिशों पर गैस कनेक्शन दिए जाने सम्बन्धी प्रश्न पर मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि सभी सिफारिशों पर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वास्तव में, ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से लोगों को संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे मन्त्रालय से और अधिक सूचना चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संसद सदस्यों की सिफारिशों को न मानने का कारण विभिन्न पंचायतों में किसी एजेंसी का उपलब्ध न होना है। प्रश्न के भाग (ख) के अनुसार, यदि 20,000 लोगों की जनसंख्या पर कोई एजेंसी नहीं है तो किरायों में थोड़ी बढ़ोत्तरी करके क्या किसी एजेंसी को उस दूरी को तय करने का सुझाव दिया जा सकता है जिससे उन लोगों को भी गैस सप्लाई की जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे सिफारिशें संसद सदस्यों द्वारा की गई हैं और वे निर्धारित आरक्षण में से हैं तो उन सिफारिशों को हर हाल में पूरा किया जाएगा और किसी भी संसद सदस्य की सिफारिश की उपेक्षा नहीं की जाएगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, संसद सदस्यों द्वारा रसोई गैस कनेक्शन सम्बन्धी सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। हमारे पास प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा की गई सिफारिशों पर जारी किए गए गैस कनेक्शनों की संख्या और प्रत्येक संसद सदस्य के आरक्षण में कितना बचा है, इन सब की एक कम्पप्यूटरीकृत सूची है। (**व्यवधान**) मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री निर्मल कांती चटर्जी : हमें बहुत से पत्र मिले हैं कि हमारी सिफारिशों पर गैस कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : कृपया धैर्य रखें। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं कह

रहा था कि मंत्रालय के पास इस बात की कम्प्यूटरीकृत सूचना है कि प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा कितने आवेदन पत्रों की सिफारिश की गई है, कितने आवेदन पत्रों पर गैस कनेक्शन दिए गए हैं तथा प्रत्येक संसद सदस्य के खाते में कितना आरक्षण बकाया है। प्रत्येक संसद सदस्य को यह सूचना उपलब्ध करा दी जानी चाहिए ताकि उन्हे पता चल जाए कि उनके पास कितना आरक्षण बचा है जिसे अभी जारी किया जाना है। मेरे विचार से इससे सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह सत्य नहीं है। हमें मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। मैं नहीं जानता कि वे कम्प्यूटरीकृत हैं अथवा नहीं या वे इस बारे में जानते हैं अथवा नहीं। (**व्यवधान**) किन्तु उन्हें मंजूरी दी जा चुकी है, किन्तु अभी तक सम्बद्ध व्यक्तियों तक वे पहुंचे नहीं हैं। (**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : देश में कुछ अलग-थलग प्रदेश हैं। देश श्री राजीव गांधी का जन्म दिवस मना रहा है जो देश के गरीब लोगों और दूर-दराज तथा अलग-थलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत चिन्तित रहा करते थे। इस अवसर पर, क्या सरकार पहाड़ी तथा दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगी जहां पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : देश के दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मैं भी माननीय सदस्य की चिन्ता में भागीदार हूं। यह एक अच्छा सुझाव है, यह एक योग्य सुझाव है। सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अभी जिस तरह से सभी एम० पीज ने कहा, मैं समझता था कि केवल मुझे ही वह चिट्ठी आई है कि कैसे गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिले हैं, पर मालूम हुआ कि काफी लोगों को नहीं मिला है, आप इसकी जांच करेंगे ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी जांच करेंगे। पिछली बार मिनिस्टर की तरफ से गैस कनेक्शन की लिस्ट आ गई कि हम इनको दे देंगे लेकिन हुआ नहीं तो बीच में यह मामला कैसे गड़बड़ हो गया। मेरी निश्चित राय है कि डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिए गए हैं लेकिन अभी एम० पीज० को पत्र पहुंचा नहीं है। मैं अभी तक यह समझता था कि मेरे साथ ही हुआ है लेकिन यह तो सब के साथ हुआ है। इसलिए कहूंगा कि इस प्रकरण की इन्क्वायरी कराई जाए और हमें बताया जाए।

[अनुवाद]

यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या उसकी इन्क्वायरी करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : जहां पर भी सरकार ने संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए

आवेदन पत्रों को मंजूरी दी है और जहां पर उपभोक्ताओं को वास्तविक कनेक्शन नहीं मिले हैं, ऐसे मामलों में तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा क्वश्चन यह है कि यह सब होलसेल में हुआ है, उन सब का क्या होगा ?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या हम वह सूचि सभा पटल पर रख दें ? मंत्री जी को जवाब देने दें (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इस प्रकार नहीं होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा था कि हम आपको सूचना दे देंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के जवाब के पश्चात्, वे जवाब देंगे।

(**व्यवधान**)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की चिन्ता में भागीदार हूं क्योंकि वे मुझे सदन के भीतर और बाहर शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है (**व्यवधान**) आप पहले मेरी बात सुनें। मैं आपके सुझाव से सहमत हूं, जो आप कह रहे हैं मैं उससे असहमत नहीं हूं। यदि कम्पनी की ओर से उन उपभोक्ताओं को जिनकी सिफारिश संसद सदस्यों ने की है, सही सूचना देने में कोई गलती हुई है और उन्हें कोई जवाब नहीं मिला हैं, तो इस मामले की जांच की जानी चाहिए, और मैं सदन से वादा करता हूं कि मैं इस मामले की जांच करूंगा और सही कदम उठाऊंगा। (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह : जब से इस एल० पी० जी० की सप्लाई की जा रही है, केवल शहरी लोग ही इससे फायदा उठा रहे हैं। क्या मंत्री जी उपलब्ध एल० पी० जी० में से एक-तिहाई कनेक्शन ग्रामीण लोगों को देने पर विचार करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं एक बहुत ही गम्भीर तथ्य की ओर सदन का ध्यान दिला सकता हूं कि इस देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ? मैं नहीं सोचता कि हम इतनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की मांग के समानान्तर एल० पी० जी० का उत्पादन कर पाने में सफल हो पाए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में जा रही है और इस देश में जनसंख्या का ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। अतः ऐसी बदलती हुई जनसंख्या के लिए उपलब्ध एल० पी० जी० की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। किन्तु इस उपलब्ध करवाना हमारा उत्तरदायित्व है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन अधिक नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि माननीय सदस्य किसी प्रकार समाज के विचारों को प्रभावित करने और उनके खयालातों को बनाने में किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं कि हमें जनसंख्या पर नियन्त्रण करना है, तो **एच० पी० सी०** वितरण प्रणाली स्वयं अपनी देख-रेख कर लेगी।

महाराष्ट्र में रेल विद्युतीकरण

***474. श्री अन्ना जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रेल विद्युतीकरण के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ख) उक्त राज्य में चल रहे रेल विद्युतीकरण कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं।

(ख) मध्य रेलवे के रास्ते दिल्ली-बम्बई ट्रंक मार्ग और नागपुर के रास्ते हावड़ा-बम्बई ट्रंक मार्ग के विद्युतीकरण की योजना के भाग के रूप में, वाघोडा-भुसावल और भंडारा रोड-नागपुर खंडों पर, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं, काम चल रहा है। दिवा-पनवेल खंड के विद्युतीकरण का काम भी चल रहा है।

श्री अन्ना जोशी : सर्वप्रथम, वाघोडा-भुसावल, दिवा-पनवेल और हावड़ा-बम्बई खंडों के अतिरिक्त अन्य कौन से प्रस्ताव रेल विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

दूसरे, विद्युतीकरण की प्रति किलोमीटर लागत क्या है और तीसरे, यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री एम० मल्लिकार्जुन : हमने पहले ही सूचना दे दी है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिसे योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

श्री अन्ना जोशी : इन तीन प्रस्तावों के अतिरिक्त, मैं उन प्रस्तावों के बारे में पूछ रहा हूं जिन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिसे स्वीकृती मिली हो।

श्री अन्ना जोशी : मैं सहमत हूं। वे कौन से प्रस्ताव हैं जिन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं यही कह रहा हूं। कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। ये तीन प्रस्ताव जिनका मैंने उल्लेख किया है—जहां पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है—वह मार्च 1992 तक पूरा हो जायेगा। ये परियोजनाएं जो प्रगति पर हैं इनमें 132 कि० मी० मार्ग की दूरी शामिल है।

जहां तक लागत का प्रश्न है विद्युतीकरण के लिए प्रत्येक एक कि० मी० के मार्ग पर 40 लाख रुपए का खर्च है।

श्री अन्ना जोशी : अगले पांच वर्षों में महाराष्ट्र के विद्युतीकरण के लिए क्या प्रस्ताव हैं ? और दूसरे, क्या कोंकण रेल मार्ग का आरम्भ से विद्युतीकरण किया जाएगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक कोंकण रेल का प्रश्न है, वर्तमान में इस लाईन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस समय हम केवल इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ट्रंक मार्ग को पूरा किया जाए जिससे यात्रियों को सुविधा हो।

महाराष्ट्र में विद्युतीकरण के प्रस्तावों के बारे में हमने जलगांव से उछवा तक के मार्ग के सर्वेक्षण के लिए कहा है और जब यह सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा तब हम इस लाइन के बारे में विचार करेंगे।

श्री राम कापसे : महोदय, मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि मार्च 1992 तक दिवा, पनबेल मार्ग का विद्युतीकरण हो जाएगा। साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दिवा, पनवेल रेल के विद्युतीकरण के पश्चात् क्या इसके ऊपर एक उप-नगरीय रेल आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह केवल दिवा-पनवेल मार्ग के पूरा होने के लिए है, जो 24 कि० मी० है।

जहां तक उप-नगरीय रेल का सम्बम्ध है, इस समय मैं इस बारे में कोई सूचना नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट

*487 **डा लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेल सुरक्षा आयुक्त ने वर्ष वार कितनी रेल दुर्घटनाओं की जांच की;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं की जांच सम्बन्धी रिपोर्टों को सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) वर्ष	रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा जांच की गई रेल दुर्घटनाओं की संख्या
1988-89	11
1989-90	4
1990-91	8

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, मुद्रित रिपोर्ट की प्रतियां संसद लाइब्रेरी में रखी जाती हैं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई थीं और उनमें आपने कितनी दुर्घटनाओं की जांच कराई। जांच के परिणामस्वरूप जो जांच-रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई, उनमें किन-किन त्रुटियों का बार-बार होना, या किन-किर गलतियों का बार-बार होना पाया गया। क्या मंत्री इस सम्बन्ध में बतायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : सर, कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी के पास इन दुर्घटनाओं की संख्या नहीं रहती है। जब भी कोई दुर्घटना होती है और कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी को कहा जाता है इंक्वायरी करने के लिए, उसी समय कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी अपनी इंक्वायरी का काम प्रारम्भ करते हैं। हर एक दुर्घटना की इंक्वायरी वे नहीं करते और इस संबंध में आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि आपको जो अब तक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर क्या तथ्य सामने आये हैं ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को टाला जा सके, दुर्घटनाएं बार-बार न हों।

श्री माधव राव सिंधिया : कई बार जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हमारे रेलवे सेफ्टी कमिश्नर अपने सुझाव भेजते हैं, अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद, रेलवे मिनिस्ट्री पर निर्भर करता है कि वह उन सुझावों के अनुसार कार्य करे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी ने जितनी जांच रिपोर्ट दीं, उसके आधार पर आपने क्या कदम उठाये। क्या उन रिपोर्टों पर विचार करके, तदनुसार आपने कार्यवाही की है या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : जांच रिपोर्टस पर कार्यवाही रेलवे मिनिस्ट्री करती है, कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी नहीं करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रश्न मूलरूप से रेल दुर्घटनाओं के बारे में है, मगर उत्तर दे रहे हैं नागरिक विमानन मंत्री, क्योंकि कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी इस मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। मैं अपना सवाल पुराने रेल मंत्री से पूछ रहा हूं।

(व्यवधान)

इतने पुराने नहीं। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री के नाते उन्हें क्या अनुभव हुए क्योंकि रेल दुर्घटनाओं की जांच बाहर होना, यह कुछ विचित्र सा लगता है। क्या रेल मंत्रालय के अन्तर्गत रेलों में होने वाली दुर्घटनाओं की जांच व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा विभाजन रेल दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है और क्या रेल मंत्रायल ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकता कि निष्पक्ष जांच हो सके। मैं चाहता हूं कि पुराने अनुभव को ध्यान में रखकर, नागरिक विमानन मंत्री उत्तर दें।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं सोचता हूं कि रेल मंत्रालय इसका प्रबन्ध निश्चित रूप से कर सकता है परन्तु समूचे देश के सामने यह पूरी तरह साबित होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो। जांच की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ही इस एजेंसी को रेलवे मंत्रालय से बाहर रखा गया है, सिर्फ इसी मकसद के लिए।

[अनुवाद]

श्री शोनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या यह उनके मंत्रालय के ध्यान में आया है कि कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि रेल चालक को 24 घण्टे तक काम करना पड़ता है और यहां तक कि कभी-कभी आने से लेकर जाने तक और अधिक काम करना पड़ता है और थकावट के कारण कभी इससे दुर्घटना भी हो जाती है? इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्या उनका मंत्रालय आवश्यक निदेश जारी करेगा जिससे कि रेल चालकों को इतनी थकाकट का सामना न करना पड़े और वे दृढ़ता से 8-घण्टे के निर्धारित समय में ही काम करें?

श्री माधव राव सिंधिया : समय-समय पर इन निष्कर्षों से अवगत कराया जाता है। रेल मंत्रालय इन निष्कर्षों को ध्यान में रखना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। किन्तु जहां तक 24-घण्टे काम करने का प्रश्न है, इसका जवाब रेल मंत्री देंगे।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने पश्चिमी रेलवे के नागदा से लेकर रतलाम तक के बीच की रेलवे लाइन की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण इस लाइन पर समुचित कार्रवाई करने के विभाग को आदेश दिए थे, यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जोशी जी, यह अलग प्रश्न है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें यह बताया गया हैं,······

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, नहीं। रेलवे सुरक्षा का एक दूसरा आर्गेनाइजेशन है, वह एक्सीडेंट हो जाने के बाद जांच करता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। इसलिए आपका प्रश्न इसमें नहीं आता है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, रेल पटरी की उम्र समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए

रेल दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। इस पश्चिमी रेलवे के इस सैक्शन पर सुधार के लिए सरकार क्या कार्रवाही कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारुक : मेरे विचार में मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नैनपुर मंडल कार्यालय

*468. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनपुर स्थित सहायक डिवीजनल रेलवे मैनेजर के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पूरी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या शिकारा में हाल ही में हुई रेल दुर्घटना नैनपुर में कम कर्मचारी होने के कारण हुई थी; और

(ग) उक्त कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कब तक पर्याप्त कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। अपर मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, नैनपुर के लिए तीन लिपिकवर्गीय कर्मचारियों तथा एक ग्रुप 'डी' कर्मचारी की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग के कार्यकरण का मूल्यांकन

*469. **श्री बलराज पासी**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1991 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सी० ए० जी० रेप्स डी० एन० ई० एस० ऑन एक्सपेंडीचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं,

(ग) इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये अधिकारियों की संख्या क्या है; और

(घ) संसाधनों की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) (i) अनुसंधान तथा विकास शाखाओं के साथ एक कूड़ा-कचरा भष्मीकरण एवं विद्युत उत्पादन संयंत्र डेनमार्क की सहायता से 1987 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। यह परियोजना डेनमार्क की एक कम्पनी द्वारा टर्नकी आधार पर स्थापित की गई थी जो संयंत्र तथा उपस्कर की आपूर्ति, अभिकल्प के लिए तथा अपेक्षित प्रौद्योगिकी देने के लिए उत्तरदायी थी। कम्पनी ने दिल्ली के कूड़े-कचरे के केलरी मान का मूल्यांकन करने और संयंत्र का अभिकल्प तैयार करने के कार्य में अपने अनुभव तथा सुविज्ञता का प्रयोग किया था। टर्नकी ठेकेदार संयंत्र के प्रचालन का सफल प्रदर्शन करने में विफल रहा। जुलाई, 1990 में, सरकार ने संयंत्र को बन्द करने का निर्णय लिया और परियोजना की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति के लिए डेनमार्क की कम्पनी से दावा किया गया है। इस मामले में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई है।

(ii) 5 मेगावाट के एक तापीय आदान प्रयोगात्मक संयंत्र की स्थापना सहित, कोयला आधारित मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक (एम० एच० डी०) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक अनुसंधान तथा विकास परियोजना सोवियत वैज्ञानिक सहयोग से 1977 में शुरू की गई थी। प्रायोगिक संयंत्र 1985 में कमीशन किया गया था जिसमें संयंत्र में कोयला से उत्पन्न नीली जल गैस का इस्तेमाल किया गया था। इसका उद्देश्य 2800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमानों पर गैस को जलाकर प्लाज्मा का उत्पादन करना और प्लाज्मा को एक मैग्नेटिक फील्ड से ले जाकर बिजली का उत्पादन करना था। कोयला को मूल ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके संयंत्र की कमीशनिंग के बाद दीर्घावधि परीक्षण दौर शुरू किए गए जिनमें प्रायोगिक संयंत्र प्रणालियों के परीक्षण के लिए उच्चतर केलरी मान एल० पी० जी० का इस्तेमाल किया गया। इस परियोजना में एम० एच० डी० प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन की प्रौद्योगिक व्यवहार्यता का प्रायोगिक स्तर पर सफल प्रदर्शन किया गया। एम० एच० डी० प्रौद्योगिकी के आधार पर बिजली का वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन करना अनुसंधान तथा विकास परियोजना का तत्काल उद्देश्य नहीं था।

(iii) 150 पवन पम्पिग यूनिटें स्थापित करने के लिए लगभग 24 लाख रुपये की राशि 1987 में आंध्र प्रदेश को स्वीकृत की गई थी। राज्य प्राधिकारियों

ने केवल 77 यूनिटें प्राप्त की थीं जिनमें 29 के काम करने की रिपोर्ट मिली थी। इस असन्तोषजनक कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर, परियोजना को 1990 में पहले ही बन्द कर दिया गया था और राज्य को रिलीज किए गए 18 लाख रुपयों में से करीबन 6 लाख रुपए वापस ले लिए गए। राज्य से कहा गया है कि वे उन यूनिटों को ठीक करवाएं जो कार्य नहीं कर रही हैं और उन्हें कार्यशील बनाएं। पवन पम्प प्रदर्शन कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में संतोषप्रद ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iv) एक 1.5 मे०वा० के पायलट संयंत्र को चलाने के लिए धान की भूसी का इस्तेमाल करने वाली एक परियोजना 2.9 करोड़ रुपए की लागत पर मई, 1986 में राज्य क्षेत्र में पंजाब सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। मार्च 1987 में, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग 1.45 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान देने के लिए सहमत हो गया और मार्च, 1988 तक कुल 1.1 करोड़ की राशि रिलीज कर दी गई। तथापि, राज्य प्राधिकारियों ने परियोजना की वित्तीय पद्धति तथा उसके क्षेत्र में संशोधन किया जिस पर अब लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। संशोधित परियोजना को अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया गया और पंजाब सरकार से कहा गया कि वे अनुदान सहायता को वापस करें। एक करोड़ रुपए की राशि रज्य द्वारा पहले ही वापस कर दी गई है।

(ग) और (घ) किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई दुर्भावपूर्ण कार्य की सूचना नहीं मिली है। संसाधनों का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं के और अधिक कड़ाई से मूल्यांकन तथा मानिटरिंग का कार्य उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समितियों तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों और संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

मचेर्ला-रायचूर और विकाराबाद-कृष्ण रेल लाइन

***475. रवि मल्लू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मचेर्ला (आन्ध्र प्रदेश) से रायचूर (कर्नाटक) तक और विकाराबाद (आन्ध्र प्रदेश) से कृष्णा तक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सर्वेक्षण कब शुरू करने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री सी० के० जाफर शरीफ : (क) जी हां।

(ख) रायचूर और माचेरला तथा विकाराबाद और कृष्णा के बीच नई बड़ी रेल लाइन के

लिए दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण 1988 में किए गए थे। विकाराबाद-कृष्णा (48 कि०मी०) रेल लाइन पर उस समय 86.31 करोड़ रुपए की लागत आने तथा उससे ऋणात्मक दर से प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। इसी प्रकार, रायचूर-माचेरला (293 कि०मी०) नई बड़ी रेल लाइन पर उस समय 191.10 करोड़ रुपए की लागत आने तथा उससे 1.5 प्रतिशत की दर से प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। प्रस्तावित लाइन को रायचूर से गदग तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई का निर्णय सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सफाई कर्मचारियों की भर्ती

*476. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण, रेलवे स्टेशन तथा रेल सवारी डिब्बे बहुत अधिक गन्दे रहते हैं;

(ख) क्या सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर जुलाई, 1981 से प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नई भर्ती करके सफाई की स्थिति में सुधार करने का है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में तेल शोधक कारखाना

*477. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र**
श्री अनादि चरण दास } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 और 31 जुलाई, 1991 को उड़ीसा की पेट्रोल और डीजल की वास्तविक मांग कितनी थी और उसे वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई और इस मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या किसी तेल कम्पनी ने इस राज्य में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए पहले कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर की गई अथवा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान 53957 मि०ट० पेट्रोल तथा 425758 मि० ट० डीजल की आपूर्ति की गई थी। अप्रैल जुलाई, 1991 के दौरान 20116 मि० ट० पेट्रोल तथा 151071 मि०ट० डीजल की आपूर्ति की गई थी। खुदरा बिक्री केन्द्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

समस्तीपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों को पुनः चलाया जाना

***479. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल मंत्री** समस्तीपुर से चलने वाली रेल सेवाओं की बहाली के बारे में 16 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भाधीन पांच रेलगाड़ियां कब से चलती आ रही थीं और इन बन्द कर दी गई रेलगाड़ियों को पुनः कब से चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : पांच जोड़ी गाड़ियों को चलाए जाने की तिथियां नीचे दी गई हैं :—

1. 331/332 समस्तीपुर-निर्मली पैसेंजर शुरू में 1.4.1958 से दरभंगा और निर्मली के बीच चलायी गयी थी तथा 1.10.1958 से इसे समस्तीपुर तक बढ़ाया गया था।
2. 459/460 समस्तीपुर-दरभंगा पैसेंजर 1-5-1985 से चलाई गई थी।
3. 425/426 दरभंगा-नरकटियागंज पैसेंजर शुरू में 1.10.1984 में दरभंगा और रक्सौल के बीच चलाई गई थी तथा 1-5-1985 से इसे नरकटियागंज तक बढ़ाया गया था।
4. 327/328 दरभंगा-जयनगर पैसेंजर शुरू में 1-5-1958 से महेन्द्र घाट-जयनगर के बीच चलाई गई थी तथा 2-5-1959 से महेन्द्र घाट-दरभंगा खण्ड पर इसका चलना बन्द कर दिया गया था।
5. 321/322 दरभंगा-जयनगर पैसेंजर शुरू में 1-4-1983 से मधुबनी-जयनगर के बीच चलाई गई थी तथा 1-10-1986 से इसे दरभंगा तक बढ़ाया गया था।

फिलहाल, इन गाड़ियों को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

इण्डियन एयरलायन्स के विमानों में यात्री क्षमता में वृद्धि

***480. श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने विमान बेड़े की यात्री क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ए-320 विमानों को क्रमिक रूप से बेड़े में

शामिल करते हुए अपनी क्षमता में 25-30 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना है। विभिन्न मार्गों पर यातायात में बढ़ोतरी के अनुरूप क्षमता में वृद्धि का फैलाव सारे नेटवर्क पर किया जाएगा।

मंगलौर तेल शोधन कारखाना

*481. **श्री सुधीर गिरि**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मंगलौर तेल शोधन कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस तेल शोधन कारखाने के कब चालू हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस तेल शोधन कारखाने पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जिस परियोजना पर 1160 करोड़ रुपए (जून, 1990 की कीमतों पर) की लागत आने का अनुमान है, उसे सरकार ने अप्रैल, 1991 में अनुमोदित कर दिया है और इसके अप्रैल, 1995 तक चालू हो जाने की आशा है।

एयरबस ए-320 की सेवाएं बन्द करना

*482. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयरबस ए-320 की सभी उड़ानों को मशीनी त्रुटियों के कारण पुनः बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हाजीपुर-बेतिया रेल लाइन

*483. **श्री शिव शरण सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हाजीपुर और बेतिया के बीच वैशाली, देवरिया, साहिबगंज और अरेराज होते हुए रेल लाइन बिछाने की मांग काफी समय से की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में सर्वेक्षण कराया था; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम में कार्यगत पूंजी प्रबन्धन

***484. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशानिक सुधार आयोग ने क्रमशः वर्ष 1975 और 1976 के संदर्भ में भारत पर्यटन विकास निगम में "कार्यगत पूंजी प्रबंधन" के दो प्रमुख पहलुओं अर्थात् (i) वस्तु सूची प्रबंधन और (ii) प्राप्य लेखों का प्रबंधन के सम्बन्ध में नवम्बर, 1974 में अध्ययन किया था तथा इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां । भारत पर्यटन विकास निगम के अनुरोध पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1974 के उत्तरार्द्ध में भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली स्थित होटलों में खरीद करने बिल बनाने, वसूली करने, आदि से सम्बन्धित वर्तमान प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया था और "वस्तु-सूची प्रबन्धन" पर जून 1975 में तथा "लेनदारी लेखों के प्रबन्धन" पर अक्तूम्बर, 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।

(ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उन पर की गई कारंवाई का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

सिफारिश	की गई कारंवाई
(क) वस्तु-सूची प्रबन्धन	
सामान के मूल्य के खातों के रखरखाव, वस्तु-सूचियों की आवधिक समीक्षा, केंन्द्रीय रेट संविदा प्रदान करने, आदि सहित वस्तु-सूची प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तरीके शुरू करना ।	मार्च, 1979 में एक वस्तु-सूची नियंत्रक की नियुक्ति की गई थी । वस्तु-सूची प्रबंधन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करके भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटल एककों को भेजे गए थे । होटल एकक वस्तु-सूची प्रबंध संबंधी कार्य स्वयं करते हैं । एम०एम० एण्ड डी० डिविजन एकक स्तर पर वस्तु सूचियों पर निगरानी रखता है, थोक में वस्तुओं की खरीद करने के लिए केन्द्रीय रेट संविदा प्रदान करता है और फालतू समान के एक एकक से दूसरे एकक में अंतरण की व्यवस्था करता है, बेकार सामान आदि को बेचता है ।

(ख) लेनदारी लखों का प्रबन्धन

बकाया राशियों की वसूली करने और अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने सहित विस्तृत उधार नीति तैयार करना ।	विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों को उधार देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करके जून, 1977 में सभी होटल एककों को भेजे गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उधार देने की शर्तों, बिल भेजने के लिए समय-सीमा, वसूली करने के लिए की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई, बकाया राशियों की समीक्षा करने, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने, आदि का विवरण दिया गया था। इसके अतिरिक्त एक उधार नीति तैयार करके जुलाई, 1982 में परिचालित की गई थी ।

आस्ट्रेलिया के लिए सीधी विमान सेवा

*485. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आस्ट्रेलिया के लिए सीधी विमान सेवाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों की सिफारिशों पर खाना पकाने की गैस के कनेक्शन जारी करना

*486. **श्री सत्यपाल सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार द्वारा संसद सदस्यों की सिफारिशों पर वर्ष 1990-91 के दौरान खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन मंजूर किए गए,

(ख) खाना पकाने की गैस के मंजूर किए गए कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की संभावना है, यदि ये नहीं दिए जाएंगे, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिशों पर खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 10 नवम्बर, 1990 से 31 मार्च, 1991 की अवधि में 12,617 कनेक्शन जारी किए गए ।

(ख) कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया स्वीकृति मिलने के तुरन्त बाद प्रारम्भ हो जाती है।

(ग) प्रत्येक सांसद एक वर्ष में 48 एल० पी० जी० कनेक्शनों की सिफारिश कर सकता है।

[अनुवाद]

नागपुर कोयला क्षेत्रों में जहरीली गैस का रिसाव

3421. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के नियंत्रणाधीन नागपुर कोयला क्षेत्रों में जहरीली गैस के रिसाव के कारण कोयला क्षेत्रों में और उनके आसपास अनेक खनिज मारे गए थे,

(ख) क्या प्राधिकारी समुचित सुरक्षोपाय करने में असफल रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में कोयला कम्पनी द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त उपाय किए गए हैं। ऐसी गैसों के स्तर को स्वीकार्य सीमा के अन्दर विनियमित करने के लिए, नियमों के अनुसार यांत्रिक वेन्टीलेटरों की व्यवस्था की जाती है। ऐसी गैसों के विद्यमान होने सम्बन्धी जांच के लिए फ्लैम सुरक्षा लैम्पों की भी व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

सूजरा स्टेशन का दर्जा बढ़ाना

3422. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली-बागपत-श्यामली खण्ड पर सूजरा स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर "ख" श्रेणी करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

राजस्थान में रसोई गैस एजेंसियां

3423. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी रसोई गैस एजेंसियां है,

(ख) क्या सरकार को विभिन्न गैस एजेंसियों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के बारे में अजमेर जिले में इन एजेंसियों के उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1.4.1991 के अनुसार राजस्थान में 158 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं।

(ख) और (ग) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच की जाती है तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आठवीं योजना के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में उत्पादन

3424. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में विशेष रूप से सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयला उत्पादन में किन लक्ष्यों का प्रस्ताव किया गया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला उद्योग का विकास किए जाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल और गैस ड्रिलिंग पर खर्च की गई धनराशि

3425. **श्री दाऊदयाल जोशी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए खोज कार्य कब से चल रहा है; और

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1958 से।

(ख) 31.3.1991 तक कुल 260.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

कर्नाटक में रसोई गैस के कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

3426. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शन की जिलेवार प्रतीक्षा सूची क्या है और राज्य में रसोई गैस की इस समय मासिक मांग कितनी है; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए क्या कदम गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1.4.91 की स्थिति के अनुसार 2.62 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे। वर्ष 1990-91 के दौरान औसत माहवार खपत 9.1 टी० एम० टी० थी।

(ख) कर्नाटक में यथासंभव अधिकतम आवेदकों को एल० पी० जी० कनेक्शन दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोल माफिया

3427. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने के बाद कोल माफिया की जमा धन राशि जब्त कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 से अब तक कुल कितनी धनराशि जब्त की गई है,

(ग) क्या सरकार को कोल माफिया की गतिविधियों के कारण भारी घाटा हो रहा है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या सरकार का विचार कोयले के वितरण में बड़े पैमाने पर होने वाले घोटाले और अनियमितताओं की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की समिति गठित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1989 में उनके द्वारा पंजीकृत किए 7 मामलों की जांच किए जाने के दौरान 3.77 करोड़ रु० की राशि की बेनामी सावधि जमा की रसीदों के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। बाद में, 2.70 करोड़ रुपये की रकम कलकत्ता उच्च न्यायालय के नांक दि22.4.91 के आदेश पर जारी कर दी गई। सूचनानुसार सभी 7 मामले सी० बी० आई० की जांच के अधीन हैं।

(ग) और (घ) असामाजिक तत्वों की गतिविधियां कोयला कम्पनियों की कार्यकुशलता और सुचारू रूप से चलने वाले कार्यकलापों पर प्रभाव डालती हैं, किन्तु इसके कारण हो रहे घाटे की मात्रा का बताया जाना कठिन है।

(ङ) और (च) वर्तमान में ऐसी समिति का गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु भारत सरकार द्वारा कोल इंडिया लि० की कोयले के वितरण किए जाने सम्बन्धी नीति की

समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के रसोई गैस उपभोक्ताओं की शिकायतें

3428. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के रसोई गैस उपभोक्ताओं को सप्लाई के लिए काफी दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हाल के वर्षों में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों में 549 अलग-अलग शिकायतें मिली हैं एवं उनकी जांच कराई गई है। एल० पी० जी० की आपूर्ति उपलब्धता के आधार पर होती है । उपलब्धता वर्षानुवर्ष अलग-अलग होती है ।

केरल में बायो गैस को उपयोग में लाना

3429. **श्री पी० सी० थामस** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में बायो-गैस ऊर्जा को उपयोग में लाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या राज्य में लघु बायोगैस संयंत्रों को राजसहायता दी जाती है, और इसको जारी रखे जाने की संभावना है,

(घ) क्या बायो-गैस का घोल एक अच्छा उवरंक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां ।

(ख) केरल राज्य सरकार के नोडल विभाग के लिए वर्ष 1991-92 हेतु 2500 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । इसके अलावा, खादी ग्रामोद्योग आयोग भी राज्य में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना कर रहा है ।

(ग) जी हां । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और आवधिक समीक्षा पर निर्भर करते हुए छोटे आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए केंद्रीय आर्थिक सहायता संभवतया जारी रहेगी ।

(घ) और (ङ) जी हां। खाद के प्रयोजनों के लिए घोल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में किसानों के खेतों में ही प्रदर्शनों का आयोजन करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, घोल के लाभों को क्षेत्रीय भाषाओं में बताने वाले साहित्य का प्रकाशन आदि शामिल है।

राजामुंदरी के लिए वायु सेवा

3430. **श्री के० वी० आर० चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामुंदरी में तेल की खोज के लिए "तेल और प्राकृतिक गैस आयोग" की भारी मांग और वहां पर स्थित गैस पर आधारित उद्योगों के कारण सरकार का राजामुंदरी के लिए वायु सेवायें सुधारने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वायुदूती इस समय हैदराबाद विजयवाड़ा राजामुन्दरी, सैक्टर पर सप्ताह में तीन दिन डोर्नियर सेवा परिचालित कर रहा है। उपलब्ध क्षमता मौजूदा यात्री-मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझ जाती है।

मंगलौर हवाई अड्डे का विस्तार

3431. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंगलौर हवाई अड्डे के विस्तार का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हवाई अड्डे का कब तक विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जबकि मंगलूर हवाई अड्डे के विस्तार की योजना तैयार कर ली गई है और भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, तथापि, विस्तार परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कटनी स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

3432. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कौन-कौन-सी परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं या लेने का प्रस्ताव है तथा इस पर अब तक क्या प्रगति हुई हुई है; और

(ख) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1990-91 के दौरान 78,600 रुपये की लागत से दो बिस्तर वाले विश्राम कक्ष की व्यवस्था की गई थी तथा कुल 3.30 लाख रुपये की लागत से प्रतीक्षालय के विस्तार का कार्य स्वीकृत किया गया है ।

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 में क्रमशः 0.78 लाख रु० तथा 1.55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परिसंपत्तियों का स्थानान्तरण

3433. **डा० सुधीर राय** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परिसंपतियों का स्थानान्तरण मुख्तियारनामे के आधार पर "एन० पी० टी० सी०" को कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो एक सफल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की परिसंपतियों का एक अन्य नवगठित सरकारी क्षेत्र को स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह स्थानान्तरण कम्पनी कानून प्रक्रिया के अनुसार तथा विधि मंत्रालय की सहमति से प्रभावी हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० ने राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम लि० (एन० पी० टी० सी०) के पक्ष में एक मुख्तियारनामा दिया है जिसके अनुसार 16 अगस्त, 1991 से राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम, पारेषण लाइनों/उपकेन्द्रों, सहायक उपस्करों सहित परिसम्पत्तियों, सम्बद्ध सुविधाओं और विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अभिन्न घटकों को छोड़कर अन्य परिसम्पत्तियां जो कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कारोबार में शामिल हैं और इससे सम्बन्धित सभी आवश्यक क्रियाकलाप, जब तक कि विधितः हस्तान्तरण सम्बन्धी समझौते के बारे में अपेक्षित औपाचारिकताएं पूरी नहीं कर ली जाती हैं, द्वारा प्रबन्ध किए जाने का अधिकार सौंप गया है ।

(ख) पारेषण प्रणाली और सम्बद्ध उपकेन्द्रों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रम को हाथ में लेने तथा केन्द्रीय क्षेत्र के विभिन्न विद्युत उत्पादन स्रोतों से क्षेत्र के अन्तर्गत और क्षेत्र से बाहर विश्वसनीय सुरक्षा और मित्तव्ययी रूप से वृहत् मात्रा में भार केन्द्रों को विद्युत का अन्तरण समेकित एवं दक्षतापूर्ण रूप से किए जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम लि० (एन० पी० टी० सी०) की स्थापना की गई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निहित वर्तमान व्यवस्था को विधि मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है ।

मध्य और पश्चिम रेलवे की आय और व्यय

3434. **श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लिए मध्य और पश्चिम रेलवे के उपनगरीय सेक्शनों की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है,

(ख) जहां उपनगरीय तथा मुख्य लाइन सेक्शन के डिवीजनों के लिए रेलवे विभाग की मूलभूत सुविधाएं एक समान हैं वहां दोनों के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मध्य तथा पश्चिय रेलवे के उपनगरीय सेक्शनों के लिए पृथक-पृथक कितने प्रथम श्रेणी टिकट और द्वितीय श्रेणी टिकट बेचे गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उप नगरीय खंडों से संबंधित आय/खर्च नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

1989-90	आय	खर्च
मध्य	108.20	133.10
पश्चिम	103.19	105.83

1990-91 दिसम्बर, 1991 में 1990-91 के वास्तविक आंकड़े संकलित करने के बाद ही वित्त वर्ष 1990-91 की आय/खर्च ज्ञात होगा।

(ख) साझे खर्च तथा आमदनी का विभाजन उपयुक्त निष्पादन प्राचलों के आधार पर किया जाता है।

(ग) जारी किए गए टिकटों की संख्या इस प्रकार है :—

(हजार में)

वर्ष	मध्य	पश्चिम
पहला दर्जा		
1989-90	859	1003
1990-91 (अनन्तिम)	880	1152
दूसरा दर्जा		
1989-90	217,331	227,940
1990-91 (अनन्तिम)	218,787	248,440

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा लाइसेन्स शुल्क की वसूली

3435. **श्री मृत्युंजय नायक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1991 को 'जनसत्ता' में "आफिसरों की लापरवाही से रेलवे को लाइसेंस फीस में भारी नुकसान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) समाचार में भारत के नियंत्रक-एवं-महालेखा परीक्षक की मार्च, 1990 को समाप्त रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जो रेलवे की भूमि के लाइसेंस शुल्क में संशोधन तथा देय राशि की वसूली में विलम्ब के बारे में है। विलम्ब मुख्यतः राजस्व प्राधिकारियों से भूमि का मूल्यांकन उपलब्ध न होने तथा कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा मुकदमा दायर करने के कारण हुआ है। रेलों ने बकाया राशि वसूल करने तथा दोषी लाइसेंसधारियों को बेदखल करने के लिए कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

मेछेडा स्टेशन (दक्षिण पूर्वी रेलवे) का नवीकरण करना

3436. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण पूर्वी रेलवे के मेछेडा स्टेशन का नवीकरण करने का विचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में "कुटीर ज्योति" योजना

3437. **श्री नवल किशोर राय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सीतामढ़ी जिले में कितने गांवों में बिजली है और कितने गांवों में बिजली नहीं है; और

(ख) इस जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां "कुटीर ज्योति" योजना लागू कर दी गई है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर भविष्य में यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का

विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1991 तक सीतामढ़ी जिले के 803 गांव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं शेष 238 गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है।

(ख) बिहार के सीतामढ़ी जिले में कुटीर ज्योति स्कीम के अन्तर्गत लगभग 1700 सिंगल प्वाइंट लाइट कनैक्शन देने के सम्बन्ध में बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है। स्कीम जोकि 88-89 और 89-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदानों से वित्तपोषित की जानी थी, के अन्तर्गत लाभभोगियों का पता लगाने का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था।

[हिन्दी]

पनवेल से करजत के बीच रेल मार्ग

3438. **श्री गोविन्द राव निकम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पनवेल से करजत तक एक रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भवना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पनवेल और करजत के बीच एक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

असम में प्राकृतिक गैस को जलाकर नष्ट करना

3439. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में काफी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस प्रतिदिन जलाकर नष्ट की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी गैस जलाई जा रही है; और

(ग) असम में जलाकर नष्टकर दी जाने वाली गैस का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) असम के लकवा, गैलेकी व रुद्रसागर सहित अनेक तेल क्षेत्रों में 1.5 एम०एम०एम० घन मीटर प्रतिदिन से भी अधिक गैस जलायी जा रही है।

(ग) गैस की उपयोगिता को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमो में नए उपभोक्ताओं की

पहचान, अतिरिक्त गैस कम्प्रेशरों की स्थापना, अतिरिक्त गैस इंजेक्शन योजना का कार्यान्वयन, व एल०पी०जी० की प्रतिप्राप्ति शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के विद्युत संयन्त्रों की उत्पादन क्षमता का उपयोग

3440. **श्री राम निहोर राय :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की रिहन्द हाइडल पावर स्टेशन, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, अनपाड़ा थर्मल पावर स्टेशन और बीजापुर थर्मल पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता कितनी है और इनमें बिजली का कितना उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या उत्पादन क्षमता और उत्पादित विद्युत की मात्रा में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अनपाड़ा थर्मल पावर स्टेशन का चरण-II कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 1991 से जुलाई, 1991 के दौरान रिहन्द जल विद्युत केन्द्र, ओबरा, अनपारा तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापति क्षमता, उनका ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्र भार गुणक का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

केन्द्र का नाम	प्रतिष्ठापति क्षमता (मे० वा०)	ऊर्जा उत्पादन (मि०यू०)	संयंत्र भार गुणक (%)
रिहन्द जल विद्युत परियोजना	300	376	*—
ओबरा ताप विद्युत परियोजना	1550	2508	57.8
अनपरा सु०ता० वि० केन्द्र	630	1346	73.0
रिहन्द सु०ता० वि० केन्द्र (बीजपुर)	1000	2145	73.3

*(जल विद्युत केन्द्र का कार्यनिष्पादन, जलाशय में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।)

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन, इसकी मांग (लोड) और पारेषण एवं वितरण प्रणाली सम्बन्धी कठिनाइयों पर निर्भर करता है। इसलिए विद्युत उत्पादन यूनिटों से उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि विद्युत केन्द्र का कार्यनिष्पादन, ताप विद्युत एवं न्यूक्लीय यूनिटों के मामले में आयोजित अनुरक्षण, जबरन बन्दी आदि सहित कई घटकों और जल विद्युत यूनिटों के मामले में जलाशयों में जल की उपलब्धता पर निर्भर

करता है। विद्युत उत्पादन, प्रणाली भार सम्बन्धी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता हैं जोकि दिन में व्यस्ततमकालीन एवं गैर-व्यस्ततमकालीन घण्टों के दौरान भिन्न-भिन्न होती है। ताप विद्युत केन्द्रों के उत्पादन में सुधार करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—पुराने यूनिटों का नवीनकरण एवं आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को आरम्भ करने में राज्य बिजली बोर्डों को सहायता प्रदान करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना, कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और पारेषण नेटवर्क में सुधार करना।

(घ) अनपारा में फेस-2 के अन्तर्गत, अनपारा-बी ताप विद्युत केन्द्र (2 × 500 मे०वा०) निर्माणाधीन है। 500 मे० वा० के प्रथम यूनिट को जनवरी, 1993 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है और 500 मे०वा० के दूसरे यूनिट को दिसम्बर, 1993 में चालू किए जाने की सम्भावना है।

फैजाबाद और मनकापुर को ब्राडगेज रेल लाइन से जोड़ना

3441. **श्री श्याम लाल कमल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और मनकापुर को ब्राडगेज रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) मनकापुर से फैजाबाद तक सर्वेक्षण को अद्यतन करना 1991-92 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर अगला निर्णय निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

बम होने की अशंका से उड़ानों में विलम्ब

3442. **श्री शिव शरण बर्मा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान बम होने की आशंका के कारण कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे कितनी राशि की हानि हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराय सिंधिया) : (क) गत तीन महीनों के दौरान, बम होने की आशंका के कारण 22 उड़ानों में विलम्ब हुआ था, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस प्रकार हुई हानि का अनुमान प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

विवरण

पृष्ठ सं०	सूचना का स्रोत	तारीख/समय	स्टेशन	उड़ान सं०	मार्ग	बिलम्ब
1 —	—	6.5.91 0740	बम्बई	एयर इंडिया 212	बम्बई-दिल्ली	2 घंटे 25 मि०
2 —	—	8.5.91 1750	बम्बई	आईसी-107 इंडियन एयरलाइंस	बम्बई-बंगलौर	2 घण्टे 45 मि०
3 —	—	12.5.91 0315	बम्बई	आईसी-161 आई० ए०	बम्बई-कोचीन	2 घण्टे 35 मि०
4 —	—	17.5.91 1730	बम्बई	आईसी-808 आई० ए०	बम्बई-दिल्ली	4 घंटे 30 मि०
5 —	—	5.6.91 1530	बम्बई	एयर इंडिया 915	बम्बई-दहरान	3 घण्टे
6 —	—	11.6.91 0228	बम्बई	एयर इण्डिया 185	बम्बई-दिल्ली-न्यूयार्क-लन्दन	9 घंटे
7 —	—	16.6.91 0145	बम्बई	एयर इण्डिया 331	दिल्ली-बम्बई	6 घंटे
8 —	—	28.6.91 1524	बम्बई	आईसी-187 आई० ए०	बम्बई-दिल्ली	2 घंटे
9 —	—	4.7.91 1330	बम्बई	एयर इण्डिया 757	बम्बई-दुबई	6 घंटे
10 —	—	9.7.91 0630	बम्बई	आईसी-671 आई० ए०	बम्बई-मद्रास	4 घंटे
11 —	—	20.7.91 1110	बम्बई	आईसी-605 आई० ए०	बम्बई-बंलौर	4 घंटे
12 —	—	20-7-91 2015	बम्बई	पाकिस्तान एयरलाइन्स पी के० 277	बम्बई-कराची	2 घंटे

1	2	3	4	5	6	7
13 —	—	31.7.91 0810	बम्बई	आईसी-631 आई० ए०	बम्बई-कराची	$3\frac{1}{2}$ घंटे
14 —	—	20.5.91 0940	दिल्ली	आरबी-502 सिरियन एयरलाइंस	दमिश्क-दिल्ली-दमिश्क	2 घंटे
15 —	—	25.5.91 2355	दिल्ली	पाकिस्तान एयरलाइंस पीके-293	कराची-दिल्ली-कराची	2 घंटे
16 —	—	28.6.91 0125	दिल्ली	एयर फ्रांस एएफ-183	मालद्वीप-हांगकांग दिल्ली-पेरिस	4 घंटे 30 मि०
17 —	—	5.7.91 1210	दिल्ली	आईसी-409 आई० ए०	दिल्ली-लखनऊ-पटना-दिल्ली	5 घंटे 40 मि०
18 —	—	21.7.91 1000	दिल्ली	एयर इंडिया 735	दिल्ली-दुबई	3 घंटे 45 मि०
19 —	—	31.7.91 220	दिल्ली	आई सी-423 आई० ए०	दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर	55 मि०
20 —	—	26.6.91 1602	मद्रास	आईसी-539 आई० ए०	मद्रास-दिल्ली	3 घंटे
21 —	—	6.7.91 0820	मद्रास	आईसी-573 आई० ए०	मद्रास-कोलम्बो	कोई देरी नहीं
22 —	—	2.7.91 1950	फ्रैंकफर्ट	ए आई-143/142	पेरिस-फैंकफर्ट-दिल्ली	3 घंटे

फरीदाबाद स्टेशन पर दक्षिण को जाने वाली गाड़ियों का रुकना

3443. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से दक्षिण को जाने वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के फरीदाबाद स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दक्षिण फरीदाबाद को आने वाले श्रमिकों की सुविधा के लिए इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) उत्तर-दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियां अर्थात् अप दिशा को जाने वाली 7022 निजामुद्दीन-हैदराबाद एक्सप्रेस, 6688 जम्मू तवी-मंगलौर नवयुग एक्सप्रेस तथा डाउन दिशा में जाने वाली 2615 मद्रास-नयी दिल्ली जी०टी० एक्सप्रेस, 2625 तिरुवनन्तपुरम/मंगलोर-नयी दिल्ली केरल मंगला एक्सप्रेस और 6687 मंगलोर-जम्मूतवी नवयुग एक्सप्रेस गाड़ियां फरीदाबाद में रुकती हैं। किसी अतिरिक्त गाड़ी को फरीदाबाद में ठहराव देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली की अवैध बस्तियों द्वारा विकास शुल्क जमा कराया जाना

3444. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अवैध बस्तियों के निवासियों ने वर्ष 1989 और 1990 में बिजली के कनैक्शन के लिए विकास शुल्क जमा करा दिया है परन्तु उन्हें अभी तक बिजली के कनैक्शन नहीं दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन बस्तियों के क्या नाम हैं जहां के निवासियों ने विकास शुल्क जमा करा दिए हैं और उन्हें कब तक बिजली के कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, कुछ अनधिकृत कालोनियों जहां निवासियों द्वारा विकास प्रभार जमा करा दिए गए हैं, में बिजली के कनेक्शन जारी न किए जाने का कारण, संबंधित रेजीडेंट एसोसिएशनों द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरा न किया जाना तथा डेसू को उपकेन्द्रों के लिए स्थान उपलब्ध न कराया जाना है।

(ग) डेसू द्वारा 1989 में 37 तथा 1990 में 46 ऐसी पात्र अनधिकृत कालोनियों के विद्युतीकरण हेतु स्कीमें जारी कर दी गई हैं जिनके मामले में निवासियों द्वारा निर्धारित विकास प्रभारों के भुगतान सहित सभी अपेक्षित वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं और डेसू को उपकेन्द्र के लिए स्थान उपलब्ध करा दिया गया है। इन कालोनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन स्कीमों का क्रियान्वनन, विभिन्न चरणों में है।

विवरण

उन अनधिकृत कालोनियों/लैफ्ट आउट पाकेट की सूची जिन्हें 1.1.81 की स्थिति के अनुसार विद्यमान घोषित किया गया था और जिनके विद्युतीकरण सम्बन्धी स्कीमें वर्ष 1989 में जारी की गई थी

1. अमर कालोनी।
2. विनोबा एन्क्लेव।
3. ई ब्लॉक, पश्चिमी विनोद नगर।
4. बिजय एन्क्लेव ए-1 ब्लॉक (लैफ्ट आउट पॉकिट)।
5. वैशाली कालोनी, डाबरी (पालम)।
6. शिवराम पार्क।
7. स्वर्ण पार्क, रोहतक रोड।
8. लैफ्ट आउट पॉकिट डी ब्लॉक, कृष्णा पार्क।
9. जे ब्लॉक, सागरपुर (लैफ्ट आउट पॉकिट)।
10. प्रेम नगर फेस 1, 2 एण्ड 4।
11. न्यू विश्वास नगर, शाहदरा।
12. पटेल गार्डन कालोनी, उत्तम नगर।
13. बुद्ध विहार।
14. लैफ्ट आउट पॉकिट ऑफ रघु नगर, पंखा रोड।
15. ब्लॉक "सी" ओल्ड रोशनपुरा एक्सटेंशन।
16. रोशनपुरा एक्सटेंशन, नजफगढ़।
17. डी ब्लॉक, दशरथपुरी डाबरी, पालम रोड।
18. बिन्दापुर एक्सटेंशन, उत्तम नगर।
19. राजापुरी उत्तम नगर।
20. जानकीपुरी कालोनी नियर विल्लेज बिन्दापुर।
21. रत्न बाग (वीना एन्क्लेव) रोहतक रोड, नांगलोई।
22. दुग्गुल कालोनी, खानपुर एक्सटेंशन।
23. गीतांजली पार्क, लैफ्ट आउट पॉकिट, सागरपुर।
24. गीतांजली पार्क एक्सटेंशन।
25. लैफ्ट आउट पॉकिट ऑफ दुर्गापार्क, नशीरपुर।

26. सी एण्ड डी ब्लॉक मोलार बैण्ड एक्सटेंशन।
27. एफ ब्लॉक पश्चिमी विनोद नगर।
28. प्रताप गार्डन, बिन्दापुर एक्सटेंशन।
29. अरविन्द एन्क्लेव, अमर कॉलोनी, रोहतक रोड़।
30. भगीरथी विहार।
31. राजनगर पार्ट-2 एक्सटेंशन (पालम कॉलोनी)।
32. लैफ्ट आउट पॉकेट ऑफ सीतापुरी कालोनी, डाबरी।
33. शिवमन्दिर मोहल्ला, बादली गांव।
34. पालम विहार कालोनी। मटियाला रोड, पालम।
35. सेवक पार्क सी ब्लॉक (शिव विहार कालोनी) नजफगढ़।
36. राजधानी पार्क कॉलोनी।
37. नेहरू विहार।

उन अनधिकृत कालोनियों/लैफ्ट आउट पोकेट्स की सूची जिन्हें 1.1.81 की स्थिति के अनुसार विद्यमान घोषित किया गया था और जिनके विद्युतीकरण सम्बन्धी स्कीमें वर्ष 1990 में जारी की गई थीं

1. चाणक्य पैलेस फेज-2।
2. अध्यापक नगर, नजफगढ़, नांगलोई।
3. प्रजापति कालोनी, उत्तम नगर।
4. बी ब्लॉक, सैक्टर ए, विष्णु विहार, उत्तम नगर।
5. सेवक पार्क कालोनी।
6. फ्रैण्ड्स एन्क्लेव, सैक्टर 5 एवं 6, सुल्तानपुरी रोड।
7. एफ ब्लॉक, साध नगर पार्ट-2।
8. प्रताप विहार, किरण एक्सटेंशन, नांगलोई।
9. ई-ब्लॉक (पार्ट), सुभाष मोहल्ला, उत्तरी घोण्डा।
10. हरिजन बस्ती, सुदामापुरी, बाबरपुर, शाहदरा।
11. गली नं० 1—8, सुभाष मोहल्ला, उत्तरी घोण्डा।
12. कोट पोट्टर्स बस्ती, होजरानी, मालवीय नगर।
13. आनन्द विहार, गुरप्रीत नगर, उत्तम नगर।
14, पश्चिमी कान्ति नगर।
15. गणेश नगर, पाण्डव नगर।

16. ए बी सी एवं डी ब्लॉक, खजूरीखास।
17. महीपालपुर गांव एक्सटेंशन।
18. विजय एन्क्लेव (सी एवं डी ब्लॉक) विनोदपुरी।
19. ओ ब्लॉक, उत्तर नगर एक्सटेंशन।
20. ई एण्ड एफ ब्लॉक, विश्वास पार्क, उत्तम नगर।
21. खजूरी एक्सटेंशन, एफ ब्लॉक।
22. मांगेराम पार्क पूठकलां।
23. बादली एक्सटेंशन, पार्ट-ए, आउटर रिंग रोड
24. चन्दूनगर, ।
25. कैलाशपुरी, पश्चिमी।
26. यादव पार्क, नांगलोई।
27. लैफ्ट आउट पॉकिट ऑफ फ्रैण्ड्स एन्क्लेव, पूर्वी नांगलोई।
28. माता दुर्गा मन्दिर, कोण्डली।
29. महावीर विहार।
30. पुल पहलाद।
31. जगदम्बा बिहार।
32. ई एण्ड टी ब्लॉक, दयाल पार्क, पश्चिमी सागरपुर।
33. केवशराम पार्क।
34. तमिलार एन्क्लेव।
35. बुद्धविहार कालोनी।
36. ताजपुर पहाड़ी।
37. लैफ्ट आउट पॉकेट ऑफ राजापुरी, उत्तम नगर।
38. मुस्तफावाद।
39. टोडरमल ब्लॉक, प्रेम नगर।
40. गोपाल नगर बी ब्लॉक, नजफगढ़।
41. संजय मोहन डी ब्लॉक, भजनपुरा।
42. लैफ्ट आउट पॉकट नोल्लर बैण्ड, एक्सटेंशन।
43. भारत विहार, कालोनी, उत्तम नगर।

44. ढ़ाका जौहर कालोनी (इन्दिरा विकास कालोनी)।

45. दुर्गापुरी लैफ्ट आउट पॉकेट एण्ड द्वारीकापुरी (विजय एन्क्लेव)।

46. महावीर गन्क्लेव डी एण्ड पी ब्लॉक।

अन्तरण वाउचर जारी करना

3445. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में किसी उपभोक्ता के अनुरोध पर रसोई गैस के डीलरों द्वारा किसी दूसरी गैस एजेंसी को अन्तरण वाउचर जारी करने की प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली-राजकोट और बम्बई-राजकोट के बीच दैनिक उड़ानें

3446. **श्री एस० एन० बेकारिया** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और राजकोट के बीच उड़ानें बन्द कर दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का लोगों तथा व्यापारी वर्ग की मांग को ध्यान में रखते हुए राजकोट-दिल्ली तथा बम्बई-राजकोट के बीच कोई दैनिक उड़ान शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) परिचालन विमान क्षमता की कमी के कारण नवम्बर, 1989 में दिल्ली-राजकोट की उड़ानें बन्द कर दी गई थीं।

(ग) और (घ) इस समय इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत बम्बई और राजकोट के बीच सप्ताह में क्रमशः तीन दिन और चार दिन सेवाओं का परिचालन करते हैं। इंडियन एयरलाइंस का वर्ष 1991 की शरदकालीन समयावलि में बम्बई और राजकोट के बीच एक दैनिक सेवा शुरू

करने का प्रस्ताव है।

विमान-क्षमता की कमी के कारण दिल्ली और राजकोट के बीच सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

गुजरात और महाराष्ट्र में और गैस टर्मिनल की स्थापना

3447. **श्री तेजसिंह राव भोंसले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितना प्राकृतिक गैस उत्पादित की जाती है और यह किन-किन क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है,

(ख) प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ग) मुम्बई हाई और समुद्र तट से दूर अन्य क्षेत्रों में उत्पादित प्राकृतिक गैस को पम्प करने के लिए किन-किन स्थानों पर अवस्थित गैस टर्मिनल हैं,

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में अतिरिक्त गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है,

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है,

(च) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/भारतीय प्राधिकरण लि० को भूमि आवंटित करने का वचन दिया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1990-91 में पश्चिमी अपतट, गुजरात, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन व तमिलनाडू के कावेरी बेसिन में स्थित तेल व गैस के क्षेत्रों से 17998 मि० घन मीटर गैस (कुल) का उत्पादन किया गया था।

(ख) नीलम, मुक्ता, पन्ना, बाम्बे हाई फील्ड में एल-II व एल-III के अतिरिक्त विकास सहित सरकार ने अनेक तेल एवं गैस विकास परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

(ग) उरान (महाराष्ट्र) तथा हजीरा (गुजरात) में।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (छ) उसार (महाराष्ट्र) में भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है।

गुजरात में पीपावव में एक टर्मिनल की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पूर्णिया, बिहार के लिए वायुदूत सेवा

3448. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उत्तरी बिहार के पूर्णिया, संभाग को वायुदूत सेवाओं से जोड़ने का है,

(ख) यदि हां, तो इसे विमान सेवा द्वारा देश के अन्य भागों से कब तक जोड़े जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ग) वायुदूत को हो रही भारी हानि के कारण उसे अपने नेटवर्क में अत्यधिक कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है। वर्तमान स्थिति में वायुदूत द्वारा नए स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

कुटीर ज्योति योजना

3449. **श्री जे० चोक्का राव** :क्या **विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर ज्योति योजना गरीबों के लिए शुरू की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है,

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य बिजली बोर्डों को पूरा धन दिए बिना ही उस पर ब्याज अर्जित किया है और प्रत्येक लाभार्थी से सेवा शुल्क के रूप में 5-5 रुपये भी काटे हैं;

(घ) यदि हां, तो अर्जित ब्याज और सेवा शुल्क के रूप में की गई कटौतियों का ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को यह निर्देश देने का प्रस्ताव है कि वह संबद्ध राज्यों को ब्याज और सेवा शुल्क लौटा दे,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबी की रेखा

से नीचे रह रहे गरीब ग्रामीणों को सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति स्कीम हेतु 25 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो कि कुटीर ज्योति स्कीम का संचालन करता है, द्वारा 5/-रु० प्रति कनेक्शन की दर से अनुमानतः 59 लाख रुपये की राशि सेवा प्रभारों के रूप में वसूल की गई। राज्य सरकारों को दी गई सेवाओं के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को, उनके द्वारा अर्जित सेवा प्रभारों को रेमिट करने हेतु, निदेश देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

3450. **श्री राम बदन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक जारी किए गए रसोई गैस कनेक्शन की जिलावार संख्या क्या है,

(ख) नये कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदनों की जिलवार संख्या क्या है; और

(ग) इन्हें शीघ्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 1.4.1991 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 9.05 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे। उत्तर प्रदेश में यथा संभव अधिकतम आवेदकों को एल० पी० जी० कनेक्शन दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

इब ताप बिजली केन्द्र, उड़ीसा

3451. **श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के इब ताप बिजली केन्द्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के एककों (2×210 मेगावाट) की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि नियत करने का है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) योजना आयोग ने 887.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इब घाटी ताप विद्युत

परियोजना (4×210 मेगावाट) को और इसे राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में शामिल किए जाने को अप्रैल, 1987 में अनुमोदित किया था। निधि सम्बन्धी बाधाओं के कारण राज्य प्राधिकारियों ने इस परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित करने का निर्णय किया था। सभी चारों यूनिटों की आधारभूत संरचनाओं सहित प्रथम चरण में 1 एवं 2 यूनिटों (2×210 मेगावाट) की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना की गई है। चरण-2 में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों (यूनिट 3 एवं 4) की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना की गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बिजली उपलब्धता की स्थिति

3452. **श्री अर्जुन सिंह यादव**
श्री गोपीनाथ गजपति
श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री राजेन्द्र कुमा शर्मा
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा

: क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां बिजली की कमी है; और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 91—जुलाई, 91 के दौरान विद्युत आपूर्ति वितरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण तथा वितरण हानियों की मात्रा में कमी करना, मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना और अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था करना।

विवरण

क्षेत्र/ राज्य/ प्रणाली	अप्रैल, 91—जुलाई, 1991			(प्रतिशत)
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	231	231	0	0.0%
दिल्ली	3262	3213	49	1.5%
हरियाणा	3271	3197	74	2.3%
हिमाचल प्रदेश	476	476	0	0.0%
जम्मू कश्मीर	1010	976	34	3.4%
पंजाब इनक्लूडिंग एन० एफ० एफ०	6538	6016	522	8.0%
राजस्थान	3880	3849	31	0.8%
उत्तर प्रदेश	10445	9441	1004	9.6%
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	29113	27399	1714	5.9%
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	8090	7772	318	3.9%
मध्य प्रदेश	6260	5999	261	4.2%
महाराष्ट्र	13110	12579	531	4.1%
गोवा	209	209	0	0.0%
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	27669	26559	1110	4.0%
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	7295	6320	975	13.4%
कर्नाटक	6205	4547	1658	26.7%
केरल	2385	2268	117	4.9%
तमिलनाडू	7685	7117	563	7.4%
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	23570	20252	3316	14.1%

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	2375	1618	757	31.9%
दामोदर घाटी निगम	2470	2002	468	18.9%
उड़ीसा	2715	2401	314	11.6%
पश्चिम बंगाल	3750	3383	367	9.8·/.
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	11310	9404	1906	16.9·/.
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	1031	965	66	6.4·/.
अखिल भारत	92693	84579	8114	8.8·/.

[अनुवाद]

राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पुरस्कार

3453. **श्री मुकुल वासनिक : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुकरणीय विशिष्ट नागर विमानन कर्मियों को अपना कर्तव्य निभाते समय उनकी वीरता और कार्यक्षमता के लिए "राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन पुरस्कार" और "राजीव गांधी राष्ट्रीय नागर विमानन पुरस्कार" आरम्भ करने सम्बन्धी सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की कीमतों की समान नीति

3454. **श्री काशीराम राणा : क्या कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैस और तेल की तरह देश में कोयले की कीमतों के बारे में भी कोई समान नीति स्वीकार करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० द्वारा पिट-हैड कोयले की कीमत एक ही ग्रेड के कोयले के लिए, चाहे वह कोयला किसी भी खान/क्षेत्र/कम्पनी द्वारा उत्पादित किया हो, समान रूप से निर्धारित की जाती है । इसी तरह

सिमरेनी कोलयरीज कम्पनी लि० के मामले में कोयले के पिट-हैड कीमत, यद्यपि यह कीमत कोल इंडिया लि० द्वारा ली जाने वाली कीमत से भिन्न हैं, कम्पनी की किसी भी खान में उत्पादन किए जाने वाले कोयले के एक ही ग्रेड के कोयले के लिए कीमत समान रूप में निर्धारित की जाती है।

माननीय सदस्य का इस सम्बन्ध में दिए गए सुझाव का आशय यह है कि उपभोक्ता द्वारा देय कोयले की सुपुर्दगी कीमत अंतः उपभोक्ता समान रूप में अदा करें जैसा की पेट्रोलियम के उत्पादों के मामले में होता है। कीमतों में इस तरह की समानता को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है, यदि कोयले के मामले में एक समान भाड़ा योजना क्रियान्वित कर दी जाए।

इस समय कोयले के मामले में एक समान भाड़ा योजना को निम्नलिखित कारणों से शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है :—

(i) कोयला एक कम क्षमता वाली तथा बड़े स्वरूप की वस्तु है और इसलिए, इसकी सुपुर्दगी लागत में भाड़े का एक बड़ा तत्व विद्यमान है।

(ii) कोयला कई स्थानों पर उत्पादित किया जाता है और इसका उत्पादन कई ग्रेडों में होता है। कई उत्पादन केन्द्रों के लिए तथा विभिन्न ग्रेडों के 210 मि० टन कोयले के लिए भाड़े में समानता करने में अनेक कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी।

(iii) कोयले के मामले में भाड़े में समानता लाए जाने से कोयला क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ स्थानान्तरित हो जाएगा और इस कार्यवाई से इष्टतम स्थल और उपभोगकर्ता उद्योगों के स्थल के लिए किफायत सम्बन्धी सिद्धांतों में भी हस्तक्षेप होगा जिससे परिहार्य फजूलखर्ची को बढ़ावा मिलेगा।

वायुदूत सेवाएं पुनः शुरू करना

3455. **श्री शंकर सिंह बघेला**
डा० ए० के० पटेल } : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने केन्द्रों को वायुदूत सेवाओं से जोड़ा गया है और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं,

(ख) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान वायुदूत सेवाएं समाप्त कर दी गई थी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और ये सेवाएं कब तक पुनः शुरू किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 14 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार 42 परिचालनात्मक स्टेशनों की सुची विवरण-1 में दी गई है।

(ख) 54 स्टेशनों की सूची जहां से 1989-90 और 1990-91 के दौरान वायुदूत

सेवाएं हटा ली गई थीं, विवरण-2 में दी गई हैं।

(ग) इन स्टेशनों से वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से सेवाएं हटा ली गई थीं। वायुदूत की वित्तीय स्थिति के कारण इस मौजूदा हालत में वायुदूत के लिए अपने परिचालनों में बढ़ोतरी करना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण-1

14 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार परिचालनात्मक स्टेशनों की सूची :

क्षेत्र			
उत्तरी	दक्षिणी	पूर्वी	पश्चिमी
1. दिल्ली	1. हैदराबाद	1. कलकत्ता	1. बम्बई
2. कानपुर	2. विजयवाड़ा	2. जमशेदपुर	2. पुणे
3. लखनऊ	3. राजामुंदरी	3. एजवाल	3. कांडला
4. चण्डीगढ़	4. तिरूपति	4. सिल्चर	4. राजकोट
5. कुल्लू	5. मद्रास	5. गुवाहाटी	5. कोल्हापुर
6. लुधियाना	6. कोयम्बटुर	6. कूच-बिहार	6. पोरबंदर
7. जोधपुर	7. पाण्डेचेरी	7. अगरतल्ला	7. केशोड़
8. जैसलमेर	8. बंगलौर	8. कैलाशहर	8. औरंगाबाद
9. शिमला	9. बेलगाम	9. शिलांग	9. बड़ौदा
10. धर्मशाला	10. मदुरै		10. अहमदाबाद
11. देहरादून	11. कोचीन		
	12. अगत्ती		

कुल : [11+12+9+10=42 स्टेशन]

विवरण-2

वायुदूत स्टेशनों की सूची जहां से 1989-90 और 90-91 के दौरान सेवाएं हटा ली गई थीं।

उत्तरी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
जम्मू एवं कश्मीर	**त्रिपुरा**	**आंध्र प्रदेश**	**गुजरात**
1. जम्मू	19. कमालपुर	35. कुडप्पा	47. दीसा
2. राजौरी	**अरुणाचल प्रदेश**	36. रामागुंडम	**महाराष्ट्र**
उत्तर प्रदेश	20. जीरो	37. विशाखापट्टनम	48. रतनागिरी
3. इलाहाबाद	21. दीपारिजो	**कर्नाटक**	49. शोलापुर
4. आगरा	22. एलांग	38. वलैरी	50. उसमानाबाद
5. वाराणसी	23. पासीघाट	39. मैसूर	51. नागपुर
पंजाब	24. तेजू	40. हुगली	52. अकोला
6. भटिंडा	**पश्चिमी बंगाल**	**तमिलनाडू**	53. नांदेड़
राजस्थान	25. मालदा	41. तंजावूर	केन्द्र शासित प्रदेश
7. कोटा	**बिहार**	42. नेवली	**दमन और दीव**
8. जयपुर	26. गया	43. तिरूचरापल्ली	54. दमन
मध्य प्रदेश	27. धनबाद	44. मदुरै	
9. जबलपुर	28. पटना	**केरल**	
10. खुजराहो	29. रांची	45. कालीकट	
11. रीवा	**उड़ीसा**	केन्द्र शासित	
12. भोपाल	30. भुवनेश्वर	**पांडेचेरी**	
13. गुना	31. जयपोर	46. पांडेचेरी	
14. बिलासपुर	32. राउरकेला		
15. रायपुर	**मणीपुर**		
16. सतना	33. इम्फाल		
17. जगदलपुर	**नागलैण्ड**		
18. इंदौर	34. दीमापुर		

[हिन्दी]

एल० पी० जी० "बार्टलिंग" संयंत्रों की स्थापना

3456. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नए रसोई गैस "बार्टलिंग" संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन्हें स्थापित किया जाना है और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल कंपनियों द्वारा केरल में कालीकट व पालघाट में, आंध्र प्रदेश में कर्नूल में, राजस्थान में उदयपुर में तथा असम में सिलचर में नए भरण संयंत्र खोले जा रहे हैं। कोचीन व गोहाटी के संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

[अनुवाद]

केरल में एल० पी० जी० एजेंसियां

3457. **श्री कोड्डी कुनील सुरेश** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में वर्ष 1991-92 के दौरान एल० पी० जी० की एजेंसियां आबंटित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उसके जिला वार स्थान कहां-कहां हैं; और

(ग) भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान बन्द की गई एल० पी० जी० की एजेसियों का जिला वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि पूर्व विपणन योजनाओं में नियोजित एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, तथापि वर्ष 1991-92 के लिए किसी नए कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) एलेप्पी जिले में एक एजेंसी को कदाचार की वजह से समाप्त किया गया था।

जालना, महाराष्ट्र में हवाई पट्टी का निर्माण

3458. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार प्रत्येक जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित करने का है,

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में, जालना में हवाई पट्टी का निर्माण कब से आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराय सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का महाराष्ट्र में जालना पर हवाई पट्टी के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऐसी हवाई पट्टी का निर्माण आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

कानपुर (उत्तर प्रदेश) में रेल लाइन पर ऊपरी पुलों का निर्माण

3459. **श्री केशरी लाल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर रेल लाइनों पर ऊपरी पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है,

(ख) कानपुर सिटी और कानपुर देहात क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर वर्ष 1991 में ऊपरी पुल का निर्माण किया जाएगा जैसाकि स्थानीय जनता ने मांग की है,

(ग) इन पुलों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेल लाइनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा तथा कब तक समाप्त हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पांच।

(ख) कानपुर में ग्रांड ट्रंक रोड पर समपार संख्या 79-डी तथा नेत्र अस्पताल के पास समपार संख्या 6 के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की मांग की गई है।

(ग) जी० टी० रोड पर ऊपरी सड़क पुल को रेलवे के 1990-91 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है तथा कार्य के लिए योजना बनाई जा रही है। रेलों को कानपुर में नेत्र अस्पताल के निकट ऊपरी सड़क पुल के लिए अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) कार्यों का शुरू किया जाना नक्शों/अनुमान को अन्तिम रूप देने तथा खर्च को स्वीकृति प्रदान करने पर निर्भर करेगा। इनका पूरा किया जाना, मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच मार्गों के पूरा करने पर निर्भर करेगा।

सम्भल-मुरादाबाद के बीच गाड़ियों का रद्द किया जाना

3460. **श्री श्रीपाल सिंह यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संभल-मुरादाबाद के बीच चलने वाली । एस० आर० 2 एस० एच०, 3 एस० आर० एम० और 4 एस० आर० एम० सवारी गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का यात्रियों की सुविधा के लिए इन गाड़ियों को पुनः चालू करने या कोई नई गाड़ी चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यद्यपि 1 एस० आर०, 2 एस०आर० और 4 एस० आर० एम० गाड़ियों को लम्बित कर दिया गया है, 3 एस० आर० एस० गाड़ी की समय अनुसूची पुनः निर्धारित की गई है ।

(ख) बहुत कम लोकप्रिय होने के कारण ।

(ग) फिलहाल नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में फतुआ-इस्लामपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3461. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में कितनी मीटर गेज लाइनों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है अथवा बन्द किया गया है और उसके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) उनमें से कितनी और किन-किन रेल लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है और उन पर गाड़िया चलाई जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का फतुआ-इस्लामपुर लाइन सहित बकाया लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फतुआ-इस्लामपुर छोटी रेल लाइन, जिसका 1985 के संसद के एक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीकरण कर लिया गया था, के अलावा बिहार में सातवीं योजना अवधि के दौरान अन्य किसी रेल लाइन को बन्द नहीं किया गया था ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि से राजस्व की प्राप्ति

3462. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करके सरकार को

कुल कितना राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मूल्यों में संशोधन के परिणाम-स्वरूप प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय वर्ष के दौरान होने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक खपत पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

3463. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस समय कच्चे तेल की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है;

(ग) 1991-92 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अप्रैल से जून 1991 की तिमाही के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कच्चे तेल का उत्पादन करीब 7.35 मिलियम टन का था।

(ख) से (घ) वर्ष 1991-92 के लिए अनुमानित कच्चे तेल के उत्पादन के संशोधित आंकड़ों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशी पर्यटकों के लिए भारतीय द्वीपों का विकास

3464. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारतीय द्वीपों को विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां, विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने की दृष्टि से सरकार का द्वीप पर्यटन को विकसित करने का प्रस्ताव है। तथापि, द्वीप पर्यटन विदेशी तथा स्वदेशी दोनों पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगा।

तेनाली स्टेशन (गुन्टूर) पर प्लेटफार्मों का निर्माण

3465. **श्री उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेनाली स्टेशन (जिला गुन्टर) से अनेक गाड़ियों के गुजरने को देखते हुए वहां पर

नए प्लेटफार्मों का निर्माण तथा विद्यमान प्लेटफार्मों के विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि में रसोई गैस की एजेंसियां

3466. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में सभी तहसील मुख्यालयों को रसोई गैस की एजेंसियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजेंसियों को आबंटित करने में महिला सहकारी समितियों को वरीयता दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हाथरस में उपरिपुल

3467. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में हाथरस जंक्शन रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल निर्माण का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ किए जाने तथा कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हाथरस जंक्शन के निकट समपार सं० 95-ए० के बदले में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए रेलवे को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने तथा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान किए जाने के बाद ही रेलवे अपने भावी निर्माण कार्यक्रम में इसे शामिल करने के बारे में विचार करेगी।

[अनुवाद]

रेलवे का कार्यकरण

3468. **श्री भवन लाल खुराना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जून, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में

प्रकाशित "टाउट्स फलरिश, ट्रेल्स फ्लाउन्डर" समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या टिकटों के आरक्षण में भ्रष्टाचार, गाड़ियों को देर से चलना, पेय जल का अभाव और गाड़ियों में खान-पान के स्तर में गिरावट के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो इन शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार यात्रियों को और अच्छी रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और इसके कार्यकरण और आय में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय में हर महीने विभिन्न विषयों पर औसतन लगभग 40 शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ग) सेवाओं और वित्तीय स्थिति में सुधार करने का प्रयास, एक सतत और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बेटिकट यात्रा करना

3469. **श्री राजवीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में और जून, 1991 तक क्षेत्र-वार अब तक कितने यात्रियों को बेटिकट यात्रा करते गिरफ्तार किया गया है;

(ख) इन यात्रियों से जुर्माने के तौर पर वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जनवरी, 1990 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जिन्हें जेल भेजा गया उनकी संख्या और उनसे वसूल की गयी न्यायिक जुर्माने की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेलवे	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया/जिन्हें गिरफ्तार किया गया	जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या	वसूल की गई न्यायिक जुर्माने की राशि (लाख रुपयों में)
मध्य	33,353	17,879	16.82
पूर्व	48,738	20,543	9.60
उत्तर	36,554	18.985	35.08
पूर्वोत्तर	19,845	11,279	17.48

1	2	3	4
पूर्वोत्तर सीमा	1,305	410	1.46
दक्षिण	3,290	620	0.82
दक्षिण मध्य	29,240	8,252	7.51
दक्षिण पूर्व	7,495	4,448	0.93
पश्चिम	55,248	20,307	14.30
जोड़	2,35,068	1,02,723	104.00

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रसोई गैस की एजेंसियां

3470. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय रसोई गैस की जिला-वार कितनी एजेंसियां हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं और इनके द्वारा अब तक रसोई गैस के कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) जिला-वार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और उन्हें गैस कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) महाराष्ट्र में जिला-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां निकट भविष्य में गैस की नई एजेंसियां खोले जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1.4.91 के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

(1) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें	—	540
(2) क्रेताओं की क्षमता	—	30.46 लाख
(3) प्रतीक्षा सूची	—	11.61 लाख

महाराष्ट्र में यथासम्भव अधिकतम आवेदकों को एल० पी० जी० के कनेक्शन दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) विपणन योजनाओं तथा समय समय पर लागू नीति के अनुसार विभिन्न शहरों में एल० पी० जी० की नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं ।

बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना

3471. **श्री एच० डी० देवगौडा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बंगलौर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

असम और बिहार को सस्ती दरों पर गैस की आपूर्ति

3472. **कुमारी दीपिका चिखलिया** क्या : **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और बिहार को सस्ती दरों पर प्राकृतिक गैस सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) असम में पहले से ही रियायती दर पर गैस की आपूर्ति की जा रही है। बिहार को गैस की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

3473. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में अब तक रसोई गैस के लिए कितने प्राथियों के नाम दर्ज किये गये हैं; और

(ख) उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1.4.91 के अनुसार मध्य प्रदेश में 3.38 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे। मध्य प्रदेश में यथा सम्भव अधिकतम आवेदकों को एल० पी० जी० के कनेक्शन दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन से निकाले गए कच्चे तेल का शोधन

3474. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कावेरी बेसिन में तेल कुओं से निकाले गये कच्चे तेल के शोधन के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड तंजौर जिले के पननगुड्डी गांव में 114.30 करोड़ रुपए की लागत पर एक 0.5 मि०ट० प्रतिवर्ष की क्रूड आसवन इकाई स्थापित कर रही है।

विद्युत परियोजनाओं की लागत

3475. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए के अवमूल्य से केन्द्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि हद तक हुई है; और

(ग) इस वृद्धि किस को पूरा करने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में किए गए रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप प्रभावित राशि 6400 करोड़ रुपए से अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को अन्तिम रूप देते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा।

चांडिल ताप बिजली संयंत्र

3476. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चांडिल बिजली ताप परियोजना स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसे स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बिहार के सिंहभूम जिले में मै० आर० पी० जी० इन्टरप्राइजेज लि० द्वारा 2 × 250 मे० वा० का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जनवरी, 1991 में प्राप्त हुआ था। कोयला लिंकेज, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना और पर्यावरण तथा बन सम्बन्धी स्वीकृति जैसे निवेश अभी सुनिश्चित

किए जाने हैं। इन निवेशों के सुनिश्चित होते ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी।

विजयवाड़ा में कोयला स्टाक यार्ड की स्थापना

3477. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में एक कोयला स्टाक यार्ड स्थापित करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदना प्राप्त हुआ है ताकि जिले में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से और समय पर कोयला उपलब्ध कराया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) (क) से (ग) सरकार को विजयवाड़ा में कोयले का स्टाकयार्ड स्थापित करने के लिए अब तक कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, कोल इंडिया लि० द्वारा नीति के अन्तर्गत स्टाकयार्डों की स्थापना किए जाने के कार्य की उक्त स्टाकयार्डों की कार्यप्रणाली के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने के कारण समीक्षा की जा रही है। कोयले के स्टाक-यार्ड को स्थापित किए जाने तथा चलाए जाने के लिए राज्य सरकारों के अभिकरणों से किसी प्रस्ताव पर प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस की एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल के खुदरा-बिक्री केन्द्र

3478. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिला-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ख) क्या बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर संभागों में बहुत कम गैस एजेंसियां हैं और बहुत से कस्बों में एक भी गैस एजेंसी नहीं खोली गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संथाल परगना के इन कस्बों में गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1.4.91 के अनुसार बिहार में एल० पी० जी० की 41 डिस्ट्री ब्यूटरशिपें थीं।

(ख) से (ङ) एल० पी०जी० की नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें विभिन्न घटकों के आधार पर आबंटित की जाती हैं जिनमें शहरों की जनसंख्या, मात्रा/दूरी मानदंड,

आर्थिक व्यवहार्यता, विपणन योजनाएं तथा समय-समय पर लागू नीति शामिल हैं ।

[अनुवाद]

जिला वाराणसी में स्टेशनों का विकास

3479. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला वाराणसी में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास और उनको सुन्दर बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक स्टेशन के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अनुरक्षण पर होने वाले व्यय के आंकड़े स्टेशन-वार अथवा जिला-वार नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) अनुरक्षण के लिए स्टेशनवार राशि निर्धारित नहीं की जाती है । स्टेशन की हालत की आवश्यकतानुसार खर्च किया जाता है ।

महाराष्ट्र में सामान की चोरी

3480. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में समान से भरे, विशेषकर कच्चे लोहे और कोयले से भरे, बैगनों के मार्ग में ही गुम होने की सूचना मिली है;

(ख) क्या रेलवे विभाग को जनता से भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) 1990-91 और 1991-92 के दौरान दावेदारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है और इस समय कितने दावों का भुगतान शेष है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र मे गंतव्यों को भेजे गये कोयले और कच्चे लोहे के परेषणों की सुपुर्दगी न दिए जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) परेषणों का पता लगाया और उनकी सुपुर्दगी की गयी अथवा सुमेल समायोजन किया गया और ऐसा न होने पाने के मामले में मुआवजे का भुगतान किया गया था ।

(घ) 1990-91 के दौरान दावेदारों का मुआवजे के रूप में 30.26 लाख रुपए का

भुगतान किया गया। 1991-92 के दौरान अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस समय निपटान के लिए 44 दावे लम्बित पड़े हैं जिनमें 43 दावे कोयले के हैं और एक दावा कच्चे लोहे का है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी पिछली रिक्तियां

3481. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितनी रिक्तियों को भरा नहीं गया है;

(ख) अब तक उनमें से कितनी रिक्तियों को भरा जा चुका है; और

(ग) क्या सरकार का विचार शेष रिक्तियों को विशेष भर्ती कार्यक्रम द्वारा भरने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पद इस प्रकार हैं :

को समाप्त वर्ष	ग्रुप ए		ग्रुप बी	
	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० ज०	अ० ज० जा०
31.3.88	—	4	इस ग्रेड में सीधी भर्ती	
31.3.89	—	—	के लिए कोई प्रावधान	
31.3.90	16	12	नहीं है	

को समाप्त वर्ष	ग्रुप सी		ग्रुप डी	
	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० ज०	अ० ज० जा०
31.3.88	1679	3192	1346	3965
31.3.89	2312	2492	2384	4104
31.3.90	1725	2057	1556	2321

(ख) कमी को दूर करना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, कमी को दूर करने के लिए सामान्य भर्ती के अलावा हर वर्ष की गयी भर्ती इस प्रकार है :—

को समाप्त वर्ष	ग्रुप "ए"		ग्रुप "सी"	
	अ० ज०	अ० ज० जा०	अ० ज०	अ० ज० जा०
31.3.88	—	4	1436	1320
31.3.89	—	—	2182	2302
31.3.90	—	—	1422	1676

	ग्रुप "डी"	
	अ० ज०	अ० ज० जा०
31.3.88	2084	2551
31.3.89	3114	4440
31.3.90*	1161	1291

*28.2.1991 की स्थिति। संघ लोक सेवा आयोग ने 1990 के बकाया रिक्त पदों के लिए ग्रुप "ए" में अनुसूचित जाति के 16 तथा अनुसूचित जनजाति के 12 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की है।

(ग) वर्ष 1990 में चलाया गया विशेष भर्ती अभियान अभी भी जारी है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन विकास

3482. **श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1990-91 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दी है :—

	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1. मवाला में पर्यटक गृह	8.39
2. अन्नावरम, पूर्व गोदावरी जिले में वन गृह	8.43
3. वेनूकोण्डा में पर्यटक बंगला	8.28
4. एल्लूरू में मार्गस्थ सुविधाएं	8.76
5. अनुपू/नागार्जुनसागर में पर्यटक बंगला	8.50
6. वारंगल किले में रेस्तरां	8.88
7. कोण्डापल्ली किले में स्नैक बार	4.40
8. टैंक बांध हुसैनसागर झील, हैदराबाद में रेस्तरां	4.25
9. बोरा गुफाओं में प्रकाश-पुंज व्यवस्था	4.50
10. जल क्रीड़ा उपस्कर	9.08

1991-92 के दौरान, अभी तक निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

1. शमिरपेट में पर्यटक परिसर	16.59
2. भवानी द्वीप पर कुटीरें एवं रेस्तरां	17.50
3. पेमबारती में पर्यटक गृह	9.48
4. पेनूकोण्डा में पर्यटक गृह	9.48
5. काल्लूरू में पर्यटक गृह	9.48
6. थालकोण्डा में पर्यटक बंगला	9.48

इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 64.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक पर्यटक परिसर, दो स्थानों पर समुद्रतट विहार-स्थलों और प्रचार सहायता के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव किया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) की बिल प्रणाली हेतु समितियां

3483. **श्री तारा चन्द खण्डेलवाल** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समय-समय पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) की बिल तैयार करने की प्रणाली एवं उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने समितियों की रिपोर्टों का परीक्षण किया है,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दि० वि० प० सं० की बिल तैयार करने की प्रणाली को सरल बनाने के लिए नए सिरे से की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार, डेसू की बिलिंग प्रणाली एवं इसके द्वारा प्रतिभूति राशि की वापसी संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा एक अध्ययन किया गया था। अपनी रिपोर्ट में उक्त विभाग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ ये सुझाव दिए गए हैं :—मीटर-शीट तैयार करने के सम्बन्ध में सभी जिलों में एक समान प्रक्रिया अपनाना, रोटेशनल मीटर रीडिंग संबंधी व्यवस्था लागू करना, ऐसे कनैक्शनों का पता लगाना जहां एक वर्ष से अधिक समय से बिल जारी नहीं किए गए है, परीक्षण आधार पर स्पाट बिलिंग प्रणाली लागू करना, मासिक/द्विमासिक आधार पर पहला बिल वास्तविक रीडिंग के आधार पर तथा अगला बिल असैस्मेंट आधार पर जारी किए जाने की संभावना का पता लगाना, सरकारी आवास के मामले में प्रतिभूति राशि जमा किए जाने और निजी आवास के मामले में प्रतिभूति राशि के अन्तरण संबंधी प्रणाली को समाप्त करना आदि।

अध्ययन दल द्वारा दिए गए सुझावों में से कई सुझावों को कार्यान्वित किए जाने और डेसू में बिलिंग पद्धति में सुधार एवं इसे सरल किए जाने तथा कम्प्यूट्रीकृत बिलिंग पद्धति को आनुक्रमिक रूप से सुस्थिर किए जाने के परिणामस्वरूप, डेसू द्वारा गलत बिल भेजे जाने एवं विलम्ब से भेजे जाने संबंधी घटनाओं में काफी कमी हुई है।

(ङ) इस समय डेसू की उपभोक्ता बिलिंग पद्धति कम्प्यूट्रीकृत है तथा इससे संतोषजनक रूप से काम चल रहा है। मुख्य कम्प्यूटर केन्द्र से बिजली के बिलों से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने एवं उक्त केन्द्र को वापिस सम्प्रेषित करने के लिए डेसू द्वारा अपने 24 जिला कार्यालयों में से 23 में कम्प्यूयर टर्मिनल प्रतिष्ठापित किए गए हैं। इससे बिजली के बिलों संबंधी शिकायतों पर उपयुक्त रूप से कार्यवाही करने/उन्हें दूर करने में सहायता मिलती है। वर्तमान कम्प्यूट्रीकृत बिलिंग प्रणाली के माध्यम से कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है। इस संबंध में डेसू द्वारा उपभोक्ताओं आदि से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

खनन क्षेत्रों का अपेक्षित विकास न किया जाना

3484. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयला खनन क्षेत्रों का अपेक्षित विकास नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खनन क्षेत्रों का समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोयला उद्योग को राष्ट्रीयकृत किए जाने से पूर्व कोयला खान क्षेत्रों को विकसित किए जाने का कार्य अपर्याप्त रूप में किया जाता था। कोयला उद्योग को वर्ष 1973 में राष्ट्रीयकृत किए जाने के बाद से कोयला कंपनियां अपने कर्मचारियों तथा आम जनता दोनों के ही जीवन के स्तर में सुधार किए जाने में विशेष प्रयास कर रही है। कोयला कामगारों की कल्याण संबंधी सुविधाओं में और पर्यावरणीय तथा कोयला क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी में भी काफी सुधार किया गया है। इस दिशा में पंचवर्षीय योजनाओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कदम उठाए गए हैं—20 सूत्री कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना, अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए जनजाति उप-योजना; और आम जनता के लाभ के लिए सामुदायिक विकास योजना।

काकीनाडा-कोटीपल्ली रेलवे लाइन

3485. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी**
श्री के० वी० आर० चौधरी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा कोटीपल्ली और अमलापुरम को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1987 में किए गए सर्वेक्षण से पता लगा है कि यह परियोजना अलाभप्रद है। इस समय रेलें संसाधनों की तंगी का सामना कर रही हैं अतः इस कार्य को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती।

अरुणाचल प्रदेश में तेल भण्डार

3486. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम भंडार मिले हैं और उनकी संभावित मात्रा कितनी है,

(ख) क्या वहां कोई खुदाई कार्य प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अरुणाचल प्रदेश के खारसंग और कुमचई में हाइड्रोकार्बन के वाणिज्यिक दोहन योग्य भंडार पाए गए हैं। इन क्षेत्रों में दिनांक 1.1.1991 की स्थिति के अनुसार बकाया प्रतिप्राप्ति योग्य तेल का भंडार 5.7 मिलियन टन का है।

(ख) व (ग) अन्वेषण के लिए खारसंग क्षेत्र में 1968 में और कुमचाई क्षेत्र में 1977 में खुदाई का कार्य शुरू हुआ था।

केरल के लिए सुपरफास्ट रेल गाड़ी

3487. **श्री ई० अहमद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल और कर्नाटक जाने के लिए केरल मंगला एक्सप्रेस में आरक्षण हेतु बहुत भीड़ होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केरल के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार एक और सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

बायो-गैस ऊर्जा का उत्पादन

3488. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो-गैस ऊर्जा के उत्पादन से गढ़वाल की पहाड़ियों में वनों की कटाई दर में कमी आएगी,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र में और अधिक बायो-गैस इकाइयां स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। बायोगैस ऊर्जा के दोहन से जलावन लकड़ी की खपत में कमी आने और उससे वनों की कटाई की दर में कमी आने की आशा है।

(ख) और (ग) राज्य नोडल विभाग तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के पांच जिलों में 1991-92 के लिए क्रमशः 140 तथा 305 पारिवारिक बायो गैस यूनिटें स्थापित करने के लक्ष्य के कार्य को हाथ में लिया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की समय पूर्व निवृत्ति

3489. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987, 1988 और 1989 के दौरान कितने रेल अधिकारियों को समय से पूर्व हटाया गया अथवा सेवा निवृत्त किया गया और उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने लोग थे; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	बर्खास्त किए गए		सेवानिवृत्त किए गए
	कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०
1987	12	3	1
1988	18	5	—
1989	21	5	—
जोड़	51	13	1

(ख) उपर्युक्त 51 अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के 3 अधिकारियों सहित ग्यारह अधिकारियों को अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सेवा से हटाया/बर्खास्त/अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया था। अनुसूचित जाति के 10 तथा अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी सहित शेष 40 अमिकारियों को भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम II के नियम 1802 (क) के अधीन जनहित में समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया था।

हवाई अड्डों पर रात के समय जहाज उतरने की सुविधाएं

3490. **श्री के० वी० तंगाबालू :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां पर रात के समय जहाज उतरने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) इस प्रकार की सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नीचे दिए गए हवाई अड्डों पर, जहां इंडियन एयरलाइन्स अनुसूचित उड़ानों का परिचालन करती है, रात्रि अवतरण सुविधा उपलब्ध नहीं है :—

(1) डिब्रूगढ़

(2) दीमापुर

(3) इम्फाल

(ख) लगभग दो वर्षों की अवधि में।

वेस्टलैंड हैलीकाप्टर

3491. **श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वेस्टलैंड हैलीकाप्टरों की उड़ानें स्थाई रूप से बन्द कर दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) जूहू, बम्बई में एक दुर्घटना होने के बाद, बेड़े को पहली बार 21 दिसम्बर, 1989 को ग्राउंड कर दिया गया था। हुसैनी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद इसे सितम्बर, 1990 में पुनः सेवा में लगा दिया गया था। नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियुक्त उप-समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में विमान-बेड़े को 9 फरवरी, 1991 से पुनः ग्राउड कर दिया गया था।

(ग) इन्हें दुबारा क्रियाशील बनाना संभव नहीं हो सका है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3492. **डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कितनी है और अन्य राज्यों को दी गई सहायता की तुलना में यह कितनी है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा 15.26 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता दी गई

थी। अन्य राज्यों को दी गई सहायता के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं :

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1990-91 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)
1.	बिहार	0.99
2.	गुजरात	1.37
3.	हरियाणा	0.23
4.	हिमाचल प्रदेश	1.17
5.	मध्य प्रदेश	4.27
6.	महाराष्ट्र	2.92
7.	उड़ीसा	5.77
8.	पंजाब	4.40
9.	तमिलनाडु	1.76
10.	प० बंगाल	4.03

तहबाजारी पर रेलवे की भूमि देना

3493. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तहबाजारी पर आवंटित रेलवे भूमि को स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से दिया जाता है;

(ख) आवंटन के लिए यह अनुमति कितने वर्षों के लिए दी जाती है; और

(ग) उत्तर रेलवे/पूर्वोत्तर रेलवे के तहबाजारी के आधार पर आवंटित कुल भू-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) तहबाजारी के लिए रेलवे भूमि को नए लाइसेंसों पर देना अमुमेय नहीं है। मौजूदा मामलों को अस्थायी तौर पर जारी रखा जा रहा है बशर्ते कि रेलवे के अपने उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता न हो।

(ग) चूंकि तहबाजारी की अनुमति विभिन्न अवधियों के लिए अस्थायी तौर पर दी जाती है और इसलिए समय-समय पर इस प्रकार दिया जाने वाला क्षेत्र भी अलग-अलग होता है।

[अनुवाद]

राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाएं

3494. **श्रीमती वसुन्धरा राजे**
श्री रामेश्वर पाटीदार } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य में इस समय दो लघु जल विद्युत स्कीमें और तीन मिनी जल विद्युत स्कीमें क्रियान्वयनाधीन हैं। स्कीमों का ब्यौरा और इनको चालू किए जाने की सम्भावित कार्यसूची निम्नवत् है :—

क्र० सं०	स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)	चालू किए जाने की सम्भावित कार्यसूची
1.	सूरतगढ़ जल विद्युत स्कीम	2×2=4	1991-92 (दोनों यूनिटों को जून, 91 में रोल किया गया)
2.	मंगरोल जल विद्युत स्कीम	3×2=6	1991-92 (सभी तीनों यूनिटों को जुलाई, 1991 में रोल किया गया)
3.	चरणवाला मिनी जल विद्युत स्कीम	1×1.2=1.2	1992-93
4.	पुगल मिनी जब विद्युत हाऊस-1 स्कीम	1×1.5=1.5	1993-94
5.	विद्युत हाऊस-2	1×.65=0.65	1991-92

ऐसी स्कीमें जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

जाखम जल विद्युत परियोजना जिसकी अनुमानित क्षमता 2×4.5 मेगावाट थी, योजना आयोग द्वारा पहले ही अक्तूबर, 1984 के दौरान स्वीकृत कर दी गई थी। तथापि, अन्वेषण सम्बन्धी किए गए अन्य कार्य के आधार पर राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्कीम सम्बन्धी विशिष्टियों में आशोधन किया गया था और संशोधित प्रतिष्ठापति क्षमता 2×2.5 मेगावाट वाली संशोधित परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 1991 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की जानी है। परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से जुलाई, 1984 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

ऐसी स्कीमें जोकि राज्य सरकार को लौटा दी गई हैं

कुल मिलाकर 372.4 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली चार जल विद्युत स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को शामिल किए जाने एवं एक स्कीम के बारे में निहित अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान किए जाने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु, इनको प्राधिकारियों को लौटा दिया गया था। स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जल विद्युत स्कीमों की सूची जिन्हें राजस्थान को पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु लौटाया गया है

क्र० सं०	स्कीम का नाम	परियोजना रिपोर्ट की तारीख/रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	राहूघाट	जून, 87 जून, 87	4×40=160	415.00	रिपोर्ट फरवरी, 88 में लौटा दी गई थी और मध्य प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय पहलुओं को निपटारा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने को कहा गया है।
2.	जवई	जनवरी, 89 मई, 86	2×0.61+ 2×0.6=2.4	6.00	राज्य प्राधिकारियों को विद्युत सम्बन्धी लाभों के निर्धारण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत वास्तविक प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करने को कहा गया था। रिपोर्ट नवम्बर, 88 में वापिस आई थी।
3.	कोटा पम्पड स्टोरेज	सितम्बर, 86 सितम्बर, 86	2×100=200	158.00 (जी) 3.00 (टी)	अक्तूबर, 89 में लौटा दी गई थी और अन्य अन्वेषण एवं विकल्पों की जांच किए जाने के बाद पुनः प्रस्तुत करने को कहा गया था। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इसे छोड़ दिया गया था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विकास हेतु वैकल्पिक स्थल की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
4.	माउन्ट आबू एम० पी० पी	अगस्त, 83	2×5=10	16.00	एम० पी० पी० होने के कारण, टी० ए० सी० द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही के० वि० प्रा० द्वारा स्कीम के विद्युत सम्बन्धी भाग के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा। परियोजना प्राधिकारियों की सलाह दी गई है कि पैनस्टाक तथा अन्य सिविल संरचनाओं की लम्बाई को कम करने हेतु विद्युत घर के लिए वैकल्पिक स्थल पर विचार किया जाये।

दिल्ली के प्लेटफार्मों पर शेड

3495. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के सभी प्लेट फार्मों को पूरी तरह से शेडों से ढकने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होगा; और

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन स्टेशनों पर पहले से ही उपलब्ध छतदार प्लेटफार्म निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त हैं।

लाईफलाइन एक्सप्रेस

3496. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लाईफलाइन एक्सप्रेस" नामक सर्वप्रथम पटरी हस्पताल को नर्सों, डाक्टरों, आपरेशन पश्चात् देखभाल की कमी, आदि समस्याओं का सामना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं,

(घ) इस हस्पताल से अब तक कुल कितने रोगियों का उपचार किया गया है; और

(ङ) इस हस्पताल में अब तक किस प्रकार के रोगों का उपचार किया गया है; और किन-किन रोगों का उपचार किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) "जीवन रेखा" परियोजना (लाईफलाइन एक्सप्रेस) इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन नामक एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा शुरू की गई है और चलाई जा रही है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, रेल मंत्रालय को इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के लिए बड़ी लाइन के मात्र 3 सवारी डिब्बे उपलब्ध कराने थे और उनके ढांचे में परिवर्तन करके उन्हें चलाने/खड़ा करने की व्यवस्था करनी थी। इस चलते-फिरते अस्पताल के संचालन के लिए चिकित्सा उपस्कर और कर्मचारियों की व्यवस्था सहित अपेक्षित सभी सामाजिक, तकनीकी और चिकित्सा सम्बन्धी कार्य इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा किए जाने हैं। रेल मंत्रालय को किसी प्रकार की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन ने शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन और बधिर व्यक्तियों के उपचार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया था।

अहमदनगर को विमान सेवा से जोड़ना

3497. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अहमदनगर को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वायुदूत को हो रही भारी हानि के कारण उसे अपने नेटवर्क में अत्यधिक कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है। वर्तमान स्थिति में वायुदूत द्वारा नये स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को बुक स्टाल आवंटित करना

3498. **श्री बारे लाल जाटव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं,

(ख) क्या इन स्टालों का अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण करने का कोई प्रावधान है,

(ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को क्षेत्र-वार कुल कितने बुक स्टाल आवंटित किए गए; और

(घ) 30 अप्रैल, 1991 को केन्द्रीय रेलवे में डिवीजन-वार कुल कितने बुक स्टाल थे और उनमें से कितने बुक स्टाल अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को आवंटित किए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार सभी नए बुक स्टाल ठेके बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारिताओं, भागीदारों, एसोसिएशनों और वास्तविक कामगारों तथा वेंडरों की सहकारी समितियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

3499. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर जिलों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है,

(ख) शेष गांवों में कब तक विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है,

(ग) प्रति वर्ष कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार हैं; और

(घ) इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों में विद्युतीकृत गांवों की संख्या उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नवत् है :—

जिले का नाम	**31.3.1991 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव**
झांसी	513
ललितपुर	320

(ख) से (घ) राज्य के समेकित लक्ष्य और योजना आयोग द्वारा निर्धारित परिव्यय पर निर्भर करते हुए राज्य स्तर पर ही जिलेदार प्राथमिकताओं को अन्तिम रूप दिया जाता है। 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार समग्र उत्तर प्रदेश राज्य में गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या 30,001 है। वर्ष 1991-92 के लिए 1550 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने हेतु योजना आयोग ने 7975/- लाख रुपये आबंटित किए हैं। 1991-92 के दौरान झांसी में 10 गांवों और ललितपुर जिले में 15 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का प्रस्ताव है। शेष गांवों का विद्युतीकरण किया जाना मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा अर्जित लाभ

3500. **डा० जी० एल० कनोजिया :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान एअर इंडिया ने कुल कितना लाभ अर्जित किया,

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान एअर इंडिया के बेड़े में कुछ और एअरबसों को शामिल करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एयर इंडिया ने वर्ष 1990-91 के दौरान 81.23 करोड़ रुपए (अनंतिम अनुमान) का निवल लाभ अर्जित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातस्थिति में सोवियत विमान को उतारना

3501. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में सोवियत विमान को उतारा गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या विमान अथवा इसके चालक दल के सदस्यों को कोई क्षति पहुंची है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जनपथ होटल में रेस्त्रां का निर्माण

3502. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के जनपथ होटल में अपने मैंडरिन रेस्त्रां के सामने पार्क में एक रेस्त्रां आदि के निर्माण का काम आरम्भ किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी/अनुमति प्राप्त कर ली गई है,

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस निर्माण के लिए मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान रेस्टोरंटों में लाभदायी व्यापार न होने के कारण भी इस विस्तार के किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम मैंडरिन रेस्तरां के बाहर अप्रयुक्त क्षेत्र को, उसमें भोजन स्टाल खुलवा कर और तिरपाल के आकार में सायबान की व्यवस्था करके ओपन एअर फूड प्लाजा बदल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह कोई स्थाई निर्माण नहीं है।

(ग) सरकार ने इस कार्य के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को 10.00 लाख रु० का अनुदान स्वीकृत किया है।

(घ) ओपन एअर फूड प्लाजा, केन्द्रीय दिल्ली क्षेत्र में आने वाले विशेषकर मध्य/निम्न

आय वर्ग के यात्रियों/पर्यटकों को तत्काल आवश्यक भोजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खोला जा रहा है।

अगरतला आने जाने के लिए विमान किराए में रियायत देना

3503. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में रेल तथा सड़क परिवहन की सुविधाओं की कमी देखते हुए और राज्य की राजधानी के साथ कोई रेल सम्पर्क न होने के कारण सरकार का अगरतला आने जाने के लिए विमान किराये में रियायत देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत दोनों ही अगरतला से कलकत्ता और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अन्य स्टेशनों के लिए आने और जाने पर अपनी सेवाओं के लिए सामान्य किराये की तुलना में कम किराया वसूल करते हैं।

विदेशी सहयोग से तेल की खोज

3504. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से किन स्थानों तथा ब्लाक क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज की जा रही है तथा विदेशी सहयोग कम्पनियों के नाम क्या हैं,

(ख) विदेशी सहयोग से खोज के लिए किन अन्य स्थानों एवं ब्लाक क्षेत्रों की पहचान की गई है,

(ग) पहले से चल रहे विदेशी सहयोग के निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है,

(घ) पहले किए गए समझौतों की तुलना में, गैर सरकारी क्षेत्र के विदेशी सहयोग कर्ता कम्पनियों के साथ प्रस्तावित निबंधन और शर्तों में यदि कोई परिवर्तन किया गया है, तो वह क्या है,

(ङ) क्या आवश्यक पूंजीगत संसाधनों एवं तकनीकी जानकारी रखने वाली विदेशी सहयोग कम्पनियों की एक छोटी सूची में शामिल कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) व (ग) फिलहाल उत्पादन हिस्सेदारी संविदा(प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रैक्ट) के अधीन मैसर्स इंटर नेशनल पेट्रोलियम

लि० एवं मैसर्स हार्डी ऑयल एण्ड गैस (यूके) लि० द्वारा कृष्णा-गोदावरी के अपतटीय क्षेत्र में 1620 वर्ग कि०मी० के एक ब्लॉक की खोज की जा रही है। कावेरी तथा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में सोवियत सहायता से टर्न-की संविदा के तहत भी अन्वेषण किया जा रहा है।

(ख) व (घ) बोली के प्रस्तावित चतुर्थ चक्र में लगभग 72 ब्लाकों (अपतटीय व तटीय दोनों) की अन्वेषण के लिए पहचान की गई है। विस्तृत नियम एवं शर्तों का ब्यौरा देते हुए निविदा आमंत्रण सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सांताक्रूज हवाई अड्डे के लिए नया स्थान

3505. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सांताक्रूज हवाई अड्डे का जीवन काल केवल वर्ष 2000 तक ही है,

(ख) यदि हां, तो सरकार वैकल्पिक हवाई अड्डा बनाने के लिए स्थान ढूंढने के लिए क्या कदम उठा रही है,

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजना के लिए नया स्थान ढूंढ लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) अगली शताब्दी के प्रारम्भ में ही बम्बई में एक और हवाई अड्डे के निर्माण की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में ब्योरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

बिहार के जिलों को राजधानी से जोड़ना

3506. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन जिलों के नाम क्या हैं, जिन्हें अभी तक राज्य की राजधानी को विमान सेवा द्वारा नहीं जोड़ा गया है,

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक जिले को राज्य की राजधानी से विमान सेवाओं द्वारा जोड़ने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) बिहार में रांची ही केवल एक ऐसा स्टेशन है जो उसकी राजधानी से इंडियन एयरलाइंस की हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

(ख) से (घ) स्थानों को उनके जिला मुख्यालय होने के आधार पर हवाई सेवा से नहीं जोड़ा जाता है बल्कि उन्हें हवाई सेवा उपलब्ध कराने की आर्थिक सक्षमता के आधार पर हवाई सेवा से जोड़ा जाता है। देश में सभी जिला मुख्यालयों को हवाई सेवा उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

किशनगंज/दलकोहा में रेलवे फाटक पर उपरिपुल

3507. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**
श्री राम विलास पासवान
श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार सेक्शन (बिहार) के अन्तर्गत किशनगंज/दलकोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे फाटक पर उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दोनों कार्यों को शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) रेलवे के साथ मिलकर लागत में भागीदारी के आधार पर किशनगंज स्टेशन के निकट मौजूदा समपार सं० एस० के०/317 के बदले में एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण तथा निक्षेप शर्तों के आधार पर दलकोहा स्टेशन के निकट एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव है। अतः राज्य सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार लागत में भागीदारी वहन करने की विधिवत सहमति के साथ-साथ, ठोस योजनाओं को अन्तिम रूप देने तथा उन्हें प्रायोजित करने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विमान सेवाएं

3508. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं,

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं; जहां चालू वर्ष के दौरान विमान सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या इंदौर हवाई अड्डे का विकास करने का कोई प्रस्ताव है जिससे वहां बोइंग विमानों के उतरने की सुविधा प्रदान की जा सके,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी,

(ङ) क्या इंदौर-भोपाल-जबलपुर को नागपुर-कलकत्ता-अहमदाबाद-मद्रास से जोड़ने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इंदौर से प्रीतमपुर के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरू करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में रायपुर, भोपाल, इन्दौर खजुराहो और ग्वालियर विमान सेवा से जुड़े हुए हैं। चालू वर्ष में राज्य में किसी अन्य स्थान को विमान मार्ग से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बोइंग सेवाएं पहले से ही इन्दौर के लिए परिचालित की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। जबकि इन्दौर और अहमदाबाद को हाल ही में विमान मार्ग से जोड़ा गया है तथापि, इस समय यातायात संभावना ऐसी नहीं है कि अन्य मार्गों पर विमान सेवा शुरू की जा सके। जबलपुर हवाई अड्डा इस समय बोइंग 737 परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

(च) जी, नहीं।

[अनुवाद]

भुसावल और बड़नेरा के बीच रेल दुर्घटनाएं

3509. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 से अप्रैल, 1991 के बीच मुम्बई-कलकत्ता सेक्शन में भुसावल और बड़नेरा के बीच कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप्रैल, 1990 से अप्रैल, 1991 के दौरान भुसावल और बड़नेरा के बीच 5 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) ये दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

हरियाणा को पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की पूर्ति

3510. **श्री राम प्रकाश चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान हरियाणा को इन मदों की कितनी मात्रा में पूर्ति की गई उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोधघाट ताप विद्युत परियोजना

3511. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की बोधघाट ताप बिद्युत परियोजना अनेक वर्षों से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बोधघाट ताप विद्युत परियोजना की प्रतिष्ठापना के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्राधिकारियों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कालीकट-मुम्बई विमान सेवा

3512. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कालीकट-मुम्बई के बीच विमानों की उड़ानों में वृद्धि की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) बम्बई और कालीकट के बीच 1 मई 1991 से दैनिक सेवा बी-787 विमान के स्थान पर ए-320 विमान से परिचालित की जा रही है, जिससे उपलब्ध क्षमता 126 सीटों से बढ़कर 168 सीट हो गई है। विमानन क्षमता की कठिनाई के कारण इंडियन एयरलाइंस इस समय इस सैक्टर में उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है।

एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण कोटा

3513. **डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसमी पास धारकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कर्णावती, नवजीवन, गोरखपुर, कोचीन और बंगलौर जैसी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सीजन टिकट धारियों को अधिकांश पैसेंजर गाड़ियों और कुछ मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने के लिए आवश्यक यात्रा सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं। बहरहाल, लम्बी दूरी की सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां होने के कारण, उन्हें इन गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

[**हिन्दी**]

बिहार की राई और खेलारी कोयलाखान क्षेत्रों में कालेज

3514. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **कोलया** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ के अन्तर्गत बिहार के राई और खेलारी कोयला खान क्षेत्रों में कोई भी कालेज नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ की राई कोलियरी में कोई कालेज विद्यमान नहीं है (खेलारी कोलियरी के नाम से कोई कोलियरी नहीं है)।

(ख) जी, नहीं। इसके लिए कर्मचारियों की ओर से कोई मांग नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

नाडियाड-कापडवंज सेक्शन का परिवर्तन एवं विस्तार

3515. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाडियाड-कापडवंज रेल लाइन को बदलने तथा मोदासा तक इसका विस्तार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) परियोजना के किस समय तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 41 प्रतिशत।

(ख) आमान परिवर्तन कार्य 1991-92 के दौरान शुरू किया जाएगा।

(ग) इस कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल में नया हवाई अड्डा

3516. **श्री टी० जे० अंजलोज :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में हवाई अड्डे के विस्तार के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की केरल में विमान क्षेत्रों के विस्तार की कोई योजनाएं नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद और टाटानगर के बीच नई यात्री गाड़ी

3517. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास धनबाद और टाटानगर के बीच बरास्ता पथेरडीह और सुदामडीह कोई नई यात्री गाड़ी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नई बड़ी रेल लाइनें

3518. **श्री दिलीप भाई संघानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में नई बड़ी रेल लाइनें बिछाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर बिछाये जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(i) भावनगर-तारापुर

(ii) वलसाड-धरमपुर-नासिक, और

(iii) बेडी, नवलखी और ओखा पोर्टों के लिए बड़ी लाइन का रेल सम्पर्क।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण ऊपर (i) और (ii) में दी गई लाइनों को फिलहाल शुरू नहीं किया जा सकता है। बेडी, नवलखी और ओखा पोर्टों को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का काम निक्षेप कार्य के रूप में शुरू किया जा सकता है क्योंकि ये एकल उपयोगकर्ता अर्थात् पोर्ट प्राधिकरण की विशिष्ट मांग के लिए अपेक्षित हैं। राज्य सरकार को समुचित रूप से सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की उड़ान सं० आई०सी० 409 और 410 को नियमित किया जाना

3519. **श्री ललित उरांव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की आई०सी०—409 और आई० सी० 410 संख्या की दैनिक उड़ानों में मई और जून, 1991 के दौरान विलम्ब होता रहा था;

(ख) क्या सरकार का इन उड़ानों को समयानुसार चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) मई और जून, 1991 के दौरान कुल 122 उड़ानों में से जो दिल्ली (आई० सी०-409) और कलकत्ता (आई० सी०-410) से होकर परिचालित की गई थी, 84 उड़ानों में इंजीनियरिंग खराबी, मौसम, हवाई यातायात नियन्त्रण और विविध कारणों से विलम्ब हुआ।

(ख) और (ग) 1 अगस्त, 1991 से कलकत्ता से आई० सी०-410 के प्रस्थान समय को 0615 बजे की जगह 0710 बजे संशोधित किया गया है ताकि रांची पर खराब मौसम के कारण

होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके। इण्डियन एयरलाइन्स स्थिति में सुधार लाने के लिए आई० सी-409/410 के परिचालन की समय-पाबन्दी पर निगरानी रखती है।

[अनुवाद]

बम्बई हाई से तमिलनाडु तक पाइपलाइन

3520. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने बम्बई हाई से तमिलनाडु तक प्राकृतिक गैस की एक पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इरादा उक्त गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) दक्षिण गैस ग्रिड मामले की अन्तर मंत्रालयीन दल द्वारा जांच की जा रही है।

धनबाद और जमशेदपुर से पटना तक वायुदूत सेवा

3521. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद और जमशेदपुर से पटना तक वायुदूत सेवायें कार्य कर रही हैं,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन नगरों के महत्व और विद्यमान अपर्याप्त परिवहन सम्पर्कों को ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं को फिर से चालू करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत लि० को देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में अत्यधिक कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है। इस समय वायुदूत की सेवाओं में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

असम में बिजली की जरूरत

3522. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में बिजली की कितनी जरूरत है और वहां उसका कितना उत्पादन हो रहा है तथा असम का केन्द्रीय पूल में और अन्य स्रोतों में कितना भाग है; और

(ख) राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 91 से जुलाई, 91 तक की अवधि के दौरान असम में ऊर्जा संबंधी आवश्यकता 699 मिलियन यूनिट थी जिसकी तुलना में असम के स्वयं के उत्पादन, केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से इसके हिस्से और पड़ौसी प्रणालियों/राज्यों से सहायता के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता 549.5 मिलियन यूनिट (मि० यू०) थी, इस प्रकार 49.5 मि० यू० (7.1%) की कमी रही।

(ख) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के उद्देश्य से असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

परियोजना का नाम	स्वरूप	क्षमता (मेगावाट)
(1) लोअर बोरपानी	जल-विद्युत	2×50
(2) धानसिरी	जल-विद्युत	15×1.33
(3) लाकवा गैस टर्बाइन	ताप-विद्युत	4×15
(4) लाकवा अपशिष्ट ऊष्मा	ताप-विद्युत	1×22

विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किए जा रहे अन्य उपायों में ये शामिल हैं :— नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तरण करना।

त्रिपुरा से गुवाहाटी तक सीधी रेल सेवा

3523. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा (कुमारघाट) से गुवाहाटी (आसाम) तक सीधी एक्सप्रेस व यात्री गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस क्षेत्र के यात्रियों की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चलाई जाएगी और यदि नहीं; तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण लमडिंग-बदरपुर खंड पर कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्रों का आयात

3524. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्रों का आयात किया है,

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है जहां से संयंत्र स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक संयंत्र का मूल्य कितना है; और

(ग) कार्यरत और कार्य न कर रहे संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनके खराब पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अनुसंधान तथा विकास शाखाओं सहित एक कूड़ा-कचरा भष्मीकरण एवं विद्युत उत्पादन परियोजना डेनमार्क की सहायता से 1987 में स्थापित की गई थी। यह परियोजना डेनमार्क की एक कम्पनी द्वारा टर्नकी आधार पर स्थापित की गई थी जिसने संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति की तथा जो इसके अभिकल्प और आवश्यक प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी थी।

(ख) यह परियोजना दिल्ली में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित की गई है जिसमें डेनमार्क की सहायता भी शामिल है।

(ग) जुलाई, 1990 में सरकार ने इस परियोजना को बन्द करने का निर्णय लिया क्योंकि डेनमार्क की कम्पनी संयंत्र का सफल प्रदर्शन करने में विफल रही।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

3525. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री राम बदन : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिलों में विद्युतीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और सरकार ने इन जिलों में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए जिले-वार कितनी परियोजनाएं स्थापित की हैं;

(ग) इन पर कितना व्यय हुआ और इन परियोजनाओं को कहां तक लागू किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया, ऐसे कितने गांव हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है और प्रत्येक जिले के शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिलों में 1987-88 से 1989-90 तक गांवों के विद्युतीकरण के लिए किसी प्रकार के औपचारिक सर्वेक्षण कार्य नहीं किए गए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में से प्रत्येक जिले में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या निम्नवत् है :—

क्र० सं०	जिला	1981 की जनगणना के अनुसार गांवों की कुल संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या	31.3.1991 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	गाजीपुर	2540	कुछ नहीं	2540
2.	बलिया	1920	214	1722
3.	जौनपुर	3254	149	2954
4.	आजमगढ़	4935	401	4528
	मऊ			

योजना आयोग द्वारा किन्हीं विशेष जिलों/गांवों हेतु ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है तथा राज्य के लिए कुल मिलाकर आबंटन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर इस बारे में प्राथमिकता सम्बन्धी निर्णय लिया जाता है। उपरोक्त जिलों में शेष गांवों का विद्युतीकरण किए जाने सम्बन्धी कार्यक्रम राज्य हेतु योजना आयोग द्वारा अनुमोदित समग्र आबंटन के अन्तर्गत इन जिलों हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए आबंटनों पर निर्भर करेगी। तथापि 1981 की जनगणना के अनुसार कुल मिलाकर 1,12,566 गांवों में से 31.3.1991 को उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 82,565 थी।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड की लाभप्रदत्ता और उसका राष्ट्रीयकरण समाप्त करना

3526. **श्री हरिन पाठक :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड लाभ कमा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) : जी, नहीं। कोल इंडिया लि० में अपनी स्थापना से, वर्ष 1981-82 तथा वर्ष 1989-90 में जबकि इसने क्रमश: 34.20 करोड़ रुपए और 80.13 करोड़ रुपए का लाभ कमाया के वर्षों छोड़कर घाटा होता रहा है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल की खोज और इसके आयात के लिए विश्व बैंक से ऋण

3527. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के तेल का उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा तथा मूल्य के तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार हाल ही में रुपए के अवमूल्यन के कारण तेल की और अधिक खोज तथा इसके आयात के लिए विश्व बैंक से ऋण ले रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1990-91 के दौरान देशी स्रोतों से लगभग 33 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया जिसका मूल्य 2235 रुपए प्रति टन की दर से लगभग 7375 करोड़ रुपए होता है। जो रिफाइनरियों द्वारा देय है। 10779 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 29.36 मिलियन कच्चा तेल आयात किया गया।

(ग) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल इंडिया लि० द्वारा चिकित्सा उपकरणों की खरीद

3528. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी सहयोगी कम्पनियों ने अपने विभिन्न अस्पतालों हेतु विदेशों से अति आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए आदेश दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अस्पताल कहां-कहां स्थित है तथा उनके इस्तेमाल के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए उपकरणों को खरीदने पर कितना खर्च किया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्पतालों की जांच की अवस्थिति, अधिप्राप्त किए जाने वाले उपकरणों के नाम और इस सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कम्पनी	अस्पताल का स्थान	उपकरण का नाम	कीमत
1	2	3	.4
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	वे०को०लि० मुख्यालय, नागपुर	सास लेने वाला उपकरण	1591.00 अमरीकी डालर
	बारकुल, छिंदवाड़ा	कम्प्यूटरिकृत पलमोनरी फक्शन लेबोरेटरी उपकरण	151339.37 अमरीकी डालर
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	काला, आसनसोल, बर्द्धमान	अंडर वाटर कैटिग डाइथ्रेमी मशीन	13509 डी० एम०
भारत कोकिंग कोल लि०	सेन्ट्रल हास्पिटल, धनबाद	ब्लड गैस एनालाइजर	41204 अमरीकी डालर
		पेटोथेरेपी यूनिट और जॉन्डीस मीटर	6796 अमरीकी डालर
		हॉल्टर मॉनीटर	12880 पौंड
		इन्क्यूबेटर	12923 पौंड
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	सेंट्रल अस्पताल रांची	कम्ब्रीलाइजर (एक सैट)	30.00 लाख रु०*
		एन्डोस्कोपिक उपकरण	146695 डी० एम०
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	तलचर बिलासपुर	कम्प्यूटरिकृत ट्रीड मिल (एक सैट))	28470 पौंड (एफ० ओ० बी०)
	बिलासपुर	—वही—)	
	बिलासपुर	2 (डी) इको कलर डोप्लर (एक सैट)	85860 अमरीकी डालर (एफ०ओ०बी०

1	2	3	4
	बिलासपुर	परोब फॉर अल्टरा साउंड स्केनर (एक सैट)	975000 जापानी येन (एफ० ओ० बी०)
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	सेंट्रल अस्पताल, सिगरौली	ट्रिड मिल से सुसज्जित कम्प्यूटरिकृत स्ट्रैस (एक सैट)	30387.5 अमरीकी डालर
		सिलिकोन-जैल फिल्ड कंडकिटव वार्मथ मैड्रेस से सुसज्जित उपचार यूनिट	13680 डी० एम०
		कम्पैक्ट ऐन्ट उपचार यूनिट (एक सैट)	63665 डी०एम०
		शिन निप्पन क्यू-आर-007 एन आटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर (एक सैट)	750000 जापानी येन

*अदायगी भारतीय मुद्रा में की जानी है।

रेलवे भर्ती बोर्ड

3529. **प्रो० राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती सम्बन्धी प्रक्रियाएं क्या हैं;

(ख) इन बोर्डों के माध्यम से किन-किन श्रेणी के पदों पर भर्ती की जाती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितने पदों पर भर्ती की गई है;

(घ) परीक्षा की योजना लिखित, मौखिक या अभिरूचि परीक्षण के लिए परीक्षा के माध्यम सहित परीक्षा की योजना क्या है; और

(ङ) परीक्षाओं में कहां तक क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी जाती है या प्रोत्साहित किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) भर्ती की प्रक्रिया में आवेदन-पत्र आमंत्रित करना, उनकी संवीक्षा करना, लिखित परीक्षाएं आयोजित करना, इंटरव्यू लेना और अन्ततोगत्वा योग्यताक्रम में उम्मीदवारों की स्थिति के आधार पर उनका चयन करना शामिल है।

(ख) रेलवे भर्ती बोर्ड तकनीकी और गैर-तकनीकी, दोनों कोटियों के ग्रुप "सी" के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करते हैं। इन पदों में अन्य के अलावा कार्यालय लिपिक, वाणिज्य लिपिक, टिकट कलक्टर, सहायक रेलपथ निरीक्षक, गाड़ी परीक्षक, आदि शामिल होते हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) रेलवे भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में उम्मीदवारों के कार्य-निष्पादन के अनुसार तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के आधार पर उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं, जो रिक्तियों की सख्या तक ही सीमित होती है।

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी होता है।

[हिन्दी]

आठवीं योजना में विद्युत उत्पादन

3530. **श्री दाऊ दयाल जोशी**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा } : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न विद्युत क्षेत्रों में कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ,

(ख) आठवीं योजना में, क्षेत्र-वार, कितना विद्युत उत्पादन होने की संभावना है,

(ग) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु उसे राज्यों में समान रूप से वितरित करने का है,

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सातवीं योजनावधि अर्थात् 89-90 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित कुल ऊर्जा निम्नवत थी :—

क्षेत्र	उत्पादित ऊर्जा
केन्द्रीय क्षेत्र	77803
राज्य क्षेत्र	155489
निजी क्षेत्र	11849
जोड़ :	245141

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा 8वीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

हिन्दी में प्रचार

3531. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रचार सामग्री का हिन्दी में मुद्रण करने के लिए आबंटित की गई धनराशि अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं में प्रकाशित सामग्री की तुलना में बहुत ही अपर्याप्त है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन विभाग हिन्दी या किसी अन्य भाषा में प्रचार-सामग्री छपवाने के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं करता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस

3532. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा, अन्टा तथा बारा क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस का वितरण करने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और यह कब आरम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में ड्रिलिंग कार्य

3533. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० द्वारा किए गए तेल और गैस अन्वेषण के क्या परिणाम निकलें हैं; और

(ख) राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई गैस का प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए थे लेकिन अब तक किसी संभावनापूर्ण स्थान का पता नहीं लगा है। महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोलियम के अन्वेषण के लिए लाइसेंस आयल इंडिया लि० के पास नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पेट्रोल और रसोई गैस की एजेंसियों की काला बाजारी

3534. **श्री अन्ना जोशी :** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा महाराष्ट्र में गत एक वर्ष के दौरान उन पेट्रोल/डीजल की खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस की एजेंसियों के विरुद्ध की गई अथवा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिन्हें पेट्रोलियम उत्पादों की काला बाजारी करते हुए पकड़ा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : विवरण संलग्न हैं।

विवरण

(जुलाई-1990 से जून-1991)

(1) **पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध :**

जिले	**मामलों की संख्या**	**की गई या की जा रही कार्रवाई**
चन्द्रपुर	1	15 दिनों के लिए बिक्री तथा आपूर्ति को अस्थगित किया जाना।
धूले	2	—वही—
सतारा	1	—वही—

(2) **एल० पी० जी० एजेंसियों के विरुद्ध**

जिले	**मामलों की संख्या**	**की गई या की जा रही कार्रवाई**
पुणे	3	डिस्ट्रीब्यूटर को चेतावनी दी गई थी कि वे रिफिलों के लिए अधिक **प्रभार** न वसूलें।
नासिक	1	—वही—
कोल्हापुर	1	—वही—
सांगली	1	शिकायत साबित न हो सकी।
अहमदनगर	2	जांच चल रही है।
जलना	1	—वही—

महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस की सप्लाई

3535. **श्री अन्ना जोशी**
श्री गोविन्द राव निकम
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने मुम्बई, थाणे और पुणे शहरों की पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के बारे में व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। तथापि गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि० ने बम्बई में नगर गैस वितरण प्रणाली के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हैदराबाद से विदेशों को जानी वाली उड़ानें

3536. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद से विदेशों को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उड़ानों की संख्या यात्री यातायात की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है,

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन उड़ानों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय एअर इंडिया दो सप्ताह में एक बार बम्बई से होकर हैदराबाद को जेद्दाह से जोड़ती है।

(ख) जी, हां.

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उद्योग में ऊर्जा और विद्युत के इष्टतम उपभोग सम्बन्धी तकनीक

3537. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सैन्टर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एण्ड इन्वाइरनमेंट" भोपाल ने औद्योगिक उपभोग के सम्बन्ध में ऊर्जा और विद्युत के इष्टतम उपभोग सम्बन्धी तकनीक पर कोई अध्ययन किया है, और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है,

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन की रिपोर्ट में इसके द्वारा की गई सिफारिशों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) औद्योगिक उपभोग के सम्बन्ध में विद्युत और ऊर्जा उपभोग तथा विद्युत प्रणालियों के स्थिरीकरण के इष्टतम उपभोग सम्बन्धी तकनीक के बारे में विद्युत विभाग द्वारा प्रायोजित अध्ययन कार्य, मध्य प्रदेण के तीन औद्योगिक समूह नामशः मण्डीदीप, देवास और पथिमपुर में नेशनल सैंटर फार ह्यूमन सेटलमेंट एण्ड इन्वाइरनमेंट, भोपाल द्वारा किए गए थे। अध्ययन कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ इष्टतम तकनीक के द्वारा विद्युत सम्बन्धी व्यवस्था, भारों की शिफ्टिग, इन समूहों में इष्टतम मांग के बंटवारे और अनावश्यक भारों की शिफ्टिंग के माध्यम से मांग सम्बन्धी कार्यक्रम के स्वरूप का पुनः निर्धारण करने हेतु कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को भेज दी गई हैं जोकि उद्योगों के समूह में इन्टर—लोड शिफ्टिग सम्बन्धी तकनीकी पहलुओं की जांच करेगा।

[हिन्दी]

हबीबगंज स्टेशन का विकास

3538. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हबीबगंज रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों पर कोई शेड नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं,

(ग) क्या स्टेशन का विकास करने की कोई योजना है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना धन खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) उसे कब लागू करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) हबीबगंज स्टेशन को "कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं" के प्रावधान की योजना के अन्तर्गत विकसित किया जाना है। इस कार्य को 9.97 करोड़ रुपये की लागत से 1989-90 में अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना पर 31.3.91 तक 0.75 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है तथा 1991-92 के दौरान इस कार्य के लिए 2.81 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हबीबगंज के दोनों प्लेटफार्मों पर 100 मी० × 7 मी० माप के एक-एक शेड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ङ) कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

केरल में ऊर्जा ग्राम योजना

3539. **श्री पी० सी० थामस :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बिजली का संकट है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या केरल में बाकी बचे गांवों को विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या कोट्टायम जिले के कानयनकवायल को ऊर्जाग्राम योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केरल में जुलाई, 1991 के दौरान 600 मि० यू० ऊर्जा की आवश्यकता की तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता 583 मि० यू० की सीमा तक थी, परिणामस्वरूप 17 मि० यू० (2.8%) की कमी रही।

(ख) विद्युत कीं उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रवन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन और अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अन्तरण की व्यवस्था करना।

(ग) और (घ) केरल पहले ही शतप्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है।

(ङ) और (च) ऊर्जा ग्राम स्कीम के अंतर्गत, इदुक्की जिले में कानायनकावायल गांव को शामिल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य नोडल एजेंसी उसी जिले के दूसरे गांव में ऊर्जा ग्राम की स्थापना के लिए पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ कर चुकी है।

बाम्बे हाई से कोचीन तक गैस पाइप लाइन बिछाना

3540. **श्री पी० सी० थामस :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई से कोचीन तक गैस पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दक्षिणी गैस ग्रिड प्रस्ताव की अन्तर-मंत्रालयीन दल द्वारा जांच की जा रही है।

बाम्बे हाई से कोचीनतटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम के भण्डार

3541. **श्री पी० सी० थामस :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई से कोचीन तक तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम के बहुत बड़े भण्डार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापक क्षेत्र में पेट्रोल निकालने के लिए उठाए गए अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी के बारे कितनी विदेशी सहायता की मांग की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जबकि बम्बई अपतट बेसिन में पहले से ही कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है तथापि केरल-कोंकन बेसिन में किए गए अन्वेषण से अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

अन्वेषण के लिए बोली के चौथे दौर में केरल-कोंकन बेसिन के बारह ब्लाकों तथा बम्बई अपतटीय बेसिन के चार गहरे पानी वाले ब्लाकों को आफर किया जा रहा है।

कोचीन मुम्बई क्षेत्र में यात्रियों को ले जाने की क्षमता में वृद्धि

3542. **श्री पी० सी० थामस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नए स्थानों के लिए भी इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं शुरू की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में यात्रियों को ले जाने की इंडियन एयरलाइन्स की क्षमता में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोचीन-मुम्बई क्षेत्र में यात्रियों को ले जाने की इंडियन एयरलाइंस की क्षमता बढ़ाने तथा यात्रियों की बढ़ती संख्या से निबटने के लिए विमान सेवाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स ने 1 अगस्त, 1991 से ग्वालियर, कानपुर और इलाहाबाद के लिए अपनी सेवाएं पुनः शुरू कर दी हैं।

(ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स ने हैदराबाद-बम्बई, हैदराबाद-दिल्ली और कलकत्ता-मद्रास सेक्टरों पर अतिरिक्त ए-320 उड़ानों को शुरू करके तथा बी-737 सेवाओं के स्थान पर ए-320 सेवाएं परिचालित करके अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

देहर भिवानी विद्युत लाइन

3543. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 400 के० वी० देहर भिवानी लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 1980 में ब्यास ट्रांसमिशन प्रणाली चरण दो के अन्तर्गत आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के भू-स्वामियों द्वारा इसके प्रति रोष व्यक्त किए जाने के कारण इस कार्य में विलम्ब हुआ है;

(ग) क्या पंजाव सरकार ने भी इस योजना पर खर्च की गई अपने हिस्से की लागत राशि देने से इन्कार कर दिया है;

(घ) इस योजना पर राजस्थान ने कितनी धनराशि खर्च की है;

(ङ) क्या यह सच है कि राजस्थान इस लाइन से लाभान्वित नहीं हो सकता; और

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) से (च) देहर विद्युत संयंत्र, चरण-दो (हिमाचल प्रदेश) से विद्युत की निकासी के लिए ब्यास निर्माण बोर्ड (बी० सी० बी०) द्वारा 1980 में 400 के० वी० देहर-भिवानी परेषण लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था ; मूलत: लाइन का मार्ग पटियाला से होकर गुजरने का था लेकिन इसकी लागत में अपने हिस्से के लिए पंजाब सरकार सहमत नहीं हुई क्योंकि उनके अनुसार इस लाइन से उनकी प्रणाली को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि इस लाइन हेतु पंजाब के हिस्से की लागत की पूर्ति 1984-85 के पश्चात् हरियाणा और राजस्थान राज्यों द्वारा की जाएगी। तदनुसार 30.6.1991 तक के लिए राजस्थान के हिस्से की राशि का लगभग 37.50 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

लाइन को जनवरी, 1990 में चालू कर दिया गया था। राजस्थान को इस लाइन से मुख्य रूप से लाभ प्राप्त होता है तथा इस लाइन ले देहर विद्युत परियोजना एवं राजस्थान और हरियाणा को बी० बी० एम० बी० प्रणाली से जोड़ने वाली 220 के० वी० प्रणाली

के द्वारा यह अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त करता है। अन्य प्रणाली के साथ-साथ यह लाइन भी राजस्थान के लिए प्रणालीगत स्थिरता तथा वोल्टता सहायक के रूप में इसकी सहायता करती है।

चूंकि राज्यों हेतु केन्द्रीय सरकार की ऋण सहायता से सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में इस लाईन को शामिल नहीं किया गया है इसलिए इस परेषण लाइन के निर्माण हेतु राजस्थान के लिए धनराशि की प्रति पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों में पर्यटक आवास

3544. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्री बलराज पासी
श्री वीरेन्द्र सिंह
श्री प्रभू दयाल कठेरिया
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण
: क्या **नागर विमान और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 1990-91 और 1991-92 (आज तक) के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता से कितने पर्यटक आवासों, होटलों और यात्री निवासों का निर्माण किया गया है और ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए भेजे गये प्रत्येक प्रस्ताव पर कितनी धन राशि आवंटित की गई; और

(ग) संघ सरकार का विचार पर्यटन के विकास और वर्ष 1991-92 के दौरान इन राज्यों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग होटलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराता। 1990-91 के दौरान, 72 पर्यटक गृहों और 4 यात्री निवासों के निर्माण हेतु क्रमशः 1066.61 लाख रुपए और 170.22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। 1991-92 के दौरान अब तक 17 पर्यटक गृहों के निर्माण हेतु 234.83 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटन के विकास के लिए बहुत-से कदम उठाए हैं, जिनमें पर्यटन आधारित संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और विदेशी बाजारों में प्रभावी प्रचार एवं संवर्धन करना शामिल हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हेतु केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत पर्यटक गृह और यात्री निवास

(लाख रुपए में)

राज्य	पर्यटक गृह		यात्री निवास	
	संख्या	स्वीकृत राशि	संख्या	स्वीकृत राशि
1990-91				
उत्तर प्रदेश	14	113.03	1	40.20
गुजरात	3	50.24	—	—
आन्ध्र प्रदेश	4	33.60	—	—
महाराष्ट्र	1	12.06	—	—
1991-92				
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—
गुजरात	2	27.66	—	—
आन्ध्र प्रदेश	6	72.01	—	—
महाराष्ट्र	—	—	—	—

"रेलवे मेटीरियल" की चोरी

3545. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्री बलराज पासी
श्री महेश कुमार कनोडिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री रमेश चन्द तोमर
श्रीमती महेन्द्र कुमारी

: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जुलाई, 1991 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "नो डिक्लाईन इन थेफ्ट ऑफ रेलवे मेटीरियल्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) इन चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान, रेल सम्पत्ति की चोरी की घटनाओं में मामूली सी कमी-बेशी हुई है। बहरहाल, रेल सम्पत्ति की चोरी से सम्बन्धित अपराधों की संख्या में और अधिक कमी लाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा निवारक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) चूंकि अपराधों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. बहुमूल्य और महत्वपूर्ण परेषणों को ले जाने वाली गाड़ियों का यथासम्भव मार्गरक्षण।
2. यार्डों और अन्य भेद क्षेत्रों/खंडों में गश्त को तेज करना।
3. जिन परेषणों की चोरी आदि होने की सम्भावना हो, उन्हें ले जाने वाले माल-डिब्बों की स्थिति का जायजा लेने के लिए, अन्तर्बदल स्थलों पर संयुक्त जांच करना।
4. जहां तक सम्भव हो, भेद्य खंडों पर रेलवे सुरक्षा बल की सशस्त्र टुकड़ियां लगायी/तैनात की जाती हैं।
5. अपराधियों की धर-पकड़ के उद्देश्य से, अपराध आसूचना एकत्र करने के लिए, सादे कपड़ों में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिक भी तैनात किए जाते हैं।
6. भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त के लिए कुत्ता दस्ते, उनकी उपलब्धता के अनुसार, तैनात किए जाते हैं।
7. अपराधियों तथा चुराई गई सम्पत्ति के प्रापकों से निपटने के लिए, विभिन्न स्तरों पर रे०सु०ब०, रा०रे०पु० और स्थानीय पुलिस के बीच निकट तालमेल बनाए रखा जाता है।

क्वाटरों का आवंटन

3546. **श्री बलराज पासी**
श्री बीरेन्द्र सिंह
श्री तेज नारायण सिंह : क्या **रेल मंत्री** दिल्ली/नई दिल्ली में क्वाटरों के आवंटन के बारे में 4 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जल आपूर्ति विभाग में अक्तूबर, 1990 से अब तक टाईप-1 के कितने क्वाटर आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या इन क्वाटरों को सेवा में वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किया गया है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान बिना बारी के कोई आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने क्वाटर आवंटित किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आगामी वर्ष के दौरान आवंटन हेतु कितने क्वाटर उपलब्ध होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छः।

(ख) जी नहीं। मौजूदा नियमों के अनुसार क्वार्टर पंजीकरण की प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किए जाते हैं। तथापि, आबंटन के लिए पहले अपनाया गया मापदण्ड सेवा में वरिष्ठता था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एक।

गुजरात में पर्यटन की सम्भावनाएं

3547. **श्री महेश कुमार कनोडिया :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान अब तक राज्य में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रस्तुत किए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा किन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है और उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) गुजरात में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1990-91 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है :—

	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1. वापी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	15.18
2. आनन्द में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.51
3. सोमनाथ में पर्यटक परिसर	16.73
4. अम्बाजी में पर्यटक गृह	17.94
5. माधोपुर में समुद्रतट विहार-स्थल	16.11
6. उभारत में पर्यटक परिसर	15.57

7. हर्षाद में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.51
8. पतंग उत्सव	1.95

1991-92 के दौरान अभी तक निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

1. श्यामलाजी में पर्यटक परिसर	16.27
2. भीमनाथ में पर्यटक गृह	11.39
3. गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड की सम्पत्तियों का उन्नयन एवं नवीकरण	36.87

इसके अलावा, गुजरात सरकार ने 1991-92 के दौरान 175.00 लाख रु० की अनुमानित लागत से चार स्थानों पर पर्यटक परिसरों, एक यात्री निवास, दो पर्यटक गृहों, टैन्टों और पैंडल वाली नौकाओं की खरीद करने और प्रचार सहायता के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन आधारिक-संरचना को सुदृढ़ करने के साथ साथ प्रचार एवं संवर्धनात्मक प्रयासों द्वारा और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहा है।

कोंकण रेल परियोजना के लिए सीमेंट स्लीपर फैक्टरी

3548. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना के लिए एक सीमेंट स्लीपर फैक्टरी स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी स्थापित किए जाने का स्थान और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक में कंकानी, महाराष्ट्र में चिपलुन तथा कंकावली और गोवा के मडगांव में पूर्वबलित कंक्रीट स्लीपर कारखाने स्थापित करने की योजना है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कारखाने से 3 लाख रेलपथ स्लीपरों का निर्माण तथा सप्लाई की जाएगी। टर्नआउटों के लिए 650 सेट कंक्रीट स्लीपरों के निर्माण और सप्लाई के लिए गोवा के मडगांव में एक और कारखाना स्थापित करने की भी योजना है। कंकानी कारखाने में अक्तूबर, 1991 में परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। चिपलुन तथा कंकावली के कारखानों तथा मडगांव के टर्न आउट कारखाने के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

सीमेंट की ढुलाई

3549. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग द्वारा रेल ढुलाई की सुविधायें अपर्याप्त होने की शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग की शिकायतें दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलें योजना आयोग के परामर्श से निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार सीमेंट की ढुलाई कर रही हैं। तथापि, सीमेंट उद्योग, रेल द्वारा लक्ष्य से अधिक सीमेंट की ढुलाई करने की मांग कर रहा है। योजना आयोग के परामर्श से कोयला, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, इस्पात संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे सामान तथा निर्यात के लिए अयस्क जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए रेल परिवहन के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा मांग को ध्यान में रखते हुए रेल द्वारा लक्ष्य से अधिक सीमेंट की ढुलाई करना व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय रेल लाइन के निर्माण के लिए निगम

3550. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेल लाइन के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए एक निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए निर्माण के लिए प्रस्तावित ऐसी रेल लाइनों के क्या नाम हैं और उन पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में पर्यटकों को सुविधाएं

3551. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा देश में कुल कितने होटल चलाए जा रहे हैं और उनका वर्गीकरण करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या है,

(ख) ये होयल कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक में कुल कितने कमरे हैं और उनका दैनिक किराया क्या है,

(ग) क्या इन होटलों में मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए कमरे उपलब्ध होते हैं,

(घ) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए उपलब्ध आवास और उसके किराए का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्यम और उच्च वर्ग के पर्यटकों को आरामदायक और सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय, भारत पर्यटन विकास निगम देश में अपने स्वामित्व में 25 होटलों का परिचालन कर रहा है। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में होंटलों का वर्गीकरण सरकार द्वारा गठित वर्गीकरण समिति द्वारा किया जाता है जिसमें यात्रा व्यवसाय एवं होटल उद्योग के प्रतिनिधि भी होते हैं। यह एक स्वैंक्छिक स्कीम है तथा इसमें 1 से लेकर 5 स्टार डीलक्स श्रेणी तक के होटल शामिल हैं।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। 3-स्टार श्रेणी और इससे कम श्रेणी के होटल उचित किराए वाले आवास की पेशकश करते हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार विभिन्न पर्यटक गंतव्य-स्थलों पर यात्री निवासों/यात्रिकाओं के रूप में सस्ते आवास का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करती है। सरकार वित्तीय प्रोत्साहन, इमदाद तथा कर में छूट देकर आवास सेक्टर में और विशेष रूप से सस्ते आवास के लिए गैर-सरकारी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन भी देती है।

विवरण

(रुपये में)

क्र० सं०	एकक का नाम और अवस्थिति	स्टार श्रेणी	क्षमता		वर्तमान कमरा किराया	
			कमरे	बेड	सिंगल ए/सी	डबल ए/सी
1	2	3	4		5	
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	* 5 स्टार डीलक्स	571	934	1800	1950
2.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	* 5 स्टार	247	486	1450	1600
3.	कुतब होटल, नई दिल्ली	* 5 स्टार	92	220	950	1100
4.	अशोक रेडिसन होटल, बंगलौर	* 5 स्टार	181	362	850	1000
5.	अशोक रेडिसन ललित पैलेस होटल, मैसूर	* 5 स्टार	54	105	1100	1250
6.	अशोक रेडिसन बीच रिसार्ट, कोवलम	* 5 स्टार	125	250	1100	1250
7.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	* 5 स्टार	149	298	1300	1450
8.	होटल आगरा अशोक, आगरा	* 5 स्टार	55	110	1050	1200
9.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	* 4 स्टार	317	634	1350	1500
10.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	* 4 स्टार	213	360	800	950
11.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	* 4 स्टार	84	168	800	950
12.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	* 4 स्टार	63	126	800	950

1	2	3	4		5	
13.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	* 4 स्टार	54	108	900	1050
14.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	* 3 स्टार	186	226	395 (350)	695(550)
15.	लोधी होटल, नई दिल्ली	* 3 स्टार	207	255	625	775
16.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	* 3 स्टार	48	96	525 (300)	675(425)
17.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	* 3 स्टार	38	76	600	750
18.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	* 3 स्टार	46	92	550	700
19.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	* 3 स्टार	43	86	395	695
20.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मामल्लापुरम	* 3 स्टार	22	44	395	695
21.	होटल बोधगया अशोक, बोधगया	* 3 स्टार	30	60	650	800
22.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	* 2 स्टार	66	132	395	695
23.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	* 2 स्टार	64	128	395	695
24.	होटल हासन अशोक, हासन	* 1 स्टार	46	92	395 (325)	695(450)
25.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	मितव्ययी श्रेणी	546	1238	— (180)	—(250)
	जोड़ :		3549	6687		

नोट : ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े गैर ए/सी किराया दर्शाते हैं।

* होटल और रेस्तरां अनुमोदन तथा वर्गीकरण समिति के अनुसार।

नई मीटर गेज लाइनों का बिछाना

3552. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और नई लाइन बिछाने की प्रति किलोमीटर लागतों की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान मीटर गेज लाइनों की बड़ी लाइन में बदलने की बजाय नई मीटर गेज लाइनें बिछाने को प्राथमिकता देने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आमान परिवर्तन की मौजूदा लागत 75 लाख रुपए प्रति कि०मी० और नई बड़ी लाइन की लागत 1 करोड़ रुपए प्रति कि०मी० है।

(ख) जी नहीं।

[अनुवाद]

खड़गपुर-खुर्दा सेक्शन का विद्युतीकरण

3553. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र**
श्री अनादि चरण दास } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के विद्युतीकरण के भविष्य के कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाई करने का विचार है; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-खुर्दा सेक्शन के विद्युतीकरण के लिए क्या कार्यवाई की गई/किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा समिति को प्रस्तावित लगभग 10,000 मार्ग कि०मी० में से समिति ने 1990-2005 की अवधि के दौरान 2510 मार्ग कि०मी० के विद्युतीकरण की सिफारिश की है। योजना आयोग ने रेल मंत्रालय को सूचित किया है कि समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रेलवे विद्युतीकरण के लिए योजना प्रस्ताव तैयार किए जायें। विद्युतीकरण प्रस्तावों पर अब तकनीकी-आर्थिक गुण-दोष और खण्ड दर खण्ड परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर कारंवाई की जा रही है।

(ग) संसाधनों की तंगी और विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं को देखते हुए खड़गपुर-खोरधा रोड खण्ड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

इरकान द्वारा विदेशी ठेके

3554. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड (इरकान) के पास विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के ठेके हैं; और

(ख) उसने वहां कितने श्रमिक काम पर लगाये हैं और इन परियोजनासों के लिए जन-शक्ति का स्रोत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) के पास अल्जीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, नेपाल, सऊदी अरब, तुर्की तथा जिम्बाबवे में ठेके हैं।

(ख) इरकान द्वारा इन परियोजनाओं के लिए भारत से तैनात किए गए कर्मियों की संख्या 295 है।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार

3555. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र**
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डा चार्टर उड़ानों के उतरने के लिए सज्जित है;

(ख) यदि नहीं तो क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(ग) भुवनेवर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के योग्य बनाने की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर बोइंग 737/ए-320 प्रकार के विमानों की चार्टरित उड़ाने परिचारित की जा सकती हैं।

(ख) उड़ीसा सरकार ने विशालकाय विमानों के परिचालन के लिए भुवनेश्वर हवाई अड्डे के धावनपथ को 9000 फुट तक विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही 8.87 करोड़ रुपये की लागत से धावनपथ में 5850 फुट से 7441 फुट तक विस्तार कर दिया है। परिणामस्वरूप, हवाई अड्डा अब एयरबस ए.320 विमानों के परिचालन के लिए उपलब्ध है। धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार किया जाना राज्य सरकार द्वारा बिना लागत के लगभग 70 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने, सड़कों तथा विद्युत लाइनों के परिवर्तन कार्य तथा साथ ही साथ विस्तार परियोजना के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है।

(घ) ऐसी योजना की निकट भविष्य में न तो आवश्यकता है और न ही यह व्यवहारिक है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को वैगनों की सप्लाई

3556. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को उस क्षेत्र में स्थिति औद्योगिक इकाइयों को कोयले की ढुलाई के लिए गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक महीने में कितने वैगनों की सप्लाई की गई;

(ख) क्या सप्लाई किए गए वैगनों की संख्या उनकी मांग की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में औद्योगिक यूनिटों के लिए कोयले की ढुलाई हेतु पश्चिमी कोयला क्षेत्रों के पेंच/कनहाल कोयला क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्रों के कोरिया रीवा और मुख्य लाइन कोयला क्षेत्रों को सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार रही हैं :—

अगस्त, 90	...	11494	माल डिब्बे
सितम्बर, 90	...	11219	"
अक्तूबर, 90	...	9070	"
नवम्बर, 90	...	12123	"
दिसम्बर, 90	...	11949	"
जनवरी, 91	...	11594	"
फरवरी, 91	...	11229	"
मार्च, 91	...	12837	"
अप्रैल, 91	...	9937	"
मई, 91	...	10001	"
जून, 91	...	8490	"
जुलाई, 91	...	9045	"

(ख) और (ग) सामान्यतः कोयला कम्पनियों द्वारा कम कोयला दिए लाने तथा ताप बिजली घरों की मांग अधिक होने के कारण उद्योगों को कोयले की ढुलाई उनके लदान कार्यक्रम से कम है। रेलें कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की पूरी तरह पूरा कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक एककों को कोयले की सप्लाई

3557. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को प्रति माह कितनी-कितनी मात्रा में नाप्प और

चूर्ण कोयला आवंटित किया गया है;

(ख) क्या यह आवंटन, राज्य में औद्योगिक एककों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या रेलवे वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण कोयले को आवंटित मात्रा के लदान पर अत्याधिक प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए हैं अथवा करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार रेलवे बोर्ड विभिन्न राज्यों को कोयले का संचालन किए जाने के लिए वैगनों की अधिकतम मासिक सीमा निर्धारित करता है। अगस्त, 1990 से जुलाई, 1991 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के मामले में वैगनों के मासिक-वार कोटे (अधिकतम सीमा के निर्धारण) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मास	स्टीम (बाक्स)	स्लैक (बाक्स)
अगस्त, 90	874	169
सितम्बर, 90	874	169
अक्तूबर, 90	874	169
नवम्बर, 90	874	169
दिसम्बर, 90	874	214
जनवरी, 91	1040	214
फरवरी, 91	1040	214
मार्च, 91	1040	214
अप्रैल, 91	1040	214
मई, 91	1040	214
जून, 91	1040	214
जुलाई, 91	1040	214

(ख) से (घ) उपर्युक्त वर्णित मासिक-वार कोटा अधिशासी निदेशक, रेल संचलन (ई०डी०आर०एम०) द्वारा राज्य-वार निर्धारित की गई वैगनों के वार्षिक कोटे पर आधारित है, जो कि सम्बद्ध राज्य सरकार के उद्योगों के निदेशक, कोयला कम्पनियों और रेलवे के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाता है। यह कोटा कोयले के संचलन के लिए वैगनों की उपलब्धता और उनकी मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोयले की पूरी मांग को केवल रेलवे के प्रेषण द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकता है और औद्योगिक यूनिटों की मांग को

पूरा किए जाने के लिए रेलवे की आपूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए कोयले का प्रेषण सड़क द्वारा किया जाता है। रेलवे द्वारा वैगनों की आपूर्ति तथा आवंटन कोयला कम्पनियों द्वारा की गई पेशकश के आधार पर किए जाने का प्रयास किया जाता है। किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा वैगनों को अनुचित रूप में रोके जाने तथा लम्बी लीड, आदि के कारणों से कभी-कभी वैगनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस समस्या से रेलवे द्वारा वैगनों के "टर्न-एराउन्ड-टाइम" में कमी करके तथा वैगनों की उपलब्धता में सुधार करके निपटने का प्रयास किया जाता है।

[**अनुवाद**]

इंडियन एअरलाइन्स की किसी भी उड़ान में आरक्षण सुविधाएं

3558. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के किसी भी भाग में इंडियन एयरलाइन्स की किसी भी विमान की उड़ान के लिए उससे कुछ ही समय पहले विमान यात्रियों को आरक्षण देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) ए-320 विमानों को पुन: सेवा में लगाने से इंडियन एयरलाइन्स की उपलब्ध सीट क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। यातायात सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए क्षमता उपलब्ध कराना इंडियन एयरलाइंस का सतत प्रयास रहेगा बशर्ते कि यातायात की सम्भावना हो और उसका औचित्य ठहराने के लिए वाणिज्यिक साध्यता हो।

विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि

3559. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आगामी तीन वर्षों में विमान यात्रियों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि होने की संभावना है और सरकार का विचार इस जरूरत को किस प्रकार पूरा करने का है,

(ख) विभिन्न क्षेत्रों की मांग की तुलना में कितनी क्षमता कम पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता कब तक प्राप्त कर लेने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) ए-320 विमान बेड़े की ग्राउंडिंग के कारण वर्ष 1989-90 में वाहित 98.5 लाख यात्रियों की तुलना में इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1990-91 में 78.4 लाख यात्रियों का वहन किया। चालू वर्ष 1991-

92 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा लगभग 95 लाख यात्रियों को ले-जाने की संभावना है। चालू वर्ष की तुलना में अगले तीन वर्षों में मांग में हर वर्ष लगभग 10 लाख यात्रियों की वृद्धि होने की आशा है, ताकि इंडियन एयरलाइंस वर्ष 1994-95 तक लगभग 125 लाख यात्रियों को ले जा सकेगी। इस समय 18 ए-320 विमान के बेड़े तथा वर्ष 1993 तथा 1994 में प्राप्त किए जाने वाले 12 और ए-320 विमानों के पूरे उपयोग से इंडियन एयरलाइन्स इस मांग को पूरा कर सकेगी।

उद्योगों को कोयले की सप्लाई

3560. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के लिए पिछले दो वर्षों से कोयले की अनुमानित मांग और सप्लाई कितनी थी,

(ख) उद्योगों को कोयले की कम सप्लाई के कारण कितना घाटा हुआ; और

(ग) सरकार ने कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य उद्योगों को कोयले की अनुमानित मांग तथा कोयले की आपूर्ति (इस्पात, सीमेंट और उर्वरक उद्योगों को छोड़कर) को नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े अनंतिम)

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग	कोयले का उठान	संतोषप्रदता (प्रतिशत)
1939-90	39.70 (1.70)	34.55	87%
1990-91	40.10 (1.27)	39.12	97.5%

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वाशरी मिडलिंग्स को दर्शाते हैं)

(ख) कोयला मंत्रालय के पास कोयले की कम आपूर्ति किए जाने के कारण उद्योगों को हुई कुल हानि के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) सरकार ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए नई खानों को खोलकर तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करके, तथा उत्पादकता में सुधार करने सम्बन्धी कदम उठाए हैं; और रेलवे वैगनों की उपलब्धता में सुधार करके कोयले के प्रेषण में वृद्धि की है।

कालीकट हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेनटेशन लैंडिंग सिस्टम शुरू करना

3561. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमैंनटेशन लैंडिंग सिस्टम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) (ख) राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण का निधियों की उपलब्धता होने की स्थिति में, आठवीं योजना अवधि के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर उपस्कर अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) की स्थापना का प्रस्ताव है।

केरल को बिजली की सप्लाई

3562. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय क्षेत्र के बिजली घरों से कितनी बिजली सप्लाई की जाती है,

(ख) क्या बिजली की कमी को पूरा करने के लिए केरल को केन्द्रीय क्षेत्र के बिजली घरों से बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1990-91 और अप्रैल, 1991 जुलाई 1991 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से केरल को कुल मिलाकर क्रमशः 1361.7 मिलियन यूनिट और 530.7 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई की गई।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उत्पादित विद्युत के बंटवारे का निर्धारण प्रत्येक क्षेत्र के घटक राज्यों के बीच किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों के सफल विद्युत में जिस मात्रा तक वृद्धि होती है उसी अनुपात में केरल को भी अधिक विद्युत सप्लाई की जाती है। रामागुंडम को कोयले की सप्लाई में सुधार किए जाने के द्वारा रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन में वृद्धि किए जाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

केरल में रेल फाटक

3563. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चौकीदार रहित रेल फाटकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन फाटकों पर शीघ्र चौकीदार नियुक्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार केरल में "सी" श्रेणी के बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 159 है।

(ख) रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने का कार्य तभी करती हैं जब राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किया जाए तथा नियमानुसार इस कार्य की लागत में हिस्सेदारी/लागत वहन करने की विधिवत सहमति प्रदान की जाए।

तथापि, यातायात के घनत्व या दृश्यता के आधार पर अपेक्षित होने पर रेलें स्वयं भी बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने का कार्य करती आ रही हैं।

दो समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने का कार्य 1990-91 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की बकाया राशि

3564. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने मार्च, 1991 में आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से बकाया राशि नकद भुगतान करने का अनुरोध किया हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अन्य राज्य बिजली बोर्डों से चैक के रूप में भुगतान स्वीकार करता है; और

(घ) यदि हां, तो भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सहित सभी राज्य बिजली बोर्डों से अपने देयों की वसूली हेतु अनुरोध किया है। हालांकि निगम की अपनी प्राथमिकता डिमांड ड्राफ्ट अथवा टेलीग्राफिक ट्रांसफार्म्स द्वारा धनराशि प्राप्त करने की है तथापि भुगतान का तरीका अन्ततः स्वयं राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तय करने के लिए छोड़ा गया है और निगम चैकों द्वारा भुगतान अस्वीकार नहीं करता है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

3565. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आधारमूल आड़चनों के कारण इस प्रकार का विस्तारण नहीं हो सकता है।

कर्नाटक को कोयले की आपूर्ति

3566. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के उद्योगों में कोयले की आपूर्ति में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है जिसके कारण कर्नाटक सहित अनेक राज्यों में उद्योगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सीमेंट उद्योग और कपड़ा ईकाइयों को इस कटौती के कारण नुकसान पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कर्नाटक के उद्योगों की कोयले की मांग का सामना करने के लिए क्या कदम उटाए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) यह सत्य है कि वर्ष 1991-92 की प्रथम तिमाही के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर अधिक कोयले का प्रेषण किया गया, जिसमें मुख्य विद्युत क्षेत्र शामिल हैं। इसलिए कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के वस्त्र-उद्योग यूनिटों सहित गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र की औद्योगिक यूनिटों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योग को भी कोयले की आपूर्ति में सामयिक रूप से कमी का सामना करना पड़ा। किन्तु अब स्थिति में सुधार लाए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। कोयला मंत्रालय ने गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को संयोजित मात्रा के न्यूनतम 50% कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए सभी कोयला कम्पनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोयले के संचलन के लिए सीमेंट क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है। कर्नाटक सहित देश के सभी उद्योगों की कोयले की आपूर्ति में सुधार आ जाने की संभावना है।

विद्युत टैरिफ ढांचा

3567. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से टैरिफ ढांचे की तरफ तुरन्त ध्यान देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों के टैरिफ के सम्बन्ध में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए टैरिफ ढांचे को संगत बनाने की आवश्यकता तथा इक्विटी भागेदारी, कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति के लिए हानियों को पूरा करने हेतु विशिष्ट अनुदान की व्यवस्था करना, टैरिफ में संशोधन, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना आदि जैसे उपाय करने के लिए विभिन्न मंचों से विचार-विमर्श में समय-समय पर राज्यों पर बल दिया जाता रहा है ताकि वे 3% आवश्यक सांविधिक अधिशेष अर्जित कर सकें।

भुवनेश्वर-मद्रास आदि के बीच विमान सेवा

3568. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी**
श्री रवि राय } : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर-मद्रास, भुवनेश्वर-बम्बई, भुवनेश्वर-जयपुर, भुवनेश्वर-राऊरकेला और विजाग सैक्शन तथा कलकत्ता सैक्शन के बीच वायुदूत सेवा सहित अन्य विमान सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स पहले ही भुवनेश्वर और कलकत्ता के बीच दैनिक सेवा परिचालित कर रही है। इंडियन एयरलाइन्स अपनी 1991 की शीतकालीन समयावलि में बम्बई/मद्रास और भुवनेश्वर सैक्टर पर सेवाएं प्रारम्भ करने पर विचार करेगी।

वायुदूत सेवायें

3569. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जहां पर वायुदूत अपनी विमान सेवाओं का संचालन कर रहा है,

(ख) क्या सरकार का वायुदूत को केवल पूर्वोत्तर और दूर-दराज के क्षेत्रों तक ही सीमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो वायुदूत द्वारा जिन शेष मार्गों पर सेवायें शुरू नहीं की गई है उन मार्गों पर सेवायें शुरू करने हेतु सरकार का विचार क्या वैकल्पिक उपाय करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उन मार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जहां इस समय वायुदूत अपनी विमान सेवाओं का परिचालन कर रहा है ।

(ख) और (ग) सरकार वायुदूत के भावी ढांचे के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है । इस मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

विवरण

14-8-91 को स्थिति के अनुसार वायुदूत द्वारा परिचालित मार्ग

उत्तरी क्षेत्र

1. दिल्ली/कानपुर/लखनऊ/दिल्ली
2. दिल्ली/चंडीगढ़/कुल्लू/चण्डीगड़/दिल्ली
3. दिल्ली/लुधियाना/चंडीगढ़/दिल्ली
4. दिल्ली/जोधपुर/जैसलमेर/जोधपुर/दिल्ली
5. दिल्ली/चंड़ीगढ़/शिमला/चंड़ीगढ़/दिल्ली
6. दिल्ली/चंड़ीगढ़/धरमशाला/चंड़ीमढ़/दिल्ली
7. दिल्ली/देहरादून/दिल्ली

हैदराबाद

1. हैदराबाद/विजयवाड़ा/राजामुन्दरी/हैदराबाद
2. हैदराबाद/राजामुन्दरी/हैदराबाद
3. हैदराबाद/पुणे/बड़ोदा/अहमदाबाद/पुणे/हैदराबाद
4. हैदराबाद/तिरूपति/हैदराबाद
5. हैदराबाद/पुणे/हैदराबाद

मद्रास

1. मद्रास/कोयम्बतूर/मद्रास
2. मद्रास/पांडिचेरी/मद्रास
3. मद्रास/तिरूपति/बंगलौर/बेलगांव/बंगलौर/तिरूपति/मद्रास
4. मद्रास/मदुरै/मद्रास
5. मद्रास/तिरूपति/बंगलौर/तिरूपति/मद्रास

6. मद्रास/मदुरै/कोचीन/अगत्ती/कोचीन/मदुरै/मद्रास

7. अगत्ती/कोचीन/अगत्ती

पूर्वी क्षेत्र

1. कलकत्ता/जमशेदपुर/कलकत्ता

2. कलकत्ता/एजवेल/सिल्वर/गुवाहाटी/सिलवर/एजवेल/कलकत्ता

3. कलकत्ता/कूचबिहार/कलकत्ता

4. कलकत्ता/अगरतल्ला/एजवेल/कलकत्ता

5. कलकत्ता/अगरतल्ला/कैलाशहर/अगरतल्ला/कलकत्ता

6. कलकत्ता/अगरतल्ला/शिलांग/अगरतला/कलकत्ता

7. कलकत्ता/अगरतला/कलकत्ता

पश्चिमी क्षेत्र

1. बम्बई/पुणे/बम्बई

2. बम्बई/कांडला/राजकोट/बम्बई

3. बम्बई/कांडला/बम्बई

4. बम्बई/कोल्हापुर/बेलगांम/बम्बई

5. बम्बई/पोरबन्दर/केशोद/बम्बई

6. बम्बई/औरंगाबाद/बम्बई

7. बम्बई/पुणे/बम्बई

अमेरिकी पर्यटक

3570. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत के कतिपय भागों को संकटपूर्ण क्षेत्र बताया है और अमेरिका पर्यटकों को ऐसे स्थानों में न जाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को अमेरिकी सरकार से भारत के कतिपय भागों को संकटपूर्ण क्षेत्र बताये जाने के कारणों को दर्शाने वाली कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरीका का विदेश विभाग अमरीकी नागरिकों को समय-समय पर यात्रा सम्बन्धी सलाह जारी करता है जिनमें उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे भारत सहित कतिपय देशों की यात्रा

करते समय सतर्क रहें। नवीनतम यात्रा-परामर्शों में भारत के जिन भागों का उल्लेख है वे हैं; जम्मू और कश्मीर, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य आदि।

(ग) और (घ) अमरीका सरकार ऐसे यात्रा-परामर्श सामान्यतः कानून और व्यवस्था की समस्याओं सम्बन्धी घटनाओं के समाचारों के आधार पर जारी करती है। यह मामला राजनयिक चैनलों के माध्यम से पहले ही अमरीका सरकार के साथ उठाया जा चुका है।

पेट्रोल की कीमत

3571. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक**
श्री फूल चन्द वर्मा
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
श्री पीयूष तीरकी
: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के कारण यह भारत में, अधिकांश विकसित और विकासशील देशों की तुलना में अधिक मंहगा हो गया है;

(ख) इसके कारण क्या है और अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विटरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, इण्डोनेशिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन और अर्जेण्टाइना में प्रति लीटर पेट्रोल का तुलनात्मक मूल्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विभिन्न देशों की पेट्रोल की कीमतों के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच करना, मिट्टी के तेल में फरफुरल को मिलाना तथा परीक्षण जांच करना आदि।

गुजरात को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

3572. **श्री काशीराम राणा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भड़ौच और सूरत को घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नौशरी, बलसाड़, वापी और बिलिमोरा शहरों में प्राकृतिक गैस आवटित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें प्राकृतिक गैस कब से सप्लाई की जाएगी; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भड़ौच में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है; सूरत शहर में आपूर्ति अभी तक आरम्भ नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्षेत्र में ऐसी-वचनबद्धताओं के लिए फिलहाल गैस उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

3573. **श्री काशीराम राणा** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के क्षेत्र में पूंजी का निवेश करने हेतु विदेशी कम्पनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) निम्नलिखित गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश हेतु विदेशी संगठनों के साथ समझौतों/अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किए गये है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	वित्त पोषण का स्रोत (मैसर्स)
1	2	3
1.	बेसिन ब्रिज जी०टी० (4 × 30 मे०वा०) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	ओवरसिज इकोनोमिक को-ओपरेशन फण्ड (ओ०ई० सी० एफ०), जापान।
2.	काठलगुडी सी०सी०जी०टी०-6(30-40 मे०वा०) जी० टी० + 3(30-40 मे०वा० एस० टी०) नीपको।	ओवरसिज इकोनोमिक को ओपरेशन फण्ड (ओ०ई० सी० एफ०), जापान।
3.	उरण अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट 1 एवं 2 (2 × 120 मे०वा०)-महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	क्रेडिटांसटाल्ट फर वाईडरोफ-बाऊ (के०एफ०डब्ल्यू) जर्मनी।
4.	दादरी सी०सी०जी०टी० (4 × 131 मे०वा० (जी० टी० + (2 × 146 मे०वा०) एस०टी०-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०)	क्रेडिटांसटाल्ट फर वाईड-रोफबाऊ के०एफ० डब्ल्यू) जर्मनी।

1	2	3
5.	कवास सी०सी०जी०टी० (4×106 मे०वा०) जी०टी० + (2×110 मे०वा०) एस०टी०-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०)	विश्व बैंक
6.	औरैया गैस पॉवर प्रोजेक्ट 652 मेगावट-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०)	विश्व बैंक
7.	अन्ता गैस पॉवर प्रोजेक्ट (413 मे० वा०) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी०सी०)	विश्व बैंक
8.	गान्धार गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण-1 (650 मे० वा०)- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०)	ओवरसिज इकोनोमिक को ओपरेशन फण्ड (ओ०ई० सी०एफ०) जापान।

[अनुवाद]

नुआपड़ा-गुणपुर सेक्शन की लाइनों को बदलना

3574. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) नुआपड़ा-गुणपुर नेरो-गेज सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अनुमानित संशोधित लागत क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य कार्यावधि की दृष्टि से पिछड़ा गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 90 कि०मी० नौपादा-गुनुपुर छोटी लाइन की बड़ी लाइन में बदलने की मौजूदा लागत लगभग 60 करोड़ रुपए होगी।

(ख) से (घ) इस परियोजना के अलाभप्रद होने और इस समय रेलों द्वारा संसाधनों की अत्याधक तंगी का सामना किए जाने के कारण इसे स्वीकृत नहीं किया गया है।

विदेशों में पर्यटन कार्यालय

3575. **श्री शंकर सिंह बघेला**
डा० ए०के० पटेल } : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पर पर्यटन कार्यालय कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1989, 1990 अथवा 1991 के दौरान कहां-कहां के पर्यटन कार्यालय बन्द किए गए और उनके बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार चालू पर्यटन वर्ष के दौरान उन्हें फिर से खोलने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विदेश स्थित 16 कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर चलाए जा रहे है :—

देश	स्थान	कार्यालयों की संख्या
1. यू०एस०ए०	न्यूयार्क और लांस एजेंल्स	2
2. कनाडा	टोरंटो	1
3. यू० के०	लंदन	1
4. जर्मनी	फ्रैंकफर्ट	1
5. स्विटरलैंड	जनेवा	1
6. फ्रांस	पैरिस	1
7. इटली	मिलान	1
8. स्पेन	मेड्रिड	1
9. नीदर लैंड	एम्स्टर्डम	1
10. आस्ट्रेलिया	सिडनी	1
11. मलेशिया	कुआलालम्पुर	1
12. थाईलैंड	बैंकाक	1
13. जापान	टोक्यो	1
14. यू० ए०ई० (संयुक्त अरब अमीरात)	दुबई और बहरीन	2

(ख) जी, हां। शिकागो स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय दिनांक 14.6.1990 को बन्द किया गया था और सिंगापुर और स्टाकहोम स्थित भारत सरकार स्थित पर्यटक कार्यालयों को 28.9.1991 को बन्द किया गया था। इन कार्यालयों को बचत के उपाय के रूप में बन्द किया गया था।

(ग) स्टाकहोम और सिंगापुर के कार्यालयों को पुनः खोलने तथा दक्षिण कोरिया में सिओएल एक नया कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिल

3576. **श्री प्रभु दया कठेरिया**
श्री भगवान शंकर रावत
श्री रमेश चन्द तोमर
श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री गोपीनाथ गजपति

: क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "डैसू शुड सिम्प्लिफाई इट्स बिल्स" समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) कथित समाचार, डसू, द्वारा बिल बनाने और प्रतिभूति राशि को लौटाने की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के बारे में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा किए गए अध्ययन कार्य के निष्कर्षों से सम्बन्धित है । उनकी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि मीटर शीटें तैयार करने के लिए सभी जिलों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए, चक्रीय मीटर रीडिंग की पद्धति लागू की जाए, ऐसे कनेक्शनों का पता लगाया जाए जिनके बारे में एक वर्ष मे भी अधिक अवधि से बिल जारी नहीं किए गए हैं, परीक्षण के आधार पर स्थल पर ही बिल बनाने की प्रणाली लागू करना, सर्वप्रथम बिल को वास्तविक रीडिंग तथा अनुवर्ती बिल को मासिक/द्विमासिक अंतराल से अनुमान के आधार पर जारी किए जाने की व्यवहार्यता का पता लगाना, सरकारी आवास के लिए प्रतिभूति राशि की प्रणाली को समाप्त करना और निजी आवास के मामले में प्रतिभूति राशि का हस्तांतरण करना आदि ।

अध्ययन दल के अनेक सुझावों का कार्यान्वियन किए जाने तथा डैसू की बिल बनाने की प्रक्रिया में सुधार करने एवं कारगर बनाने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों एवं कम्प्यूटर के द्वारा बिल बनाने की प्रणाली में शनै: शनै: स्थिरता आने के परिमाणस्वरूप डेसू त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से बिल बनाए जाने की घटनाओं की संख्या को कम करने में सक्षम हो पाया है ।

बिहार में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

3577. **श्री तेज नारायण सिंह**
श्री राम टहल चौधरी } : क्या **विद्युत और गै-रपरंपरागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने मधुबनी और रांची जिलों में तीस मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है,

(ख) इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अन्य राज्यों में ऐसे सोर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराने के लिए क्या प्रावधान किया है और उन्हें किस-किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिहार के मधुबनी और रांची जिलों में सौर ऊर्जा आधारित 30 मे० वा० क्षमता

के विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि मुंगेर तथा गया जिलों में प्रत्येक में 207 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2 × 30 मे० वा० सौर तापीय विद्युत स्टेशनों की स्थापना के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक निवेशों और आंकड़ों के उपलब्धता हो जाने पर कार्यान्वियन हेतु इन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा।

(ग) अब तक कोई सौर तापीय विद्युत संयंत्र मंजूर नहीं किया गया है, इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया में अभियन्ता सहायकों की नियुक्ति

3578. **श्री तेज नारायण सिंह**
श्री राम टहल चौधरी } : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों और विनियमों क उचित रूप में पालन किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार तथा जुलाई, 1991 तक इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित कितने लोगों की अभियन्ता सहायक के रूप में नियुक्ति की गई,

(ग) इस सम्बन्ध में तैयार की गई चुने हुए प्रत्याशियों की सूची में से 30 जुलाई, 1991 तक कितनों की नियुक्ति की गई,

(घ) क्या सूची की अवधि जुलाई, 1991 से आगे बढ़ा दी गई है और यदि हां, तो इसे कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है,

(ङ) सूची में दर्ज शेष प्रत्याशियों की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियरी हैल्परों के रूप में नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1989	43	19
1990	14	6
1991 (जनवरी से जुलाई, 91)	3	—

(ग) चालू पैनल में से 30 जुलाई, 1991 तक नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :—

अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	33
अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	19

(घ) हैदराबाद और कलकत्ता में इंजीनियरी हैल्परों के पैनल जो 1.3.91 और 30 7.91 को समाप्त हो गए थे उन्हें क्रमश. 1.1 .91 और 31.8.91 तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) और (च) खाली स्थानों के उपलब्ध होने पर पैनल में बचे बाकी उम्मीदवारों को पैनल की वैधता की अवधि के दौरान नियुक्त किया जाएगा।

[अनुवाद]

मुम्बई में रेल परियोजना

3579. **श्री तेजसिंहराव भोंसले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यात्रियों तथा माल ढोने की बढ़ती हुई आवश्यकता का सामना करने के लिए ग्रेटर बम्बई क्षेत्र में कोई नई रेल परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख निर्माण कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल है :—

(i) बांद्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनें तथा इनका पूरा होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ii) थाणे क्रीक पर एक पुल सहित मानखुर्द से बेलापुर तक एक नई लाइन का निर्माण।

इस परियोजना की लागत नगर औद्योगिक विकास निगम/महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 67:33 के अनुपात में वहन की जा रही है। चूंकि इस परियोजना के निष्पादन में प्रस्तावित लाइन पर किए गए अतिक्रमण से बाधा उत्पन्न हो रही है

इसलिए इसका पूरा होना इस तरह के अतिक्रमणों के हटाये जाने पर निर्भर करेगा।

(iii) कुर्ला में नया यात्री टर्मिनल :

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त किए जाने के छः महीनों के अन्दर इस टर्मिनल को चालू किया जाएगा।

(iv) बांद्रा टर्मिनल :

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त किए जाने के छः महीनों के अन्दर इस टर्मिनल को चालू किया जाएगा।

(v) दोहरी निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए बम्बई वी० टी० के उपनगरीय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करना।

चालू वर्ष में इस कार्य के पूरा होने की संभावना है।

(vi) बम्बई और कल्याण के बीच धीमी गति के गलियारे पर सिगनलों का पुनः अन्तरण।

इस कार्य को पूरा करने के लिए अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

3580. **श्री केशरी लाल :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर और कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन जिलों में उन गांवों की संख्या कितनी है जिनका विद्युतीकरण हो गया है तथा उनकी संख्या कितनी है जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है,

(घ) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभानना है; और

(ङ) 1990-91 के दौरान कितने गांव का विद्युतीकरण किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) निधियों की उपलब्धता एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर राज्य स्तर पर जिलेवार विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेपपुर जिलों में विद्युतीकरण एवं गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1991 के अंत में निम्नवत थी :—

जिला	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांव की संख्या
कानपुर नगर	1204	681
(कानपुर देहात)		
फतेहपुर	1095	254

(घ) उपरोक्त जिलों में शेष गांवों का विद्युतीकरण किया जाना, राज्य के समग्र आबंटन में इन जिलों के लिए राज्य द्वारा किए गए आबंटन पर निर्भर करेगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान कानपुर नगर में 6 गांवों, कानपुर देहात में 54 गांवों और फतेहपुर जिले में 33 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां

3581. **श्री केशरी लाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990 और 1991 के दौरान अब तक आबंटित रसोई गैस की एजेंसियों का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) कानपुर शहर, कानपुर देहात और फतेहपुर जिले में आवंटित एजेंसियों की संख्या क्या है,

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, जिनको यह एजेंसियां आवंटित की गई हैं, की संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वैच्छिक कोटे में से वहां पर आवंटित एजेंसियों की संख्या क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क)

आई० ओ० सी०	बी० पी० सी०	एच० पी० सी०
16	6	12

(ख) शून्य

(ग) दो

(घ) इक्कीस। इनकी पुनरीक्षा की जा रही है।

कानपुर तथा दिल्ली के बीच विमान सेवाओं का निलम्बन

3582. **श्री केशरी लाल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और दिल्ली के बीच की इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान निलम्बित कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो कब और किन कारणों से,

(ग) क्या सरकार ने उसे पुनः चालू करने सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्राप्त किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसे पुनः कब आरम्भ करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सितम्बर, 1990 में खाड़ी देशों से भारतीय राष्ट्रिकों को निकालने हेतु चार्टर उड़ानें परिचालित करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स की कानपुर और दिल्ली के बीच सेवाएं तथा कई अन्य सेवाएं भी बन्द कर दी गई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स को इस सेवा के पुनः चालू किए जाने के लिए कानपुर के व्यापारियों और व्यापारिक घरानों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स ने 1.8.91 से यह सेवा पुनः आरम्भ कर दी है।

[अनुवाद]

दक्षिण गैस ग्रिड

3583. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा**
श्री संतोष कुमार गंगवार
श्री प्रकाश बी० पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गैस ग्रिड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) इस मामले की अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा जांच की जा रही है।

चित्र दुर्ग और दावणगेरे रेल लाइन

3584. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्र दुर्ग और दावणगेरे के बीच यात्रियों के अत्यधिक आवाममन को देखते हुए इन दो केन्द्रों के बीच एक रेल लाइन निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[**हिन्दी**]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

3585. **प्रो० रासा सिंह रावत** : **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की कुल मांग कितनी है,

(ख) देश में उत्पादन किए जा रहे पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की कुल आवश्यकता का प्रतिशत क्या है,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए पेट्रोल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा क्या है तथा किन-किन देशों से इन्हें आयात किया गया है और इन वस्तुओं के आयात पर कुल कितनी लागत आई,

(घ) क्या सरकार ने पेट्रोल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) :

	मांग (मिलियन टन)	**देसी उत्पादन (प्रतिशत)**
पेट्रोल	3.884	100%
पेट्रोलियम उत्पाद	56.781	86% (लगभग)

देश में प्राकृतिक गैस का वर्तमान में लगभग 33 एम० एम० एस० घन मीटर प्रतिदिन उपयोग होता है । प्राकृतिक गैस देसी उत्पाद है ।

(ग) **वर्ष**	**मात्रा (हजार टन में)**	**कीमत (करोड़ रुपये में)**
1988-89	6495	1559.84
1989-90	6564	2254.71
1990-91	8660	4660.21

*काम चलाऊ

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात, आवधिक संविदा व तत्काल खरीद दोनों के तहत किया जाता है। तत्काल खरीद सदैव किसी देश विशेष से ही नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों में, देसी कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी, मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार तथा नयी ग्रास रुट रिफाइनरियों की स्थापना द्वारा शोधन क्षमता में वृद्धि करना, मांग प्रबंध और संरक्षण के उपाय अन्तर-ईंधन प्रतिस्थापन आदि शामिल है।

[अनुवाद]

कालीकट हवाई अड्डे का विस्तार

3586. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से बम्बई से कालीकट के लिए इंडियन एयर-लाइन्स को दैनिक उड़ान शुरू करने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स बम्बई और कालीकट बीच एक दैनिक ए-320 सेवा का परिचालन कर रही है।

कनाडा के लिए सीधी उड़ान

3587. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया का कनाडा के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयर इण्डिया ने 1 जून, 1991 से लन्दन होकर टोरंटों के लिए दो सप्ताह में एक बार की सेवाएं पहले ही आरम्भ कर दी हैं।

पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री पर प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप बिक्री मुद्रा की बचत

3588. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : पेट्रोल डीजल की खपत पर किसी विशेष तत्व के प्रभाव को परिमाणित करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

गया और हावड़ा के बीच रेलगाड़ी

3589. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और गया के बीच इस मार्ग पर पड़ने वाले तीर्थस्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों और व्यापारिक उद्देश्यों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कोई दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस ग्रांड कोर्ड लाइन पर, छोटा नागपुर स्टेशन से होते हुए, कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 4 जोड़ी दैनिक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां ऐसी हैं जो हावड़ा और गया के बीच सीधी गाड़ी सेवा उपलब्ध कराती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छतरा, बिहार में रेलवे बुकिंग कार्यालय

3590. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छतरा के (बिहार) के जिला मुख्यालय में एक रेलवे बुकिंग कार्यालय (वाह्य एजेंसियां) खोलने की लम्बे समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाई रने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चात्रा, बिहार में रेलवे आउट एजेंसी खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) चात्रा से प्राप्त होने वाले सम्भावित यातायात से यहां आउट एजेंसी खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

छोटा नागपुर-संथाल परगना क्षेत्र में बुकिंग कार्यालय

3591. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार छोटा नागपुर-संथाल परगना क्षेत्र के उन जिलों मुख्यालयों में रेलवे बुकिंग कार्यालय खोलने का है जिन्हें अभी रेलवे लाइनों से जोड़ा नहीं जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हजारीबाग और दुमका की आउट एजेंसियां बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट निगम (बी०एस०आर०टी०सी०) द्वारा परिचालित

की जा रही थीं। बी०एस०आर०टी०सी० के असंतोषजनक कार्य निष्पादन तथा कम यातायात प्राप्त होने की वजह से, आगे कार्य जारी रखने में उनकी असमर्थता के कारण क्रमशः 1.8.88 और 1.9-88 से ये आउट एजेंसियां बन्द कर दी गयी थीं। इन स्थानों पर आउट एजेंसियों को पुनः खोलने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब सरकारी या निजी ठेकेदार मानक शर्तों और निबंधनों के आधार पर कार्य शुरू करने की इच्छा व्यक्त करें।

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनें

3592. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर नई रेल लाइनें बिछायी जा रही हैं अथवा बिछायी जानी हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : निम्नलिखित खण्डों पर नयी लाइनों के निर्माण का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है :—

(i) मथुरा-अलवर

(ii) रामपुर-न्यू हल्द्वानी (काठगोदाम)

(iii) बगहा-छितौनी (पुनः स्थापना कार्य)

(iv) गुना-इटावा

आठवीं योजना के लिए अभी तक किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

3593. **डा० लाल बहादुर रावल**
श्री राम बदन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने और नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मैनपुरी जिला को जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद और हरदोई/संडीला के बीच नई लाइन के निर्माण का अनुरोध किया है।

(ग) प्रस्तावित रेल लाइन, जिसमें गंगा नदी पर रेल पुल का निर्माण भी शामिल है, के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी और संसाधनों की तंगी के कारण इस पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियों से चूल्हों की खरीद

3594. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नए गैस उपभोक्ताओं को एल०पी० जी० एजेंसियों द्वारा उनसे गैस चूल्हे, गैस प्लेट, रबड़ पाइप आदि खरीदने के लिए मजबूर किया किया जाता है; और

(ख) एल०पी०जी० डीलरों को, उपभोक्ताओं को इनकी खरीद के लिए मजबूर न करने सम्बन्धी निर्देश जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एल०पी० जी० डीलरों के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ एल०पी०जी० स्टोव की जबरन बिक्री के मामले में तेल कम्पनियों द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने की भी व्यवस्था है ।

बाम्बे हाई से हजीरा तक पाइप लाइन

3595. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाम्बे से हजीरा तक अतिरिक्त गैस पाइपलाइन के वित्त पेषण हेतु विश्व बैंक से सम्पर्क किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गैस दहन को कम करने की परियोजना का एक घटक है । इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3596. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव रखा गया है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यों हेतु 2749.05 लाख रुपए का बजट प्रावधान हैं ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

3597. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के अधिकांश गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मार्च, 1991 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया था ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के 71352 गांवों में से मार्च, 1991 के अन्त तक 63,007 (88%) गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इसमें राज्य के कुल 25,825 जन-जातीय गांवों में से 22,197 जन-जातीय गांवों का विद्युतीकरण शामिल है। राज्य में समग्र विद्युतीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पेट्रोल/डीजल की फूटकर दुकानों और एल०पी०जी० एजेंसियों का आबंटन

3598. **श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये पेट्रोल/डीजल फुटकर बिक्री केन्द्रों और एल०पी०जी० एजेंसियां आबंटित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) कर्नाटक में अब तक श्रेणी-वार कितने पेट्रोल/डीजल के फुटकर बिक्री केन्द्र और एल०पी०जी० एजेंसियां आबंटित की गई हैं; और

(ग) चालू वर्ष में जिला-वार कितने डिस्ट्रीब्यूटर शिप आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों तथा एल०पी०जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों विभिन्न घटकों पर आधारित होती है जिनमें मात्रा/दूरी मानदण्ड, शहरों की संख्या, विपणन योजनाएं तथा अभ्यार्थियों के लिए पात्रता मानदण्ड आदि शामिल हैं।

(ख)

	कुल	आरक्षित श्रेणियों में संख्या
		(1.4.91 के अनुसार)
—एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों	234	133
—खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों	925	131

(ग) विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार विभिन्न शहरों में एल०पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्ड को वित्तीय सहायता

3599. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान कर्नाटक में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान क्या लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को 30.6.1991 तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 1988-89 के दौरान 313 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जब 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य द्वारा शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त किया गया। अतः 1991-92 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों को जून, 1991 तक दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	संवितरित ऋण-राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	43333
2.	अरुणाचल प्रदेश	1660
3.	असम	18613
4.	बिहार	35557
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	25607
7.	हरियाणा	15842

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	11520
9.	जम्मू व कश्मीर	7534
10.	कर्नाटक	21471
11.	केरल	10272
12.	मध्य प्रदेश	82740
13.	महाराष्ट्र	47446
14.	मणिपुर	3750
15.	मेघालय	5234
16.	मिजोरम	1493
17.	नागालैंड	3319
18.	उड़ीसा	26134
19.	पंजाब	23533
20.	राजस्थान	32937
21.	सिक्किम	2508
22.	तमिलनाडु	25414
23.	त्रिपुरा	4163
24.	उत्तर प्रदेश	61417
25.	पश्चिम बंगाल	32040
26.	अन्य	1350
जोड़ :		544887

कर्नाटक के बिजली घर

3600. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** :क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली घरों को एक दक्षिणी गैस ग्रिड द्वारा चलाने का प्रस्ताव रखा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेलेकेरा में सागर-तट सैरगाह

3601. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1987 में एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने कर्नाटक के बेलेकेरा में एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सागर-तट सैरगाह बनाने के सम्बन्ध में वहां की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) केन्द्रीय सरकार के एक अध्ययन-दल ने बेलेकेरा सहित कर्नाटक में समुद्र-तटों का सर्वेक्षण किया था और उन स्थानों के विकास के लिए कुछ सिफारिशें की थीं।

(ख) अध्ययन-दल की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने बेलेकेरा में 80 बिस्तरों वाले समुद्र-तटीय विहार-स्थल (बीच रिजॉर्ट) के निर्माण हेतु एक परियोजना तैयार की थी। चूंकि परियोजना की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करें।

भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न पार्टियों, ग्राहकों की ओर बकाया राशि

3602. **श्री सूर्य नारायण सिंह**
श्री कड़िया मुण्डा
श्री राम टहल चौधरी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 31, 1991 को भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न पार्टियों/ग्राहकों की ओर एकक/क्रियाकलाप-वार बकाया राशि कितनी है,

(ख) निर्धारित अवधि के भीतर भुगतानों की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक एकक/प्रभाग/क्रियाकलाप तथा साथ ही इसके निगमित कार्यालय की ऋण स्थिति की समीक्षा की जाती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम के प्रत्येक एकक/प्रभाग और क्रियाकलाप के बीजक और ऋण वसूली के बीच समायोजन हेतु कौन-से प्रयास किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) 31 मार्च, 1991 को बकाया राशि के कार्यकलाप-वार अनन्तिम आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(लाख रु० में)

कार्यकलाप	बकाया राशि
होटल और केटरिंग प्रतिष्ठान	1665.46
निगम संचार	116.46
अशोक ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स	512.94
शुल्क मुक्त व्यापार	28.15
ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन, लाल किला	0.09
मुख्यालय	274.06
	2597.16

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम अपने ग्राहकों से बकाया राशि यथासंभव कम से कम समय में वसूल करने के निरंतर प्रयास करता रहता है।

(ग) प्रधान प्रबंधक/लेखा प्रभारी एकक स्तर पर विविध देनदारों की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष एककों के लेखा प्रभारी/प्रधान प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित करके निगम स्तर पर भी इनकी समीक्षा करते हैं।

(घ) बिल बनाने तथा ऋण वसूली की एक निरंतर प्रक्रिया है और एकक अध्यक्ष बकाया राशि की वसूली करने के लिए अपने एकक में प्रयासों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है। इसके अलावा, मामले को संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ उपयुक्त स्तर पर उठाकर भी वसूलियां कराने के लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जाते हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा ग्राहकों को "क्रेडिट" देने के लिए मार्गनिर्देश

3603 **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों/सेवाओं द्वारा ग्राहकों को उधार सेवाएं प्रदान करते समय कौन-सी नीतियां और मार्ग निर्देश अपनाये जाते हैं; और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की प्रत्येक यूनिट/डिविजन/सेवा द्वारा ट्रैवल एजेंटों, सरकारी विभागों, सरकारी कम्पनियों, प्राइवेट कम्पनियों, एयर लाइनों और व्यक्तियों जैसे विभिन्न

श्रेणियों के ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं का कितने प्रतिशत उधार में जाता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की उधार नीति में अन्य बातों के साथ-साथ अपने ग्राहकों को 30 दिन से 60 दिन तक की अवधि देने के लिए उधार की सुविधा देना शामिल है।

(ख) एकक/प्रभाग/सेवा कार्य कलापवार उधार-बिक्री के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते। वर्ष 1990-91 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 31.3.91 की स्थिति के अनुसार श्रेणी/ग्राहकवार बकाया की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है :—

श्रेणी/ग्राहक का नाम	31.3.91 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि (अनन्तिम) (करोड़ रु० में)	कुल बकाया के साथ ग्राहकवार बकाया की प्रतिशतता
सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियां	15.77	60.72
यात्रा अभिकर्ता	4.76	18.33
लाइसेंस धारी	1.57	6.05
एअरलाइनों, व्यक्तियों और अतिथि लेजर खातों सहित निजी कंपनियां	3.87	14.90
	25.97	100.00

मनुगुरु ताप विद्युत संयंत्र

3604. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव**
डा० डी० वेंकटेश्वर राव } : क्या **विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मनुगुरू में एक ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। प्रस्ताव में 500-500 मे०वा० वाली दो यूनिटों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ख) परियोजना के लिए कोयला लिंकेज तथा वित्तपोषण के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति सुनिश्चित करना अपेक्षित होना। मुख्य संयंत्र उपस्कर के एवार्ड की तिथि से 5 वर्ष के

भीतर 500 मे०वा० की प्रथम यूनिट को चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कृष्णा-कावेरी बेसिन पर खर्च की गई राशि

3605. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान कृष्णा-कावेरी बेसिन में समुद्र तट और समुद्र तट से दूर गवेषण कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) कृष्णा-कावेरी बेसिन में सम्भावित तेल की अनुमानित राशि क्या होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 171.93 करोड़ रुपये।

(ख) 1 जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार करीब 17 मिलियन मीट्रिक टन प्रति प्राप्ति योग्य भंडारों का अनुमान लगाया गया था।

पम्पसैटों का आधुनिकीकरण और नवीकरण

3606. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पम्पसैटों को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए इनका आधुनिकीकरण और नवीकरण का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि तां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और कितनी लागत आएगी; और

(ग) आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान अवस्था क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कृषि पम्पसैटों का सुधार करने तथा इनको ऊर्जा-क्षम बनाने की दृष्टि के बारे में राज्य बिजली बोर्डों एवं अन्य संगठनों से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर संसाधनों की उपलब्धता एवं तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए सहायता हेतु सरकार द्वारा विचार किया जाता है। केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में लगभग 75000 विद्युत प्रचालित पम्पसेटों का पहले ही सुधार किया जा चुका है। आंशिक रूप से (फुटवाल्व, सक्शन और डिलीवर पाइपों को बदलना) और पूर्णतः (मोनोब्लाक पम्पस, पाईपिंग सिस्टम, फुटवाल्व आदि) दोनों प्रकार के सुधार कार्य हाथ में लिए गए हैं। अप्रैल, 1985 से मार्च, 1991 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में केंद्रीय सहायता से 8175 ऊर्जा अक्षम वैद्युत पम्पसेटों में सुधार किया गया है। आंशिक रूप से सुधार किए जाने की प्रति पम्प औसत लागत लगभग 1750/- रु० है और पम्पसैट के आकार एवं बदले

जाने वाली पाइपों पर निर्भर करते हुए पूर्णत: सुधार किए जाने की प्रति पम्प की लागत 6000/- से 12,000/- रु० तक भिन्न-भिन्न होती है।

हैदराबाद हवाई अड्डे पर उद्घोषणाएं

3607. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे पर उद्घोषणाएं, हिन्दी में की जाती है न कि तेलुगू में जो कि राज्य राजभाषा है,

(ख) उद्घोषणाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित की गई है,

(ग) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे पर तेलुगू में भी उद्घोषणाएं आरम्भ करने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) हैदराबाद हवाई अड्डे पर उद्घोषणाएं तेलुगू में भी की जा रही हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण

3608. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) आदिवासी क्षेत्रों का पूर्ण विद्युतीकरण कब पूरा होने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार के 17,250 जनजातीय गांवों में से मार्च, 91 के अंत तक 7,383 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) योजना आबंटन के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु गांवो को लिए जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड का वर्ष 91-92 के दौरान 170 जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

दामोदर घाटी निगम की भूमि से विस्थापित लोगों का पुनर्वास

3609. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम ने मिथॉल, पंचेट और चन्द्रपुरा बांध के निर्माण के लिए कितने व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया था,

(ख) इनमें में श्रेणीवार कितने-कितने विस्थापितों को इस निगम में रोजगार दिया गया है;

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी रोजगार नहीं दिया गया है तथा ऐसे परिवारों की जीविका के लिए कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई है,

(घ) कितने परिवारों को अभी तक न तो रोजगार दिया गया है और न ही मुआवजा राशि दी गई है; और

(ङ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मैथान एवं पंचेत बांधों तथा चन्द्रपुरा विद्युत केन्द्र के लिए क्रमशः 5211 परिवारों (28030 सदस्यों), 10399 परिवारों (41461 सदस्यों) और 480 परिवारों (829 सदस्यो) की भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ख) से (ङ) भूमि अधिग्रहण करते समय भूमि खोने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नकद मुआवजे का भुगतान किया गया था अथवा इसके बदले में भूमि दी गई थी। ऐसे विस्थापित परिवारों के सदस्य जोकि सक्षम और इच्छुक थे, को रोजगार भी दिए गए थे। इस प्रकार का रोजगार दिए जाने के बारे में अलग से किसी प्रकार का रिकार्ड नहीं रखा गया था। तथापि, विस्थापितों के वंशज को रोजगार दिए जाने के बारे में दामोदर घाटी निगम द्वारा 1978 से रिकार्ड रखा जा रहा है जिसके अनुसार विस्थापितों के वंशज का दावा करने वाले 339 व्यक्तियों को दामोदर घाटी निगम में समूह "ग" पदों के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

जसीदीह और रांची के बीच रेलगाड़ी का चलाया जाना

3610. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संथाल परगना और रांची के बीच कोई रेलगाड़ी नहीं चलती,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जसीदीह मे रांची तथा रांची से जसीदीह के लिए कोई शाम या रात की गाड़ी चलाने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित रेल सेवा कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 5027/5028 रांची-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस जसीडीह और रांची के बीच सीधी गाड़ी सेवा उपलब्ध कराती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में नई कोयला कम्पनी

3611. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स से अलग करके वहां पर कोयला खानें विकसित करने हेतु नई कंपनी की स्थापना करने की स्थाई मांग है,

(ख) यदि हां, तो मांग पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, ता उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) यह सुझाव दिया गया है कि राजमहल, एस० पी० माइन्स-कंकरतोला, निरसा और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कापसरा कोयला क्षेत्रों मे कोल इंडिया लि० के अधीन एक नई कंपनी का गठन किया जाए। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था चूंकि राजमहल कोयला-क्षेत्रों को छोड़कर अन्य कोयला क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन में कोई संभावित वृद्धि नजर नहीं आई और इन कोयला क्षेत्रों से कोयले का कुल उत्पादन कोयले के न्यूनतम 20 मि० टन के उत्पादन से नीचे रहा जिसके आधार पर किसी नई कंपनी के गठन पर विचार किया जाता है।

दिल्ली जयपुर मार्ग पर सुपरफास्ट गाड़ियां

3612. **श्री राम नारायण बैरवा**
श्री चेतन पी० एस० चौहान } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपुर मार्ग पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए इस सेक्शन पर और अधिक गाड़ियां चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली और गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों के लिए अतिरिक्त यात्री डिब्बे

3613. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों में यात्री डिब्बों की संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अपर्याप्त है और उसके परिणामस्वरूप यात्रियों को यात्री डिब्बों की छतों पर यात्रा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्किम में हवाई पट्टी

3614. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल सिक्किम ही ऐसा राज्य है जो विमान सेवा से नहीं जुड़ा हुआ है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को सिक्किम सरकार से सिक्किम में हवाई पट्टी का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ग) यदि हां, तो क्या वहां स्थल का चयन कर लिया गया है,

(घ) यदि हां, तो हवाई पट्टी का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय सिक्किम के लिए कोई हवाई सम्पर्क नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिक्किम में हवाई पट्टी के निर्माण कार्य के लिए दो स्थलों का प्रारंभिक निरीक्षण किया है और यह पाया है कि गंगतोक से 13 किलोमीटर पांग थांग पर एक स्थान लगभग 2500 फीट लम्बे धावनपथ के साथ हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त होगा । अनुमान है कि परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी । हवाई अड्डे का निर्माण, मौसम-विज्ञान सम्बन्धी और रूप रेखा आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण पर्यावरण एजेंसियों से अनुमति प्राप्त करने और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई निधियों पर निर्भर करेगा ।

राजगीर-बोधगया रेल लाइन

3615. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए राजगीर-बोधगया रेल लाइन बिछाने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल द्वारा भूमि का अधिग्रहण

3616. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने रेलवे द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि के मूल्य में वृद्धि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

द्वारापुड़ी स्टेशन पर हाल्ट

3617. **श्री के० वी० आर० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारापुड़ी रेल स्टेशन का सुधार करने और वहां एक्सप्रेस रेल गाड़ियों का हाल्ट उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) द्वारापुड़ी में पांच जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां ठहराती हैं। अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस स्टेशन पर मुहैय्या कराई गई सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोच रिपेयर फैक्टरी भोपाल में चिकित्सा सुविधा

3618. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कोच रिपेयर फैक्टरी भोपाल की कालोनी के रहने वाले श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं करती हैं;

(ख) सृजित किए गए डाक्टर का पद कब तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) श्रमिकों को किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं देने का विचार है, वर्ष 1921-92 के दौरान बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है और वहां किन-किन श्रेणियों के पदों का सृजन किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) अंतरंग सुविधाओं (50 पलंग), नैदानिक, प्रसूति, ओ० टी०, ई० सी० जी०, एक्स रे, प्रयोगशाला और उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कारखाना अस्पताल के लिए 60 लाख रुपयों का बजट आबंटन किया गया है।

जिन कोटियों के पदों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है, उनमें चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य परा-चिकित्सा कर्मचारी शामिल होंगे।

[हिन्दी]

आगरा में नागरिक हवाई अड्डा

3619. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का आगरा स्थित खेड़िया में एक अलग नागरिक हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों का सम्मेलन

3620. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों के चेयरमैनों का सम्मेलन जुलाई, 1991 में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए और इन्हें लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में रसोई गैस एजेंसियां

3621. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गाचक, हल्दिया में रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : दुर्गाचक में एल०पी०जी की

एजेंसी के चालू होने में विलम्ब होने का कारण डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चयन नहीं किया जाना है क्योंकि तेल चयन बोर्ड को असिगित कर दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3622. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया गया है; और

(ख) उन राज्य के नाम क्या हैं, जहां आठवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण विद्युतीकरण किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य यंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31.3 1991 की स्थिति के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा सिक्किम ने 1981 की जनगणना के सन्दर्भ में शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है जबकि नागालैण्ड एवं तमिलनाडु ने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण 1971 की जनगणना के सन्दर्भ में प्राप्त किया था।

(ख) यह आठवीं योजना, जिसे योजना आयोग द्वारा अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, में विभिन्न राज्यों हेतु ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए आवंटन पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

हरियाणा में बिजली का उत्पादन

3623. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागय ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में बिजली संयंत्रों की बिजली उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राज्य में बिजली की उपलब्धता और मांग के बीच कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथराय) : (क) इस समय हरियाणा में कुल प्रतिष्ठापति विद्युत उत्पादन क्षमता 863 मे०वा० है।

(ख) अप्रैल, 91 से जुलाई, 91 तक की अवधि के दौरान, हरियाणा में ऊर्जा की आवश्यकता 3271 मि०यू० थी जिसकी तुलना में उपलब्धता 3197 मि०यू० थी जोकि 74 मि०यू० (2.3%) कमी का द्योतक है।

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है :—

परियोजना का नाम	स्वरूप	क्षमता (मे०वा०)
(1) दादूपुर	जल विद्युत	4 × 2.5
(2) पानीपत विस्तार चरण-4, यूनिट 6	ताप विद्युत	1 × 210

विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न अन्य उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था करना।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में कोयले के भण्डार

3624. **श्री लाईता उम्बरे : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में कोयले के भण्डार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ये भण्डार किस-किस स्थान पर और कितनी मात्रा में मिले हैं और उनकी गुणवत्ता क्या है;

(ग) क्या वहां पर कोई खुदाई कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला भंडारों की अवस्थिति, मात्रा और गुणवत्ता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

कौयला क्षेत्र	जिला	गुणवत्ता	भण्डार मिलियन टन में			
			प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
1. नामचिक नामफुक	चागलांग	निम्न राख, उच्च गंधक युक्त कोयला पकाई की विशेषता सहित	31.23	11.04	41.96	84.23
2. मियाअ बुम	—वही—	अमूल्यांकित	—	—	6.00	6.00
			31.23	11.04	47.96	90.23

(ग) और (घ) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ने अन्वेषण का कार्य किया था और इसने 1984 में एक भू-गर्भीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० ने नामचिक में 31.18 करोड़ रु० की पूंजीगत परिव्यय से 0.25 मिलियन टन क्षमता का वार्षिक उत्पादन किए जाने के लिए एक ओपनकास्ट खान की एक व्यवहार्यरता रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद आयल इंडिया लिमिटेड ने यह मत व्यक्त किया कि कोई भी कोयला खनन कार्य आरम्भ नहीं किया जाए, क्योंकि इससे इस क्षेत्र में चल रहे तेल के अन्वेषण कार्य में रुकावट आएगी। अरुणाचल प्रदेश में कोयले का अन्वेषण किए जाने की आगे की योजनाएं योजना आयोग क परामर्श से कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं।

सैनिक वीरता पदक प्राप्तकर्त्ताओं को रेल यात्रा में रियायत

3625. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक स्वतन्त्रता सैनानी अपने/अपनी पति/पत्नी और एक परिचय के साथ प्रथम श्रेणी में जितनी दूर चाहें निःशुल्क यात्रा करने का अधिकारी है,

(ख) यदि हां, तो स्वतन्त्रता सेनानियों को इस सम्बन्ध में दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या सरकार का "परम वीर चक्र" और "अशोक चक्र" जैसे वीरता पदक प्राप्त करने वालों को भी बिना किसी पाबंदी के ऐसी ही सुविधाएं देने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतन्त्रता सैनानी या उनकी विधवाएं हैं, उन्हें पहले दर्जे के अखिल भारतीय मानार्थ कार्ड पास जारी किए जा रहे हैं जो स्वयं स्वतन्त्रता सैनानी और उसके एक सहयोगी, जो पति/पत्नी हो सकती है, के लिए वैध है तथा ये एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं जिनका हर वर्ष नवीकरण किया जाता है। वे पहले दर्जे या वातानुकूल शयनयान में यात्रा कर सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-देहरादून मार्ग पर सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाना

3626. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली से देहरादून और सहारनपुर तक वर्तमान रेल सेवाएं न केवल अपर्याप्त हैं बल्कि रास्ते में बहुत से स्टेशनों पर रुकने और लम्बे हाल्टों के कारण यात्रा में समय भी बहुत लगता है,

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली से देहरादून तक (बड़ौत-शामली-सहारनपुर.लक्शर और

हरिद्वार होते हुए) एक ऐसी सुपरफास्ट रेल गाड़ी शुरू करने का विचार है, जो उसी दिन लौट भी सके, और

(ग) यदि हां, तो उसे कब तक लागू करने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली और देहरादून/सहारपुर के बीच चलने वाली मौजूदा गाड़ियों को इन स्थानों के बीच होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है। मौजूदा ठहरावों को समाप्त करके इन सेवाओं की रफ्तार बढ़ावा फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। किसी भी छोर पर पर्याप्त टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा सवारी डिब्बों एवं रेल इंजनों की कमी के कारण इस मार्ग पर कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति

3627. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान कितने अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड में पदोन्नत किया गया और उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्ति थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	जोड़	अ०जा०	अ०ज०जा०
1987	69	6	—
1988	288	26	5
1989	165	11	5

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजना

3628. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान रेलवे के कितने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है और उनमें से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी थे; और

(ख) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का भी अधिकारी नहीं भेजा गया, तो उसके क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)

वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों की संख्या	अ०जा०/अ०ज०जा० की संख्या
1987	353	13
1988	250	9
1989	266	9

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूरत और भुसावल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को खंडवा तक चलाना

3629. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत और भुसावल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी सात घंटे तक भुसावल में रुकी रहती है,

(ख) यदि हां, तो क्या इतनी देर वहां रोकने के बजाय, यात्रियों की सुविधा के लिए इसे खंडवा तक चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भुसावल में 113/114 सूरत-भुसावल पैसेंजर की पड़ाव अवधि 8 घंटे और 35 मिनट है। अन्य गाड़ियां यथा 75/76 और 77/78 सूरत-भुसावल पैसेंजर की भुसावल में पड़ाव अवधि 7 घंटे से कम है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जोधपुर-जैसलमेर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3630. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जोधपुर और जैसलमेर के बीच की वर्तमान मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना बना रही है,

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है, और उसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा उसके वित्त पोषण के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) परियोजना शुरू करने के बाद उसको पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जोधपुर-जैसलमेर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन, आगरा से बाड़मेर/जैसलमेर तक सीधी बड़ी रेल लाइन सम्पर्क के चरणII, का हिस्सा है जिसे सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया गया है। इस कार्य का चरण-I, जिसमें सवाई माधोपुर-जयपुर आमान परिवर्तन कार्य, जयपुर से फुलेरा तक समानांतरण बड़ी रेल लाइन का निर्माण और फुलेरा से मेड़ता रोड, मेड़ता रोड-जोधपुर और बीकानेर (लालगढ़-मेड़ता रोड) के आमान परिवर्तन शामिल

हैं, शुरू कर दिया गया है। चरण-I की पर्याप्त प्रगति हो जाने के बाद तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चरण-II का कार्य शुरू किया जाएगा।

पारेषण और वितरण घाटा

3631. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार, अखिल भारतीय औरत पारेषण और वितरण घाटा कितना होता है; और

(ख) इसे कम करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में पारेषण एवं वितरण हानियां लगभग 23% हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान औसत पारेषज एवं वितरण हानियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इन हानियों का कम करने के सम्बन्ध में विद्युत युटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं—अत्याधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत घटकों का पता लगाने हेतु ऊर्जा संबंधी लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करना, वोल्टता संबंधी परिदृश्य में सुधार करने हेतु कैपेसिटर प्रतिष्ठापित करना, युटिलिटीज की पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने एवं उनमें सुधार करने हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना उर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रूफ मीटर बाक्स लगाना और ऊर्जा की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत, अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।

पारेषण एवं वितरण हानियों की कमी करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 1987 से, राज्य बिजली बोर्डों के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम आरम्भ की गई थी।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों में प्रतिशत परिणमन, पारेषण एवं वितण हानियां (विद्युत की चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियों सहित)

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/विभाग	1989-90@
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	29.19
	2. हिमालय प्रदेश	18.74†
	3. जम्मू और कश्मीर	49.46*

1	2	3
	4. पंजाब	18.96†
	5. राजस्थान	21.97*
	6. उत्तर प्रदेश	26.10
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	22.08†
	2. मध्य प्रदेश	19.48
	3. महाराष्ट्र	17.60
दक्षिणी क्षेत्र	1. आंध्र प्रदेश	20.20†
	2. कर्नाटक	20.00
	3. केरल	22.00*
	4. तमिलनाडु	18.46
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	21.50*
	2. उड़ीसा	23.99
	3. सिक्किम	23.36
	4. पश्चिम बंगाल	21.58*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम	21.58
	2. मणिपुर	20.83†
	3. मेघालय	10.90
	4. नागालैण्ड	18.00**
	5. त्रिपुरा	29.78†
	6. अरुणाचल प्रदेश	27.60†
	7. मिजोरम	29.00†

टिप्पणी : 1. @अनन्तिम

2. मेघालय के मामले में अपेक्षाकृत कम पारेषण एवं वितरण हानियां, इसके द्वारा पड़ोसी राज्यों को ऊर्जा की अत्याधिक मात्रा में बिक्री किए जाने के कारण है।

स्रोत : 1. पी० डी० बी० एण्ड आई० निदेशालय, के० वि० प्रा०।

2. † राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत विभाग।

3. * संसाधनों के संबंध में योजना आयोग में हुआ विचार-विमर्श।

4. ** वार्षिक योजना 1991-92 के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।

विकासपुरी में पेट्रोल पम्पों की स्थापना

3632. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासपुरी, नई दिल्ली से सबसे निकटतम पेट्रोल पम्प 6-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है,

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में पेट्रोल पम्पों के लिए दो स्थानों की स्वीकृति दी है,

(ग) यदि हां, तो विकासपुरी में पेट्रोल पम्प आवंटित नहीं करने के कारण क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली के अन्य किन-किन क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आवंटित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं। केवल एक स्थान का अनुमोदन किया गया है।

(ग) स्थान का अधिग्रहण अभी नहीं दिया गया है।

(घ) विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार विभिन्न शहरों में पेट्रोल/डीजल की नई डीलरशिपों तथा एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं।

विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र

3633. **श्री के०बी० तंगाबालू** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की विजयवाड़ा ताप विद्युत परियोजना चरण-तीन को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है और इसके लिए निर्धारित की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है तथा इसे कब तक पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विजयवाड़ा ताप विद्युत परियोजना, चरण-तीन जिसमें 210-210 मेगावाट की

दो यूनिटें प्रतिष्ठापति किए जाने की परिकल्पना की गई थी, इसको 585.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1991 में अनुमोदित कर दिया गया था। वार्षिक योजना 1991-92 के लिए योजना आयोग ने अनन्तिम रूप से 39.60 करोड़ रुपए के परिव्यय हेतु सिफारिश की है।

(ग) मुख्य उपस्कर के लिए आशय पत्र अप्रैल, 1990 में भेल को जारी कर दिया गया था और इस सम्बन्ध में फरवरी, 1991 में भेल को अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था। पहले यूनिट को 1993 94 और दूसरे यूनिट को 1994-95 में चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

ज्वारीय तरंगों का उपयोग करना

3634. **श्री के० वी तंगाबालू** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते दामों पर बिजली का उत्पादन करने हेतु ज्वारीय तरंगों को उपयोग में लाने के लिए नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सस्ती दरों पर ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन हेतु नई प्रौद्योगिक प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। कच्छ ज्वारीय परियोजना पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं।

तेल उत्पादन का लक्ष्य

3635. **श्री के० वी० तंगाबालू** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की तेल की कम्पनियों ने वर्ष 1991-92 के लिए अपने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लक्ष्य में छः मिलियन टन से भी अधिक कमी करने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल कम्पनियों ने यह संकेत दिया है कि विभिन्न कारणों से वर्ष 1991-92 के अनुमानित कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आएगी संशोधित अनुमानित उत्पादन के आंकड़ों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला क्षेत्र से जोड़ा जाना

3636. **श्री के० वी० तंगाबालू :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला आपूर्ति के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र को निकटतम कोयला खान से जोड़ा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक विद्युत परियोजना को कोयला खान से जोड़े जाने का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोयला संयोजन का निर्णय लेते समय तापीय विद्युत गृहों को कोयले का संयोजन मुहैया किए जाने के लिए किसी युक्तिसंगत स्रोत से संयोजन किए जाने का सदैव प्रयास किया जाता है। चूंकि देश के दक्षिण-पूर्वी भागों में कोयले के भण्डार सीमित हैं, अतः किसी समीप के कोयला क्षेत्र से कोयले का संयोजन मुहैया किया जाना सदैव सम्भव नहीं हो पाता है।

(ख) जुलाई-सितम्बर, 1991 की तिमाही के लिए कोयले के मासिक संयोजन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े 000 टन में)

तापीय विद्युत गृह का नाम	अनुमोदित मासिक संयोजन जोड़	कम्पनी का नाम	स्रोत
1 2	3	4	5
I. उत्तरी क्षेत्र			
1. बदरपुर	300	से०को०लि०	द० कर्णपुरा
		से०को०लि०	उ० कर्णपुरा
		भा०को०को०लि०	झरिया
2. आई०पी०स्टेशन	100	से०को०लि०	द० कर्णपुरा
		भा०को०को०लि०	झरिया
3. राजघाट	40	से०को०लि०	उ० कर्णपुरा
जोड़ दिल्ली	440		
4. फरीदाबाद	60	से०को०लि०	द० कर्णपुरा
5. पानीपत	180	से०को०लि०	धोरी
		से०को०लि०	द० कर्णपुरा (कूजू)
जोड़ हरियाणा	240		

1	2	3	4	5
	6. भटिडा	180	से०को०लि०	उ० कर्णपुरा
			से०को०लि०	राजरप्पा
			भा०को०को०लि०	झरिया
	7. रोपड़	300	से०को०लि०	उ० कर्णपुरा
	7. रोपड़		से०को०लि०	धोरी
	7. रोपड़		भा०को०को०लि०	झरिया
	जोड़ पंजाब	480		
	8. कोटा	200	ना०को०लि०	सिंगरौली
	8. कोटा		सा०ई०को०लि०	कोरिया रेवा
	8. कोटा		भा०को०को०लि०	झरिया
	जोड़ राजस्थान	200		
	9. हरदुआगंज "ए"	5	से०को०लि०	द० कर्णपुरा
	10. हरदुआगंज "बी" और "सी"	80	भा०को०को०लि०	झरिया
	10. हरदुआगंज "बी" और "सी"		से०को०लि०	धोरी
	11. कानपुर (केसा)	0	ई०को०लि०	रानीगंज
	12. पांकी (पुराना)	5	से०को०लि०	द० कर्णपुरा
	13. पांकी विस्तार	60	भा०को०को०लि०	झारिया
	13. पांकी विस्तार		से०को०लि०	धोरी
	14. परीचा	60	भा०को०को०लि०	झरिया
	14. परीचा		से०को०लि०	धोरी
	15. टांडा	60	से०को०लि०	धोरी
	15. टांडा		भा०को०को०लि०	झरिया
	16. ऊंचाहार	90	से०को०लि०	गिद्डी/राजरप्पा
	16. ऊंचाहार		से०को०लि०	उ० कर्णपुरा
	17(ए) लखनऊ	3	से०को०लि०	द० कर्णपुरा
	18. ओबरा "ए" और "बी"	575	ना०को०लि०	सिंगरौली
	18. ओबरा "ए" और "बी"		से०को०लि०	उ० कर्णपुरा

1	2	3	4	5
19.	अन्नपारा	300	ना०को०लि०	सिंगरौली
20.	सिंगरौली एसटीपीएस	600	ना०को०लि०	जयन्त
21,	रिहंद	3‸0	ना०को०लि०	दुधीचुआ/अमलो
22.	एन०सी०टी०पी०पी०	0	से०को०लि०	उ० कर्णपुरा
	जोड़ : उत्तर प्रदेश	2138		
	जोड़ : उत्तर क्षेत्र	3498		
II.	पश्चिमी क्षेत्र			
23.	अहमदाबाद	150	सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
24.	धुवरन	0		
25.	गांधी नगर	160	सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
26.	उकाई	270	सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
27.	वानकबोरी	450	ना०को०लि०	सिंगरौली
27.	वानकबोरी		सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
27.	वानकबोरी		भा०को०को०लि०	झरिया
28.	सिक्का-विस्थापन	50	सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
	जोड़ गुजरात	1080		
29.	अमरकंटक	120	सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
29.	अमरकंटक		सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
30.	कोरबा-ईस्ट	180	सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
30.	कोरबा-ईस्ट		सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
31.	कोरबा-वेस्ट	330	सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
32.	सतपुरा	350	वे०को०लि०	पेंच
32.	सतपुरा		वे०को०लि०	पाथरखेड़ा
32.	सतपुरा		वे०को०लि०	पेंच/नागपुर
33.	कोरबा एस०टी०पी०एस०	750	सा०ई०को०लि०	मेनलालन
34.	विध्याचल एस०टी०पी०एस०	390	ना०को०लि०	निघाई/अमलोरी
	जोड़ मध्य प्रदेश	2120		

1	2	3	4	5
35,	भूसावल	180	वे०को०लि०	एन०पी०के० डब्लू०
35.	भूसावल		सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
36.	चन्द्रपुर (एम०एस०ई०बी०)	400	वे०को०लि०	दुर्गापुर/पदमपुर
36.	चन्द्रपुर (एम०एस०ई०बी०)		वे०को०लि०	सस्ती/धोपतल्ला
36.	चन्द्रपुर (एम०एस०ई०बी)		वे०को०लि०	चांदा
37.	कोराडीह	420	सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
37.	कोराडीह		वे०को०लि०	सिलवाड़ा/कम्पटी
38.	कापरखेड़ा	180	वे० को०लि०	पेंच
38.	कापरखेड़ा		सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
39.	नासिक	370	वे०को०लि०	एन०पी०के० डब्लू०
39.	नासिक		सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
40.	परली	300	वे०को०लि०	चंदा
40.	परली		सिं०को०कं०लि०	सिंगरेनी
41.	परास	30	वे०को०लि०	उमरेर
42.	ट्रामबे	20	सा०ई०को०लि०	कोरिया-रेवा
	जोड़ महाराष्ट्र	1900		
	जोड़ पश्चिमी क्षेत्र	5100		
III दक्षिणी क्षेत्र				
43.	कोठागुडम	250	सि०को०कं०लि०	सिंगरेनी
43.	कोठागुडम		सिं०को०कं०लि०	सिंगरेनी
44.	रामागुंडम "बी"	30	सिं०को०कं०लि०	सिंगरेनी
45.	विजयवाड़ा	360	सिं०को०कं०लि०	सिंगरेनी

1 2	3	4	5
45. विजयवाड़ा		सा०ई०को०लि०	तालचेर
45. विजयवाड़ा		सिं०को०कं०लि०	सिंगरेनी
46. नेललोरे	15	सिं०को०कं०लि०	सिंगरेनी
46. रामागुंडम एस० टी० पी० एस०	600		
47. रामागुंडम एस० टी० पी० एस०		वे०को० लि०	वर्धा
जोड़ आंध्र प्रदेश	1315		
48. रायचुर	270	वे०को०लि०	चांदा
48. रायचुर		सिं०को०कं०लि०	सिंगरेनी
जोड़ कर्नाटक	270		
49. एनोरे	210	सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
50. तूतीकोरिन	330	ई०को०लि०	रानीगंज
50. तूतीकोरिन			
50. तूतीकोरिन		ई०को०लि	मुग्मा
50. तूतीकोरिन		भा०को०को०लि०	झरिया/दामागोरी
50. तूतीकोरिन		सा०ई०को०लि०	मेन लाइन
51. मेट्टूर	360	सा०ई०को०लि	तालचेर
51. मेट्टूर		सा०ई०को०लि	मेनलाइन
जोड़ तमिलनाडु	900		
जोड़ दक्षिण क्षेत्र	2485		
IV पूर्वी क्षेत्र			
52. बरौनी	60	ई०को०लि०	मुग्मा/चित्रा
52. बरौनी		से०को०लि०	गिरीडीह
52. बरौनी		भा०को०को०लि०	
52. मुज्जफरपुर	60	ई०को०लि०	मुग्मा/चित्रा

1	2	3	4	5
53	मुज्फरपुर		से०को०लि०	गिरीडीह
53.	मुज्जफरपुर		भा०को०को०लि०	
54.	पतरातु	150	से०को०लि०	उ०कर्णपुरा
54.	पतरातु		से०को०लि०	द०कर्णपुरा
55.	पटना	2	ई०को०लि०	रानीगंज
	कुल : बिहार	272		
56.	बोकारो (ए+बी)	120	से०को०लि०	सेल० धोरी
56.	बोकारो (ए+बी)		डी०वी०सी०	डी०वी०सी० माइन्स
57.	बोकारो (ए+बी)		से०को०लि०	कारगली डब्लू/एम
57.	चन्द्रपुर	150	से०को०लि०	धोरी
57.	चन्द्रपुर		भा०को०को०लि०	झरिया/ लोहापट्टी
57.	चन्द्रपुर		भा०को०को०लि०	दुग्दा डब्लू/एम
58.	दुर्गापुर (डी०वी०सी०)	100	ई०को०लि०	मुग्मा-सालनपुर
58.	दुर्गापुर (डी०वी०सी०)		भा०को०को०लि०	पाथरडीह डब्लू/एम
58.	दुर्गापुर (डी०वी०सी०)		ई०को०लि०	रानीगंज
	जोड़ : डी०वी०सी०	370		
59.	तालचेर	100	सा०ई०को०लि०	जगन्नाथ
	जोड़ उड़ीसा	100		
60.	बडेल	130	ई०को०लि०	रानीगंज
60.	बंडेल		ई०को०लि०	मुग्मा-सालनपुर
61.	संतालडीह	60	ई०को०लि०	रानीगंज

1	2	3	4	5
61.	संतालडीह		भा०को०को०लि०	सुदामडीह डब्लू/एम
61.	संतालडीह		भा०को०को०लि०	भोजूडीह डब्लू/एम
62.	कोलाघाट	250	ई०को०लि०	रानीगंज
62.	कोलाघाट		ई०को०लि०	मुग्मा
62.	कोलाघाट		भा०को०को०लि०	पाथरडीह/ लोडना
62.	कोलाघाट		सा०ई०को०लि०	मेनलाइन
63.	कलकत्ता (सी०ई०एस०सी०)	90	ई०को०लि०	रानीगंज
64.	साउथ जन-स्टेशन	40	ई०को०लि०	रानीगंज
65.	टीटागढ़	80	ई०को०लि० ई०को०लि०	रानीगंज मुग्मा/सालनपुर
66.	दुर्गापुर (डी०पी०एल०)	70	ई०को०लि० ई०को०लि०	रानीगंज मुग्मा-सालनपुर
67.	फरक्का एस०टी०पी०एस०	300	ई०को०लि०	राजमहल
	जोड़ पश्चिम बंगाल	1020		
	जोड़ पूर्वी क्षेत्र	1762		
V उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
68.	बोंगाईगांव	45	ई०को०लि०	रानीगंज
	जोड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र	45		
	जोड़ बड़े तापीय विद्युत गृह	12890		

वायुदूत सेवाओं को बन्द करना

3637. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायुदूत सेवाओं को बन्द करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इसके परिणाम स्वरूप वायुदूत के कुल कितने कर्मचारी फालतू/बेरोजगार हो जाएंगे; और

(घ) सरकार का विचार इन कर्मचारियों का पुनर्वास किस प्रकार से करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) सरकार वायुदूत लिमिटेड के भविष्य के ढांचे के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रसोई गैस की आपूर्ति और मांग

3638. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस की वर्तमान वार्षिक मांग और आपूर्ति कितनी है,

(ख) मांग की पूर्ति न होने के क्या कारण है; और

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान रसोई गैस की मांग और आपूर्ति में कितना अन्तर होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ग) जबकि फिलहाल प्रतीक्षा सूची में लगभग 70 लाख आवेदकों का संचय है, 1990-95 के दौरान एल० पी० जी० की उपलब्धता निम्न प्रकार होगी।

वर्ष	एल० पी० जी० की अनुमानित उपलब्धता (.000 मिट्रिक टन में)
1990-91	2417
1991-92	2495
1992-93	2629
1993-94	2803
1994-95	3184

(ख) उत्पाद की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सम्पूर्ण मांग की पूर्ति नहीं की जा रही है।

महाराष्ट्र में तेल-शोधक कारखाना

3639. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पूर्ति मांग अनुमानों के आधार पर पश्चिमी भारत में 6 मि० ट० प्रति वर्ष की क्षमता की एक ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3640. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने 11 जुलाई, 1991 को एक सांकेतिक हड़ताल की थी,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने मांगों को पूरा करने और भविष्य में ऐसी हड़तालें न होने देने के लिए क्या कार्यवाई की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 11.7.91 को कोई सांकेतिक हड़ताल नहीं हुई थी। शायद प्रश्न का सम्बन्ध 11.7.90 से है जब इंडियन एयरलाइन्स के पांच संगठनों ने सांकेतिक हड़ताल की थी।

(ख) संगठनों की मांगे इस प्रकार थी :—

1. संकट का समाधान करने के लिए संगठनों/संघों के साथ संयुक्त रूप से तत्काल बातचीत शुरू की जाए।
2. ए-320 विमानों के परिचालन पर तत्काल एक निश्चित निर्णय ले लिया जाए और ऐसा निर्णय लिए जाने तक, इंडियनलाइन्स किसी विदेशी एजेंसी से वेट लीज पर कोई विमान न ले।
3. निजी प्रचालकों को भारत में वाणिज्यिक विमान परिवहन शुरू करने से रोका जाए।
4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों के परिचालन की ही अनुमति दी जाए और यह विदेशी विमान कम्पनियों से वेट लीज पर विमान प्राप्त न करे।
5. वायु निगम अधिनियम, 1953 के अनुसार प्राधिकार इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधक

वर्ग को सौंप दिया जाए ताकि विमान कम्पनी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) : (1) ए-320 विमानों को बाद में सेवा में लगा दिया गया था।

(2) अंतर्देशीय हवाई सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के सम्बन्ध में संगठनों के प्रतिनिधियों को सरकार की नीति पूर्णतया स्पष्ट कर दी गई थी। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जबकि इंडियन एयरलाइंस सरकार से सारी सहायता प्राप्त करेगी और आने वाले समय में स्पष्टतः यह प्रमुख अन्तर्देशीय वाहक होगी, तथापि, सरकार अंतर्देशीय विमान सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देगी और इसे उदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

(3) वायुदूत के सम्बन्ध में, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वायुदूत अपने मामले में स्वयं निर्णय लेने के लिए हकदार है। तथापि, सितम्बर, 90 से वायुदूत ने ही विदेशी विमान कम्पनियों से वेट लीज पर विमान लेना बन्द कर दिया है।

(4) वायु निगम अधिनियम, 1953 के अनुसार प्राधिकार इंडियन एयरलाइन्स के पास हैं।

राउरकेला में पहिया-धुरी संयंत्र

3641. **श्री रवि राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राउरकेला में एक पहिया-धुरी संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या "राइटस' (रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विस) ने राउरकेला में इस संयंत्र को स्थापित करने के पक्ष में रिपोर्ट की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों पर खाद्य सामग्री के मूल्य

3642. **श्री महेश कुमार कनोड़िया**
श्री चेतन पी० एस० चौहान } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर बेचे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों तथा शीतल पेय के मूल्य इन्हीं वस्तुओं के बाजार मूल्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उचित दामों पर बस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाने

का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) साधन सामग्री की लागत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों के लिए निर्धारित की गई कीमतें उचित समझी जाती हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता से चलाई जा रही विद्युत परियोजनाएं

3643. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ विद्युत परियोजनाएं विदेशी सहायता से स्थापित की जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कहां-कहां पर चल रही हैं,

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने में काफी विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उतर प्रदेश में विदेशी सहायता से निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	स्थल
1.	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना	840	गाजियाबाद
2.	संयुक्त साइकल गैस आधारित विद्युत परियोजना (दादरी)	817	—वही—
3.	टिहरी जल विद्युत काम्प्लैक्स	2400	टिहरी गढ़वाल
4.	अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना	1000	सोनभद्रा
5.	ऊंचाहार (विस्तार) ताप विद्युत परियोजना	420	राय-बरेली
6.	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	330	पौड़ीगढ़वाल

(ग) और (घ) टिहरी जल विद्युत काम्प्लैक्स, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना और

अनपारा "ख" एव ऊंचाहार (विस्तार) ताप विद्युत परियोजनाओं को पूरा किए जाने में कुछ विलम्ब हुआ है। टिहरी परियोजना के मामले में विलम्ब का मुख्य कारण पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति का मामला होना है और अन्य परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकार के पास रुपये सम्बन्धी संसाधनों की बाधाएं होना है।

[**अनुवाद**]

रेल कर्मचारियों के लिए साक्षरता मिशन

3644. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राष्ट्रीय साक्षरण मिशन के अन्तर्गत रेल-कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी सफलता मिली है,

(ग) प्रत्येक रेल मण्डल में कितने प्रतिशक्ष केन्द्र हैं और गत दो वर्षों के दौरान कितने लोगों ने इनमें भाग लिया; और

(घ) उड़ीसा में किन स्थानों पर भविष्य में ऐसे केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[**हिन्दी**]

दिल्ली में बिजली की दर

3645. **श्री राजबीर सिंह : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने विजली शुल्कों की दर में कितनी बढ़ोतरी की है और यह किस तारीख से लागू की गई है,

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के तहत सरकारी आवासों में बिजली की खपत की रीडिंग प्रतिमाह ली जाती है,

(ग) यदि नहीं, तो बिजली बिल प्रतिमाह वास्तविक रीडिंग जोकि बहुत कम होती है के आधार पर भेजने के बदले दो या चार महीनों के बाद की गई मीटर रीडिंग जो कि बहुत अधिक बिजली की खपत दर्शाती है, के आधार पर ऊंची दर पर भेजने के कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) एन० डी० एम० सी० द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिजली के बिल मासिक रीडिंग के आधार पर जारी किए जाते हैं। किन्ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मीटर रीडिंग लेने आदि में विलम्ब हो जाने के मामले में उपभोक्ता से आनुपातिक उपभोग के आधार पर प्रभार वसूल किए जाते हैं। ओवर-बिलिंग आदि का कोई विशेष मामला एन० डी० एम० सी० की जानकारी में लाया जाता है तो इसमें सुधार किया जाता है।

विवरण

1.3.91 से लागू एन० डी० एम० सी० की संशोधित विद्युत टैरिफ को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	श्रेणी	संशोधन पूर्व टैरिफ (पैसे प्रति यूनिट)	संशोधित टैरिफ (1.3-91 से लागू) (पैसे प्रति यूनिट)
1.	घरेलू (लाइट, पंखा, पावर)		
	प्रथम 100 यूनिट	29	42
	आगामी 100 यूनिट	34	52
	अनुवर्ती 100 यूनिट	77	152
	300 यूनिट से अधिक	77	202
2.	घरेलू (पावर)	77	102
3.	वाणिज्यिक (100 किलोवाट आवर तक)	92	153
4.	**वाणिज्यिक** (पात्र दातव्य और धर्मपरायण निकायों के लिए 100 किलोवाट आवर से कम हेतु)		
	प्रथम 100 यूनिट	29	78
	100 यूनिट से अधिक	34	139
5.	रियायती वाणिज्यिक पात्र दातव्य और धर्मपरायण संस्थानों हेतु (100 किलोवाट और इससे अधिक के लिए)	52+10%	139+10%

1	2	3	4
6.	रियायती वाणिज्यिक पात्र लघु पैमाना औद्योगिक यूनिटों के लिए (100 किलोवाट आवर से कम हेतु)	78	128
7.	वाणिज्यिक (100 किलोवाट और इससे अधिक) निम्न वोलल्टता	185 पैसे + 10%	244 पैसे + 10%
8.	वाणिज्यिक (उच्च वोल्टता)	185	244

[अनुवाद]

जबलपुर स्टेशन का आधुनिकीकरण

3646. **श्री श्रवय कुमार पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के तौर पर विकसित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, तथा 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ख) वहां पूरे किए गए और अभी शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जबलपुर आदर्श स्टेशन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1991-92 में स्वीकृत राशि निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	राशि लाख रुपयों में
1988-89	4.60
1989-90	21.58
1990-91	34.71
1991-92	10.30
	71.19

(ख) पूरे किए गए, कार्यों, चल रहे कार्यों तथा अभी शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) पूरे किए गए/चल रहे कार्य

क्रम सं०	काम का नाम	लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	कोटा पत्थर डाडो की व्यवस्था करना और फर्श, एफ० आर० पी० कुर्सियों में सुधार करना और रोशनी की व्यवस्था में सुधार करना।	1.00
2.	आधुनिक किस्म का फर्नीचर, बड़े आकार के इलैक्ट्रानिक इन्डीकेटर बोर्डों, टिकटें जारी करने के लिए एस० पी० टी० सी० मशीन की व्यवस्था करना।	2.52
3.	प्लेटफार्मों तथा प्रतीक्षालयों के लिए कोटा पत्थर की फर्श की व्यवस्था करना।	1.94
4.	दूसरे दर्जे के साधारण और महिला प्रतीक्षालय तथा प्रतीक्षा कक्षों के शौचालयों और स्नानगृहों में सुधार करना।	0.70
5.	शहर की ओर बुकिंग एवं आरक्षण कार्यालय का विस्तार करना।	1.42
6.	एल्यूमिनियम के दरवाजों तथा खिड़कियों की व्यवस्था करके स्टेशन इमारत के दरवाजों और खिड़कियों में सुधार करना।	3.00
7.	स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय और अन्य कार्यालयों में मौजेक टाइलों की फर्श और आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था करना।	1.50
8.	लाइसेंसधारी पार्टरों के लिए विश्राम स्थल की व्यवस्था करना।	1.50
9.	15 अदद सी० सी० टी० वी० की व्यवस्था करना	1.98
10.	आरक्षण कार्यालय में जल शीतक की व्यवस्था करना।	0.80
11.	मौजूदा विभागीय भवनों और क्वार्टरों को तोड़कर के परिचलन क्षेत्र का विस्तार करना। चाहरदीवारी की व्यवस्था करना, पहुंच सड़कों को चौड़ा करना और उन पर डामर बिछाना। पार्किंग स्थलों, यातायात लेनों, परिचलन क्षेत्र में	19.38

1	2	3
	सोडियम वैपर लैम्पों की व्यवस्था करना, फूलदार और छायादार वृक्षों को लगाना आदि ।	
12. (क)	मौजूदा इमारत में परिवर्धन और परिवर्तन करना ताकि दो बिस्तर वाले एक गैर वातानुकूल तथा दो बिस्तर वाले एक वा० कू० डीलक्स विश्रामालयों और केयरटेकर कक्ष की व्यवस्था की जा सके ।	4.40
(ख)	प्रस्तावित दो बिस्तरों वाले 4 और चार बिस्तरों वाले 3 अदद जनता विश्रामालय	39.50
13.	प्लेडफार्म नं० 1 पर सायवान का विस्तार	15.00
14.	अप और डाउन प्लेटफार्म का विस्तार और प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर सायबान की व्यवस्था करना ।	21.32
15.	प्लेटफार्म नं० 1 और 2 पर धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था करना ।	40.00
16.	मुख्य भवन के दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार करना और मौजूदा भवन में पहले दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था करना ।	10.00
17.	अप और डाउन प्लेटफार्म कर जल शीतकों का व्यवस्था करना ।	2.50
(2)	**कार्य जो अभी शुरू किए जाने हैं**	
18.	दिल्ली छोर पर मौजूदा ऊपरी पैदल पुल को पश्चिमी की ओर परिचलन क्षेत्र तक और प्लेटफार्म नं० 2 और 3 को प्लेटफार्म सं० 1 तक बढ़ाना ।	11.09
19.	शहर की ओर साइकिल/स्कूटर स्टैंड में सुधार करना ।	5.00
20.	पार्सल कार्यालय इमारत का विस्तार करना ।	5.00
21.	प्लेटफार्म नं० 1 पर चार शौचालय सीट और प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर चार शौचालय, चार स्नानगृहों की व्यवस्था करना ।	2.00
22.	प्लेटफार्म नं० 3 पर अल्पाहार स्टाल की व्यवस्था करना ।	0.80
23.	शहर की ओर के बुकिंग कार्यालय में शौचालय की व्यवस्था ।	0.15
24.	कांकोर्स, प्लेटफार्म आदि में अतिरिक्त सोडियम वैपर लैम्पों की व्यवस्था करके रोशनी की व्यवस्था में सुधार करना ।	4.00
25.	प्लेटफार्म तथा प्रतीक्षालयों पर मूत्रालयों की व्यवस्था	0.50
26.	प्लेटफार्म तथा कांकोर्स में पानी के नलकों की व्यवस्था करना ।	0.03

वाईगाई एक्सप्रेस रेलगाड़ी का तांबमम् में रूकना

3647. **श्री बी० राज रवि वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाईगाई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ताबरम् में रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम में माल सूची नियंत्रण

3648. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री लोकनाथ चौधरी } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने निगमित कार्यालय में एक "ऋण नियन्त्रण प्रकोष्ठ" की स्थापना की थी और इसके साथ ही "सामग्री प्रकोष्ठ" का भी सृजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो दोनों प्रकोष्ठों की यदि कोई उपलब्धियां, हों, तो वे क्या हैं, और पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का विकास निगम की कार्यशील पूंजी के कुशल प्रबन्ध पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) बकाया राशियों की वसूली में एककों की सहायता करने के उद्देश्य से जुलाई 81 में निगमित कार्यालय में ऊधार एवं वसूली कक्ष की स्थापना की गई थी। चुंकि मूल रिकार्ड केवल एकक स्तर पर ही उपलब्ध होते हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया कि स्टाफ को सम्बन्धित एककों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाए। तथापि, बकाया राशियों को मानिटर करने, उधार नियन्त्रण और उधार कार्डो को जारी करने का कार्य निगम स्तर पर ही किया जाता है।

निगमित कार्यालय में तालिका कक्ष ने मार्च 79 में कार्य करना शुरू किया था। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में तालिका प्रबन्ध के वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त, तालिकाओं को मानिटरिंग आदि के ब्यौरे सभी होटल एककों जारी किए गए थे। तालिका-प्रबन्ध के बारे में दिन-प्रतिदिन के कार्य स्वयं एककों द्वारा ही किए जाते हैं। निगमित कार्यालय में कार्यरत सामग्री प्रबन्ध और विकास प्रभाग. उचित तालिका नियन्त्रण रखने, एक एकक से दूसरे एकक में सामान अन्तरित करने को व्यवस्थित करने, बेकार और फालतू वस्तुओं की पहचान करके बेचने ओर दिल्ली स्थित होटल/केटरिंग प्रतिष्ठानों के लिए नई आपूर्ति सहित वस्तुओं की थोक खरीद के लिए केन्द्रीय दर पर ठेका देने में सहायता करता है।

[हिन्दी]

छोटा नागपुर-संथाल परगना के जिलों में रेल सम्पर्क

3649. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटा नागपुर-संथाल परगना क्षेत्र के जिला मुख्यालयों को रेलवे लाइनों से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को रेलवे वैगनों की सप्लाई

3650. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड को पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं कराये हैं,

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं, और

(ग) पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलें ने केवल सिंगरेनी कोल फील्ड्स जिससे वे सम्बन्द्ध है, से आन्ध्र प्रदेश के ताप बिजली घरों को कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की मांग ही पूर्णतः पूरी कर रही हैं अपितु वे वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और तालचेर कोल फील्ड्स, जो युक्तिसंगत स्रोत नहीं है, से सप्लाई में मदद कर रही हैं ।

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा शुरू करने से पहले, कल श्री आडवाणी ने एक मुद्दा उठाया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विदेश मंत्री महोदय से सोवियत संघ की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने के लिए कह रहा हूं। कृपया आप लोग बैठ जाइए।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सोवियत संघ की राजनीतिक स्थिति

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : सरकार ने सोवियत संघ के कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री जी०आई० यनायेव, प्रधान मंत्री पेवलोव तथा सोवियत रक्षा परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष बेकलानोव के हस्ताक्षरों से जारी किया गया यह बयान देखा है कि सोवियत संविधान के अनुच्छेद 127.7 के अनुसार सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राष्ट्रपति का प्राधिकार श्री एम०एस० गोर्बाचोव से लेकर उप-राष्ट्रपति के सुपुर्द कर दिया गया है। सरकार ने श्री जी०आई० यनायेव की ओर सभी देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों तथा संयुक्य राष्ट्र महासचिव को जारी की गई यह अपील भी देखी है जिसमें यह सूचना दी गई है कि 19 अगस्त, 1991 से सोवियत संघ के संविधान और कानूनों के अनुसार 6 महीने की अवधि के लिए आपातकाल स्थिति लागू की जा रही है और इस अवधि में सोवियत संघ में आपातकालीन स्थिति की राज्य समिति समस्त शक्तियों का और प्राधिकार का उपयोग करेगी।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के साथ अपने सम्बन्धों को भारत बहुत महत्व देता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सार्वभौम रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर चलाने पर आधारित हैं और जो भारत-सोवियत शान्ति, मैत्री एवं सहयोग संधि में प्रतिलक्षित हैं। दोनों देश इस संधि को बहुत महत्व देते हैं और यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने इस संधि को आगामी 20 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाने की अपनी मंशा की सम्मिलित रूप से घोषणा की थी। इस तरह सोवियत संघ की ये घटनाएं हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भारत सरकार वहां की स्थिति पर इन घोषणाओं की खबर मिलने के बाद से ही निरन्तर और सतर्कतापूर्वक निगाह रख रही है और इस सम्बन्ध में हालात से बराबर सम्पर्क साधे हुए है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : राजी गांधी हत्याकांड मामले के मुख्य अभियुक्त शिवरासन और शुभा के बंगलौर में आत्महत्या कर लिए जाने का समाचार है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। एक और घोषणा भी करनी है।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए कि क्या उन्होंने

आत्महत्या की है अथवा क्या···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह कृपया बैठ जाइए। कल सदस्य यह चाहते थे कि गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें कि श्री चिदम्बरम और अन्य संसद सदस्यों के सम्बन्ध में तमिलनाडु में क्या हुआ। मैंने कहा था कि एक वक्तव्य देना चाहिए। गृह मंत्री महोदय ने मुझे यह जानकारी दी कि उन्होंने जानकारी एकत्र कर ली है लेकिन वह दुबारा इसकी जांच करना चाहते हैं और इसके बाद वह वक्तव्य देगें। मैंने भी उन्हें इसकी जांच करने के बाद वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है।

एक माननीय सदस्य : वक्तव्य कब दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः कल होगा, आज नहीं होगा।

(**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार और मंत्रियों द्वारा अनेक वक्तव्य दिए जाने हैं जिनका हमें समय पता होना चाहिए ताकि हम उन्हें सुन सकें। उदाहरण के लिए कल रात 7.30 बजे अथवा 8.00 बजे कश्मीर के प्रवासियों के बारे में एक वक्तव्य दिया गया था और हमें इस बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। यदि हमें इसकी सूचना दी गई होती तो हम उसी प्रकार से समय निकाल लेते। अतः समय पहले से बताया जाना चाहिए···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इससे सहमत हूं कि बेहतर यही है कि सदस्यों को इस बारे में जानकारी दे दी जाए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे सहमत हूं कि सदस्यों को सूचना दी जानी चाहिए और उन्हें यह सूचना प्राप्त होने से उन्हें यह पता रहेगा कि सभा में क्या कहा जा रहा है। लेकिन एक और बात को ध्यान में रखना है कि यह सभी वक्तव्य कार्य सूची में उल्लिखित न किए गए कार्यों के बारे में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में दिए जा रहे हैं। मैं सहमत हूं कि कल माननीय सदस्यों ने कहा कि वक्तव्य दिया जाना चाहिए और मैंने कहा था कि वक्तव्य दिया जाना चाहिए और वक्तव्य दिया गया अन्यथा मैं यह कहता कि वक्तव्य आज ही इसी समय दिया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उदाहरण के लिए इस वक्तव्य विशेष पर शुक्रवार को सहमति हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : किस वक्तव्य पर।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में यह सहमति हुई थी कि गृह मंत्री महोदय कश्मीरी प्रवासियों के सम्बन्ध में वक्तव्य देगें और इसलिए इसे सोमवार की सूची में रखा जा सकता था अथवा यदि इसे नहीं रखा गया तो इसे मंगलवार की सूची में रखा जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : असूचीबद्ध कार्य और ऐसे वक्तव्यों को आमतौर पर हम कार्यसूची में नहीं रखते हैं। यह सब असूचीबद्ध कार्य है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में समझ सकता हूं। उसमें भी यदि वक्तव्य देने से कुछ घंटे पहले···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उन मामलों में किया जा रहा है जिनका कार्य सूची मे उल्लेख नहीं है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में बात दिमाग में रहनी चाहिए।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं इसमे सम्बन्धित हूं इसलिए इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[**अनुवाद**]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : एक मिनट। महोदय, यदि यह सूची में शामिल नहीं है तो इस बारे में पूर्व प्रथा यह थी कि एक नोट परिचालित किया जाता था कि इस समय मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा। असूचीबद्ध बक्तव्यों के मामले में हमेशा ही ऐसा होता रहा है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब सहमत हैं तब मैं इसे स्वयं नियम पुस्तिका में शामिल करवा दूंगा। ताकि यह असूचीबद्ध न रहे। जो चर्चा अब हम कर रहे हैं वह सूची में शामिल नहीं है। इसका नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। यदि आप इसका उल्लेख करना चाहते हैं तो हम नियमों में इसका उल्लेख कर देगें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न यही नहीं है। मेरा यह कहना है कि पूर्व प्रथा यह थी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। मैंने आपकी बात समझ ली है और इसे ध्यान में रखूंगा।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : कश्मीर माइग्रंटस पर जो लाठी चार्ज हुआ इसका ईशू मैंने उस दिन उठाया था। अगले दिन उठाया तो यह कहा गया कि आज स्टेटमैंट दिया जाएगा। लेकिन यहां ऐसी घटना हो गई कि हाउस एडजर्न हो गया···**(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वक्तव्य दिया था।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : आपके कमरे में होम मिनिस्टर ने यह कहा कि इसका स्टेटमैंट सोमवार को दिया जाएगा। मैंने कल फिर यह ईशू उठाया, शाम को चार बजे मैं फिर मिला क्योंकि छः बजे वाटर मिनिस्ट्री ने मीटिंग बुलाई थी।···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी, शून्य काल में जो कुछ हुआ मैं उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहता। अन्यथा हम नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख कर देंगे और नियमों के अनुसार कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बता दीजिए कि कश्मीर से आए हुए बेचारे माइग्रेंटस की समस्याओं को हम कहां डिस्कस करें।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हमने स्टेटमैंट करवाया।

श्री मदन लाल खुराना : स्टेटमैंट आठ बजे करवाया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वक्तव्यों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न-उत्तर नहीं होंगे, हां, हन्नान मोल्लाह जी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा निवेदन है कि कल जो स्टेटमैंट हो गया···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको वक्तव्य मिल गया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उसके बारे में हमको कुछ बताया नहीं गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपको रूलिंग दी हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, किन्हीं खास मामलों में, ऐसे नहीं, हां, हन्नान मोल्लाह जी।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह रिपोर्ट है कि राजीव हत्याकाण्ड के मुख्य अभियुक्तों-शिवरासन शुभा ने आज सुबह बंगलौर में आत्महत्या कर ली है जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विशेष जांच दल की असफलता है कि उन्हें पकड़कर हत्याकाण्ड के पीछे वास्तविक षडयन्त्र का पता लगता। हमने इन्दिरा गांधी की हत्या भी देखी है। अनेक लोग मारे गए। इसलिए हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : हन्नान मोल्लाह जी आप बोलते जाएं, आपके पीछे जो बैठ हैं, मैं उनको कह रहा हूं ।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री महोदय शीघ्र जांच करें और वक्तव्य दें कि ऐसा कैसे हो सकता है—मुख्य अभियुक्तों को मारा जा सकता है, मैं नहीं जानता कि किसने उन्हें मारा और क्या हुआ···(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, गृह मंत्री जी यहां हैं । उन्हें वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : यह अति महत्वपूर्ण मामला है ।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक बोलें ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि विदेशी हाथ होने की आशंका है । मुख्य अभियुक्तों को इस प्रकार मार दिया गया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक बोलिए । मैंने श्री चन्द्रजीत यादव को अनुमति दी है । आपके दल के सदस्य इस पर बोल चुके हैं । हां श्री चन्द्रजीत यादव ।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम गृह मंत्री महोदय से एक वक्तव्य चाहते हैं । यदि यह संतोषजनक नहीं है तब मैं एक सभा समिति गठित करने की मांग करूंगा जो इसकी जांच करे कि क्या हो रहा है । यदि विदेशी हाथ होने की आशंका है और उन्होंने एक के बाद एक सबूत नष्ट कर दिए है तब क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति जी, आपके दल के एक सदस्य इस पर पहले ही बोल चुके हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यदि यह सच्चाई है तो उन्हें उत्तर देना होगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए । कृपया बात को समझिए । यदि आप सभी एक साथ बोलेंगें तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा । यदि आप एक-एक करके बोलेंगें तो सभी कुछ कार्यवाही वृत्तांत में जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : लेकिन आप हमें तो बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की दुःखद हत्या के बाद यह बात प्रकाश में आई है कि एल० टी० टी० ई० ने स्वयं को बड़े पैमाने पर संगठित किया है और उनकी न केवल तमिलनाडु में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी गहरी जड़े हैं। यह तथ्य अब प्रकाश में आ रहा है। यह भी गंभीर बात है कि जिन मुख्य अभियुक्तों की खोज की जा रही है वह आत्महत्या कर रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रही है। ऐसा लगता है कि सबूत मिटाने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें। एल० टी० टी० ई० जो इस प्रकार गठित है वह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। मेरे विचार मे गृह मंत्री महोदय को पूर्ण और विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए। मेरी यही मांग है।(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने लोकनाथ जी को अनुमति दी है। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठे जाइए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। कृपया बात को समझिए। यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिए अत्यन्त चिंता का विषय है और गृहमंत्री पहले ही कह चुके है कि इसके पीछे कोई अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और इस बारे में मैं उनसे सहमत हूं। किन्तु एक बात है, सारे प्रमाण मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है और मैं गृहमंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों पर सुरक्षा का भार है उन्हीं को अब जांच का काम भी सौंपा है। महोदय, जब कोई घटना हो जाती है, तो स्वभावतः वे स्वयं को बचाने का प्रयास करेंगे और जांच भी उसी तरह की होगी। इसलिए, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री को इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिन व्यक्तियों पर सुरक्षा का भार हो, उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए और ये घटनाएं उसी का प्रमाण है। इसलिए, इस बिन्दु पर गृह मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय हन्नान मोल्लाह साहब द्वारा उठाए गए तथ्यों के बारे में चिंतित है और इस सदन के द्वारा यह देश माननीय गृह मंत्री से एक स्पष्टीकरण की मांग करता है कि क्या यह सत्य है कि श्री राजीव गांधी की हत्या के मुख्य अभियुक्त और उनके साथी

*कार्यवाही-वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

ने आत्महत्या की है। महोदय, आज सदन के स्थगन से पूर्व हमें तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। महोदय, इसके साथ ही, आज माननीय श्री राजीव गांधी का जन्मदिवस होने के कारण मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की याद में श्री पेरम्बटूर में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, कल रात्रि को ही हमको कुछ पत्रकारों ने बताया कि इस मामले में जो सबसे प्रमुख अभियुक्त माना जाता है, शिवरामन, उसने शायद आत्महत्या कर डाली है। अब काफी समय हो गया है, इस सारे मामले को लटकते हुए और जिसकी चर्चा बहुत होती है।

[अनुवाद]

किसी व्यक्ति को ढूंढने का इतिहास में सबसे बड़ा अभियान।

[हिन्दी]

और शिवरासन के नाम से 10 लाख रुपये का पुरूस्कार हमने दिया है। बीच में एक व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसकी जिस प्रकार से रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई, लगता है कि यह रहस्य अधिक रहस्यपूर्ण होता जा रहा है। अच्छा होगा कि सरकार इस मामले में सदन को विश्वास में ले और यह जो बीच-बीच में र्यूमर्स चलता हैं, उन र्यूमर्स को खत्म करने के लिए स्पष्टीकरण करे कि वस्तु-स्थिति क्या है।

काफी समय से प्रतीक्षा हो रही थी कि गृह मंत्री आकर सदन को जानकारी देंगे कि यह जो जघन्य हत्या हुई, श्री राजीव गांधी की, आज राजीव जी का जन्म दिवस है, उस दिन तो कम से कम जानकारी दें कि इस मामले में सरकार ने कितनी प्रगति की है और कितनी सफलता पाई है ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मंत्री यहां उपस्थित हैं। हम यह जानना चाहते है कि यह खबर सत्य है अथवा नहीं। सरकार के पास क्या सूचना है ?

दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि श्री राजीव गांधी की हत्या में कोई विदेशी हाथ है, हांलाकि लिट्टे को किसी विदेशी ताकत ने उकसाया। उन्होंने यह भी वादा किया कि मामले की जांच करने के लिए न्यायिक जांच की जाएगी। अब, यह विलम्ब क्यों हो रहा है ? उन्हें इस सदन में यह स्पष्टीकरण देना चाहिए। जांच को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या के पीछे कौन थे और क्या षड्यंत्र था। महोदय, हम अत्यन्त गंभीर हैं, हम जानना चाहते हैं कि यह विलम्ब क्यों हैं और उस जांच को वे कब शुरू करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, जो पहले कहा जा चुका है, उसे मैं नहीं दोहराऊंगी। मैं सिर्फ इस ओर गृहमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं कि क्या यह सत्य है कि जब उन्होंने कहा कि यह एक अमरीकी षड्यंत्र है तो अमेरिकी राजदूत

[**श्रीमती गीता मुखर्जी**]

ने इस बारे में उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि वह गलती से ऐसा बोल गए। अगर यह सही है, तो मैं आश्चर्यचकित हूं। (**व्यवधान**) इसलिए, महोदय, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि वे इस बारे में एक विस्तृत वक्तव्य दें। यह षडयंत्र सिर्फ कर्नाटक से असम तक ही नहीं है, अपितु सारे पूर्व में और पश्चिम तक है। कृपया वे हमें यह बात बताएं।

[**हिन्दी**]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : अध्यक्ष जी, यह बड़े खेद की बात है कि राजीव जी कि हत्या के बाद जिस तरीके मे एक के बाद एक···

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी वक्तव्य चाहते हैं ?

[**हिन्दी**]

श्री मनोरंजन भक्त : हत्यायें हो रही हैं या सरकार के काबू के बाहर जा रही है···इससे एक गम्भीरता पैदा हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी साजिश इस देश के अन्दर अगर इस तरीके से होती रहेगी, अगर हमारे देश के लोगों की जान व माल की रक्षा नहीं होगी, तो आगे जाकर देश की अखण्डता और आजादी के ऊपर खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जो खुले से खुला सारी बात सदन के सामने रखें। इसके ऊपर सरकार की कौन-सी पाबन्दी है, किस लिए इस किस्म की घटनायें घट रही हैं और सरकार काबू नहीं पा रही है। इसके इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, तब भी सरकार काबू नहीं पा रही है। ये बातें सदन के सामने लानी चाहिए। आज राजीव गांधी जी का जन्म-दिवस है, इसलिए आज के दिन क्या सही ढंग से कार्यवाही की जा रही है, ये सारी बाते सदन के सामने आनी चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, आज से आठ-दस दिन पहले जीरो-आवर के दौरान इसी सदन के अन्दर मैंने यह कहा था कि हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, चाहे रॉ हो, चाहे आई० बी० हो, वे राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकतीं और फेल्युअर रही हैं। इन्फार्मेशन यह है कि ये सब आफिशियल्स इन सब गवाहियों को या तथ्यों को इस तरीके से पर्दाफाश न हो जाए, सामने न आ जाए, इसीलिए इस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं।···(**व्यवधान**)···इस कारण राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में रहस्य और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। कहीं अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि आप कह रहे हैं, षड्यंत्र है और उसके साथ-साथ देश के अन्दर भी क्या कुछ ऐसे तत्व है कि अगर यह केस चला तो उनके ऊपर ऊंगली उठेगी और वह चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। इसलिए इस तरह से विटनैस को समाप्त करने के लिए साजिश हो रही है। चाहे इस देश के अन्दर तत्व हैं या···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : भाषण हो रहा है, खुराना जी इस तरह से कैसे चलेगा।

श्री मदन लाल खुराना : इसके बारे में मंत्री महोदय ज्ञात करायें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से केवल बंगलौर में हुई घटना के बारे में ब्यान नहीं चाहता हूं। हमारी यह मान्यता है कि यह जो स्पेशल-इन्वैस्टिगेशन-टीम नियुक्त की गई थी, यह एजेंसी अपने काम में बिल्कुल ही नाकामयाब साबित हुई है। इस नाकामयाबी के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी सदद को विश्वास में लेने का काम करें। पिछले दो महीनों में कुछ व्यक्ति, जो इसमें अपराधी समझे जाते थे, जो कभी कलकत्ता में दिखाई दिए किसी को, कभी दिल्ली में दिखाई दिए किसी को और कभी नेपाल में दिखाई दिए किसी को, इस प्रकार के बयान फैलाने का काम हुआ है। ये बयान कि वे लोग कहां हैं, इसकी जानकारी रहते हुए, देश को गुमराह करने के वास्ते कि हम लोग सही दिशा में हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के बयान दिए गए अथवा जो लोगों का पीछा हो रहा था, उनको मालूम न हो कि हम लोग पीछे हैं।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत चर्चा हो गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं इसके पीछे वजह बताता हूं, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। एस० आई० टी० के आफिसर हिन्दुस्तान के हर महानगर में घूमने का, भ्रमण करने का काम पिछले दो महीनों से करते रहे हैं। उस भ्रमण के पीछे क्या वजह थी, जो अपराध करके, जिसको आप मानते हों, वह कहीं आस-पास मद्रास या बंगलौर के आस-पास पड़े हों और इनके एस० आई० टी० के आफिसर समूचे देश का भ्रमण करते हों, यहां पाए गए और वहां पाए गए, हम इन की जानकारी चाहते हैं।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से इन्वैस्टिगेशन में इम्पैडीमेंट हो सकती है। इसलिए एक लिमिट के अन्दर ही अपनी बात कहें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इसीलिए वे इस पर बयान दें।

···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

डा० राजागोपालन श्रीधरन (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, कल कांग्रेस (आई) के एक सदस्य ने तमिलनाडु सरकार को तुरन्त बर्खास्त करने की मांग की थी। यहां मैं अपने दल की ओर से, संबंधित सदस्य से तुरन्त क्षमा याचना करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उन्हें इस सदन में ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। जहां तक विधान सभा का सम्बन्ध है, हमारे 225 विधायक हैं। (**व्यवधान**) इसलिए, मैं उनसे तुरन्त क्षमा याचना करने की मांग करता हूं। (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : कल शून्य काल के दौरान श्री अडईकलराज और श्री सी० के० कुप्पुस्वामी ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि वे वक्तव्य दे रहे हैं। आप अब यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री पी० जी० नारायणन : कल शून्य काल के दौरान श्री अडईकलराज और श्री सी० के० कुप्पुस्वामी ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। किन्तु तथ्य यह है कि तमिलनाडु में अभी जो उपचुनाव हो रहा है। उनमें हमारे मुख्य मंत्री और अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : इसे वक्तव्य के बाद उठाएं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपके सहयोगी ने भी अपनी बात कह दी है।

(**व्यवधान**)

श्री पी० जी० नारायणन : हम केन्द्र में कांग्रेस का समर्थन भी कर रहे हैं। महोदय, उन दोनों कांग्रेस सदस्यों को राज्य सरकार को बर्खास्त करने सम्बन्धी अपनी मांग को वापस लेना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपना वक्तव्य वापस लेने के लिए नहीं कह सकता। कृपया बैठ जायें। अब आप स्थिति को समझ सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

श्री पी० जी० नारायणन : यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। (**व्यवधान**) यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनका वक्तव्य कांग्रेस दल द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। क्या आप वक्तव्य देते समय अपने साथियों से बैठने को कहेंगे ?

(**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : वे अपना वक्तव्य माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० नारायणन : कल दो कांग्रेसी सदस्यों ने तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी, किन्तु तथ्य यह है कि अभी तमिलनाडु में जो उपचुनाव हो रहा हैं, उसमें हमारा दल और हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस दल के लिए प्रचार कर रहे हैं। किन्तु उनका रुख कांग्रेस दल के रुख के विपरीत है, और इसलिए या तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा या अपना वक्तव्य वापस लेना होगा। अन्यथा हमें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा। (**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ चौधरी : आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। वहां क्या है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

डा० राजागोपालन श्रीधरण : हम तुरन्त क्षमायाचना चाहते हैं। यही हम चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपको अब एक वैवाहिक सलाहकार की आवश्यकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : जब सदन को वास्तव में एक परामर्श-दाता की आवश्यकता पड़ी तो मैं परामर्शदाता के रूप में सिर्फ श्री सोमनाथ चटर्जी को चाहूंगा, और किसी को नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना देते हैं? (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैं अन्नाद्रमुक दल के अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा···

डा० राजागोपालन श्रीधरण : सहयोगी दल।

श्री अर्जुन सिंह : जब मैंने मित्र कहा है, तो यह सहयोगी से अधिक है। मैं कहना चाहूंगा —माननीय सदस्य कृपया यह ध्यान रखें—कि इस मुद्दे पर कल अत्यन्त जोरदार बहस हुई थी। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है और मैं यह भी जोडूंगा कि जहां तक दल का सम्बन्ध है, तमिल-सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। ऐसा प्रश्न ही नहीं है। अब, मुद्दा यह है कि किसी ने गर्मागर्मी में कुछ कह दिया है और हमें इस बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरुचेंगोड़) : हम क्षमा याचना की मांग करते हैं।

डा० राजागोपालन श्रीधरण : उन्होंने ऐसी मांग क्यों की? हम क्षमा-याचना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया समझें कि आपने जो भी मांगा आपको सरकार से वह मिला। उसके बाद भी आप उत्तेजित खड़े है, बोल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। हम नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाएं। आप इस तरह नहीं कर सकते। आप इस तरह बार-बार नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार के प्रतिनिधि ने वही कहा है जो उन्होंने सदन में कहा था। अब आप क्या चाहते हैं?

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : उन्होंने तमिलनाडु की जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। हम क्षमा-याचना की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मत चिल्लायें। यह सही नहीं है। आप जो भी कह रहे है वह सदन में प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है।

(**व्यवधान**)

डा० राजागोपालन श्रीधरण : हम इस बारे में परेणान नहीं हैं। हम संबंधित संसद सदस्य से क्षमा-याचना की मांग करते हैं। उन्होंने कल तमिलनाडु विधान सभा को भंग करने की मांग की थी। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए हम इस बारे में परेशान नहीं है। (**व्यवधान**)

12.35 म०प०

इस समय श्री राजागोपालन श्रीधरण और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)*

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कृपया सभा स्थगित कर दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यहां पर क्या गपशप चल रही है? क्या यह दलों की बैठक करने का स्थान है? काफी हो चुका। वे पीठासीन अधिकारी के साथ अत्यधिक अनादरपूर्वक पेश आ रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 1 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 1.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा 1.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

1:04 म० प०

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह ठीक नहीं है। उन्हें बाहर जाने दीजिए। वे इस पर चर्चा करें तथा फिर वापस आएं। सभा की मर्यादा को बनाए रखना है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे विचार-विमर्श तथा परामर्श करना चाहते हैं, तो वे दीर्घा में जाकर ऐसा कर सकते हैं तथा फिर वापस आ जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम चाहते हैं कि वे वापस आयें तथा सभा में की जाने वाली चर्चाओं में भाग लें। मैं आशा करता हूं कि इसका समाधान किया जा चुका है तथा श्री अर्जुन सिंह ने उन्हें संतुष्ट कर दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि उन्होंने बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय बोलेंगे।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, मैं निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहूंगा :

"ईस्टर्न कोल फील्डस की कुनोस्टोरिया स्थित कोयला खानों में 2 तथा 8 अगस्त को हुई गम्भीर दुर्घटनाएं।"

महोदय, उपर्युक्त दोनों दुर्घटनाओं से कोयला-खान मजदूरों के जीवन को भारी नुकसान पहुंच सकता था। इन दोनों दुर्घटनाओं से पता लगता है कि प्रबन्ध की ओर से खान मजदूरों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है यद्यपि टेलीविजन फिल्मों के माध्यम से गलत सूचना प्रसारित की जाती है तथा इस प्रकार से बहुधा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जाता है तथा प्रचार यह किया जाता है कि इस सार्वजनिक क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटड में खानों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। पहली दुर्घटना कुनोस्टोरिया कोयला खान में दिनांक 2.8.91 को कंदा सीम में पानी भर जाने के कारण हुई थी जहां पर मजदूरों को काम पर लगाया जाता है जैसा कि महाबीर कोयला खान दुर्घटना जो नवम्बर 1989 में घटी थी जिसमें 71 व्यक्ति नीचे खान में फंस गए थे। जिनमें से छः की मृत्यु हो गई। दूसरी भयंकर दुर्घटना दिनांक 8.8.91 को ऊपरी परत के धंस जाने के कारण हुई थी जिसके परिणामस्वरूप इस कोयला खान के प्रबन्धक तथा अभिकर्ता के निवास स्थल तक इसमें धंस गए थे। खानों की सुरक्षा को इतना कम महत्व दिया जाता है कि अभिकर्ता, प्रबन्धक यहां तक कि कोमला खान के सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी अपने निवास स्थानों तथा परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए। तब उन पर कोमला खान मजदूरों तथा कोयला खान क्षेत्र में रह रहे ग्रामवासियों की सुरक्षा निश्चित करने सम्बन्धी विश्वास कैसे किया जा सकता है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है रानीगंज कोयला क्षेत्र में ऐसी असंख्य खतरनाक दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि प्रबन्धक तथा खान सुरक्षा सम्बन्धी महानिदेशालय खान सुरक्षा प्रवर्तित करने वाले अधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं।

महोदय, मैं माननीय कोयला मंत्री का ध्यान आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आकर्षित करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में नालन्दा अन्तर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और पिछले 4 वर्ष पहले भारत सरकार ने वहां यह निर्णय लिया था कि यहां पर ओपन यूनिवर्सिटी खोली जाएगी लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार की ओर से जो फण्ड आबंटन किया जाना चाहिए था या जो कुछ भी मदद राज्य सरकार को दी जानी चाहिए थी उसका घोर अभाव है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सिलसिले में निर्देश दे और अविम्ब केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को मदद दे कर वहां यूनिवर्सिटी के काम को शुरू करायें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मैं उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कल सभा के नेता ने यह कर एक अत्यधिक गैर-जिम्मेदार ना वक्तव्य दिया है कि हमेशा की तरह राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी।

महोदय, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा लगभग पचास लाख व्यक्ति अभी भी असहाय अवस्था में हैं। चावल का मूल्य 10 रु० प्रति किलो पहुंच गया है तथा अव्यवस्था के कारण यह उपलब्ध भी नहीं हो रहा है। इस समय मेरी मांग है कि उड़ीसा सरकार द्वारा जैसी कि मांग की गई है उसके अनुरूप भारत सरकार को वहां पर चावल तथा आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में भेजी जानी चाहिए। मेरी यह भी मांग है कि प्रधानमंत्री को उन क्षेत्रों का तुरन्त ही दौरा करना चाहिए। महोदय, उड़ीसा के ग्यारह जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तथा अभी भी उन पर असर है। आज भी लगभग पचास लाख व्यक्ति असहाय हैं।

मैं उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं तथा यह भी मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त जाना चाहिए। कल श्री अर्जुन सिंह द्वारा दिया गया वक्तव्य वास्तव में संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमेशा की तरह सहायता दी जाएगी। यह कोई सामान्यतः आने वाली बाढ़ नहीं है। यह पूरी तरह से एक अलग प्रकार की बाढ़ है जिससे पर्यावरण नहर व्यवस्था, संचार व्यवस्था तथा लोगों के जीवन को भारी क्षति पहुंची है। अतएव मेरी मांग है कि भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए तथा राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए ताकि वह लोगों को बचाने तथा उन्हें राहत प्रदान करने की स्थिति में पहुंच सके।

मैं पुनः श्री अर्जुन सिंह से अपील करता हूं कि वह राज्य सरकार के इस अनुरोध पर ध्यान दें जिसमें उड़ीसा सरकार को पर्याप्त राहत सामग्री प्रदान करने के लिए कहा गया है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं आप से एक अनुरोध करना चाहता हूं। स्थिति अत्यधिक गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम संसद में एक बार उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति के बारे में देश को अपना वक्तव्य दें। देश के समाचार पत्र भी इस पर गौर

नहीं कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि मुझे सदन के नेता से ही अनुरोध करना चाहिए कि कम मे कम उन्हें ही उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठा रहा हूं। दो सप्ताह से बाढ़ तथा सूखे पर मेरा संकल्प प्रस्ताव सभा में लम्बित पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हम इस बारे में कितने गम्भीर हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, हमारे कक्ष में आप से जो बातचीत हुई है उसे यहां बताने के लिए मैं बाध्य हो जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : आपके साथ भी मेरी सहानुभूति है चूंकि आप भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन हम इह पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : बाढ़ की स्थिति पर क्या सरकार सभा में अपना वक्तव्य देगी ? यह मेरी मांग है। सभा के माननीय नेता को जवाब देना चाहिए। यह कोई छोटी बात नहीं है। **(व्यवधान)** लाखों लोग तबाह हो गए। **(व्यवधान)** सरकार उन्हें राहत देने में असमर्थ है। **(व्यवधान)** एक किलो चावल का मूल्य 12 रुपया है। यह अमानवीय है। बच्चे खुले आकाश के नीचे पैदा हो रहे हैं। सरकार को इस पर वक्तव्य देना ही चाहिए। अब सात-आठ दिन हो गए हैं। **(व्यवधान)** हमारी मांगे युक्तिसंगत हैं। हम चाहते है कि उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति पर सरकार का वक्तव्य दे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, अब वक्तव्य दें। आपको अपनी बातें थोड़े में ही कहनी है किसी बात को दुहराएं नहीं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा में आती ही रहती हैं। लेकिन इस तरह की बाढ़ से गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है और लोगों की दुखद स्थिति अकथ्य और अवर्णनीय है। आठवें वित्त आयोग के अनुसार यह प्रावधान है कि राज्य को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। **(व्यवधान)** मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा में बाढ़ से प्रभावित लोगों की रक्षा करे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हवाई सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए विशेषकर प्रभावित लोगों के बचाव के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके वक्तव्य का उत्तर देने के लिए वह खड़े हो गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इसे समझिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बोलने के लिए खड़े हैं और आप उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) **:** अध्यक्ष जी, मैंने भी इस बारे में एक नोटिस दिया है । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उनकी बात सुनें ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं समझता हूं कि कल ही इस मामले को उठाया गया था । ज्यों ही इस मामले को उठाया गया था, इसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया है । उन्होंने निदेश दिया है कि बाढ़ पीड़ित लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को हर प्रकार की सहायता मुहैय्या कराई जाए । अब, इसके बाद यदि इसमें कुछ और भी करने की आवश्यकता है तो मैं वह समझ सकता हूं । **(व्यवधान)**

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) **:** कोई भी केन्द्रीय मंत्री उड़ीसा के दौरे पर नहीं गया है । **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : यदि आप यह मानते है कि इसके लिए कुछ और भी करने की आवश्यकता है तो वह किया जा सकता है । हम आपसे कतराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । लेकिन ऐसा कहना कि हमने और प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, अनुसूचित है । उन्होंने इस पर ध्यान दिया है और संबंधित लोगों से कहा है कि वह उड़ीसा सरकार को सहायता उपलब्ध कराएं । यदि आप कुछ और भी चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं और हम सभी वह सब करने के लिए तैयार हैं । **(व्यवधान)**

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम उनके वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं । **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । क्या यह ठीक नहीं होगा कि उड़ीसा की स्थिति पर एक वक्तव्य देने को कहा जाए और यह बताया जाए कि केन्द्र सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध क्या किया है ? मैं समझता हूं कि यह उचित होगा ।

श्री अर्जुन सिंह : इस पर कोई आपत्ति नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है आप वक्तव्य से संतुष्ट न हो। यदि आप वास्तव में इस मुद्दे को गम्भीरता से ले रहे हैं तो आपके राज्य के सांसद संबंधित मंत्रियो से मिल सकते हैं, स्थिति पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं और तब इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है इसका निर्णय लिया जा सकेगा।

(व्यवधान)

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार और इस सदन का ध्यान बिहार डालमिया नगर उद्योग की ओर खींचना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा उद्योग था जिसकी 6 यूनिटस थीं लेकिन 1984 में मजदूरों और मालिकों के झगड़े में, हड़ताल हो जाने से यह उद्योग बन्द हो गया था। फिर 24.10.1989 को उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा, इस उद्योग को फिर से खोले जाने के लिए भारत सरकार को आदेश दिए गए और यह उद्योग चालू भी हो गया। न्यायालय के आदेशानुसार 6 जुलाई से इसमें मजदूरों की पुनः बहाल करना था। चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 15 करोड़ रुपए और बिहार सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए और उसके एम०डी०···*···को नियुक्त किया गया। इस उद्योग में कुल 15 हजार मजदूर लगे हुए थे। लेकिन इस उद्योग के एम०डी०···*···न्यायालय के आदेश को नजर अंदाज कर मनमाने ढंग से मजदूरों को बहाल करते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री राम प्रसाद सिंह : अभी तक इस उद्योग के जो यूनिटस चालू हुए हैं, वे हैं—एस्बैस्टोस, डालडा और सीमेंट। परन्तु जो सबसे बड़ा यूनिट इस उद्योग का है—पेपर फैक्टरी—वह अभी बन्द है। उसमें काफी रुपए की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करुंगा कि इस उद्योग की सहायता की जाए ताकि पेपर फैक्टरी चालू हो सके। इस उद्योग में जो 15 हजार मजदूर भूखों मर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत दी जाए। इसके साथ-साथ, मैं मांग करुंगा कि वहां के एम०डी० जो मनमाने ढंग से, गलत ढंग से रुपया व्यय कर रहे हैं, जो रुपया 15 करोड़ मजदूरों के लिए दिया गया था, उसमें से 10 करोड़ रुपए का रॉ-मैटीरियल खरीद लिया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। एसबैस्टोस यूनिट चालू तो हो गया है परन्तु उसके लिए सीमेंट नहीं हैं, वह भी बन्द प्रायः है। मैं चाहूंगा कि उद्योग के एम०डी० के कार्यों की जांच के लिए सदन की एक कमेटी बनाई जाये और उनके मनमाने ढंग से कार्य करने पर अंकुश लगाया जाये। साथ ही, पेपर फैक्टरी को तुरन्त चालू करवाये जाने की व्यवस्था की जाये।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, मैं सिक्किम की दुखद स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कई माननीय सदस्यों ने सूखा और बाढ़ की स्थिति पर सभा में विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन, मेरा यह मानना है कि देश में पर्वतीय श्रृंखलाएं भी हैं जहां भूस्खलन के कारण लोगों की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसे लोग महसूस

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं करते।

महोदय, हाल ही में सिक्किम में छः लोग मारे गए और कई स्थानों पर सड़क यातायात अस्तव्यस्त हो गया और संचार सम्बन्ध ठप्प पड़ गए। एक ही परिवार के चार व्यक्ति जीवित दफन हो गए और दो व्यक्ति नदी में वह गए। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करती हूं कि वह राज्य सरकार को इसके लिए सहायता दे और प्रभावित परिवारों को राहत दे साथ ही अस्तव्यस्त यातायात और संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित अथवा उसका पुनर्निर्माण करे।

[**हिन्दी**]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय हैजे का प्रकोप जबदस्त हो गया है और अकेले हमारे देवरिया जिले में इस अगस्त महीने में 200 के करीब लोग हैगे की इस गम्भीर बीमारी से काल-कवलित हो गए हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, डाक्टरों का अभाव है, दवाओं का अभाव है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे और अपनी मैडीकल टीम देवरिया पडरौना और गोरखपुर के इलाके में भेजे। देवरिया में इसके लिए विशेष व्यवस्था करे और जो हैजे के प्रकोप से मर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था केन्द्र सरकार की तरफ से हो।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली पुलिस द्वारा किए जा रहे गम्भीर अपराध की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, बहुत संक्षिप्त में बोलना है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, कल श्री जय राम को पुलिस ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया।

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी आपके बोलने का लहजा ऐसा है कि आप लगता है बात लम्बी करेंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुत संक्षिप्त में बात कहें।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। आप मुझे कहने तो दीजिए।

पुलिस ने पूछताछ के लिए पटेल नगर पुलिस स्टेशन पर जय राम को, उसकी बीवी को, उसकी 13 वर्ष की लड़की बसन्ती को, उसके 11 वर्ष के लड़के मनोज कुमार तथा उसके दूसरे लड़के दिलीप कुमार को बुलाया और पुलिस ने जय राम की पीट-पीट कर हत्या कर दी।

अध्यक्ष जी, मामला यह था कि एक वहां बारात आई। एक वहां पर उस ब्लॉक में एक आनन्द टैंट हाउस है, उसमें स्वर्णदीप कौर का एक पर्स गुम हो गया। मनोज कुमार शक में पटेल नगर थाने में बुलाया गया।

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, यह सारी की सारी बात कहने की जरूरत नहीं है, जो घटना हुई है, उस पर कोई कार्रवाई करने की बात कहें, तो ठीक रहेगा।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा हूं। शक में उनको बुलाया गया और जय राम को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बीवी को इतना मारा गया कि उसका सारा जिस्म अभी भी सूजा हुआ है। अध्यक्ष जी, ये सारी खबरें अखबारों में आई हैं, ये देखिए ये अखबारों में आई हैं।

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, अखबार दिखाने की जरूरत नहीं है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, यह इलाका मेरे क्षेत्र में है और थाने में वहां पर उनको शक में बुलाया गया, पीटा गया, उनकी हत्या की गई। सबको गम्भीर चोटें लगीं। जो 13 साल की लड़की बसन्ती थी, उसको भी मारा। जब मुझे समाचार मिला, मैं घटनास्थल पर पहुंचा, तो वे बिलख रहे थे।

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि पटेल नगर पुलिस स्टेशन में यह पहली घटना नहीं हुई हैं, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। दो-तीन साल में पुलिस अधिकारियों ने इसी तरह से पांच हत्याएं की हैं। इसी प्रकार की एक घटना अभी दो महीने पहले की है। प्रेम नगर के एक व्यक्ति को पटेल नगर पुलिस थाने में बुलाया गया, उसको भी इसी तरह से पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वहां के पुलिस अधिकारियों को, पुलिस प्रमुख को, एस०एच० ओ० को तुरन्त स्थानांतरित किया जाए। जय राम के परिवार को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए।

अध्यक्ष जी, चूंकि इसकी जांच विजिलैंस को सौंपी है और विजिलेंस भी स्वयं पुलिस विभाग ही है, इसलिए हमें शक है कि इस केस में न्याय नहीं मिलेगा। अत: मेरी मांग है कि इसकी जांच सी०बी०आई० से कराई जाए और अपराधी व्यक्तियों को तुरन्त सजा दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह इतना जो जघन्य अपराध हुआ है, यह जो इतनी निर्मम हत्या हुई है, यह जो संगीन अपराध दिल्ली में पुलिस कर रही है, इस सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय, सदन में अपना बयान दें और बताएं कि आखिर ऐसी घटनाएं जो होती हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है और इस घटना पर क्या एक्शन लिया गया है ?

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) **:** ऐसी घटनाएं पूरे देश में बार-बार घट रही हैं और इसके प्रति लोगों भाव शून्यता है। इसलिए मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं। यहां एक घटना है जो दिल्ली में ही घटी है। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लाया गया और उसे इतना पीटा गया कि वह मर गया। उसके अन्य संबंधियों को भी पीटा गया। इस मामले को परीक्षण के तौर ही लीजिए। यदि सरकार इस पर तुरन्त कार्रवाई करती है तो पूरे पुलिस प्रशासन पर अनुकूल प्रभाव होगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली है। मैं पूरा ब्यौरा एकत्र कर

रहा हूं। आज शाम तक इस घटना के सम्बन्ध में तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है उस पर इस सभा में वक्तव्य देने की आशा मैं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको कल तक का समय देते हैं। आप कल इस पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, जो गम्भीर स्थिति मेरे क्षेत्र में हो रही है उसकी ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मेरे इलाके का दौरा किया है, आपको मालूम है कि वहां न पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्री है न प्राइवेट सैक्टर की है, वहां पर सैल्फ इम्प्लायमेंट की स्कीम चालू है। श्री वाजपेयी जी ने भी वहां जाकर देखा है। वहां पर पुलिस फोर्स के लिए जो भर्ती की जाती है वह 45 प्रतिशत वहां के लोगों को दी जाती है। इस मामले में हम बहुत जमाने से आरग्यू करते आए हैं। श्री गुलाम नबी आजाद जब स्टेट मिनिस्टर थे तब होम मिनिस्ट्री की एडवाईजरी कमेटी में हम यह बात लाए थे। उनके प्रति यह डिसक्रिमिनेशन क्यों होना है। अभी जो रिक्रूटमैंट होने जा रहा है उससे यूथ काफी टैन्शन में हैं। होम मिनिस्टर को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए कि वहां के लोगों को ही फोर्स में लिया जाएगा बाहर के लोगों को नहीं लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : कल्याण मंत्रालय ने नशाबंदी पर एक अध्ययन शुरू किया है, भारत में इसके वैधानिक, प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक प्रभाव के पहलु। इस अध्ययन दल की अवधि नवम्बर 1985 से दिसम्बर 1989 तक चार वर्षों के लिए थी। महोदय, इस अध्ययन दल ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे बहुत ही चौंकाने वाली है। इन चार वर्षों के दौरान 736 मामलों में लिप्त 7,440 व्यक्तियों से 30,400 किलोग्राम नशीली वस्तुएं और अन्य ऐसी वस्तुएं पकड़ी गईं। पकड़ी गईं वस्तुओं में 52 किलोग्राम हेरोइन, 901 किलोग्राम अफीम, 10,467 किलोग्राम चरस, 2 126 किलोग्राम गांजा और 50 किलोग्राम कोकीन शामिल है। ये वस्तुएं तो जब्त की गई हैं लेकिन इसकी जितनी मात्रा बेची गई है और उपयोग में लाई गई है वह कहीं अधिक है। इसमें कहा गया है कि न पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा उससे कई गुणा अधिक होने की संभावना है और अवैध रूप से पहुंचने वाले नशीले पदार्थों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि नशीले पदार्थों के अभिशाप से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से देवरिया, जनपद में एक कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह पालियामेंट का दुरुपयोग हो रहा है, कब्रिस्तान के रास्ते का सवाल पालियामेंट में नहीं होना चाहिए।

श्री हरि केवल प्रसाद : 29 जुलाई को 29 घरों को लूटा गया, उनकी सारी फसलें लूट ली गईं, घरों से निकाल दिया गया और करीब 45 लोग हवालात में हैं। इसी सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उन 29 घरों को दो-दो किलो आटा जिला प्रशासन ने उपलब्ध करवाया है।···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, आजकल रैगिंग कालेज में आने वाले नए छात्रों को शारीरिक क्षति और मानसिक कष्ट पहुंचाने का एक माध्यम बन गया है।

महोदय, हाल ही में आई० आई० टी० खड़गपुर के प्रथम वर्ष के छात्र श्री सदीप सिंह राय को दूसरी मंजिल के संकरे मुंडेर पर चलने के लिए वरिष्ठ छात्रों द्वारा मजबूर किया गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वे वरिष्ठ छात्र रात में चले गए। सुबह में जब उक्त छात्र के सहपाठी आए तो उन्होंने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। इसके बाद भी कालेज के अधिकारियों ने उस छात्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि उन्होंने उस छात्र के प्रति कोई सहानुभूति भी व्यक्त नहीं की। इतना ही नहीं, छात्रों और शिक्षकों का एक वर्ग और संस्थान के निदेशक भी पुलिस छानबीन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

महोदय, मैं सरकार से और विशेष रूप से मानव संसाधन मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि इस सच्चाई को पता लगाने का कार्य शुरू करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनारावृत्ति न हो।

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : आई० आई० टी० खड़गपुर के अधिकारियों ने रैगिंग को रोकने के बजाय छात्रों को धमकी दी है वे संस्था को ही बन्द कर देंगे। वे रैगिंग को बढ़ावा दे रहे हैं जो शिक्षा-विरोधी कार्य है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में आवश्यक सावधानी बरतें।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपके आदेश से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला "वन रैंक वन पेंशन" की योजना को एक्स-सर्विसमैन पर लागू करने सम्बन्धी मामले को उठाने की अनुमति आपसे ले रहा हूं। इसमें तीन प्वाइंट हैं। मेरा पहला प्वाइंट यह है कि···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट आ रहा है, उसमें चर्चा कर सकते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पहला प्वाइंट यह है कि इस बारे में अनेक कमेटियां बनाई गई। एस्टिमेट कमेटी ने 1980-81 में अपनी 15वीं रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया था। फिर हाई लैवल कमेटी बनी थी। उस समय भी ये सब कहा गया। सबसे लेटेस्ट जो बात हुई

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

13 अक्टूबर, 1990 को, उसमें सिपाही से सूबेदार तक के रैंक में यानि कि नौसेना और वायुसेना के बराबर पेंशन में बढ़ोत्तरी की घोषणा की, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक सारे देश के एक्स-सर्विसमैन हजारों की संख्या में वोट-क्लब पर धरना देने के लिए आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में सभी दलों ने अपने मैनिफैस्टो में बहुत साफ कहा है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और 13 अक्टूबर, 1990 का जो आर्डर है, उसको लागू करवाने के लिए सरकार कुछ कार्रवाई करें। "वन रैंक वन पेंशन" की योजना को लागू करने के लिए सरकार कदम उठाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कालेज एक बहुत बड़ा कालेज है जो कि पूरे देश में एकमेव है। यहां पर तीन तरह के कोर्सिज कम्पलीट किए जाते हैं—एक तो सब-आफिसर्स का 25 हफ्तों का कोर्स है, दूसरा स्टेटशन आफिसर्स कोर्स है जो कि 25 हफ्तों का है और तीसरा डिविजनल आफिसर्स कोर्स 22 हफ्तों का है। इसमें सर्टिफिकेट/डिप्लोमा दिया जाता है। 1978 में यहां पर बी० ई० (फायर इंजीनियरिंग) का कोर्स शुरू हुआ था। इसका रिकॉग्निशन नागपुर यूनिवर्सिटी के जरिए किया गया था। नागपुर यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ करने के लिए कहा। 1989-90 में इस कालेज के लिए प्रॉपर कैम्पस बनाने के लिए योजना भी बनाई गई थी। इसके लिए जमीन भी खरीदी गई थी। इसके लिए बहुत सा पैसा यानी कि चार करोड़ रुपया दिया गया था लेकिन वह राशि इस्तेमाल नहीं की गई और न ही इसकी पूर्ति हुई। इस वजह से आज वह कालेज बन्द होने जा रहा है···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : यह सेंट्रल गवर्नमेंट का कालेज है ?

श्री तेजसिंह राव भोंसले : यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। यदि यह बंद हो गया तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला है। यहां पर फायर ब्रिगेड की बहुत सोफेस्टिकेटेड मशीनें लाई गई थीं। 5-6 करोड़ रुपये का सामान लाया गया था। ट्रक और एयर-कंडीशन एम्बुलेंस लाई गई ···(**व्यवधान**)···इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : कालेज बन्द नहीं होना चाहिए, इतना ही कहना है।

[अनुवाद]

प्रो० के० वेंकट गिरि गौड (बंगलोर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, लगभग दो दशक पहले, वर्ष 1971 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर्नाटक में दो उद्योगों की आधार-शिला रखी। इनमें एक विजयनगर का इस्पात संयंत्र और दूसरा मंगलौर में उर्वरक संयंत्र था। इन दोनों संयंत्र को न केवल केरल की अर्थव्यवस्था के लिए अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण कहा जा रहा था।

योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दोनों उद्योगों के लिए प्रावधान किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कर्नाटक

[प्रो॰ के॰ वेंकट गिरि गौड]

के लोगों ने और कर्नाटक की सरकार ने केन्द्र सरकार से इन दोनों उद्योगों के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी कारण कर्नाटक के लोग निराश हैं, और उनका भ्रम टूट गया है। अगर तुरन्त ही कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वे जल्द ही संघर्ष के रास्ते पर जा सकते हैं।

ये दोनों उद्योग कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत सहायक हैं, ये उद्योग कर्नाटक के उन लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे जो बेरोजगार हैं, ये दोनों उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे।

दूसरे विजयनगर में लोहा और इस्पात संयंत्र लौह-अयस्क और लोहे और इस्पात का निर्यात विदेशों को करेगा और विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा। इस प्रकार ये दोनों उद्योग न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी करेंगे। मंगलौर का उर्वरक संयंत्र उर्वरकों के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। अतः, इन दोनों उद्योगों को यदि तत्काल शुरू किया जाए तो देश आज जिस विदेशी मुद्रा संकट से गुजर रहा है, उसका ये संयुक्त रूप से सामना कर सकते हैं। क्या सरकार कर्नाटक के लोगों की सहायता हेतु तथा साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए इन दोनों उद्योगों को तत्काल शुरू करेगी।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, विगत 15 दिनों से देश भर में जितनी जीवन रक्षक औषधियां हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनका बिल्कुल अभाव हो गया है और उनका मिलना दुर्लभ हो गया है। दवा निर्माताओं के बीच में इस प्रकार की बातचीत चल रही है, उन्होंने धमकी दी है कि हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे, यदि दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सरकार इस बारे में मौन है। यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, यही मेरा कहना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में एक आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरी है जिसमें 30 आइटम्स रक्षा परिधान बनाए जाते हैं। इनमें से 18 आइटम्स सरकार द्वारा 1986 में प्राइवेट ट्रेडर्स को बनाने को दे दिए गए हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि 10 हजार मजदूर और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनका रिट्रेंचमैंट हो रहा है और रिक्त स्थानों को भरा नहीं जा रहा है। मैंने शासन से कई बार मांग की है कि जो 18 आइटम्स प्राइवेट ट्रेडर्स को बनाने को दे दिए गए हैं, जो सब स्टैण्डर्ड बनते हैं, उनको उसी फैक्टरी में बनवाया जाए, जबकि आलरेडी फैक्ट्री है, मशीनें हैं, जिससे कि वहां जितने भी कर्मचारी हैं, उनका भविष्य जो अन्धकारमय हो गया है, वह कुप्रभावित हो।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार

के नोटिस में एक बहुत ही भयानक घटना जो 14 अगस्त, 1991 को, हमारे स्वतन्त्रता दिवस मनाने के केवल एक दिन पहले घटी थी, लाना चाहता हूं।

नलगोण्डा जिले में चलाकुर्ती कस्बे में 48 वर्ष की एक महिला, श्रीमती मुत्तम्मा को निःवस्त्र किया गया। फिर उसे जबर्दस्ती मंडी ले जाया गया। वहां उसे खड़े होने के लिए कहा गया। बाद में, उसे उस गांव की गलियों में दिन में उच्च जाति के तीन व्यक्तियों द्वारा घूमने के लिए कहा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका विचार था कि उसका सम्बन्ध एक ऐसी घटना से था जिसमें एक पिछड़े वर्ग का लड़का और एक उच्च वर्ग की लड़की के मध्य आपस में प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया था। चूंकि उनके प्रेम-प्रकरण को उनके माता-पिता ने स्वीकार नहीं किया, अतः उन्होंने वह स्थान छोड़ने का फैसला किया।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार से संपर्क स्थापित करे ताकि दोषियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

मेरा सुझाव है कि सी० पी० सी० (भारतीय दण्ड संहिता) में आवश्यक संशोधन लाया जाए ताकि उन लोगों को कड़ी सजा दी जा सके जो महिलाओं की इज्जत से खेलते हैं।

1 40 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय (विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र) की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-एक)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी०—418/91]

(2) गृह मंत्रालय (विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र) की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-दो)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या —एल० टी-०419/91]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुनानों की विस्तृत मांगें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी०—420/91]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री अजित कुमार पांजा एक वक्तव्य देंगे।

1.41 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए।**]

1.42 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

आयातित अखबारी कागज का मूल्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : माननीय सदस्य जानते ही हैं कि आयातित अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि, माननीय सदस्यों के मन को और समाचारपत्र उद्योग को उद्वेलित करती रही है। समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने आयातित अखबार कागज की कीमतों में अचानक वृद्धि, विशेषतया राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) द्वारा उन पर करीब 60 करोड़ रुपये का भार डालने के प्रस्ताव का विरोध किया था। राज्य व्यापार निगम ने स्टेंडर्ड अखबारी कागज की कीमत में 4,670/—रुपए प्रति मीट्रिक टन और ग्लेज्ड अखबारी कागज की कीमत में 10,410/—रुपए प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि का प्रस्ताव किया था। राज्य व्यापार ने अखबारी कागज की कीमतों में इस वृद्धि का प्रस्ताव विनिमय दर समायोजन के प्रभावों, विशेषकर विगत में विदेशी मुद्रा की संचित देनदारियों पर पड़ने वाले प्रभावों के परिणामस्वरूप किया था। समाचारपत्र उद्योग इस भार को वहन करने के लिए तैयार नहीं था। इससे गतिरोध पैदा हो गया। जहां बड़े समाचारपत्रों का यह दावा था कि इस वृद्धि से समाचारपत्रों के मूल्य और विज्ञापन की दरें तेजी से बढ़ जाएंगी वहां कई छोटे और मझौले समाचारपत्रों ने बन्द हो जाने की आशंका व्यक्त की।

पिछले दो सप्ताह के दौरान सरकार, राज्य व्यापार निगम और समाचारपत्र उद्योग के बीच कई बार विचार-विमर्श किया गया। ऐसे विचार-विमर्श और चर्चाओं के कई दौरों के बाद दिनांक 16 अगस्त, 1991 को हुई अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति की बैठक में समस्या का समाधान हो गया। यह समाधान उद्योग और राज्य व्यापार निगम के बीच लागत भागीदारी के आधार पर आपसी सहमति से निकला। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने इस गतिरोध को दूर करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। इस सहमति के अनुसार अब आयातित स्टेंडर्ड अखबारी कागज की कीमत 16,000/—रुपए प्रति मीट्रिक टन और ग्लेज्ड अखबारी कागज की कीमत 23,300/—रुपए प्रति मीट्रिक टन ही रहेगी। समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को स्टेंडर्ड अखबारी कागज पर 800/—रुपए प्रति मीट्रिक टन और ग्लेज्ड अखबारी कागज पर 2,300/—रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त अधिभार देना होगा।

यह उपकर कुल मिलाकर 2,50,000 मीट्रिक टन स्टेंडर्ड अखबारी कागज और 40,000 मीट्रिक टन ग्लेज्ड अखबारी कागज पर वसूल किया जाएगा।

सरकार प्रेस के स्वस्थ विकास के लिए वचनबद्ध है। इसी वचनबद्धता के कारण ही

अखबारी कागज को अत्यावश्यक वस्तु माना गया है और देशी उत्पादन और आवश्यकता के बीच अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। यद्यपि देशी उत्पादन का स्तर लगभग 2.8 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष पर ही टिका रहा है, तथापि अखबारी कागज की मांग बराबर बढ़ती जा रहा है। देश अब अखबारी कागज की कुल आवश्यकता का 40 से 45 प्रतिशत तक आयात कर रहा है। जहां एक ओर, देश में अखबारी कागज के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करने होंगे, वहां दूसरी ओर, अखबारी कागज के सभी उपभोक्ताओं को इस दुर्लभ वस्तु का संरक्षण करने के लिए हरसम्भव उपाय करने होंगे और इसका इष्टतम उपयोग करने का प्रयास होगा। सरकार को कुछ समाचारपत्रों से, विशेषतया, बड़े समाचारपत्रों से अखबारी कागज के आयात का विसरणीकरण (डिकैनेलाइजेशन) करने के बारे में मांग प्राप्त हुई है। यद्यपि सरकार विकरणीकरण के मार्ग में बाधा उपस्थित नहीं करना चाहती, तथापि इस मांग पर विचार करते समय हमें सबसे अधिक चिन्ता अनिवार्यता छोटे और मझौले समाचारपत्रों की होगी। जो अलग-अलग तौर पर अखबारी कागज का आयात करने का इन्तजाम नहीं कर सकते।

सरकार ने सरकारी विज्ञापनों के नये दर ढांचे की सिफारिश करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया है। अखबारी कागज की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अंतिम उपाय के रूप में सरकारी विज्ञापनों की दरों में 18 प्रतिशत ही वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अगस्त, 1991 से लागू होगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 421/91]

1.44 म० प०

सभापति तालिका के सदस्य के नाम-निर्देशन के बारे में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे सभा को सूचना देनी है कि लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने श्री राम नाईक को सभापति तालिका का सदस्य मनोनीत किया है।

अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

1.45 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की और इस क्षेत्र में खनिजो का पता लगाने के लिए धन राशि निर्धारित करने की आवश्यकता

राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : सम्पूर्ण देश का समग्र विकास करने और पिछड़े तथा

[राव राम सिंह]

अविकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की सरकार की नीति रही है। इसी नीति के अनुसरण में नो इंडस्ट्री डिडिस्ट्रक्ट योजना बनाई गई थी। इस योजना के अधीन बहुत सी सुविधाओं छूट और रियायतों की घोषणा की गई थी।

हरियाणा का महेन्द्रगढ़ जिला खनिजों के मामले में समृद्ध है। राजस्थान के पड़ोसी जिलों में खेतड़ी तांबा परियोजना इसका बहुत स्पष्ट प्रमाण है। परन्तु इस जिले में एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से अब तक यह क्षेत्र पिछड़ा और अविकसित है।

मेरा यह अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस जिले में खनिजों का पता लगाने के लिए सुविधाएं प्रदान करे और राशि निर्धारित करे तथा केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में, जोकि जौ, सरसों और गुआर के उत्पादन में समृद्ध है, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना पर भी विचार करे।

(दो) बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रयोग की जाने वाली मुद्रण स्याही का उचित रिकार्ड रखने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैंक नोट प्रेस देवास (म०प्र०) में नोटों की छपाई में प्रयुक्त होने वाली स्याही के स्टाक का आज तक सत्यापन नहीं होने पर इससे सुरक्षा की दृष्टि से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के सत्यापन अधिकारियों के एक दल ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि लाखों रुपए की स्याही बाजार में बिक गई है। यह स्याही विदेश से मंगाई जाती है एवं देवास बैंक नोट प्रेस में भी बनायी जाती है।

बैंक नोट प्रेस (देवास) में इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि छपाई में कितनी स्याही खर्च हुई तथा स्टाक में कितनी है। यह रिकार्ड रखना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त जरूरी है। बैंक नोट प्रेस देवास में अनेकों अनियमिताएं होती रहती हैं तथा छपे हुए नोट गायब होना मामूली बात है। अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि स्याही प्रकरण की तुरन्त जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(तीन) पूर्वी उत्तर-प्रदेश के 18 जिलों को मिलाकर पूर्वांचल प्रदेश बनाने की आवश्यकता।

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है, प्राकृतिक संपदा से भरपूर है और पर्याप्त श्रम भी है। फिर भी औद्योगिकीकरण आवागमन तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास की अपर्याप्त योजनाओं के अभाव के कारण यह क्षेत्र काफी पिछड़ गया है आज स्थिति यह है कि ग्रामीण युवकों को तेजी से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है जिससे कृषि कार्य भी

प्रभावित हो गया है। मैं माननीय सदन के समक्ष इस विषय को प्रस्तुत करते हुए यह मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को मिलाकर एक अलग पूर्वांचल प्रदेश बनाया जाए ताकि इसका त्वरित विकास हो सके।

(चार) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उड़ीसा में भुवनेश्वर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार आदि की अपनी योजना पर कार्य शुरू करने के निदेश देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में पर्यटन विकास की दृष्टि से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भुवनेश्वर हवाई अड्डे के वास्ते हवाई पट्टी के विस्तार नये टर्मिनल भवन के निर्माण आदि के लिए एक मास्टर योजना तैयार की गई थी। भूमि के अधिग्रहण हेतु भी उड़ीसा सरकार से भी परामर्श कर निर्णय लिया गया था और तदनुरूप इस उद्देश्य हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। वस्तुतः 62 लाख रुपए की कुल अधिग्रहण लागत में से 25 लाख रुपयों का भुगतान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है।

लेकिन हवाई अड्डे का विस्तार करने के प्रति अपनी बचनबद्धता से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्वयं हट गया और उनके द्वारा राज्य सरकार से अधिग्रहण हेतु दी गई धनराशि को वापस करने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इस निर्णय से राज्य सरकार के एक उलझनपूर्ण स्थिति में पड़ जाने के अतिरिक्त, पर्यटन के विकास की प्रक्रिया भी पीछे पड़ जाएंगी।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि पूर्व निर्णय के अनुसार भुवनेश्वर हवाई अड्डे के विकास के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर दबाव डाले।

(पांच) मेघालय के जैंतिया हिल्स जिले के गांवों में सुपारी के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली रहस्यमयी बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए तुरन्त उपचारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : दावकी, मुक्तापुर, सोबखा, नौंगतालांग, लामिन और मेघालय के जैंनतिया पर्वतीय जिले के (बंग्लादेश की सीमा पर) अन्य अनेक गांवों के किसानों को अपनी जीविका हेतु अराकोनेट्स (क्वाई) के उत्पादों पर निर्भर रहना पड़ता है। हाल के महीनों में, इन वृक्षों में एक विचित्र बिमारी लग गई है और इसके कारण हजारों अराकोनट्स के वृक्ष बरबाद हो गए है। उस क्षेत्र के नेताओं ने भूतपूर्व कृषि मंत्री को मार्च, 1991 में शिलोग के उनके दौरे के दौरान उस विचित्र बिमारी और उसके प्रभावों की जानकारी दी थी। फिर भी, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं सरकार से शीघ्र ही सुधारात्म उपाय करने और इस क्षेत्र के प्रभावित किसानों को सहायता पहुंचाने का अनुरोध करता हूं।

(छः) ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्य का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत करवाया जाता है। इसके वर्तमान निर्देशों के अनुसार ग्राम में यदि एक भी विद्युत कनेक्शन है, चाहे वह निजी नलकूप का हो या राजीय नलकूप का या अन्य प्रकार का हो, उक्त विद्युत कनेक्शन पूर्व में ही कट चुका हो या ग्राम के मध्य विद्युत लाइन गुजरती हो तो उक्त ग्राम को विद्युतीकृत माना जाएगा। इस कारण से देश के विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या कागजों में नम्बरों के हिसाब से तो बढ़ रही है, परन्तु वास्तविक विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है और ग्रामीण जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम की समीक्षा करे और ऐसे निर्देश दे जिससे ग्रामों का वास्तविक विद्युतीकरण किया जा सके और उसमें यह भी निर्देश दिया जाए कि ग्राम की 80 प्रतिशत जनसंख्या विद्युतीकरण में आए, जिसमें अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के क्षेत्र अनिवार्य रूप से सम्मिलित किए जाएं।

(सात) केरल के कोट्टायम जिले में इरात्तुपेट्टा टेलीफोन केन्द्र में उपभोक्ता ट्रंक डाईलिंग सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मार्च 1991 से पहले केरल के कोट्टयम जिले में इरातुपेट्टा टेलीफोन केन्द्र में एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान की जानी थी। सभी तकनीकी कार्य किए जा चुके थे और एस० टी० डी० कोड नम्बर भी दिया जा चुका था और यह टेलीफोन निदेशिका में प्रकाशित भी हो चुका था। ऐसा सुनने में आया है कि यद्यपि एस० टी० डी० उपलब्ध नहीं है फिर भी दूरसंचार उपभोक्ताओं को आवंटित कोड नम्बर के नाम पर गलत बिल जारी किए गए हैं। इस टेलीफोन केन्द्र में एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी किए गए वायदे का क्या हुआ, यह अभी तक मालूम नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि इरातुपेट्टा में एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।

(आठ) नागपुर में नरखेड़ा रेलवे स्टेशन के कामगारों को वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस

महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

नागपुर जिले के नरखेड़ स्टेशन में कार्यरत निर्माण विभाग के रेल श्रमिकों को दिनांक 31.5.91 से वेतन नहीं दिए जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, जिस कारण श्रमिकों में भारी असंतोष है। यदि शीघ्र ही रेल मंत्रालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया तो स्थिति काफी विस्फोटक हो जाएगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए रेल मंत्रालय अविलंब कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ अनुमोदित विषय-वाक्य ही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किए जाएंगे

1.55 **म० प०**

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1991-92
उद्योग मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 51 से 54 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए आठ घंटे का समय नियत किया गया है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण जिनके अनुदानों की मांग सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके है, यदि वे चाहें तो अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। वे जिन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें क्रमानुसार एक पर्ची पर लिखकर 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर दें। केवल ऐसे ही कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत माना जाएगा।

प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए एक सूची शीघ्र ही सूचना पट पर लगा दी जाएगी। उस सूची में यदि कोई सदस्य किसी प्रकार की विसंगती पाते है तो अविलम्ब इसे सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 से 54 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
उद्योग मंत्रालय					
51.	औद्योगिक विकास विभाग	73,47,00,000	6,00,000	73,48,00,000	6,00,000
52.	भारी उद्योग विभाग	15,05,00,000	137,72,00,000	15,05,00,000	137,72,00,000
53.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	71,00,000	...	70,00,000	...
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	157,74,00,000	141,43,00,000	157,74,00,000	141,43,00,000

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं उद्योग मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू कर रहा हूं, इनीशियेट करने में मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं। आपके माध्यम से मैं मंत्रालय से अपेक्षा करूंगा कि जो अच्छी-अच्छी बातें इस अनुदान की मांगों

की चर्चा में आएं इसका ध्यान से अभ्यास करें और आपका उद्योग मंत्रालय इसके पीछे लगे कि कितने सजेशन्ज उपयोगी हैं। इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी उद्योग नीति या आपका पूरा इकोनॉमिक सैट-अप इसमें और सजेशन्ज मांग रहा है। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद कोई भी ऐसा वित मंत्री इनको नहीं मिला, जो दो साल के बाद में तीसरा बजट पेश करने में अपने आपको भाग्यशाली समझे। जितने भी वित्त मंत्री आए एक साल, दो साल में, दो बजट के बाद तीसरा बजट रखने में कभी उनका कांटीन्यूअस प्रौसैस नहीं रहा। देश की इकोनॉमी चाहे कोई भी पार्टी चलाए, इसका लक्षांत होता है, इसका मतलब होता है और वह देश का विकास होता है। सामान्य आदमी इससे सुखी हो, देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो और दुनिया भर में इसका नाम हो कि हिन्दुस्तान कोई ऐसा देश है जिसमें उद्योग के आधार पर जो लोग हैं, वे सुखी हैं।

लेकिन वित्त मंत्री के हिसाब से जो कान्टीन्यूटी होनी चाहिए देश में, दो बजट के बाद, कोई भी वित्त मंत्री हो, तीसरा बजट रखने में कभी कामयाब नहीं हुआ। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करूंगा कि अगर सरकार माइन्योरिटी में है फिर भी सही ढंग से चले तो वित्त मंत्री से और भी तीन, चार, पांच बजट जो टर्म आपको लोगों ने दी है, उसमें रखवाने में आपको पार्टी भी सहयोग दें।

40 साल के बाद आप देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इतने साल में आपका जो ध्येय था, उस ध्येय को, उस लक्षांक को पाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई जिस नीति से 40 साल के बाद देश की इकोनॉमी, आर्थिक हालत तबाह हो गई। इतने साल बाद आप करवट बदल रहे हैं। अभी पब्लिक में कह रहे हैं कि इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए। 40 साल तक इस देश में इकोनॉमी रखने वाले आप थे या आपके सहयोगी थे। इस देश में कोई कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसकी विचारधारा अलग हो। कांग्रेस या कांग्रेसी कल्चर के लोग ही देश में शासन करते रहे, 1977 से 1979 तक ढाई सालों को छोड़कर, इतने साल तक आपने ही देश में राज्य किया है। आपने ही देश की आर्थिक नीति को गड़गड़ किया है। आपने आर्थिक नीति ऐसी कैसी बनाई जिससे आज देश की हालत तबाह हो गई। आज आपको एक साथ दुनिया भर की इण्डस्ट्रियल पॉलिसी रखनी पड़ी, रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा, व्यापार नीति और नयी करनी पड़ी। अच्छे अर्थशास्त्री को कंसल्ट करके अगर आप देश को चलाते तो अच्छा होता। आपने क्या चलाया? आपने अपनी पार्टी की पॉलिसी इम्पलीमेंट करने के लिए देश की हालत खराब कर दी, आपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, कौन से वर्ग का हम ज्यादा अच्छा करें चाहे देश भाड़ में जाए और नीति भाड़ में जाए, वोट मिलने चाहिएं, वोटों पर आधारित आर्थिक नीति आपने इम्पलीमेंट की। आपकी पार्टी की गलत नीति रही।

आपकी पार्टी की वोट ओरियेन्टेड इकोनोमिक पालिसी देश को तबाह के रास्ते पर ले गई और चालीस साल में आज दुनिया भर में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान को नीचा देखना पड़ता है। आज हम जिसको भीख मांगने का शकोरा बोलते हैं, वह लेकर आप जानते हैं तो कोई आपको रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। आइ०एम०एफ० भी लोन देता है तो कंडीशन रखता है। यह कि

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

हिन्दुस्तान जहां भी लोन मांगे तो दूसरे लोग लोन देते थे। उस समय दुनिया भर के अर्थशास्त्री कहते थे कि हिन्दुस्तान को विचार करना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। उस लोन में हम आर्थिक आजादी भी गंवाते हैं। आज दुनिया में अपना नम्बर देखिए। विकसित देशों में पीछे से तीसरा-चौथा नम्बर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस देश को तबाह करने वाला कौन है। आपने जो यह किया वह एक अपराध है, देश के साथ धोखाधड़ी है और हिप्पोक्रेसी है। देश को इस रास्ते पर ले गए और बड़ी-बड़ी बातें की। जो देखना चाहिए वह नहीं देखा। लेकिन, वोट बैंक और गलत पार्टी पॉलिसी को इम्पलोमेंट करते हुए, देश को यहां ले आए हैं। आज डा० सिंह यहां पर नहीं हैं लेकिन श्री कुरियन बैठे हुए हैं। डा० मनमोहन सिंह ऐसा समझ रहे हैं कि मैं देश को कहीं और ले जा रहा हूं, इकोनोमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रीयल पालिसी या बजट का सहारा लेकर देश की आर्थिक धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डा० सिंह इतने साल कहां थे। क्या आप बीस साल तक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे, रिजर्व बैंक और इन्दिरा जी के साथ नहीं थे। डा० सिंह को कभी ऐसा नहीं लगा कि "हेयर नो फरदर" मैं एक भी गलत बात मानने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और भारत सरकार की नौकरी जरूर करता हूं। अगर गलत नीति आप अमल में रखने के लिए जा रहे हैं तो "आइ एम सारी," मैं आपको सहयोग नहीं दूंगा, "हेयर इज माई रेजिग्नेशन"। आप कह रहे हैं कि देश तबाही पर पहुंच गया है। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि देश की नीति चेंज करनी है। तो चालीस साल तक चेंज क्यों नहीं की। आप नेहरू जी का नाम ले रहे हैं। इस विचार पर मैं बाद में आऊंगा। वित मंत्री जी मसीहा बनने निकले हैं। मेहरबानी करके मसीहा बनने की कोशिश न करें। सौ करोड़ रुपया राजीव गांधी फाइन्डेशन और फर्टिलाइजर सब्सिडी को विदड्रा करने के लिए दबाव डाला तो आपको मानना पड़ा। इस हालत में दूसरा बजट पेश करने में आप कामयाब होंगे या नहीं, मुझे शंका है। आप मसीहा न बने। आप इकोनोमिस्ट हैं और आपकी पार्टी सरकार में हैं तो पार्टी की पालिस के हिसाब से बजट रखिए और इंडस्ट्रीयल पालिस भी रखें। विपक्ष और देश में भी अच्छे-अच्छे अर्थशास्त्री हैं। उनसे कंसलटेशन होता तो अच्छा रहता। यह बड़े दुख की बात है कि आप आर्थिक मामलों में कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। आपको कंसल्ट करना चाहिए। सब आपको सहयोग देंगे जिसको आप माने या न माने। आज एक आपने जो इम्पलीमेंटेशन किया, उसका क्या परिणाम हुआ। आज दुनियाभर में आर्थिक और राजकीय रेप्युटेशन हिन्दुस्तान की गिर गई है और प्रतिष्ठा पर धब्बा लग गया है और आइ०एम०एफ० के सामने घुटने टेकने पड़े और कहना पड़ा कि जो भी आपकी कंडीशन है, वह हम मान लेंगे। आइ०एम०एफ० क्या कंडीशन लगा रहा है और क्या बातें हो रही हैं, उसको सदन में रखें। यह देश की जनता को जानने का अधिकार है। कोई एक सरकार का अधिकार नहीं है। आइ०एम०एफ० की कंडीशन होती है कि वह हिन्दुस्तान के कामन सिटीजन से कन्सर्न करता है। जब आदमी बाहर जाता है तो लोग कहते हैं कि यह भारतीय है और आइ०एम०एफ० के आगे घुटने वाले देश का नागरिक है।

आप कैसे घुटने टेक रहे हैं, उसने कौन-सी शर्ते लगाई हैं, इनके बारे में आप श्वेत पत्र

निकालें। यह भी बतायें कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में पहले बच्चा जन्म लेता था तो वह अपने पिता का कर्ज लेकर पैदा होता था, लेकिन आज वह भारत सरकार का कर्ज लेकर जन्मता है। जबकि इसका अधिकार आपको नहीं है। मेहरबानी करके जितने भी इससे निकलने के उपाय हैं आप सबसे बातचीत करके इस समस्या का समाधान करें, सब आपको इसमें सहयोग देगे।

40 साल तक आप नेहरू जी का नाम लेते रहे। नेहरू जी की सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की जो बात थी उसके दिमाग से तब युगोस्लाविया, रूस और चीन जैसे साम्यवादी देशों का असर था। नेहरू जी ने कभी कृषि नहीं देखी, गांव नहीं देखे उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी। वे ऐसे परिवार से आये थे जहां यह सब कुछ नहीं था और महात्मा गांधी ने उन्हें स्वतन्त्रता संग्राम के बाद उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें प्रधान मंत्री बनवाया। सरकार और नेहरू जी के बीच वे नेहरू जी को पसन्द करते थे। प्रधान मंत्री बनने के बाद नेहरू जी देश को ऐसी जगह ले जाना चाहते थे कि ख्वाब में अच्छी बातें थी जो वे कहते थे, लेकिन यथार्थ में वे सही नहीं उतरती थीं। वास्तविकता तो यह थी कि जितने हमारे देशवासी थे उनको आगे ले जाने वाली नीतियों की तब आवश्यकता थी। हमारा देश गांवों में बसता है, वह कृषि पर आधारित है, खेती पर जीता है। अगर नेहरू जी ने कृषि पर आधारित औद्योगिक नीति बनाई होती और कृषि को ज्यादा प्राथमिकता दी होती और बड़े-बड़े उद्योगों के चक्कर में न फंसते तो आज देश की हालत यह न होती। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, आज उनका जन्मदिन है, ये भी उसी पुराना नीति पर चलते रहे जो कि ख्वाबों में तो अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है। अगर आपने नेहरू परिवार को यश देना है तो वह दे दें, लेकिन देश की वर्तमात हालत की जिम्मेदारी, अपयश भी इन्हीं पर है। हमारे प्रधानमंत्री भी यही बात करते हैं।

अगर इन्होंने नेहरूजी की समाजवाद वाली बात मानी होती तो आज ऐसी बात न कहते : यह नेहरू जी बात को लेकर कह रहे हैं कि नई औद्योगिक नीति वास्तव में पण्डित नेहरू के विलक्षण औद्योगिक जीवन दर्शन का समयानुकूल विस्तार है। यह नीति समयानुकूल सन्दर्भ में पुनर्रचना के प्रयासों की कड़ी है जिसके आधार पर देश के आर्थिक आधार का नया अध्याय शुरू हो रहा है, यानी आप उनकी पहले की बातों को समाप्त कर रहे हैं और पुराने अध्याय को समाप्त कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकती हूं कि वह किसे सम्बोधित कर रहे हैं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस माननीय सभा को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह आपको सम्बोधित कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूं। लेकिन और किसे सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री ..कर सिंह वाघेला : इस मामले में सरकार उचित रूप से ध्यान नहीं दे रही है। (व्यवधान)

उपा.. क्ष महोदय : मैं जानता हूं कि गीता जी के मन में कुछ विचार उठ रहे हैं।

श्री .. य प्रताप सिंह (मैनपुरी) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपको अथवा सत्ता पक्ष के खाली पड़े स्थानों को सम्बोधित कर रहे हैं।

अपा.. क्ष महोदय : वे अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शं..र सिंह वाघेला : महोदय, उद्योग नीति और अब उद्योग मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। यदि वित्त और उद्योग मंत्री यहां उपस्थित होते ो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

जिसके साथ ही देश के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है, देश की समग्र औद्योगिक रूपांतरण की इस महती प्रक्रिया के तहत औद्योगिक क्षेत्र को उन्मुक्त, उदार और प्रतियोगी बना दिया है। नेहरू जी उन्मुक्त नीति को नहीं मानते थे। वे उदार और प्रतियोगी नीति को नहीं मानते थे। वे समाजवाद को मानते थे। मगर समाजवाद की 1956 में जो औद्योगिक नीति रही उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के हिसाब से जो नीति बनाई। उस नीति ने देश को चौपट किया। क्या हुआ? उस नीति के हिसाब से अगर समाजवादी की जगह गांधी जी की बातों पर नेहरू जी जाते या देश जाता। गांधी जी को वोट बटोरने हैं तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी। देश को ठीक करने मे गांधी जी की बातें आपने इम्प्लीमेंट की होती। इनकी जो दो-चार बातें थीं। आत्म-निर्भरता यानि देश को सम्मान के हिसाब से जीना चाहिए, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, कैसा भी देश हो, आधुनिकीकरण होना चाहिए। आपने आधुनिकीकरण किया लेकिन कम्प्युट्राईज किया। बाकी जिसमें करना चाहिए, उसमें आपने नहीं किया। विकेन्द्रीकरण की जहां तक बात है, आप दुनियाभर का विकेन्द्रीकरण ले करके बैठे हैं इसका ही रिजल्ट है।

[अनुवाद]

राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

विकेन्द्रीकरण आर्थिक नीति में या उद्योग में पार्टी नहीं करती या बाकी के बीच में इसका इम्प्लीमेंट करती तो विकेन्द्रीकरण सामान्य आदमी को आशीर्वाद रूप मिलता। आपका कोई भी काम हो आओ दिल्ली, आओ दिल्ली, चलो उद्योग भवन। उद्योग भवन में क्या होता है। लाइसेंस, कोटा, परमिट। क्या प्रो० कुरियन आप जानते हैं कि लाइसेंस, कोटा, परमिट सब में रुपए लेते हैं। उद्योग भवन में जो दो नम्बर के लोग जाते हैं कि लाइसेंस, परमिट में रुपए लीजिए और कोटा दिलाइए। ब्यूरोक्रेसी का ऐसा कंट्रोल है कि आपकी डी-सैंट्रलाईज की पालिसी कभी अगर कार्यान्वित

की होती तो भी ब्यूरोक्रेसी इसे सेंट्रलाईज कर देते। करप्शन इतनी भारी है यहां पर तो जूं तक नही रेंगती है। यदि गांधी जी की विकेन्द्रीकरण की बात को भी मानते तो देश का कुछ उद्धार होता। गांधी जी दरिद्र नाराण की सेवा की भी बात करते थे। आप बात करते हैं गरीबों की लेकिन गरीबी रखना चाहते हैं। अगर गरीबी हट गई तो चुनाव में गरीबी हटाओ की बात आप कहां से करते ? इसलिए गरीब आपके लिए आशीर्वाद है और देश अनपढ़ रहे, गरीब रहे। आपके चुनाव में गरीबी हटाओ की बात आपका भला करने वाला मसीहा है। इस हिसाब से चुनाव में वोट बटोरने के लिए गरीबी से ही आपको ज्यादा फायदा है। गरीबी में दरिद्र नारायण की सही सेवा उसको कंसेशन देने से नहीं, वह खुद आत्मनिर्भर हो, खुद अपने पैरों पर खड़ा रहे, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। वाकई जो दरिद्र नारायण की सेवा हो, वह सही होनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर सर, आप और हम 21वीं सदी में जा रहे हैं हर पार्टी में गरीबों के बारे में कंपीटीशन कर रही है, देश में सबने गरीबों की बात करने में गौरव समझा। कभी वहां से निकल कर सामान्य मानव को सुखी करने की बात की होती तो अच्छा होता। आप इंडस्ट्री में भी स्पून फीडिंग के हिमायती नहीं हैं। यह बात इंडस्ट्री में निकल जाना चाहिए, इन्सान को क्यों रखते ? अब आप 40 साल के बाद भी गरीब को स्पून फीडिंग पर जिन्दा रखेंगे ? उसको आपने कोई धन्धा नहीं दिया है। कितनी बेकारी बढ़ी है, कितने गरीब बढ़े हैं ? गरीबी की बात करने वाले चालीस वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग उठाये हैं ? आज 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, किसने बढ़ाये हैं ? गरीबी की रेखा से नीचे इतने लोग हो गये है कि उनको खाना नहीं मिलता हैं और हम कहते हैं कि मण्डल कमीशन या वह कमीशन बनाइये। गरीब दरिद्र की सेवा कब होगी ? कंपीटीशन गरीबी बढ़ाने का नहीं, उसे मिटाने का हो। जिस तरह इंडस्ट्री को स्पून फीडिंग में नहीं रखते हैं, उस हिसाब से इनसान को भी स्पून फीडिंग में मत रखिए। कुछ समय आने के बाद धक्का मार के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ऊपर धकेलिए। आप गरीबी रेखा से नीचे बचाने में गौरव मत अनुभव करें। आप कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे से निकालकर ऊपर धकेले, इस दिशा में विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि देश के सामान्य आदमी को फायदा होगा।

डिप्टी स्पीकर सर, इस समय जो सरकार बार-बार नेहरू जी की बात करती है। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा था कि नेहरू जी समाजवाद पर चलते थे। वजह एक है— नेहरू जी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नेहरू जी का समाजवाद। समाजवाद आज दुनिया भर में मर रहा है। थोड़ा-सा बचा था रशिया में और वह भी कल गोर्बाचेफ की क्या हालत कर दी, वह देख रहे हैं। समाजवाद क्या चीज है ? साम्यवाद, समाजवाद जिस रास्ते पर चलने के लिए इतने साल लगे उसमें से क्या बाहर निकल रहा है। चाइना की हालत देखिए, रशिया की हालत देखिए पूर्व योरोप की हालत देखिए। जब दुनिया समाजवाद को छोड़ रही है तो आप नेहरू जी और समाजवाद की बात हिम्मत से छोड़ने की करिए। नेहरू जी स्वर्गवासी हो गए।

[अनुवाद]

समाजवाद समाप्त हो गया। नेहरू जी अमर रहें। समाजवाद बरकरार रहे। ये तीनों अमर रहें।

[हिन्दी]

तो आप सिर्फ नेहरू जी को खुश रखने के लिए या नेहरू जी के परिवार को खुश रखने के लिए नेहरू जी की नीति और समाजवाद की नीति, जिसको दुनिया छोड़ रही है, आप उसको ऐसे कपड़े पहनाने की कोशिश मत करिए। इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। आज भी आप बैंकों की हालत देखिए, कर्मचारी क्या कर रहे हैं? आप इसमें सुधार कर रहे हैं तो जल्दी करिए, हिम्मत से करिए। राजीव जी ने भी कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने की बात कही। आपने वह बात छोड़ दी। ठीक है, जो निर्यात की चीजें हैं उनमें फर्क आता है। लेकिन जो नेहरू जी की, इंदिरा जी और राजीव जी की पॉलिसी थी, उसको अपने छोड़ दिया है। गोर्बाचोव ने कहा कि मैं छोड़ रहा हूं। चीन के लोग कह रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं, वह हिम्मत से कह रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अच्छी बात है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात में विश्वास करते हैं कि भारत में जो भी हो रहा था वह सब समाजवाद था अथवा नहीं।

[हिन्दी]

लेकिन आप शरमाइए मत। हिम्मत से कहिए कि हमने समाजवाद को छोड़ दिया है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सब समाजवाद था।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अगर 40 साल की उम्र वाले एक व्यक्ति की मूंछें भी नहीं उगी हैं, पांच फीट हाइट भी नहीं है तो आप उसको पूरा आदमी नहीं कहेंगे। जिस सही रास्ते पर आज हिन्दुस्तान ने चलना शुरू किया है अगर 40 साल पहले शुरू किया होता तो आज हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत होता।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : इन्हें समाजवाद विरोधी समझा जाता है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं समझता हूं कि कभी भी कुछ होना है तो वह चलता रहेगा लेकिन हमें तो जिन्दा रहना है। (**व्यवधान**) जो प्रोग्राम हैं वह बने, इतना रुपया खर्च करने के बाद इतना भी ठीक नहीं बना। मैं कहता हूं कि आज तो मामला खत्म कर दिया गया है। देश की आबरू देखिए दुनिया में क्या है? कहां जा रहे हैं हम? अगर हम सही रास्ते पर होते तो क्या यह स्थिति हिन्दुस्तान की होती? गांधी जी ने दरिद्रनारायण की सेवा चाही थी, उन्होंने कृषि पर आधारित उद्योगों की बात कही थी और बेरोजगारी उन्मूलन की बात भी उसमें आती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके ध्यान में सिर्फ यह बात लाना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा हेतु आठ घंटे का समय दिया गया है। कांग्रेस को 3 घंटा 15 मिनट, भाजपा को 1 घंटा 40 मिनट, जनता दल को 49 मिनट, सी० पी० आई० (एम०) को 30 मिनट, सी० पी० आई० को 11 मिनट, तेलगु देशम पार्टी को 11 मिनट, ए० आई० ए० डी० एम० के० को 10 मिनट, जे० एम० एम० को 5 मिनट, जनता पार्टी को 4 मिनट, निर्दलीय सदस्यों को 12 मिनट। हमें इन समयों के अनुसार ही अपने भाषणों को समायोजित करना है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : आप थोड़ा सजेशन दीजिए न वघेला जो।

[अनुवाद]

हम आपका परामर्श जानना चाहते हैं। कृपया अपनी सलाह दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसि में भी दुनिया भर की बात थी। (**व्यवधान**) जिस समय जिस भाषा में बात होती है, मैं उसी में बात करता हूं। (**व्यवधान**) आपने कहा था कि 100 दिन के अन्दर मंहगाई को कंट्रोल करेंगे। जिस दिन ओथ टेकिंग हुई थी, उस दिन आपके जो भाव थे, उस दिन में आप अगर वापस देश को भेज देंगे तो देश का बड़ा भारी कल्याण होगा। आपने जो हालत की है, उसके ऊपर मैं बाद मैं आऊंगा। आपने जो शुरूआत देश को ठीक करने के हिसाब से जैसे बजट से शुरू किया है, तो बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेज को मैं समझ सकता हूं। डायरेक्ट टैक्सेज में कॉमन मैन पर शुगर, फर्टिलाइजर, पेट्रोल पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का प्रभाव है। इसका नतीजा आप भोग रहे हैं। 100 दिन नहीं, 300 दिन में भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को तेजी मिलेगी। उसके बाद, इसके जो कैस्केडिंग ईफैक्टस होंगे, उससे भी आप और हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए जो चीजें आप करने जा रहे हैं, उससे कौमन मैन पर क्या असर पड़ रहा है जिस कौमन मैन को आपने प्रौमिज किया था, जिन दिन आपने अपनी गवर्नमैंट बनायी थी, यदि उस दिन के प्राइस लेवल तक भी आप रेटस को वापस ला सकें तो भी हम आपके आभारी होंगे।

उपाध्यक्ष जी, अब मैं अपनी बातों को शौर्ट करता हूं क्योंकि खाद वाली बाद और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात, उससे पहले, इंडस्ट्रियल पौलिसी की हालत, जिन दिनों में आपने यहां रखी, इकौनौमिक सर्वे के बाद, आपने इंडस्ट्रियल पौलिसी सदन में रखी, उसमें जिन बातों को शामिल करना चाहिए था, केवल तीन बातों को मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी वजह से देश को जो प्रौब्लम्स हुई वे हैं—फिस्कल डैफिसिटी, यह बिल्कुल अक्षम्य अपराध आपका है, राजकोषीय घाटा है विदेशी व्यापार घाटा यानी बैलेंस ऑफ पेयमैंट डैफिसिट और डबल डिजिट इन्फलेशन। इसकी वजह से तीन तरफा मार पड़ी यानी तीनों बातें उसमें से निकलीं।

[श्री शंकर सिंह बाघेला]

उससे क्या हुआ, पिछले तीन सालों की हालत आप देख लीजिए। पिछले तीन सालों के आंकड़े मैं आपको बताता हूं। औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि की दर होनी चाहिए थी : वर्ष 1988-89 में 8.7 परसेंट थी, 1989-90 में 8.6 परसेंट थी, 1990-91 में 8.4 परसेंट और फिर 1991-92 में एप्रौक्सिमेट 7.5 परसेंट। इसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट जो आपका होना चाहिए था, उसमें दिन-प्रति-दिन गिरावट आती गई, तीन सालों में वह लगातार डिक्रीज होता गया।

इसके बाद प्राइस राइज के आंकड़े आप देखिए, आपने तीन सालों में प्राइस राइज किस हालत तक पहुंचा दिया—1988-89 में 5.7, 1989-90 में 9.1, 1990-91 में 12.1 और 1991-92 में 14.5 परसेंट। अब विदेशी कर्जे के आंकड़े देख लीजिए—1988-89 में 69,383 करोड़ रुपये का कर्जा था, 1989-90 में वह 80,135 करोड़ हो गया, 1990-91 में 1,20,000 करोड़ रुपये हो गया और 1991-92 में 1,85,000 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा आपके पास जो फौरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे—1988-89 में 6,300.5 करोड़ रुपये के थे, 1989-90 में घटकर 5,787 करोड़ रुपये के रह गए, 1990-91 में और घटकर 4,388 करोड़ रुपये के रह गए और फिर घटकर 2500 करोड़ रुपये के रह गए। आज स्थिति यह है कि यदि आपके पास 1500 करोड़ रुपये के रिजर्व भी हैं तो भी मैं आपको नसीबदार मानता हूं। आज देश की हालत क्या हो गई है, रिजर्व जीरो हो गया है, फौरेन एक्सचेंज की हमारे पास भारी कमी है। आखिर हम कहां जा रहे हैं और यह सब कैसे हो गया। इंडस्ट्रियल उत्पादन में जो वृद्धि होना चाहिए थी, उसमें कैसे डिक्रीज आ गई। प्राइस राइज कहां तक हो गया और फौरेन एक्सचेंज कैसे माइनस हो गया, इस सब की जिम्मेदारी सीधे सरकार की है और इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद हम दे सकें, वह कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट से पहले, जिस तरह से सरकार ने रुपये का डिवैल्यूएशन किया, औफिशियली 20 परसेंट डिवैल्यूएशन आपने किया लेकिन रिजर्व बैंक की जो पौलिसी है, हमारे पास जितना फौरेस एक्सचेंज है, कुछ देशों के साथ हम रूपी में बद्ध हैं, अटैच्ड हैं। जैसे ही कुछ होगा अपने आप इंटरनेशनल फौरेन एक्सचेंज के रेट में हमारा रुपया अपनी जगह बना लेगा। रिजर्व बैंक की जो पौलिसी रही है, वह मस्ट होती है। उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसी क्राउलिंग पैग की पौलिसी को इम्पलीमैंट करते हुए, धीरे-धीरे, 1991 में आपने रुपये को 50 परसेंट डिवैल्यूएट कर दिया। इससे पहले एक साल में 20 परसेंट अवमूल्यन रुपये का हुआ था। फिर आपने औफिशियली 20 परसेंट रुपये का अवमूल्यन कर दिया। कुल मिलाकर एक रुपये में से, 90 पैसे इस तरह आपने पिछले डेढ़ साल में कम करके, रुपये की वैल्यू को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ थोड़ा-सा बचा, तो आपने ऑफिशियली ही 20 परसेंट डीवेल्यू किया, उसके बाद आपको 5 परसेंट और करना पड़ा। यानी कि पूरे के पूरे रूपी का एक साल में वैल्यू ही गंवा दिया। रिजर्व बैंक की पॉलिसी के हिसाब से जो क्रॉलिंग पैग की पॉलिसी है, उसमें 50 परसेंट चला गया ऑफिशियल, उसमें आपने 20 परसेंट कर दिया फिर 5 परसेंट का किया

और इसलिए जो एडजस्ट करना चाहिए आपको उस अनुकलन के लिए, उस एडजस्टमेंट में पूरा का पूरा डिवेल्यूएशन खत्म हो गया। इस प्रकार से आपको रूपी को तबाह करने का कौन-सा राइट है। यह आपके पाप का प्रायश्चित है। इतने पाप किए हैं, इसके बाद भी यदि रुपया बचता है और यह पॉलिसी रही और फिर कोई कमिटमेंट नहीं आया, सही दिशा में आप नहीं जाएंगे, तो फिर से रूपी डिवैल्यू होगी, उसको आप रोक नहीं सकते।

महोदय, अभी मैं रिजर्व बैं की बात कर रहा था। इसी सम्बन्ध में एक दूसरी बात मार्जिन मनी की है। देखिए, आपके पास डॉलर नहीं है, व्यापारी को डॉलर चाहिए, उसको डालर नहीं देंगे, फारेन एक्सचेंज नहीं देंगे, तो आपने इतना मार्जिन मनों क्यों बढ़ाया है? आप सब को बोल दीजिए डॉलर नहीं मिलेगा, फारेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। बिजनैस मैन को नहीं मिलेगा, किसी को बाहर जाना है, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना है, जिसमें सबका कमीशन होता है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज की बात आड़े नहीं आती। आपने मार्जिन मनी 50 से 200 परसेंट कर दिया, ऐसा क्यों किया है? आप सब के लिए मार्जिन मनी रखिए और मेहरबानी करके वह मार्जिन मनी घटाइए, मार्जिन मनी की परसैंटेज नीचे ले आइए। जिस व्यापारी के लिए फारेन एक्सचेंज जरूरी है, जिस बिजनैस मैन को आप अपने हिसाब से समझते हैं कि यह ठीक है और इसको जरूरत है तो उसको आप दीजिए। इस मामले में जो आप कर रहे हैं उस पर आप विचार कीजिए। नेशनलाइज्ड बैंकों ने बिजनैसमैन का क्रेडिट भी खत्म कर दिया और आप रूपी पेमेंट के देश और हमारे दूसरे डालर के हिसाब से व्यापार करने वाले देशों के साथ मार्जिन मनी, सेफ है। इसमें जिस प्रकार मे भेद करना चाहिए, वह आप नहीं कर रहे हैं। आपके पास डालर नहीं है, आप यह समझते हैं, तो रूपी पेमेंट वाले देश रशिया हो या ऐसे ईस्ट यूरोप के देश हों, इनके साथ व्यापार में क्या तकलीफ है? देखिए, आप इम्पोर्ट करते हैं—सीमेंट, फर्टिलाइजर या एक्स० वाई० जैड०, तो जो रूपी पेमेंट वाले देशों में हैं, उनको आप डॉलर के देशों में क्यों घसीट ले जाते हैं? अगर प्राइस और क्वालिटी कन्ट्रोल की प्रॉब्लम है, तो प्राइस और क्वालिटी कंट्रोल को ठीक से देखिए। आप मेहरवानी करके रूपी पेमेंट वाले देशों से व्यापार क्यों नहीं करते हैं? मैं कम्युनिस्ट कंट्रीज के फेवर की बात नहीं करता, लेकिन रूपी पेमेंट वाले देश जो हो, वहीं से इम्पोर्ट होना चाहिए जिससे डॉलर वाला मामला तो बीच में न आए क्योंकि हमारे पास फारेन एक्सचेंज नहीं है। इसलिए आपने इसकी भी चिन्ता नहीं की है। आप इसमें ऐसे काम नहीं करेंगे, तो ऐसे कौन से पाप हमने किए हैं यानी गवर्नमेंट से हुए है जिनका फल हम भुगत रहे हैं।

महोदय, बजट में अनलिमिटेड डैफिसिट है, विदाउट लिमिट, एग्रीकल्चरल बेस को नैग्लैक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इनएफीशिएंसी को वहां देखना और पॉलिटिशियन और बिजनैसमैन से साथ मिलकर, जहां-जहां ये उद्योग भवन और अन्य इस प्रकार के भवन हैं वहां जो घपले हैं, उनको आप दूर कीजिए। ये जो मिली भगत से काम हो रहे हैं, इनको दूर कीजिए। इसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय करने चाहिए, जिससे लाइसेंस, कोटा पद्धति, जिसे आप खत्म करने जा रहे हैं, वह इम्पलीमेंट हो सके और इसको सख्ती से आपको इम्पलीमेंट करना चाहिए। इसमें जो अन्य लोगों की दखलगीरी है, उसे बन्द करना चाहिए।

महोदय, मंत्री जी ने वन विंडो वाली बात कही है। कम से कम आप उनको विंडो दिखाइए तो सही कि विंडो है कहां। आज लाइसेंस, कोटा पद्धति से माल लेने वाले लोग खुश नहीं हैं। इसको आप देखिए जब आपने यह पद्धति जारी की है, तो यदि इसका कुछ असर नहीं होता है, लोग खुश नहीं होते हैं, तो आप अपने आपसे पूछिए कि कहां गलती है, कहां क्या मामला हो रहा है। अगर आप अपने देश में रूपी की वैल्यू मेंटेन कर पाएंगे, तो ही विदेश में रूपी की वैल्यू रहेगी। यहां अगर उसकी खरीद शक्ति कम होगी, तो विदेशों में भी रूपी की वैल्यू कम होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां आप फारेन एक्सचेंज की बात करते हैं, तो उससे पहले और रूपी की वैल्यू डिवैल्यू करने से पहले, अपने देश में रूपी की वैल्यू को मैंनटेन करिए। यहां उसको खत्म नहीं होने दीजिए वरना फिर डिवेल्यूएशन और फिर डिवेल्यूएशन होगा, इससे आप बच नहीं पाएंगे।

महोदय, जो निरूत्पादक और निरर्थक सरकारी खर्च है, उसको समाप्त करिए। कम से कम इसकी शुरूआत आप अपने घर से तो करें। दूसरी बात यह है कि जो जवाहर रोजगार योजना या जो इस प्रकार की दूसरी योजनाएं हैं, जो वोट ओरिएंटेड हैं, इस प्रकार की वोट ओरिएंटेड जितनी भी स्कीमें हैं, उनको आप रिव्यू करिए। अगर वे सही ढंग से चल रही हैं और ठीक हैं, वरना इसमें करप्शन ही करप्शन है। गांव वालों को जो मिलता है, उसमें मिली भगत चलती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप वोट ओरिएंटेड पॉलिसी इम्पलीमेंट मत करिए। इस प्रकार से आप इन योजनाओं में वोट लेने के लिए अगर इस प्रकार से करोड़ों रुपया लगाएंगे, तो कहां से इतना पैसा लाएंगे ? इसलिए ऐसी जितनी स्कीम हैं उनको रिव्यू कीजिए, जो ठीक नहीं हैं उनको बन्द कीजिए। प्रोडक्शन पर कंट्रोल छोड़ दीजिए और इनकम पैदा करने के जितने स्टैप्स हैं उनको प्रोत्साहन दें और ऐग्जीक्यूट करें। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि फिसकल डैफीसिट की मैंने जो बात की थी उसमें जी० डी० पी० में 6.5 प्रतिशत मेनटेन करने की कोशिश हमारे फाईनेंस मिनिस्टर ने की है। लेकिन आप देखिए जितने भी फाईनेंस मिनिस्टर आए सब इसमें फेल हो गए, मैं नहीं समझता ये फाइनेंस मिनिस्टर इसमें सक्सैसफुल हुए, ये भी सौ प्रतिशत फेल होंगे। इसलिए इसके बारे में भी कुछ कीजिए। आप अभी लिवरल बनते जा रहे हैं। आपने और भी जो इस पर किया है उस पर आप स्ट्रांग नहीं हैं. अगर लिवरल बनना है तो ये बातें छोड़ दीजिए। पार्टी को खुश करके, पार्टी का नाम बीच में रखकर, वोट वाली राजनीति छोड़कर लिवरल वाली कोशिश मत कीजिए।

इसके बाद प्राइस राइज़ के हिसाब से और भी जो खर्चे बढ़ेंगे उनमें कंट्रोल कीजिए। ब्लैक मनी के बारे में आपने जो स्कीम बनाई, उसमें एम० आर० आई० स्कीम में और भी लिबरल बनिए, यह पूछना छोड़ दीजिए कि विदेश वाला या एन० आर० आई० रुपया कहां से लाया, वह रुपया यहां से गया या इंटस्ट्रियलिस्ट का है, ब्यूरोक्रैट्स का है या पौलीटिशियन का है। अगर आप लिवरल नहीं बनेंगे तो वही मोर दैन टैन थाउजैंड करोरस ऑफ रूपीज विदेशों के बैंकों में पड़े रहेंगे। रूपया यहां पर लाना है तो कहिए कि इनकम टैक्स में जो भरना है भरिए, रूपया बढ़ेगा। इसमें 20-25 परसेंट की जो बात है उससे सही एक्सपोर्टर अलग हो जाएगा। एग्जिम

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

कहां से आया है यह नहीं पूछना है। तब इसमें आपको राहत मिलेगी।

इंडस्ट्रियल उत्पादन का जो ग्रोथ है वह स्टैगनेट हो गया है, इसमें उसे थोड़ा और धक्का लगेगा और इन्टरनल वीकनैस ऑफ दी इकोनौमो को भी धक्का लगने पर ठीक होगा। आज आपको शेयर बाजार अच्छा लगता होगा। अभी वित्त मंत्री ने हमारे अर्थतंग की वाह-वाह कहकर भाषण दिया। लेकिन इस धोखे में मत रहिए, जितना आप देखते हैं वह सही नहीं है। कौमन मैन को जाकर पूछिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को जाकर पूछिए, शुरूआत में जो चीजें अच्छी लगती हैं एक महीने के बाद वह सही नहीं होती हैं। आज जो अच्छा लगता है वह आउटलुक है, इटरनल मैटर नहीं है इसलिए अन्दर से देखिए कि क्या हो सकता है।

इसमें रिजर्व बैंक की जो बात थी, रिजर्व बैंक को आप लीगल कंट्रोल में, गवर्नमैंट के हिसाब से लिमिट में रखिए। रूपया क्यों खत्म हो गया। नोट प्रिंट करने के लिए मिल्टन फ्रीडमैन, नोबल प्राइज विनर ने 1956 में रूल्स वर्सेस डिस्क्रीशनरी की बात हमारे संदर्भ में कहीं थी, उसमें उन्होंने कंट्रोल रखने की बात की थी कि रिजर्व बैंक जो नोट छापती है उसके हिसाब से प्रपोरशनेट ऐमाउंट डिपोजिट कीजिए। लेकिन 1956 की पौलिसी में आपने कहा कि नहीं मिनिमम इतना रिजर्व होगा नोट चाहे जितने भी छापिए। दुनिया में बहुत कम देशों में ऐसा है। आपको भी नोट छापने से पहले प्रपोरशनेट रेटस के हिसाब मे अगर रिजर्व बैंक में रिजर्व करना है तब तकलीफ होगी क्योंकि सोना आदि कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से चक्रवर्ती कमेटी में भी यह बात थी। यदि यह किया होता तो आज यह हालत नहीं होती। यह आप फिर से कर सकते हैं, कल यह नहीं होगा। रिजर्व बैंक में जितना रिजर्व है उस प्रपोरशन के हिसाब से आप नोट छापिए, ज्यादा नहीं छाप सकते हैं। इसे आप लीगल कंट्रोल में लाइए तब यह बच सकता है।

बजट या इंडस्ट्रियल पौलिसी या दूसरी जो पौलिसी है वह सब हमारे साधन हैं। आपको देश का विकास करना है, कौमन मैन का भला करना है। साधन सामान्य जन को सुलभ कराना है। उसके लिए इंडस्ट्रियल पालिसी ठीक और ट्रेड पालिसी अच्छी रखिए। इनकम पालिसी जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूं, उसमें आपको फर्क करना चाहिए। आपने जो लाइसेंसिंग परमिट छोड़ना शुरू किया है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन यह पूरा-पूरा नहीं है। इसमें भी दोष हैं। आपकी पालिसी लिम्पिंग है, वह लंगड़ी ही रहेगी, पूरी जम्प नहीं कर पाएगी। इसमें जितने भी दोष हैं अगर उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो लिम्पिंग पालिसी इकोनमी को लिम्पिंग रखेगी, गवर्नमेंट को भी लिम्पिंग रखेगी और वह दौड़ में भी आगे नहीं आ पाएगी। इसमें जितने भी दोष हैं, उनमें आप सुधार करें चाहे कितने ही स्ट्रौंग हैंड से क्यों न काम लेना पड़े लेकिन इसको ठीक जरूर करिए। बड़े-बड़े उद्योगपति जिनको यह पसन्द नहीं आ रही है, उन सबसे इस बारे में चिन्ता लगी है।

व्यापार नीति में इम्पोर्ट सब्जिच्यूट की बात भी चली। इससे बड़ी इंडस्ट्रीज को लाभ मिलता है। अगर आपको लिबरल नहीं बनना है तो इम्पोर्ट सब्जिच्यूट की बात करिए। आप फॉरेन एक्सचेंज पाने के लिए स्ट्रौंग रहें। आपने एग्जिम स्क्रिप्ट की जो बात की है, उसमें अलग-अलग लोगों को अलग-अलग हिसाब से दिया है। इसमें स्पेशल ग्रुप काम करेगा। इससे करप्शन

स्क्रिप्ट 40-45 परसेंट का जो प्रीमियम रखा गया है, उसको नीचे लाइए जिससे कम से कम 20-25 परसेंट की जो आपने बात कही है, उससे लाभ होगा। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको आप आवश्यक समझते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइए।

अब मैं वेज पालिसी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज पब्लिक सेक्टर के चपरासी को दो हजार और क्लर्क को पांच हजार रुपए मिल रहे हैं। ऐसे में वहां के चपरासी के मन में आता है कि मैं एक ज्यादा लगाने वाला हूं। दूसरा चपरासी है जो बराबर काम करता है लेकिन मुझे तनख्वाह उससे कम क्यों मिलती है। चाहे कोई कर्मचारी किसी पब्लिक अंडरटेकिंग में हो या बैंक में हो या किसी सरकारी दफ्तर में हो लेकिन सबको एक जैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए। वेज पालिसी में एक नाप होना चाहिए। राज सुनने में आता है कि पब्लिक अंडरटेकिंगस में इतने स्केल बढ़ गए लेकिन वहां के काम में कुछ प्रगति दिखाई नहीं देती है। आप वेज को काम के साथ जोड़िए। आपने कुछ दिन पहले लेबर यूनियन के लीडरों से बात की। आप इन यूनियन्स के लीडरों से कहिए कि पहले अपने यहां काम करके दिखाइये। अगर काम नहीं करना है तो पे-स्केल नहीं बढ़ाये जाएंगे। जिन जगहों में स्ट्राईक करके उत्पादन को हानि पहुंचाई जाती है उसकी क्षति-पूर्ति के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं—हमारे स्कूल में एक टीचर था, वह दुनिया भर का शराबी और गंदा आदमी था। उसको न तो मैनेजमेंट निकाल सकती थी और न ही गवर्नमेंट निकाल सकती थी। गवर्नमेंट आफिस में कोई काम नहीं करता है, गड़बड़ करता है और वह चालू किस्म का आदमी है, भ्रष्टाचार करता है फिर भी उसे कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता है। आप कायदा-कानून चेंज करिए। अगर कोई आदमी काम नहीं करेगा देश के साथ गद्दारी करेगा, लंच के लिए एक घंटा मिलने पर तीन घंटा खराब करता है तो आप उसको पकड़ कर रखिए। ऐसा अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप और आगे बढ़ाइये। मेरा कहना यह है कि कोई वर्क-लिंक होना चाहिए। अगर किसी प्राइवेट कम्पनी में या किसी अंडर टेकिंग में वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ानी है तो पहले उसका काम देखना चाहिए। अमेरिका, जर्मनी और जापान आदि देशों ने इस कारण बहुत प्रगति की कि वहां के लोगों ने काम में पूरी रुचि लेकर प्रोडेक्शन को बढ़ाया। अगर वहां कोई काम नहीं करता है तो उनको निकालने वाला भी कोई है। तो यह भी आप कानून को चेंज करके कीजिए, उसमें इस चीज को एड करिए।

इसके बाद यह जो आपने इण्डस्ट्री की बात की है, उद्योग को अनुदान देने की बात है, आपकी अनुदान के हिसाब से दूसरी जो इण्डस्ट्रीज हैं, इसके बारे में आपने सोचा है? कोल, स्टील, एनर्जी उद्योग को ठीक करने के लिए कहां है एनर्जी? जितने भी राज्यों के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स देखिए, कार्यक्षम बहुत कम होंगे यहां, मेरे ख्याल से सब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटा देते हैं। क्यों? आप जल्दी से जल्दी बिजली पैदा करने में अपनी पुरानी नीति छोड़ दीजिए। आप उसको थर्मल या हाइडल या टाइडल या गैस बेस्ड या सोलर या एटोमिक तो जिसका प्रयोग आपने कर दिया है, हाइडल और थर्मल का तो आप प्रयोग कर रहे हैं अब टाइडल का भी देखिए। हमारे गुजरात में कैम्बे है, कैम्बे में टाइडल से बहुत अच्छी बिजली पैदा हो सकती है। सोलर एनर्जी का प्रयोग

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

आपने क्यों छोड़ दिया है ? हिन्दुस्तान इतना गर्म देश है, आप सोलर एनर्जी का प्रयोग करिये। इससे आपको बहुत फायदा होगा। सबसे खराब बात है, गैस की, माफ करना, ओ०एन०जी०सी० पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का सबसे जो कमाने वाली बात करने का अंडरटेकिंग है, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन है। एक-एक इम्पोर्ट में करप्शन, इम्पोर्ट करने वाले एक-एक आफिसर में करप्शन है। मेरे ख्याल से जुलाई में इण्डस्ट्रियल वीकली में एक राय चौधरी का लेख है, आप इण्डस्ट्रियल वीकली मंगवाकर उस रायचौधरी की बात पढ़िए। उसने कहा कि इस क्षेत्र में इतना तेल है, पेट्रोल है, इतनी गैस है कि उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसका ज्योलोजिकल सर्वे तय करें कि कहां तेल निकलता है, उसको आप देखिए। उसको आप प्राइवेट लोगों को दे दीजिए, आप भी करिए प्राइवेट पार्टी से भी कराइए। दुनिया भर से टैण्डर इन्वाइट करिए और टैण्डर इन्वाइट करने में आप अपनी बात पब्लिकली करिए, आक्शन करिए कि यहां से गैस तेल निकालना है, दुनिया का कोई भी आदमी आये। वह आयल और गैस निकालेगा, उसका आप एक साल में एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोफेसर कुरियन, एक साल में। ओ०एन०जी०सी० इस देश की नाक दबा रहा हैं, उसके करप्ट आफसिर्स इस देश में ज्यादा एक्सप्लोरेशन न हो, इसके लिए गुमराह कर रहे हैं और गैस क्यों जला रहे हैं, आपका दिल कभी जलता है ? 1974 में प्रयोग हुआ कि उस गैस से कार चलती है, कार गैस से चलती है, उसको कितने साल हो गए, कार को गैस से चलाइये न। आपके गवर्नमेंट आफिसर के पास एक-एक एम्बेसडर कार, दो-दो कार, तीन-तीन कार है, उस एम्बेसडर कार को आप गोली से मारिए। आप इनको मारुति दीजिए, फिएट दीजिए, इनको डीजल व्हिकल दीजिए।

पेट्रोल का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले आप हैं और पेट्रोल सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले भी आप हैं। आउट डेटिड एम्बेसडर कार क्यों रखते हैं आप ? अगर दिल्ली में घूमते हैं तो मारुति से क्यों नहीं घूम सकते हैं आप ? वह आफिसर अगर अपने लिए घूमते हैं तो एम्बेसडर में घूमते हैं क्या ? आप अपने लिए जाते हैं अगर शहर में दिल्ली में तो एम्बेसडर में आते हैं क्या ? आप गैस जला रहे हैं तो कम से कम गैस इस कार में भी पेट्रोल का जगह काम में आती है, सक्सेसफुली काम में आती है। एक महीने में जितनी गैस जलती है, आप उसमें मकेनिज्म करिये, आदमी आये, कार फिल-अप करे, दूसरी जगह जाय, लगायें वहां लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। पता नही, आपके दिमाग में बात कहीं आती, गैस टैरेस हो रही है, बम्बई के लोग मांग रहे हैं कि हमको गैस दीजिए, हमारा पूरा गुजरात, सूरत, और सब लोग मांग रहे हैं कि हमको गैस दीजिए, हमारा अहमदाबाद मांग रहा है कि हमको गैस दीजिए तो गैस क्यों नहीं देते ? मैं मेरे खर्चे से गैस अहमदाबाद के लोगों को देने के लिए तैयार हूं, मेरे कारपोरेशन से। सूरत के लोग, बम्बई के लोग अपने खर्चे से, जहां गैस जलाई जाती है, वहां से गैस ले जाने के लिए दूसरी मशीनरी तैयार है, आप सैंक्शन क्यों नहीं देते ? कौन बैठा है वहां, जो इतनी मामूली बात, कुछ टैक्नीकल बात नहीं है, कुछ नहीं है फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ओ०एन०जी०सी० को और आपको यह सामान्य बात एम्बेसडर कार की मालूम नहीं पड़ती कि क्यों एम्बेसडर कार रखते हो, दफा कर दो सब को। मैं कोई एम्बेसडर कार का विरोधी नहीं हूं लेकिन कितना पेट्रोल

उसमें जलता है । अगर वह मुफ्त में चलती तो मैं डबल डैकर एम्बेसडर की बात करता लेकिन वह मुफ्त में नहीं चलती । वह सबसे ज्यादा पेट्रोल कंज्यूमिंग कार, आप उसको डीजल में कन्वर्ट करके सबको डीजल एम्बेसडर कार दीजिए । मैं समझ नहीं पाता कि आप इतनी सादी बात एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकते ?

इसके बाद कोल की बात है । कोल और रेलवे का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध है । गैस से बिजली पैदा करने के लिए हमारा पूरा गुजरात कह रहा है, हमारी गैस जल रहा है । गैस की बिजली के लिए आप अनुमति दीजिए, डीसैण्ट्रलाइज करके आप कह दीजिए, जहां गैस निकलती है, वहां प्रयोग करिए, वहां आप रिफाइनरी बनाइए ।

आपकी एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन है, 2200 करोड़ रुपया आपने उसमें लगाया है, उसकी क्या हालत है ? आज उसका आधा भी उपयोग नहीं हो रहा है । 2200 करोड़ रुपया आप कहां से लाए, कहां से पाइप आपने इम्पोर्ट किया, क्यों लगाई, क्यों गैस ले जाते हो ? जहां गैस निकलती है, वहीं क्यों नहीं इसका प्रयोग करते ? मैं समझता हूं कि जो चीज वहां से निकलती है, उसके आधार पर बनाइए । भारत सरकार बनाए, राज्य सरकार को आप मत दीजिए । गैस निकलती है, तो उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए । उद्योग को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और जब उनको एनर्जी मिलेगी, तो कॉस्ट आफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन अधिक होगा, लेकिन आप गैस को जला रहे हैं । इसी प्रकार कोयला बिहार में निकलता है । ले जाइए उस को दो हजार किलोमीटर दूर और ले जाने के लिए साधन रेलवे है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज रेलवे के रैंक के क्या भाव चल रहे हैं ? इन्डस्ट्रियललिस्ट्स आते हैं, उनको कहा जाता है कि कोयला नहीं है और कोयले वाले कहते हैं कि कोयला ले जाओ । कोयले को ले जाने के लिए रेक चाहिए और रेलवे में रेक नहीं है । कहा जाता है कि एक लाख रूपया लाओ, रेक मिलेगा । रेल भवन में रेक के लिए एक-एक लाख रुपया मांगा जाता है । कोयला नहीं होगा, तो उद्योग नहीं चल सकता है । कोयले के लिए रेक तभी सैंग्शन होगा, जब लाख रुपए देंगे और बात करते हैं कि आप इंडस्ट्रीज चला रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके जहां चैंक करना है, वहां चैंक कीजिए । रेक का भी एक सिस्टम होना चाहिए, लिस्ट बनाई जानी चाहिए, जिसका नाम आए उसको रेक सैंग्शन होनी चाहिए । एडवांस में डिमांड रहे और डिमांड के हिसाब से रैंक सैंग्शन होनी चाहिए । आप क्यों नहीं सिस्टम बनाते हैं । अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिस्टम को चला रहे हैं, जो हमको गुलाम समझते थे । आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपका दिमाग भी हिन्दुस्तान के कॉमन आदमी को गुलाम समझ रहा है । आप उस दायरे से कभी बाहर नहीं आएंगे और अपना माइन्ड एप्लाई नहीं करेंगे । मिनिस्टर बनने के बाद आपके घर में भी कोई प्राब्लम होगी, तो आप काम नहीं कर पाएगे । आपकी पार्टी में भी कोई गड़बड़ी होगी, तो आप काम नहीं कर पाएंगे । इसलिए मेहरबानी करके जो मंत्री बने हैं, उनको कहिए वे काम करें । ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठिए, और कॉमन आदमी का फायदा कराइए ।

इसके अलावा मैं एक बात पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में कहना चाहता हूं । नेहरू जी

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

ने जब कोई बात कही होगी, तब कही होगी । क्या है पब्लिक अंडरटेकिंग्स ? आज नुकसान करने वाली कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन्डस्ट्री हो, उसको आप स्क्रेप क्यों नहीं करते हैं । मजदूरों को आप जितनी तनख्वाहें देते हैं, इससे ज्यादा भी तनख्वाह दें और फिर भी उनको रखें तो हमको मरना है । पब्लिक अंडरटेकिंग्स जितने हैं, उन सब को आप कह दीजिए कि ये नुकसान करने वाली पब्लिक अंडरटेकिंग्स हमको नहीं चाहिए । अगर यही स्थिति प्राइवेट में हो, तो क्या आप उनको घर में रखेंगे । मेरी समझ में नहीं आता है कि खुश करने की कोई हद है, और लिंगर करने की भी कोई हद होती है । कितने सालों से ये घाटे में चल रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं बंद कर देते हैं ? प्रो० कुरियन साहब आप पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में रहे हैं और आपको पता भी है कि यह ऐसे चलता रहता है । इसलिए मेहरबानी करके आप क्यों नहीं निर्णय लेते हैं और निर्णय ले करके जिनको खत्म करना है, उनको पकड़िए । फिर कहिए कि इतनी इन्डस्ट्रीज को हम एक महीने में औक्शन करके स्क्रेप कर देंगे । फर्क क्या पड़ता है, दुनिया भर में हम भीख मांगते हैं और ये मजा करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम एकाउन्टेबल हैं, तो वे आफिसर भी एकाउन्टेबल हैं । ओ० एन० जी० सी० या कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग घाटे में जाती हैं, तो उनके डायरेक्टर्स, चेयरमैन और एम० डी० को पकड़िए । देखिये, अगर ये एन० आर० आई०—नान रेजीडेंट इंडियन में आते है तो एन० आई० का रूपया भी इनका है । जहां भी पब्लिक अंडरटेकिंग में करोड़ों रुपयों का घपला है, तो उसके लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन और एम० डी० रिस्पांसिबल है । अगर कोई पब्लिक अंडरटेकिंग मुनाफे में जाती है, तो इनको प्रमोशन दीजिए और भी सुविधायें दीजिए तथा तनख्वाह बढ़ाइए । अगर ये घाटे में चलती हैं, तो इनकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिए । घाटे में ले जाने के लिए अगर ये ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं, तो उनको भी कन्ट्रोल करिए और वे भी इसके लिए एकाउन्टेबल होने चाहिए । मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, कितनी एम० डी० की पोस्ट्स वेकेंट हैं और डायरेक्टर्स की पोस्ट्स खाली हैं ? इन पोस्ट्स को भी आपने सरकार में से ही भरना है, तो उनको भी भरिए । जहां घाटा होता है, उनके आफिसर को आप एकाउन्टेबल करिए कि आपकी जिम्मेदारी है और इन अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट के साथ लाकर कम्पीटीशन में रखिए ।

आखिर में, मैं एक बात सिक यूनिट के बारे में कहना चाहता हूं । मेहरबानी करके सिक वाली बात ज्यादा दिनों तक सिक न रखिए । स्मॉल और टाइनी यूनिट्स के बारे में मैं समझ सकता हूं । आपने एक विनडो की बात कही है । मैं एक संसद सदस्य हूं, मेरा लड़का इन्डस्ट्री खोल रहा था । मैंने आफिसरों को नहीं कहा कि यह मेरा लड़का है । मैंने कहा कि देखो, क्या धन्धा है । छः-छः महीने तक लोन सेंक्शन नहीं होता है ।

नेशनलाइजड बैंक ने लोन नहीं देना है, बाकी इंस्टीट्यूट हैं, इसमें 50 सर्टिफिकेट एक-दो नहीं, एक विण्डो नहीं, दुनिया भर की जगहों में घूमो, ये कागज ले आओ वो कागज ले आओ, निकम्मे कागजात जितने भी हैं और अगर वे कागजात नहीं मिलेंगे तो वह पैसा देगा और कहेगा कि लो साहब सर्टिफिकेट नहीं मिला, इतना परसेंटेज आप ले लीजिए । तो कम से कम जो सिक यूनिट्स है इनको लोन देने वाला बैंक का आफिसर, सिक यूनिट्स वाला इण्डस्ट्रीयलिस्ट

और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और कई जगह तो अपने आप इण्डस्ट्री को सिक करने वाले लोग हैं, वे सब मिलकर करते हैं कि इण्डस्ट्री को सिक करो और सबसिडी ले लो। तो सबसिडी लेने के लिए यह काम किया जाता है, जिस सबसिडी को आप फर्टिलाइजर के लिए किसान को देने के लिए तैयार नहीं हैं। मेहरबानी करके आप कृषि को भी इण्डस्ट्री बोल दीजिए, कृषि उद्योग है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको कृषि को भी सबसिडी देनी पड़ेगी, आपको कृषि को भी स्माल यूनिट्स या टाइनी यूनिट्स करना पड़ेगा। आपको वहां भी लोन, रोड इलैक्ट्रीसिटी और पानी देना पड़ेगा, यानी कि इण्डस्ट्रीज में इण्डस्ट्रीयलिस्ट, वहां गरीब किसान हैं, उस गरीब किसान को आपने कहा कि बड़े किसान की सबसिडी नहीं देनी चाहिए, तो बड़े किसान देश में बचे ही नहीं हैं। कम से कम हमारे गुजरात में तो नहीं हैं। तो आप सबसिडी पूरी जो है 10 परसेंट नहीं, 40 परसेंट या जो भी है आप उसको रहने दीजिए, टाइम बीइंग रहने दीजिए। इतने सबसिडी के रुपये तो आपके उद्योगपतियों के टैक्सेस बाकी हैं, फिल्म के अभिनेताओं के टैक्स बाकी हैं। इन टैक्सों को आप कलेक्ट करेंगे तो एक साल का सबसिडी का घाटा निकल जाएगा। मेहरबानी करके वहां आप कलेक्ट करिए, लेकिन जहां देना हो वहां दीजिए।

जो सिक यूनिट्स हैं, बड़ी इंडस्ट्रीस, मीडियम, स्माल उनको अगर आपने सिकनेस की, शुरूआत में ही अगर आप किसी रोग का इलाज कर दें तो रोग नहीं बढ़ेगा और अगर आप उसका इलाज शुरू में नहीं करवाएंगे तो वह दिन आएगा जब उसका आपरेशन कराना जरूरी हो जाएगा और अगर कैंसर जैसा रोग हो गया तो उसका आपरेशन से भी इलाज नहीं होगा, इसलिए अगर आप इसको अभी से नहीं देखेंगे तो रोग का इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो इसकी शुरूआत है। अभी तो इसका इलाज हो सकता है।

आपने सब जगह इण्डस्ट्रीयल यूनिट्स को सिक यूनिट्स बना दिया है, लेकिन वे क्या करते हैं, उनके यूनिट्स सच्चाई में सिक हैं या नहीं यह वे नहीं देखते हैं। इण्डस्ट्रीयलिस्ट आकर उसको सलाम करे, उनके साथ कुछ मिली भगत करे तब जाकर उसकी इण्डस्ट्री को मदद मिलती है। इसलिए जितनी भी सिक इण्डस्ट्रीस हैं उनके लिए आप निर्णय कर दीजिए कि इतने परसेंटेज सिकनेस होगी। उसको गोद ले लीजिए और उसकी पूरी मदद कीजिए, लिबरल बन करके उसकी मदद करिए। अगर कोई रोग का खतरा है तो उसको आप गोली दे दीजिए, नीम्बू पानी पिला दीजिए तो वह करेंट में आ जाएगा, लेकिन जो ऐसा मरीज है उसको आप प्योर घी का हलवा भी पिला दो तो फिर भी उसमें करेंट नहीं आएगा, तो ऐसे मरीज को आप क्यों खिला रहे हैं? लेकिन जो इण्डस्ट्री इतनी सिक हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, प्रो० कुरियन कभी अपने इण्डस्ट्रीयलिस्ट को सिक सुना, जिसकी इण्डस्ट्री सिक है वह कभी बीमार पड़ा, उसको कभी ताप आया, उसको कोई बीमारी नहीं लगी। वे तो अपनी बीबी के नाम से दुनिया भर का काम करता है, मरता तो मजदूर है, इण्डस्ट्री का मालिक नहीं मरता है। इसलिए बीमारी का सही इलाज ढूंढिए और ऐसी सिकनेस है, इसमें कनसेशन की बात छोड़ दीजिए तो

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

[अनुवाद]

इसके लिए उद्योगपति ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं।

[हिन्दी]

छोटे हो या बड़े हों, लेकिन बड़ा ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए आप टाइनी और स्माल स्केल, कोटेज बेसड, विलेज बेसड और एग्रीकल्चर बेसड जो हैं उनको अच्छी मदद करिए और देश में छोटे-छोटे इण्डस्ट्री के जाल कों ऐसे गांवों में बिछाइए जहां उसको रोजी मिले, बेकारी कम हो, बेकारी का उन्मूलन हो और बड़ी इण्डस्ट्रीज जो हैं उसकी सिकनेस के बारे में आप सोचिए कि यह सही सिक हैं या मिली भगत है। एक और मामला है पूरी प्रोपर्टी उनकी जब्त करके जब तक सरकार का रुपया न निकले तब तक उसको बांधे रखिए। ऐश करने का अधिकार अगर मजदूर को नहीं है तो मालिक को भी नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मालिक जो जानबूझ कर इण्डस्ट्रीस को सिक बना रहे हैं आप उनको ध्यान में रखकर एक लिस्ट बनाकर उनको कहिए कि यह मामला नहीं चलेगा। सरकार की जो पालिसी है, उसमें आपने पूरे हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी उपेक्षा पैदा कर दी है, हाई एक्पेकटेशन, डा० मनमोहन सिंह जी आप यहां आए हैं लेकिन होना कुछ नहीं है।

हाई एक्सपेक्टेंशस का एक हिसाब होता है, उस हिसाब से इकनामिस्टों का एक नया सिद्धांत आया है, कोई सहमत हो या न हो, लेकिन अर्थशास्त्रियों का एक नया सिद्धांत है। जैसा मैंने कहा कि आप सक्सेस होने वाले नहीं है, 100 दिन नहीं बल्कि 300 दिन बाद भी प्राइस कंट्रोल होने वाला नहीं हैं। इंडस्ट्रियल पालिसी या आज की जो बात है, जैसा मैंने कहा कि यह "फूल गुलाबी चित्र" है, यह रहने वाला नहीं है, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेंशस लोगों के दिमाग में जगी है। रेशनल एक्सपेक्टेशंस का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार लोग अपने आपको, अपने व्यवहार में लोग समझते हैं कि यह गवर्नमेंट की बात है। "प्रिंसीपल आफ रेशनल एक्सपेक्टेंशस" इसमें से लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में फर्क करेंगे तो कंज्यूमर और इन्वेस्टर के बीच में आएंगे, जिससे जो रिजल्ट आना चाहिए, उसमें रेशनल एक्सपेक्टेंशस का सिद्धांत आड़े आएगा। यह विवादास्पद है, लेकिन आप अपना माइंड अप्लाई करके और इकनामिट्स से कंसल्ट करके इसको देखिए, क्योंकि हिन्दुस्तान में रेशनल एक्सपेक्टेंशस वाला प्रिंसीपल ज्यादा लागू होगा। आपने 40 साल के बाद करवट बदली है और उससे लोगों को लगता है कि इसमें से कुछ निकल रहा है तो हाई एक्सपेक्टेंशस हैं और इसमें अगर कुछ नहीं होगा तो आपको जरूर मार खानी होगी, देश तबाही की ओर जाएगा। यह रेशनल एक्सपेक्टेंशस वाला प्रिंसीपल बीच में आड़े न आए, इसका सर्वे करके देश की इकानमी को सही रास्ते पर ले जाइए और नेहरू जी की बात छोड़ कर महात्मा गांधी जी की बात की ओर देखिए, जिसमें डीसेंट्रलाइजेशन, गरीबी उन्मूलन, बेकारी उन्मूलन, कृषि आधारित उद्योग आदि बातें हैं। इससे लोगों को सुख देने का काम आप करेंगे तो हमारा समर्थन रहेगा। नहीं तो प्राइस-राइस इसी तरह से होता रहेगा, डबल डिजिट, 15-17 परसेंट प्राइस राइस होगा तो आप देखिए कि लोगों की, कामन-मैन की क्या हालत होगी। जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, उनकी कीमतों पर कंट्रोल

करके आप लोगों को सुख दे सकते हैं। इसी तरह से मैंने गैस के बारे में कहा है और भी मैंने जो सुझाव दिए हैं, उनको ध्यान में रखिए और जो चीजें आपको ठीक लगें, और लोगों से कंसल्ट करके उन चीजों को जल्दी एग्जीक्यूट करवाइए, ताकि कामन-मैन को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मोहन विष्णु रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

महाराष्ट्र में कोंकण के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। (14)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मुम्बई में प्रदूषण फैलाई वाले उद्योगों की स्थापना को निरूत्साहित करने की आवश्यकता। (16)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग के 100 रुपये कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र में मुम्बई, थाणे तथा पुणे में प्रदूषण को नियंत्रित न करने के लिए उद्योगों के प्रबंध मंडलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता (17)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

महाराष्ट्र में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। (18)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।"

मछलीपटनम में एक भारी उद्योग की मंजूरी प्रदान करने की आवश्यकता। (27)

"कि सरकारी उद्योग विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।"

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अकुशल अधिकारियों को जबरन सेवा-निवृत्त करने की आवश्यकता। (28)

"कि सरकारी उद्योग विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च अधिकारियों, विशेष रूप से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों द्वारा उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक परिसंपत्तियों की खरीद की जांच करने की आवश्यकता। (29)

"कि सरकारी उद्योग विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

अनिवासी भारतीय उद्यमियों के उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (30)

"कि सरकारी उद्योग विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों के कार्यकरण पर सतत् निगरानी रखने की आवश्यकता। (31)

"कि लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृषि तथा कुटीर उद्योगों को विकसित करने की आवश्यकता (32)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

आगरा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। (45)

"कि लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

आगरा के शिक्षित बेरोजगार युवकों विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के युवकों को स्वयं अपना उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता (52)

"कि लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

आगरा में जिला उद्योण केन्द्र के माध्यम से वहां लघु तथा कुटीर उद्योगों में औद्योगिक एककें स्थापना करने की आवश्यकता। (53)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके। रुपया किया जाये।"

देश में रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने में असफलता। (57)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके। रुपया किया जाये।"

51 प्रतिशत या इससे अधिक की इक्विटी वाली विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग की अनुमति प्रदान करना (58)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भारत में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बहुत बड़े स्तर पर अनुमति देने सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने में असफलता। (59)

"कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रूपया किया जाये।"

हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाए रखने में असफलता। (61)।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रूपया किया जाये।"

सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में असफलता। (70)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रूपया किया जाये।"

50 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी की भारत में भागीदारी की नीति। (71)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश के रुग्ण उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता। (72)

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

औद्योगिक सामान की देशी बाजार में खपत बढ़ाने की आवश्यकता। (73)

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भारत में कंपनियों को विदेशी पूंजी की 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक इक्विटी देने की नीति की समीक्षा करने में असफलता। (56)

"कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाने वाली 293 औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृत देने की

आवश्यकता। (87)

"कि सरकारी उपक्रम विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुशल प्रबन्धकों और कर्मकारों को उचित प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (88)

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, नई औद्योगिक नीति देश की आर्थिक स्थिति…।

श्री दिलीप भाई सिंघानी (अमरेली) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जा रही है—अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य श्री चन्द्राकर अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

3.00 म०प०

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : उपाध्यक्ष जी, आज नयी उद्योग नीति पर चर्चा करने के लिए अभी मेरे पूर्व वक्ता, बी०जे०पी० के एक माननीय सदय श्री वघेला ने अपने विचार प्रकट किए। मुश्किल यह है कि औद्योगिक नीति को बताते समय इन्होंने परस्पर विरोधी बातें कहीं हैं। अभी इन्होंने कहा कि नेहरू जी की नीति को छोड़ दीजिए। क्योंकि ये नेहरू जी का विरोध करते हैं, यह कोई नई बात नहीं कही है। ये हमेशा नेहरू जी की अच्छी बात का विरोध करते हैं। आज एक नई बात कही कि महात्मा गांधी की नीति पर चलिए। जिस पार्टी के लोगों ने, कुछ सदस्यों ने, जिन लो ों के साथियों ने महात्मा गांधी की हत्या की…**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि इन लोगों को पता नहीं है कि जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई उस समय मैं उनके कुछ ही कदम पीछे था। इसलिए पीछे था क्योंकि उन दिनों मैं महात्मा गांधी के भाषणों को रिपोर्ट करके आल इण्डिया रेडियों द्वारा उन भाषणों को प्रसारित करवाता था। इसलिए मैं उनके पीछे था। मेरे सामने हत्या की गई · दोस्तो, आप लोगों को थोड़ा सा मानसिक चीज को समझना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मेरे पूर्व वक्ता वघेला जी ने कहा कि नेहरू जी की नीति पर चल कर देश खोखला हो गया, यह देश बर्बाद हो गया। दोस्तो, याद रखिए अगर नेहरू जी की नीति, उद्योग के सम्बन्ध में जो उन्होंने 1956 में बनाई थी, जिसमें मिश्रित औद्योगिक प्रणाली थी, जिसमें सामाजिक और निजी क्षेत्र दोनों का समावेश था, दोनों को अगर नेहरू जी नहीं रखते तो आज देश की परिस्थिति क्या होती। आप देखिए, जरा सोचिए पूर्वी यूरोप का क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ। यही एक देश है जिसने दुनियां को रास्ता दिखाया कि मिश्रित उद्योग चलाने से ही

देश की तरक्की हो सकती है। कुछ उद्योगों को सामाजिक क्षेत्र में लाना आवश्यक था, क्योंकि बुनियादी उद्योग भी है, कुच उद्योगों को बड़े-बड़े लोगों, करोड़पतियों के हाथों में नहीं दिया जा सकता। कुछ उद्योगों को निजी हाथों में देना था, निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि कम उद्योग हैं। इस क्षेत्र में भी बहुत से उद्योग हैं, बहुत से बड़े-बड़े उद्योग बड़ी-बड़ी इमारतें निजी हाथों में हैं, लेकिन थोड़े से उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा।

हम जानते हैं कि औद्योगिक नीति चाहे किसी तरह से हो, आपको सार्वजनिक उद्योग का विरोध करना ही है। आपकी पार्टी ने, जयपुर में आपका प्रस्ताव था कि पब्लिक सैक्टर में जितने उद्योग हैं उनको खत्म करना चाहिए। इसलिए मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक महीने में इन सब सार्वजनिक उद्योगों को खत्म कर दिया जाए, आॅक्शन कर दें। दोस्तो, हम ऐसा आॅक्शन करने वाले नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी हम चाहते हैं कि सुधार हो। इस औद्योगिक नीति में हमने साफ तौर से कहा है कि जहां हमारे पब्लिक सैक्टर में हानि हो रही है उसमें सुधार करेंगे, रिफार्म करेंगे, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तीन-चार चीजों को ध्यान में रखिए. पहला इस औद्योगिक नीतिगिक नीति का मुख्य उद्देश्य है कि हम आर्थिक स्थिति सुधारेंगे।

3.02 म०प०

[श्री शरद दिघे—पीठासीन हुए]

देश का उत्पादन बढ़ाने और सुधारने को आप देखने नहीं है, सुधारने को देखेंगे तो सुधरेगा। चालीस साल में देश बहुत सुधरा है। दूसरी बात यह है कि विदेशों को जो सामान भेजते हैं, उसके लिए तेजी से सामान भेजने का प्रयत्न करना है। हम नये लोगों को उद्योग में लाना चाहते हैं ! इस औद्योगिक नीति की बहुत बड़ी विशेषता है। आप दूरदर्शी नहीं हैं और समझ नहीं पाए। देश में आज युववों की बेरोजगारी बढ़ रही है।······(**व्यवधान**) बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसको दूर करने के लिए इस सरकार ने अति लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है जिसमें दो, तीन या चार लाख रुपया लग सकता है। नये-नये उद्यमी तैयार होते हैं। किसान या मजदूर के बेटे को न तो ट्रेनिंग है और न उसको मैनेजमेंट का मालूम है इसलिए अति लघु उद्योग चालू किया गया है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। हमारे पूर्व साथी ने कहा है कि हम उद्योग नीति में मौलिक चीज लाए हैं। वह आलोचना कोई नई बात नहीं है। लेकिन वही नीति 1956 की इंडस्ट्रीयल रेजोल्युशन की नीति है। उसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया है और इस बार भी जो हमारे देश की आवश्यकता है, उसके अनुकूल परिवर्तन किया गया है। आप स्वयं कह रहे थे कि हमारे देश में 1989 तक विदेशी मुद्रा की स्थिति लगभग छह हजार करोड से अधिक थी और 1991 तक लगभग 1500 करोड़ हो गई। आपने यह भी कहा कि गैर-कांग्रेस सरकार डेढ़ साल रही और उसने छह हजार करोड़ से ऊपर की रमक को लाकर के 1500 करोड़ कर दिया। पन्द्रह दिन के लिए बाहर से सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था इसलिए औद्योगिक नीति में

[श्री चन्दू लाल चन्द्राकर]

आवश्यक और क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया है।...(व्यवधान) हमारी सरकार ने पहली बार इस बात की कोशिश की कि विदेशी कम्पनियों को 51 परसेंट विदेशी पूंजी लगाने का शेयर दिया गया है। उसके पीछे यह नहीं है कि देश को किसी तरह से गिरवी रखना है और न आइ०एम०एफ०, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न वर्ल्ड बैंक और न किसी लॉबी के दवाव पर किया गया है 51 परसेंट इसलिए किया गया है ताकि विदेशी मुद्रा अधिक आ सके। सन् 1989 तक जब कांग्रेस सरकार थी तो हर साल लगभग विदेशी मुद्रा 389 करोड़ आती थी और अब 122-25 करोड़ हो गई है। विदेशी मुद्रा कम्पनियों के जरिये यहां पर पूंजी लगाने के लिए बहुत कम हो गया है इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए 51 परसेंट रखा गया है। केवल 51 परसेंट उनको शेयर का अधिकार देने से विदेशी पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आएगी। इसके लिए हमने बहुत से नियम बनाने हैं लेकिन उनको अमल करने में दिक्कतें होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह हैं कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी कम्पनी को जमीन देने के बारे में, बिजली देने के बारे में, पानी देने के बारे में या कस्टम आदि की सुविधाएं देने के बारे में देरी लगायेंगे या आनाकानी करेंगे तो वह कम्पनी या तो अपना उद्योग नहीं लगायेगी या कम पैसे लगायेगी। सिर्फ 51 प्रतिशत कर देने से विदेशी धन नहीं आएगा। उसके लिए पूरी मशीनरी को तैयार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में 51 प्रतिशत से कम है, वहां विदेशी पूंजी लगाने के जो शेयर हैं वे बहुत कम हैं, लेकिन पिछले साल 7.7 बिलियन अमेरिकन डालर्स की पूंजी वहां पर आई थी। उसी तरह से मलेशिया और थाईलैंड भी है जहां पर 5-6 बिलियन डालर्स की पूंजी आई थी। जब कोई बाहर से उद्योगपति धन लेकर आता है तब चाहता है कि सप्ताह के अन्दर-अन्दर उसे जमीन, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं मिल जायें। कुछ देशों में ऐसा होता है कि वहां बड़े-बड़े उद्योगपति आते हैं अपने उद्योग लगाने के लिए तो उनको वहां से टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है कि हमने इस उद्योगपति को दो-तीन दिन में सारी सुविधाएं दे दी हैं। इस तरह इस तरह का वातावरण अपने देश में हमें तैयार करना पड़ेगा।

इसलिए हमें सबसे पहले यह सोचना है कि हमारे देश में जो विदेशी पूंजी आये उसका ठीक से उपयोग हो। सरकार ने बताया है कि इन-इन उद्योगों में सरकार विदेशी पूंजी निवेश करने की अनुमति देगी। जो पहले लाइसेंस प्रणाली थी अब डी-लाइसेंस कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया है जिससे देश में अधिक-से-अधिक उद्योग पनपें और उनमें उत्पादन बढ़े और उसके साथ-साथ अधिक लोगों को काम मिले।

हमारे यहां पर्यटन विभाग है, हमारे देश में इसको अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी कम है। मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सिंगापुर की आबादी 26 लाख है, वह एक छोटा सा देश है। लेकिन वहां पर प्रतिवर्ष 47 लाख के करीब पर्यटक आते हैं, लगभग वहां की आबादी से दुगुने। जबकि हमारे यहां सालभर में 15 से 17 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। इसलिए कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए वातावरण बनाना होगा। यह बहुत आवश्यक है...

एक माननीय सदस्य : वातावरण तो आपने बिगाड़ दिया है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : 1977 और 1989 में आपने ही बिगाड़ा है। हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें काफी समस्याएं हैं। लेकिन तीन-चार समस्याएं बहुत गम्भीर रूप धारण कर रही हैं। एक तेजी से बढ़ती हुई आबादी, दूसरे तेजी से बढ़ती हुई बेकारी, तीसरे विदेशी मुद्रा की कमी और चौथे कृषि तथा अन्य उद्योगों का उत्पादन न बढ़ाना। इन चार चीजों को सही करने के लिए ही नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है।

सन् 2000 तक हमारी आबादी लगभग 100 करोड़ हो जाएगी। उसे एक तिहाई युवक होंगे। देश में 80 फीसदी युवकों की संख्या गांवों में है। इसलिए हमें चाहिए कि उनका दृष्टिकोण बदलें। उनको उद्योग में आने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके लिए आवश्यक है कि उनको काम करने की ट्रेनिंग दें, बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें। मानव संसाधन मंत्रालय के बजट में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है। यह बहुत बड़ी कमी है। इस बात की ओर हमें ध्यान देना होगा। श्रमिकों के हितों की रक्षा करना भी इस परिस्थिति में खासतौर से बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि हाई-टैक्नीक उद्योग आयेगा तो आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग देने के लिए आई०टी०आई० जैसी संस्थाएं हमारे देश के हर शहर, गांव, कस्बे में हों। इससे छोटे उद्योग गांव में जायेंगे और श्रमिकों को काम भी मिलेगा। यह बात जरूर है कि सरकार के पास साधनों और विदेशी मुद्रा में कमी है। इसके लिए सरकार ने अपनी नीति में जो किया है, हमारी पार्टी ने 10-12 चीजों पर दाम काफी कम करने की कोशिश की है और इसमें कोई शक नहीं कि चीजों पर दाम बढ़ा है।

सभापति महोदय, हम लोगों को अपने यहां रासायनिक खाद मंगाने में लगभग छः हजार करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर ही रासायनिक खाद के दाम बढ़ाए गये हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उत्पादन भी कम होगा, इसलिए हमारी सरकार को पुनर्विचार करके देखने की आवश्यकता है। यदि यह 30 परसेंट है, वह उसको काटकर साल में 20 परसेंट कर दिया जाए या जैसा भी हो, किसानो को यदि कोई आपत्ति या नाराजगी है तो उसे दूर करना चाहिए।

सभापति जी, आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में अमेरिका और यूरोप के देशों के किसानों को बहुत अधिक सबसिडी दी जाती है और यूरोप में तो एकनामिक कमेटी बनी है, वह बहुत अधिक आर्थिक सहायता देती है। अमेरिका की सरकार भी अपने किसानों को कितनी अधिक आर्थिक सहायता देती है, इस बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के किसानों पर जो यह थोड़ा सा बोझ बढ़ा है, उसको कम करना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक बात जरूर है कि हम एक तरफ तो रासायनिक खाद बनाने की, उसके उत्पादन की चिन्ता करते हैं लेकिन दूसरी ओर जो गोबर गैस है, उसमें कितना रासायनिक खाद बनता है। मैं बहुत अधिक आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यदि देश के हर 5 लाख 76 हजार गांवों में औसत 15 गोबर गैस लगा दिए जायें तो देश में 6 हजार करोड़ की रासायनिक खाद मंगानी पड़ती है, वह निश्चित रूप से···

एक माननीय सदस्य : देश में रासायनिक खाद बनने लगा है या कारखाना लगाना है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि रासायनिक खाद कारखानों में बनता है, उस कमी को दूर करने के लिए गोबर गैस से जो खाद बनाया जाता है, उस ओर सरकार ध्यान दे तो निसंदेह जो विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, वह कम होगी। दोस्तो, गोबर गैस हिन्दुस्तान से निकला है और चीन में गया···

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वार) : दोस्तों से क्या मतलब है ? चेयरमैन को एड्रेस कीजिए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैंने आपका संशोधन स्वीकार किया। सभापति महोदय, आज चीन में इतने अधिक गोबर गैस लगाए गये है कि वहां रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती है।

आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने बेरोजगार लोग हैं और खासकर हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा हैं। इसके साथ-साथ उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र और हमारे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बहुत ही गरीब क्षेत्र हैं इसलिए दुर्ग शहर में नए उद्यमियों को ट्रेनिंग देने के लिए और उद्योगों में बिजनैस मेनेजमेंट को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग केन्द्र खोले जाएं।

दूसरा, भिलाई क्षेत्र में चूंकि वह बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां लेदर और फुटवियर की बहुत अधिक बिक्री होती है जिन्हें दूसरे स्थानों से लाना पड़ता है। इसलिए लेदर और फुटवियर इंडस्ट्री भिलाई में खोल देने से वहां के लोगों को भी काम मिलेगा और बहुत सस्ते फुटवियर भी मिलेंगे। इसी तरह से दुर्ग जिले में पाटन क्षेत्र है जहां सोप और डिटरजेंट उद्योग खोला जा सकता है। धमधा क्षेत्र में कांसा और पीतल के बरतन के उद्योग खोले जा सकते हैं। वहां कुछ उद्योग हैं जो मर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने से उनको अधिक लाभ मिलेगा। साझा क्षेत्र में हौजरी और रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग खोला जा सकता है। बेमेतरा क्षेत्र में प्लास्टिक और प्रोसेसिंग उद्योग खोले जा सकते हैं। नवागढ़ क्षेत्र में हथकरघा उद्योग और शहद उद्योग खोला जा सकता है। खेरथा क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोली जा सकती है।

सभापति जी, दुर्ग में चार साल से बोरई क्षेत्र में ग्रोथ सेन्टर खोला गया है। लेकिन उसके लिए जिस तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, अभी कुछ उद्योग वहां खुलने लगे हैं लेकिन उनको आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़कें, टेलीफोन आदि भी नहीं मिल रही हैं। इसकी वजह से जो उद्योग लगाना भी चाहते हैं वह देर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पर जो उद्योग खुलें, उनमें स्थानीय लोगों को ही अधिक से अधिक काम मिले। टैक्निकल काम के लिए बाहर से लोग आते हैं लेकिन साधारण काम के लिए वहां पर काफी व्यक्ति मिल जाते हैं, इसलिए वहां पर ये जाएं।

सभापति जी, आपने देखा कि उद्योग लाइसेंस हटाने के बारे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, नई उद्योग नीति बनाई है, उससे देश को निस्संदेह बहुत लाभ होगा और अभी जो हमारे साथी, पहले के वक्ता बोल रहे थे उन्होंने नेहरू जी की उद्योग नीति के बारे में, बार-बार कहा कि नेहरू परिवार ने 40 साल तक जो यहां शासन किया, उस शासन में कोई भी प्रगति नहीं हुई। मैं समझता हूं कि ऐसा जो कह रहे हैं, वह स्वयं अपनी आत्मा से पूछें किस इन 40 सालों में कितनी प्रगति हुई है। देश में पांच लाख पचहत्तर हजार से अधिक गांव हैं जिनमें चार लाख से अधिक गांवों में बिजली जा चुकी है। लेकिन यह कहना कि औद्योगिक क्षेत्र में भी तरक्की नहीं हुई है और इसी देश में 40 साल में कितनी प्रगति हुई है, हमारे देश के आजाद होने के बाद लगभग 97 और दूसरे देश आजाद हुए हैं। आस पास के या दूर के देश को तथा उन 97 में से देख लीजिए। जितनी औद्योगिक और किसानी क्षेत्र में प्रगति हमारे यहां हुई है, दुनिया के किसी देश में नहीं हुई है। इसलिए हमारी सरकार की जो नीति है उसी के कारण से हम देख रहे हैं कि कभी देश में अकाल भी पड़ता है, तब भी हमें विदेशों से अनाज नहीं मंगाना पड़ता है। अगर यहां 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार नहीं आई होती तो हमारे देश में जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी, औद्योगिक प्रगति हो रही थी और खास तौर से कृषि प्रगति हो रही थी उसमें और बहुत तेजी से प्रगति होती, लेकिन इन लोगों ने इसमें बाधा डाली। हम सभी इसे जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को जो सब जगह टीम बनाकर काम कर रहे थे, कहां-कहां फेंका और हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति कई सालों के लिए ठप्प हो गई। उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद स्थिति सुधरी लेकिन काफी समय लगा। हमारे कई साथियों ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि खास तौर से इंदिरा जी के शासन के समय इंदिरा जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के जो काम किए हैं, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है ऐसी मिसाल आप दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे। हर क्षेत्र में उन्होंने किया। यहां तक कि उन्होंने और बाद में राजीव गांधी जी ने भी देश को स्वावलंबी बनाने में हर तरह का प्रयत्न किया। उन्होंने देश को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ एकता बनाए रखी। उसकी वजह से हमारा देश स्वावलंबी बना और मैं इससे ज्यादा न कहकर इतना ही कहता हूं कि हमारे देश की औद्योगिक नीति निस्संदेह प्रशंसनीय है और देश की आवश्यकता के अनुरूप है। इतना ही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : मैं अत्यधिक दुःखी मन से उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं, जो कि इस सभा में 24 जुलाई को घोषित नई औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प पर आधारित हैं।

स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि राज्य का यह ध्येय होगा कि समाज को सामाजिक पद्धति में स्थापित करके सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा था कि 1956 की औद्योगिक नीति सम्बन्धी

[श्री अजय मुखोपाध्याय]

संकल्प इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए तैयार किया गया था। संसद ने दि..म्बर, 1954 में इस औद्योगिक नीति-संकल्प का अनुमोदन किया था। वास्तव में इस देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन का भी यही सन्देश था। लेकिन हमें इस बारे में कोई भ्रम नहीं था। हमने यह कभी नहीं सोचा कि जिस नीति के तहत हमारे देश में सरकारी क्षेत्र को सामरिक भूमिका दी गई थी, वह वर्ग आधारित समाज को समतावादी में बदल सकेगी जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित होगा। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत उच्च स्तर प्राप्त सरकारी क्षेत्र पर जोर देना एक स्वागत योग्य कदम था और हमने इस नीति का समर्थन किया था क्योंकि इससे औद्योगिकरण का आधार तैयार हुआ और काफी हद तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली। इसके साथ ही हम कांग्रेस सरकार की लोक-विरोधी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध चार दशकों से आन्दोलन कर रहे हैं जो कि एकाधिकारवादियों तथा सामन्तवादी जमींदारों के हितों के लिए बनी थीं।

संकुचित वर्ग के नजरिए पर आधारित इस नीति से बहुत खतरनाक ढंग से, तेजी से धन एकत्र किया जा रहा है तथा आय में विसंगति भी हो रही है। आज देश के सामने जो अप्रत्याशित संकट खड़ा है वह इसी वर्ग नीति का अपरिहार्य परिणाम है। यह अपरिहार्य इसलिए है कि पूंजी-पतिवाद को सामन्तवाद के टुकड़ों पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी। अब वे इस संकट को, जिसने बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमा ली हैं और जो इस सरकार द्वारा पैदा की गई समस्या है, सुलझाने के नाम पर सब कुछ उलट-पलट कर रहे है। सार्वजनिक क्षेत्र कि नीतिगत भूमिका की महत्ता को कम दिखाकर, लगभग सभी उद्योगों का निजीकरण करके, अधिकतर उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस की प्रथा को समाप्त करके और विदेशी पूंजी को उनकी टेक्नोलोजी के साथ अन्धाधुन्ध आमन्त्रण देते हुए औद्योगिक नीति प्रस्ताव पिछली आत्म-निर्भरता की नीति के बिल्कुल उल्टे होने का प्रमाण है। यह पिछली नीति के एकदम प्रतिकूल है। क्या इसमें स्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है और अथवा यह परिवर्तन बदतर है? आपके नए दर्शन के आईने में हमें भाजपा का चेहरा दिखता है।

यह शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता के चवालिस वर्षों के पश्चात् भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवाद शक्तियों को अपनी मनमानी करने दी गई है। आपकी इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आगे घुटने नहीं टेके हैं। वास्तव में, नया औद्योगिक नीति प्रस्ताव, आपकी व्यापार नीति तथा वित्त नीतियों के साथ, तथाकथित भारतीय राष्ट्रवादियों और उस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बीच की अपवित्र सांठ-गांठ है, जो 'नए विश्व की व्यवस्था' को बनाने के नाम पर नव-उपनिवेशवाद की अपनी भूख को शान्त करना चाहती है।

आपके पास कम से कम झूठ को झूठ और सच को सच कहने का साहस और ईमानदारी होनी चाहिए थी। अतः नए औद्योगिक नीति प्रस्ताव की उद्घोषणा करने से पहले आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निदेशक सिद्धांतों को हटाने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत

करना चाहिए था। किन्तु आपमें यह साहस नहीं है। अतः मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव बड़े-बड़े वायदों और धर्म के विवाद के आवरण में धोखाधड़ी का एक दस्तानेज है।

इस संकल्प के अनुसार, लगभग सभी उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस की प्रथा को समाप्त किया जा रहा है, मैं उद्धत करता हूं :

"भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक, अधिक योग्य और आधुनिक बनने से फायदा होगा और औद्योगिक प्रगति के संसार में इसे अपना सही स्थान मिलेगा।"

संकल्प में आगे कहा गया है :

"उद्यमी अपने व्यावसायिक निर्णयन के आधार पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लेंगे।"

कितनी अजीब बात है। यह बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार पूंजीपति, जिनका एकमात्र उद्देश्य फायदा और केवल फायदा है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर निर्णय ले सकते हैं। यहां तक कि प्रगतिशील पूंजीपति देश जैसे जापान और जर्मनी में भी किसी न किसी प्रकार का ऐसा हस्तक्षेप मौजूद है, जिससे कि उन देशों में उद्योग स्थापित करने को इच्छुक पूंजीपतियों को उद्योगों की प्राथमिकताओं और जीवन-क्षमताओं सम्बन्धी सुझाव दिए जा सकें।

देश में सरकारी स्तर पर इस प्रकार के किसी तंत्र की अनुपस्थिति से पूर्णरूपेण अराजकता फैलने की आशंका है। इससे क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ेगा तथा इससे अलगाववादी तथा अन्य पृथक्क-वादी शक्तियों को और अधिक बल मिलेगा। किन्तु फिर भी इस नये औद्योगिक नीति संकल्प से हमें यह आश्वासन मिलता है कि राष्ट्रीय हितों की किसी भी प्रकार अनदेखी नहीं की जाएगी।

महोदय, 'फेरा' विनियमों का पालन नहीं हो रहा है। अधिक प्राथमिकता वाले 34 उद्योगों में विदेशी इक्विटी भागीदारी को बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि वे विदेशी निवेशकर्ता, विशेषतया बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलौजी के के साथ इन संस्थाओं और उद्योगों की वास्तविक मालिक बन जायेंगे। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियो की की अनियन्त्रित स्वतन्त्रता से भारतीय उद्योगों के विकास को अवश्य ही भारी चुनौती मिलेगी और वे उपनिवेशी पूंजीवाद के सहायक उद्योग हो जाएंगे और भारतीय जनता नव-उपनिवेशवाद के शोषण की निरीह शिकार हो जायेंगी। क्या आप इसका खण्डन कर सकते हैं?

इसमें दो राय नहीं है कि मुख्य क्षेत्रों में, जिनमें आधुनिकीकरण आवश्यक है, टेक्नोलौजी के आयात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोई भी इससे असहमत नहीं है। किन्तु कोई प्रथमिकता दिए बिना ही विदेशी टेक्नोलॉजी के अनियन्त्रित रूप से देश में आने से, जैसा कि नीति प्रस्ताव में सोचा गया है देशी टेक्नोलॉजी एक असमान और अहितकारी प्रतिस्पर्द्धा में फंस जाएगी और इससे देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में पहल करना हतोत्साहित हो जाएगा। यह बात भी स्मरणीय है कि तृतीय बिश्व के देशों में विदेशी निवेशकर्ता अत्याधुनिक टेक्नोलाजी नहीं लाते

[श्री अजय मुखोपाध्याय]

हैं। वे सामान्यतया तृतीय विश्व के देशों को बेकार की और पुरानी टेक्नोलॉजी भेजते हैं। भारत को उन बेकार की टेक्नोलॉजियों को जमा करने का एक गोदाम नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

इस बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रौद्योगिकी सम्बन्धी इस क्रांति के फायदों का सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखे बिना अन्धाधुन्ध प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक विशेष टेक्नोलॉजी जो किसी एक राष्ट्र विशेष के लिए फायदेमंद तथा मददगार है वह सम्भवतः किसी अन्य देश में अन्य आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसे नहीं भूला जाना चाहिए।

श्री विलास मुत्तेमवार : आपकी टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र के लिए है ? (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : खिलौनों के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी हैं। क्या यह आपको पसन्द है—धनी वर्ग के लिए खिलौने ? (**व्यवधान**) आप जानते हैं कि आपने वे खिलौने बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का आयात किया है, जो देश की केवल एक प्रतिशत जनसंख्या द्वारा खरीदे जाते हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप इन सभी बातों को छोड़िए। आप पीठासीन महोदय को सम्बोधित करें और जारी रखें।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस आंखों देखे हाल की उपेक्षा कीजिए और पीठासीन महोदय को सम्बोधित करें।

(**व्यवधान**)

श्री अजय मुखोपाध्याय : टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक सूझ-बूझ की आवश्यकता हैं, अन्यथा, देश का औद्योगिक विकास धीरे-धीरे विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएगा जो खतरनाक है।

नया औद्योगिक नीति प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध भारी दुष्प्रचार करने वाला है और यह कोशिश की जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार-क्षेत्र को उद्योग के आठ वर्गों तक सीमित किया जाये। सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित सूचि में दो सबसे प्रभावशाली उद्योगों, इस्पात और ऊर्जा जो सर्वदा से ही केन्द्र क्षेत्र माने गए हैं, को शामिल नहीं किया गया है। अब, ऐसा स्पष्ट इशारा दिया गया है कि इन दो मुख्य क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को शत-प्रतिशत लगाया जाएगा। इस्पात, भारी अभियान्त्रिकी, ऊर्जा संयंत्र और ऐसे अन्य क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय पूंजी के आगमन से बी०एच०ई०एल०, एच० ई० सी, एच०एम०टी०, इत्यादि का अन्त सन्निकट है। इस प्रस्ताव के अनुसार, "विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले उद्योगों पर किसी क्षेत्र विशेष होने सम्बन्धी कोई रोक नहीं होगी।" अतः यह बिलकुल स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र को तोड़ना ही मुख्य उद्देश्य है। किन्तु किस लिए ? औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कई दोष पाए गए हैं, किन्तु इन दोषों का निदान बहुत ही आसान है। रोगी की हत्या कर दो और उसके रोगों का निदान करने

हेतु कोई गम्भीर प्रयास मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कारण स्पष्ट है। विदेश बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय एकाधिपतियों द्वारा प्रभुसत्ता की शक्ति पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सार्वजनिक क्षेत्र है। अत:, निजीकरण अत्यवश्यक है। किन्तु क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन दोषों के लिव उत्तरदायी कौन है, जिनका आपने उल्लेख किया है? क्या इस तथाकथित क्षय के लिए गलत और अवैज्ञानिक नीति, अयोग्य तरीके से कार्य करना और नौकरशाही का हस्तक्षेप तथा केन्द्रीय सरकार का दवाव उत्तरदायी नहीं है? **(व्यवधान)** किन्तु, महोदय, यह दुःख की बात है कि स्वयं को सुधारने के स्थान पर आपने सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करना ही उचित समझा। क्या बढ़िया विचार है। निवेश न करने की योजना द्वारा सरकार न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण औद्योगिक एककों को अपितु लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का भी निजीकरण करना चाहती है। पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध विपरीत जनमत जगाने लिए एक पूर्ण रूप से तैयार किया गया सुविचारित प्रचार अभियान चल रहा है। क्या आप इसका खण्डन कर सकते है? यहां तक कि तेल ओर प्राकृतिक गैस आयोग, जो सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, को भी बख्शा नहीं गया है। हांलाकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले इसके विपरीत कहा था। ऐसे स्पष्ट संकेत हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को भी निजी क्षेत्र में लाने का कार्यक्रम है। **(व्यवधान)** किन्तु निजीकरण इसका इलाज नही है। रूग्णता केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। निजी निजी क्षेत्र में भी यह कम नहीं है, अपितु इससे अधिक ही है। क्या कोई इस बात का खण्डन कर सकता है कि निजी क्षेत्र की तथाकथित खुशहाली सार्वजनिक क्षेत्र की कोमत पर है? कोई भी इसका खण्डन नहीं कर सकता। निजी क्षेत्र में, विशेषतया बड़े और मध्ययम उद्योगों में मुख्यतया सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश किया गया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिबन्धित नहीं किया है। हम निजी क्षेत्र को आठ क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह वार्ता नहीं है। वह भाषण दे रहे हैं और मंत्री महोदय जवाब देंगे। जब आपकी बारी आए, तब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय : आपने सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र उद्योग बनाने की बात की है, आपकी नीति में ऐसा उल्लिखित है। **(व्यवधान)** निजी क्षेत्र के लोगों ने सार्वजनिक धन का हजारों करोड़ रुपया, अपने आपको समृद्ध करने के लिए, अपव्यय किया है। इस सम्बन्ध में अनेकों तथ्य और आंकड़े हैं। यह आंकड़े और तथ्य मेरे पास है। किन्तु मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता।

अब सरकार द्वारा एम० आर० टी० पी० अधिनयम को भी बदलने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि निजी उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में एंटर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यह पालिसी है, लेकिन विभाग की जो पुस्तिका है, इसके कुछ अंश मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मंत्री के इंटरवेशन में तथा उद्योग विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में आपस में विरोधाभास है। अतः माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि सही कौन है ? (**व्यवधान**)

श्री कालका दास (करोल बाग) : सभापति जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ये अपनी पालिसी के विरोध में बात कर रहे हैं। आप इनको सुन ही नहीं रहे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। यदि इसमें कोई असंगति है तो वह चर्चा के दौरान उत्तर देंगे। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। कृपया अपनी बात जारी रखें, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब, कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए। आप अपनी बात जारी रखें।

*(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप, कृपया बैठ जाईये। कृपया आपना भाषण जारी रखें।

श्री कालका दास : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात बाद में अपने भाषण में कह सकते हैं। हम यहां कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं अपितु इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : चूंकि माननीय मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट अवश्य करें।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आपको, माननीय मंत्री जी को बीच में बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं नीति के संगत हिस्से को पढ़ देता हूं।

सभापति महोदय : मानीय मंत्री जी बहस का उत्तर देने में सक्षम हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं स्पष्ट कर रहा हूं। एक मिनट आप मुझे दीजिए। मैंने यह कहा है, कि नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आठ मदें आरक्षित की हैं। वे अन्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही हैं। आप कृपया नीति को पढ़िएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आठ मदें रखी गई हैं और उनमें निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दी जाएगी।

यही मैंने कहा है।

दूसरे, इस नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे किसी अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश करने के लिए स्वतन्त्र है जिसका संचालन निजी क्षेत्र कर रहा है। मैं इसको दौहरा देता हूं। मैंने नीति पढ़ ली है; आपने नीति को नहीं पढ़ा है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अजय मुखोपाध्याय : आपने जो कहा है, वह सही नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जो कुछ मैंने कहा है, वह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित है।

श्री अजय मुखोपाध्याय : आपके नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में से उस हिस्से को मैं पढ़ देता हूं : मैं उद्धृत करता हूं :

"सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्रों में चुनिंदा आधार पर क्षेत्र निजी क्षेत्र का प्रवेश वर्जित नहीं होगा।"

इसका क्या अर्थ हुआ। ऐसा आपके नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में उल्लिखित है। मैं आपकी नीति के उद्धरण दे रहा हूं। यह मेरा कथन नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुख्य भाग इससे संगत नहीं है। यह केवल अनुबन्धों से सम्बन्धित है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अनुबन्धों को पढ़िएगा। इसके बारे में भी वहां हमने कहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या इसका अभिप्राय: यह है कि माननीय मंत्री महोदय औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में दिए गये अनुबन्ध के अतिरिक्त शेष सभी भागों को वापिस ले रहे हैं। नहीं, मंत्री महोदय को यह अधिकार है कि वे नीति सम्बन्धी संकल्प उद्धरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं उद्धृत करता हूं :

"सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्रों में चुनिंदा आधार पर निजी क्षेत्र का प्रवेश वर्जित नहीं होगा।"

इसका क्या अर्थ है ? (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। मंत्री महोदय आगे कुछ कहने से पहले अवश्य स्पष्ट करें। नीति की उद्घोषणा से लेकर, इस परिचर्चा के शुरू होने तक क्या सरकार ने अपनी इस नीति में कोई परिवर्तन किया है ? हम इसकी स्थिति जानना चाहेंगे। क्या सरकार ने तब से लेकर अपनी इस नीति में कोई परिवर्तन किया है ? (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : औद्योगिक नीति में एक बात कही गई है और अब मंत्री महोदय किसी दूसरी बात का जिक्र कर रहे हैं।

इसका क्या अर्थ है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अगर क्लेरीफाईन नहीं होगा तो डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी। (**व्यवधान**)

श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या आप अपने वक्तव्य से वह हिस्सा निकाल रहे हैं जिसका मैंने अभी-अभी हवाला दिया है ? (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से टेलीफोन पर बातचीत करने के पश्चात् इसका उत्तर देगें। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : मंत्री महोदय, इस विषय में अब क्या दृष्टिकोण अपना रहे हैं ? क्या आप इस भाग को निकाल रहें है ? अब क्या चर्चा का विषय है बिना किसी उचित उत्तर के हम चर्चा को कैसे जारी रख सकेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री जी, अन्त में, इसका उत्तर देंगे।

(**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : माननीय सदस्य द्वारा एक महत्वपूर्ण मामला मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया है। इसको लेकर लोगों के मन मे कुछ भ्रम है। इन्हें स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखने दें।

(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : वे कैसे जारी रख सकते हैं। पहले मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : सभापति जी, कृपया सभा की बैठक स्थगित कर दीजिएगा। ये तैयारी करके आयें। कृपया तब तक सभा की बैठक स्थगित कर दीजिएगा।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : माननीय सदस्य की भावना को समझिए। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : बिना किसी स्पष्टीकरण के चर्चा को जारी रखने का क्या औचित्य है ?

श्री अनिल बसु : हम यह जानना चाहेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वे कुछ नहीं बोल रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइये। उनका व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इनका व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूं। कृपया बैठ जाइयेगा।

श्री श्रीकांत जेना : मैं आपके ध्यान में केवल एक महत्वपूर्ण तथ्य लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जहां तक औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है, हम सरकार के नीति विषयक निर्णय से अवगत हो चुके है। अभी-अभी मंत्री जी ने बताया है कि स्थिति यह है। परन्तु वास्तव में औद्योगिक नीति के अनुसार स्थिति ऐसी नहीं है। हम औद्योगिक नीति तथा उद्योग मंत्रालय को अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। हम यह समझ रहे हैं कि औद्योगिक नीति में जो भी उल्लेख किया गया है। सरकार की वही नीति है। परन्तु अब मंत्री जी भिन्न स्थिति बता रहे हैं। हमारी स्थिति क्या होगी ? हमें किस दिशा में चलना चाहिए ? क्या हमें औद्योगिक नीति अथवा मंत्री जी के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हम औद्योगिक नीति को उद्धत करेंगे तथा मंत्री के वक्तव्य को गलत ढंग से उद्धृत करें ?···(**व्यवधान**)···आपके हस्तक्षेप करने से कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं।

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हम ठीक से चर्चा नहीं कर पाएंगे।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। वह काफी अच्छा भाषण दे रहे हैं। उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें। अन्त में, मंत्री जी उत्तर देंगे।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री द्वारा बिना व्यवधान डाले हुए सदस्य महोदय को अपना भाषण जारी रखने दें। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपको औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी मिल गई है। आपने मंत्री जी के हस्तक्षेप को भी देख लिया है। आप उनके हस्तक्षेप का अर्थ अपने अनुसार लगा सकते हैं। आप उसके अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री कालका दास : क्लेरीफिकेशन देने की बजाय हाऊस को मिस-लीड किया है। मिनिस्टर के इंटरवेन्शन से ही झगड़ा हुआ है।···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) **:** वे इस समय हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ? सभा को इस मुद्दे पर चर्चा करने दीजिए। औद्योगिक नीति एक ऐसा दस्तावेज है जो हर एक के लिए उपलब्ध है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है। मैं उस पर स्पष्टीकरण दूंगा। परन्तु जिस समय मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, कुछ सदस्यों को कुछ संदेह थे तथा उन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। उतना ही पर्याप्त है। अब माननीय सदस्य को अपनी बात जारी रखने दें।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : मैं जानना चाहूंगा कि उनका वक्तव्य सही है अथवा औद्योगिक नीति सही है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उस सम्बन्ध में वह अन्त में वह स्पष्टीकरण देंगे।

(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं दोहराना चाहूंगा कि इसका कोई प्रतिवाद नहीं है। मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आठ मदें आरक्षित हैं तथा सरकार की नीति उसमें किसी भी निजी क्षेत्र को प्रवेश न करने देने की है। **(व्यवधान)**

श्री अजय मुखोपाध्याय : अपने वक्तव्य के उस भाग को क्या आप पढ़ेंगे ? **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अन्त में आपको कई स्पष्टीकरण दूंगा। मैं दोहरा रहा हूं कि आठ मदों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है तथा सरकार की नीति उसमें निजी क्षेत्र को प्रवेश न करने देने की है। **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : नीति में क्या कहा गया है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप जो कह रहे हैं वह मैं जानता हूं। आप यह कह रहे हैं कि "यदि सरकार चाहती है तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है।" हां, यह ठीक है। यदि सरकार चाहती है, तो हम इसकी घोषणा करेंगे। पूर्व नीति में भी ठीक यही स्थिति थी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। नीति के अनुसार जब यह लागू हो, जब तक सरकार विशेष रूप से इसकी अनुमति न दे निजी क्षेत्र आठ क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। वह एक अलग बात है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह इसके विपरीत है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : नहीं, यह विपरीत नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रो० कुरियन मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे उनकी नीति में विश्वास नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अजय मुखोपाध्याय : सभापति महोदय, नीति संकल्प में यह लिखा हुआ है कि विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने वाले क्षेत्रों के लिए चुनींदा रूप से कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी समय आप इसे निजी क्षेत्र के लिए खोल सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में भी ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया था ? आप क्या कह रहे हैं ? सभा को भ्रमित करने का प्रयत्न मत कीजिए। **(व्यवधान)**

श्री अजय मुखोपाध्याय : अब सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की परिसम्पत्ति सीमा को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव लेकर आई है। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि जिस प्रावधान का नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया है उसे बिना किसी संशोधनकारी विधेयक जो हमारे समक्ष नहीं हैं उनको लाए बिना इसे लागू किया जा सकता था। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए इन दो विधेयकों को लाना आवश्यक है। उन विधेयकों को सभा के समक्ष नहीं रखा गया है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम

में परिसम्पत्ति सीमा को समाप्त करने से निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर पूंजी के एकाधिकार की पकड़ और अधिक मजबूत होगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थिति काफी खराब हो जाएगी तथा अन्त में उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाएगी।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात पूरी कीजिए चूंकि समय समाप्त हो गया है। यदि आपको तीस मिनट का समय दिया गया है और आपने चालीस मिनट ले लिए हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, परन्तु मंत्री जी ने मुझे उत्तर देने में बीस मिनट ले लिए हैं।

मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में रोजगार की सम्भावना सर्वाधिक हैं तथा आर्थिक सर्वेक्षण 1991-92 से यह पता लगता है कि वर्ष 1989-90 में इस क्षेत्र में रोजगार क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत थी वृद्धि हुई थी जबकि बड़े निजी क्षेत्र के उद्योगों में केवल 0.4 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। निर्यात के क्षेत्र में वर्ष 1989-90 में लघु उद्योग क्षेत्र ने 7,626 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की जो कि उस वर्ष की कुल निर्यात आय का एक चौथाई है। इस समय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है।

भारतीय और विदेशी एकाधिकारी उस अखाड़े में आक्रमण के लिए स्वतन्त्र होंगे। इसके परिणामों की सहज ही कल्पना की जा सकती है।

4.07 म० प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

इन उपायों का परिणाम देश के लिए घातक होगा। 2.4 लाख से अधिक सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयां, इसका शिकार होने जा रही हैं जिससे इन उपक्रमों में काम कर रहे लाखों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इस उदार औद्योगिक नीति और व्यापारिक व वित्तीय नीतियों के परिणाम स्वरूप भारी संख्या में कामगर और कर्मचारियों उनके परिवारों सहित बेकार हो जाएंगे। जहां तक मुझे पता है, लगभग 100 केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अनावश्यक हो गए है जिनके कारण भारी संख्या में कर्मचारी फालतू हो गए हैं। उनका भाग्य क्या होगा ?

महोदया, यह समझा गया है कि कपड़ा मंत्री पटसन से बने बोरों के मामले में दिए जा रहे सहायता उपायों को 1 अप्रैल 1992 से वापस लेने का पहले से ही निर्णय ले चुके हैं। पटसन उद्योग और श्रमिकों के लिए भी यह और भी घातक होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार अभी और भी कई कदम उठाए जाने हैं। इसके स्वाभाविक परिणाम होंगे कि इससे अधिक रूग्णता, अधिक तालाबंदी, अधिक बेरोजगारी और अधिक दुर्दशा होगी। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि "इससे प्रभावित होने वाले श्रमिकों के हितों

[श्री अजय मुखोपाध्याय]

की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया बनाई जायेगी। यह मात्र लोगों में उत्तेजन पैदा करने की बात है। आपको सदन को बताना होगा कि यह प्रक्रिया क्या है? मेरा आपसे अनुरोध है कि खून-पसीना बहाने वालों के साथ धोखा करने की कोशिश न की जाए। बल्कि इनके अनयक श्रम और असीमित बलिदान के बिना, उत्पादन व धन में वृद्धि, जिसकी प्रायः आप बात करते हैं अर्जित नहीं की जा सकती थी। इसलिए, उन्हें धोखा देने का प्रयास न कीजिए।

तबाही की यह प्रक्रिया, कीमतों में तीव्रता से वृद्धि के कारण पहले से ही बड़े पैमाने पर प्रारम्भ हो चुकी है। आपने हमारे आरक्षित सोने को गुप्त ढंग से गिरवी रखने की शुरूआत की और अब आप बाजार में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने निकल पड़े हैं। यह सच है या नहीं, प्रेस में प्रकाशित हुआ है कि हल्दिया फर्टिलाइजर कम्पनी केवल एक करोड़ रुपये में बिकने जा रही है। यह एक खोफनायक बात है। मशीनरी, भवन, भूमि आदि सभी चीजों को छोड़कर वहां रखा केवल फर्नीचर ही एक करोड़ रुपये से अधिक राशि का होगा।

मैं यह जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचने का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के पास कहां से आ गया? क्या ऐसा कोई कानून है? यदि ऐसा है, तो कानून कहां है? यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय द्वारा कुछ कुर्सियां, मेजें, पंखे आदि बेचे जाने हो तो भी कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अति भयावह स्थिति है।

सरकार ने बड़ी चालाकी से विवशता का विचार दौड़ाया है। वह हमसे और देशवासियों से यह चाहती है कि इस सब को स्वीकार कर लिया जाए चूंकि अन्य कोई सहज विकल्प नहीं है। परन्तु वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के लोगों को छोड़कर, आपने और किसी से सलाह नहीं ली। औद्योगिक जगत के मामलों से सुपरिचित ट्रेड यूनियनों से भी परामर्श नहीं लिया गया। इस प्रस्ताव को तैयार करने से पूर्व आपने इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी इस बारे में चर्चा नहीं की। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समर्थक नौकरशाही की मंत्रणा ही इस बारे में अन्तिम बात नहीं हो सकती।

छंटनी और तालाबंदी को रोकना, पूंजी का नियंत्रण, औद्योगिक इकाईयों को रुग्ण बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करना और प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ऐसे कुछ उपाय है जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना है। और यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त ऋण के साथ इन इकाईयों का श्रमिकों को सोंपना, पूंजीगत सामान के अन्धाधुंध आयात पर रोक, विलासता के प्रसाधनों की उत्पादन प्रौद्योगिकी व ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनका आधुनिकरण किया जाना अनिवार्य है—की प्रौद्योगिकी के निर्यात को बढ़ावा देना आदि पर भी तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इस सबसे बढ़कर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण पर

रोक लगाना, और सभी आधारभूत उद्योगों को, उनमें निहित अकार्यकुशलता व नौकरशाही प्रबन्ध के असली कारणों को दूर करने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखने की तरफ भी तत्काल ध्यान किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ अभी भी समय है कि उत्तेजना में विदेशी बाजार के प्रयासों की बजाए अपने आन्तरिक बाजार के विस्तार हेतु शीघ्र ही कदम उठा लिए जाएं। शहरी और ग्रामीण लोगों की बहु-आयामी क्रय-शक्ति को बढ़ाकर, लघु व कुटीर उद्योगों के उत्थान को बाधक सभी कठिनाइयों को दूर कर रोजगार गारन्टी योजना आदि और इन सबसे बढ़कर मौजूदा हदबंदी कानून की खामियों को दूर करके प्रभावकारी भूमि सुधार लागू करके और अधिकतम सीमा से ज्यादा व अन्य अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करके ऐसा किया जा सकता है।

परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि आप हर बार भूमि सुधार के मामले को बड़ी सावधानी से टालते आ रहे हैं। आपके नीति संबंधी प्रस्ताव में, बजट में अथवा अन्यत्र कहीं भी इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। परन्तु वर्तमान संकट से उबरने, और हमारे देश की औद्योगिक व सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने का यही एक मात्र रास्ता है। आप इस बात को जहन में रखिएगा कि आपके भरसक प्रयासों के बावजूद भी उन्नत पूंजीवादी देश सही मायनों में भारत को अपने बाजार में प्रवेश नहीं करने देंगे।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप नहीं रुकते और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिखाये गये रास्ते से नहीं हटते और हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता से समझौता करते हैं, तो हमारी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का साम्राज्यवाद—विरोधी पहलू लुप्त हो जाएगा। आज की दुनिया का सबक और अनुभव यही है कि यदि आर्थिक प्रभुसत्ता चली जाती है तो राजनीतिक प्रभुसत्ता संकट रहित नहीं रहती। उस अवस्था में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान्यतः इस देश के देश भक्त लोग और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग चुपचाप नहीं बैठेगा। इन शब्दों के साथ, मैं नई औद्योगिक नीति के प्रस्ताव और अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) · सभापति महोदया, मैं वर्ष 1991-92 के लिए उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं दो पूर्व वक्ताओं के भाषण सुन रहा था—इनमें से एक वक्ता भा०ज०पा० के और दूसरे वक्ता वाममोर्चा के। यहां दो अतिवादी बिचार व्यक्त किए गए हैं। किन्तु एक क्षेत्र है जहां दोनों सहमत हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके कुछ विशिष्ट शब्द हैं—नेहरू-समाजवाद, नेहरू परिवार, पिछले चालीस वर्षों का गांधी प्रभुत्व का शासन। सिर्फ इस एक मुद्दे को छोड़कर उनमें दोनों में अन्य सभी मामलों और नीतियों में मतभेद है।

पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय इन कुछेक विशिष्ट शब्दों के बारे में कहना बहुत आसान है। ये सिर्फ विशिष्ट शब्दावली है और कोई नहीं जानता कि वे क्या हैं। एक विधि के प्रोफेसर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तभी सामाजिक न्याय का प्रश्न सामने आया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की विद्वान प्रोफेसर सालमण्ड ने इस प्रकार व्याख्या की है—न्याय एक शत्रु से घिरे हुए शहर में भोजन की भांति है जिसमें एक बराबर

[श्री ए० चार्ल्स]

वितरण अनिवार्य है। विद्वान प्रोफेसर के अनुसार यह वास्तविक न्याय है। किन्तु विद्यार्थियों को जो प्रोफेसर पढ़ा रहा था उसने कहा यह सच्चा न्याय नहीं है। उस प्रोफेसर के अनुसार, न्याय एक नित्य धारा की भांति होना चाहिए, ताकि जो भी उसमें से अपना भाग लेना चाहे, ले सके।

मैंने यह उदाहरण सिर्फ सामाजिक न्याय पर विभिन्न विचारों को बताने के लिए दिया है। अतः ऐसे शब्दों पर हम सभी एकमत कैसे हो सकते हैं।

मैं अपने मित्र श्री अजय मुखोपाध्याय की बात को ध्यान से सुन रहा था। उनकी शिकायत थी कि हम अब भाजपा का मार्ग अपना रहे हैं और अब हम दक्षिण पंथ की ओर बढ़ रहे हैं। मैं माननीय मित्र से पूछना चाहता हूं कि आठवीं लोकसभा के दौरान भाजपा के सिर्फ दो सदस्य थे। मैं वाममोर्चा के माननीय सदस्यों के साथ उनके हृदय टटोलने के लिए उनका समर्थन करूंगा। उनकी शक्ति वर्तमान संख्या तक कैसे पहुंच गई? किन्तु हमें निर्णय को मानना होगा क्योंकि यह जानता का निर्णय है। किन्तु हमें दोष न दें कि आज देश में जो त्रीसदी चल रही है उसके लिए हमीं दोषी हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत में जो प्रगति हुई है वह स्वतन्त्रता के बाद ही हुई है और यह पिछले 40 वर्षों के दौरान कांग्रेस दल के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। देश 1947 में स्वतन्त्र हुआ। उस समय देश में हम एक पिन का भी निर्माण नहीं कर सकते थे। अब विश्व के औद्योगिक क्षेत्र हमारा स्थान है।

यह सत्य है कि हमारी भी समस्याएं है। हमारी समस्याएं अलग-अलग किस्म की है। एक वक्ता गरीबी रेखा के बारे में बोल रहे थे। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि गरीबी रेखा ऊंची उठ गई है। यह पुरानी गरीबी रेखा नहीं है। 1947 में हम लोग 34 करोड़ थे। अब हम 90 करोड़ होने जा रहे हैं। पिछले 40 वर्षों में हमने 50 करोड़ अतिरिक्त लोगों को भोजन दिया। परिवार नियोजन में हम असफल रहे हैं। यह सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। हमें जनता को शिक्षित करना है।

मेरे पास सीमित समय है। अतः मैं सिर्फ औद्योगिक नीति और कार्यक्रम तक ही स्वयं को सीमित करने का प्रयास कर रहा हूं। भाजपा के एक वक्ता अभी बता रहे थे कि पिछले एक वर्ष में कुछ नहीं हुआ और सारा उद्योग असफल रहा है। मैं उनका ध्यान उद्योग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 5 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं—

> "सातवीं योजना की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन हुआ है। केन्द्रीय सांख्यिकी संघ द्वारा तैयार किए गए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के आधार पर सातवीं योजना की अवधि के दौरान औसतन वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान, आंकड़े दिसम्बर, 1990 तक ही उपलब्ध हैं। 1989-90 में इसी अवधि में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।"

हांलाकि अब औद्योगिक नीति में काफी परिवर्तन किए गए हैं, फिर भी औद्योगिक नीति

संकल्प, 1956 अभी भी हमारी औद्योगिक नीति का आधार है। अनुभव से सीखें तो पिछले तीन दशकों में हमने समय की आवश्यकतानुसार कई बार अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है। श्री राजीव गांधी के शासन के दौरान 1985-86 में महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन किए गए। उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन अब तक की सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचा। सातवीं योजना की अवधि के दौरान यह लगभग 8.5 प्रतिशत है।

आज देश को एक गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट से उभरने और गरीबी और बेरोजगारी इन दोनों जुड़वा समस्याओं का समाधान करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने देश को विश्व बाजार में खड़ा करें और विश्व अर्थव्यवस्था के एक अंग के रूप में इसको विकसित होने दें। वर्तमान संकल्प में भी इसी की कल्पना की गई है। महोदया, यदि हम इस पृष्ठभूमि में स्थिति को देखें। तो इस नीति के आलोचक भी यह मानेंगे कि नए औद्योगिक नीति संकल्प में जिन परिवर्तनों की अवधारणा की गई है वह प्रगति की ओर और सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

महोदया, इस क्षेत्र में जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं (i) कम नियंत्रण (ii) सरकारी खर्च में कमी (iii) मुद्रा स्फीति में कमी और (iv) गरीबों के लिए रोजगार के अधिक अवसर और गरीबों व अन्य कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यदि हम नए औद्योगिक नीति संकल्प और उसमें निहित परिवर्तनों को ईमानदारी से से लागू करें तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हो सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की काफी आलोचना हुई है। महोदया, मैं भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य से प्रसन्न नहीं हूं। वर्तमान नीति संकल्प के अनुच्छेद 12 से मैं उद्धृत करता हूं :—

> "परिणाम यह हुआ कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान सरकार को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा उस पर भारी बोझ बन गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की मौलिक अवधारणा भी काफी हद तक समाप्त हो गई हैं। सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि निजी क्षेत्रों से रुग्णा इकाइयों का अधिग्रहण। सार्वजनिक क्षेत्र की यह वर्ग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कुल घाटे के लगभग एक तिहाई घाटे का कारण है।"

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण में थोड़े से परिवर्तन पर अभी शंका प्रकट की गई है, क्या वे रुग्ण इकाईयों के अधिग्रहण और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में चालू रखने के पक्ष में हैं अथवा नहीं, जिससे राजकीय कोष को करोड़ों रुपए का घाटा होता है जो हमारे देश के करोड़ों लोगों की पसीने की कमाई है। मेरे एक मित्र ने आधुनिकीकरण का समर्थन किया है। महोदया, आपके द्वारा मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान अपने उस अनुभव की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जबकि मैं एक संसदीय समिति के साथ कलकत्ता गया था। हमने वहां अनेक कपड़ा मिलों का दौरा किया। जहां तक मुझे स्मरण है, सिर्फ सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान ही कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर लगभग 7500 करोड़ रुपए खर्च किए

[श्री ए० चार्ल्स]

गए थे। मेरा विनम्र निवेदन हैं कि यह सारा पैसा व्यर्थ खर्च किया गया है क्योंकि कपड़ा मिलों की रुग्णता और उसके कारणों का उचित रूप से पता ही नहीं लगाया गया। उनकी रुग्णता के अनेक कारण थे। आधुनिकीकरण भी आवश्यक है। इन सभी कारणों को जान बिना, और अन्य समस्याओं का समाधान किए बिना, आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जब भी आधुनिकीकरण होता है तो अतिरिक्त स्टाफ की समस्या सामने आती है। अतः नीति की आलोचना करने में हमें सावधानी बरतनी होगी। मैं भी अनुभव करता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य संतोषजनक नहीं है। उनकी रिपोर्ट के पृष्ठ 7 पर एक अत्यन्त चेतावनी पूर्ण दृश्य का चित्रण किया गया है। 189 प्रतिष्ठान, जिनके बारे में अस्थाई आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन्हें 2730 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। महोदया, 234 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं और उनकी रिपोर्ट के अनुसार, 1990-91 के लिए सिर्फ जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ये आंकड़े भी अस्थायी है। यह शायद आडिट रिपोर्ट में विलम्ब के कारण हो किन्तु मैं इस भाग पर प्रश्न नहीं कर रहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों का क्या हुआ। उनके लेखे तक को दर्शाए नहीं गए। हम यह भी नहीं जानते कि वहां क्या कार्य हो रहा है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का यही कार्य निष्पादन है तो हमें उनके प्रति सावधान रहना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान मंत्री महोदय ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए है। ऐसा समाचार है कि क्रिया शुरू हो गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन का अध्ययन हो रहा है। किन्तु मेरा अनुरोध है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए जिससे पूर्व सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अध्ययन पूरा हो जाए और जब भी हमें लगे कि उनमें से कुछ को लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता तो उन्हें बन्द कर देना चाहिए और जब भी हम देखें कि उन्हें लाभप्रद बनाने की सम्भावना है, तो हम उनका पुनः राष्ट्रीयकरण कर दें। ऐसे उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस अत्यन्त सीमित समय में, में आपका ध्यान पुनः रिपोर्ट के पृष्ठ 9 की ओर आकृष्ट करता हूं। दो श्रेणियां हैं।

पहले, 12 उपक्रमों ने लाभ में वृद्धि या घाटे में कमी दिखाई हैं। एक और श्रेणी है। आज श्रेणी में भी, 1989-90 में, दक्षिण पूर्वी कोयला खानों में 32 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और इस वर्ष घाटा नहीं हुआ। किन्तु इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड को 1989-90 में 104 करोड़ रुपए का और इस वर्ष 51 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। भारतीय सीमेंट निगम को 1989-90 में 62 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इस वर्ष, 32 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

दूसरी श्रेणी चेतावनी पूर्ण है। हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को 1989-90 में 169 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इस वर्ष घाटा बढ़कर 228 करोड़ रुपए हो गया है।

भारतीय उर्वरक निगम को वर्ष 1989-90 मे 146 करोड़ रु० का घाटा हुआ है तथा इस वर्ष यह घाटा बढ़कर 170 करोड़ रुपए हो गया है। अतः भारतीय उर्वरक निगम को हुआ यह घाटा अत्यन्त चिन्ताजनक है। उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता वापस लेने की काफी

आलोचना की गई है। महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि उर्वरकों के लिए जितनी भी राजसहायता दी जाती है वह सब उन सार्वजनिक उपक्रमों को नहीं दी जानी चाहिए जो किसी के प्रति भी जिम्मेवार नहीं हैं तथा जिनका प्रबन्ध सही नहीं हो रहा है तथा जो सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जितनी भी राजसहायता दी जाती है वह सब सीधे किसानों को दी जानी चाहिए। मैं पूरी तरह से इस नीति का समर्थन करता हूं।

लाइसेंस समाप्त करने के सम्बन्ध में मैं यही चाहूंगा कि मैं लाइसेंस समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। क्योंकि मेरे विचार में यह एक दूसरा क्षेत्र था जहां पर कि लघु उद्यमियों तथा बड़े व्यापारिक घरानों को भी कुछ दिक्कतें हो रही थीं। परन्तु मैं विनम्रता पूर्वक एक क्षेत्र विशेष का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें लाइसेंस प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया है। वह कार उद्योग है।

अनुबन्ध-II में उन उद्योगों की सूची दी गई है जिनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। उसमें कार उद्योग भी है। वर्ष 1987 में केरल के संसद सदस्यों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को एक अभ्यावेदन किया था कि उस राज्य में एक छोटी कार परियोजना जिसकी स्थापना प्रस्तावित थी, उसे लाइसेंस दे दिया जाए। वह 800 सी० सी० डीजल कार परियोजना थी। तब श्री राजीव गांधी ने दिनांक 1 मई, 1987 को हमें लिखा था :

> "आपके द्वारा तथा केरल के अन्य संसद सदस्यों द्वारा केरल में एक छोटी कार इकाई स्थापित करने के बारे में दिनांक 28 अप्रैल 1987 के अभ्यावेदन को मैंने देख लिया है। इस मामले को उद्योग मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।"

वर्ष 1987 से ही यह परियोजना लम्बित पड़ी हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि नीति को उदार बनाए गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस बड़े क्षेत्र को अनुबन्ध-II अन्तर्गत क्यों रखा जा रहा है जिसके अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। मुझे क्षमा किया जाए यदि कोई यह कहता है कि यह केवल वर्तमान कार बनाने वाली इकाई के हितों की रक्षा करने के लिए ही है। हम जानते हैं कि इस देश में केवल मारुति उद्योग लि०, दि एम्बेसडर, दि प्रीमियर तथा दि साइपेनिस जैसी या चार इकाई हैं।

महोदया, इन चार वर्तमान इकाइयों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने ग्राहकों के प्रति काफी सख्त रुख अपना लिया है। 'साइपेनिस' एक निजी उपक्रम है तथा किसी के प्रति भी जबावदेह नहीं है। कार की बुकिंग के लिए उन्हें ग्राहकों से करोड़ों रुपये प्राप्त हो गए हैं। उन्हें वचन दिया गया था कि मोन्टाना कारों में निसान इंजन लगाए जाएंगे। परन्तु कार में "जय" इंजन लगाया गया था जिसे कोयम्बतूर में बनाया गया था। तथा इस समय कोई भी कार ठीक चालू स्थिति में नहीं है। अतएव उनके साथ भारी धोखाधड़ी हुई है। अतः निजी क्षेत्र को सरकार अथवा जनता के प्रति जबावदेह बनाया जाना चाहिए।

अतएव मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाए तथा इस समय आपने जो परिवर्तन किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप कार उद्योग के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं।

[श्री ए० चार्ल्स]

कुछ विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। मुझे खुशी है कि लगभग सत्तर केन्द्रों में विकास केन्द्र आरम्भ किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखने पर मैं समझता हूं कि आप केरल में भी ऐसे दो विकास केन्द्र आरम्भ करने जा रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव का मूलतः विरोध करता हूं। प्रश्न यह नहीं है कि यह कहां पर स्थापित है बल्कि यह ऐसा दूसरा क्षेत्र है जहां पर हम कोई नया कार्य आरम्भ करने जा रहे हैं। वचन यह दिया गया था कि इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से लघु तथा मध्यम उद्योगों की सहायता करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बुनियादी सुविधाओं सहित विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इस योजना से संभवतः उन क्षेत्रों के विकास केन्द्रों को मदद मिलेगी जहां पर बुनियादी तथा अन्य सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। परन्तु केरल जैसे राज्य में इसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सके। क्योंकि केरल की ऐसी हजारों इकाई हैं जो रुग्ण हैं। वहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनकी रुग्णता के कारणों का अध्ययन किया गया है। इसके कई कारण हैं जैसे कच्ची सामग्री, बिजली, विपणन तथा कोई उचित वित्तीय व्यवस्था इत्यादि का अभाव। परन्तु कम से कम तीस प्रतिशत मामलों में समस्या केवल पर्याप्त निधि की है। ठीक समय पर निधि नहीं दी जा रही है। अतएव यदि हम उचित वित्तीय व्यवस्था के अभाव में रुग्ण इकाइयों का पता लगा सकते हैं तथा यदि इस पैसे को उन इकाइयों पर व्यय किया जाता है, तो तीन महीने में ही आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक आपको सतर्क करना चाहूंगा। यदि आप इन विकास केन्द्रों की स्थापना करना आरम्भ कर देते हैं तथा इस बीच में आप भूमि भी अधिग्रहित कर लेते है तथा कुछ शेड भी बना देते हैं, आपका पूरा धन व्यय हो जाएगा तथा कोई संसाधन, उद्योग नहीं लग सकेगा तथा जो धन आप पहले ही व्यय कर चुके हैं, वह धन वापस नहीं हो सकेगा। मैं आपको केरल के अपने अनुभव के आधार पर ही यह बता रहा हूं।

अन्त में, मैं एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् लघु उद्योग क्षेत्र पर आ रहा हूं। मेरी इसमें शुरू से ही रुचि रही है। इस समय लघु उद्योग क्षेत्र को काफी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से अधिकांश उद्योग रुग्ण हैं। मैं लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता के सम्बन्ध में रिपोर्ट के पृष्ठ 7 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदया, यह अत्यन्त चिन्ताजनक है। नवीनतम प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र में कुल 25,32,055 ऐसी इकाई हैं जिनमें कुल लगभग 12 करोड़ रु० की राशि लगी हुई है। इनमें से 240573 लाख इकाई हैं जो 9.5 प्रतिशत हैं तथा जिन्हें रुग्ण इकाई माना गया है तथा जिन पर 2141 करोड़ रुपये की बैंक की राशि बकाया है। उन्होंने 2,37,113 रुग्ण इकाइयों का बड़े स्तर पर अध्ययन किया है तथा उनमें से 13033 इकाइयों को व्यवहार्य पाया गया है। उनमें से 7788 इकाइयों को उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि जब लगभग 25,000 लाख इकाइयां रुग्ण हैं, तो वर्तमान उपचार कार्यक्रम केवल 7788 इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए ही बनाया गया है। अन्य सभी इकाइयों को छोड़ दिया गया है।

बी० आई० एफ० आर० रुग्ण एककों के हितों की रक्षा करता है। परन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि कुल एककों का केवल एक प्रतिशत ही बी० आई० एफ० आर० के क्षेत्र में आता है। निन्यानवें प्रतिशत एककों को छोड़ दिया गया है। लघु उद्योग विकास बैंक ने अब अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस बैंक को रुग्ण इकाइयों की देखभाल का दायित्व सौंपा जाए। आपकी नीति में यह बताया गया है कि निगरानी करने का कार्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया जाएगा। यदि आप राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ही रुग्ण एककों की निगरानी का कार्य करवाना जारी रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे सम्पूर्ण उद्योग का ही अन्त हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक लघु इकाइयों के सम्बन्ध में बहुत सन्तुष्ट नहीं है। जब कभी भी समर्थक ऋणाधार का सम्बन्ध होता है, उस पर जुर्माना के रूप में ब्याज लगाया जाता है जिसमें भारी राशि लगती है। इससे पूरी की पूरी इकाई ही रुग्ण हो जाती है तथा उन उद्योगों को पुनः चालू करना संभव नहीं होगा।

मैं लघु और अति लघु क्षेत्रों को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ सुझाव दूंगा अवधि ऋण तथा चालू पूंजी के लिए ब्याज की दर चार प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इन इकाइयों को पूरी तरह से उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर से स्थायी आधार पर मुक्त रखा जाना चाहिए जैसा कि खादी तथा ग्राम उद्योगों को इन करों से मुक्त रखा गया है। मेरा यह भी सुझाव है कि बिक्री में छूट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां तक सम्भव हो सके, ऋणों के लिए समर्थक ऋणाधार छोटी इकाइयों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। सभी छोटी रुग्ण इकाइयों के लिए जुर्माना स्वरूप ब्याज की दर निरपवाद रूप से माफ की जानी चाहिए। छोटी इकाइयों के लिए ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदनों को यथासम्भव कम से कम समय में जो कि किसी भी मामले में तीन माह से अधिक नहीं में ही निपटाया जाना चाहिए। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत भारी श्रमिक कानूनों तथा अन्य कानूनों से भी छोटी इकाइयों को मुक्त किया जाए। मेरा यह भी सुझाव है कि सरकारी विभागों, सरकार नियंत्रित तथा अर्द्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों को अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीद केवल लघु उद्योग क्षेत्र से ही करने के लिए कहा जाए बशर्ते कि उन वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में ही किया गया हो। यदि इस सुझाव को लागू किया जाए तो इससे यह सुनिश्चिय हो जाएगा कि विपणन सम्बन्धी कोई समस्या नहीं रहेगी। लघु इकाइयों को रियाययी दर पर बिजली दी जानी चाहिए।

चूंकि एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत ऋण की राशि पांच लाख रु० से बढ़ाकर 20 लाख रु० कर दी गई है, राष्ट्रीय साम्या निधि को भी बीस लाख रु० तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। बिना उच्चतम सीमा निर्धारित किए हुए सहायता राशि पन्द्रह प्रतिशत होनी चाहिए।

छोटी रुग्ण उद्योग इकाइयों को पुनः चालू करने के मामले में एकल खिड़की योजना में विस्तार किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थायें जो अवधि ऋण प्रदान करती हैं उन्हें ही लघु उद्योग इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए राष्ट्रीय साम्या निधि और कार्य चालन पूंजी की मंजूरी देनी चाहिए।

[श्री ए० चार्ल्स]

नीति में उल्लिखित विशेष निगरानी एजेंसी को अपने विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी औद्योगिक तथा वित्तीय गतिविधियों की निगरानी करने, संशोधन करने तथा उनकी सिफारिश करने के अधिकार होने चाहिए। एजेंसी सांविधिक होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ इसे कार्रवाई करने का सिफारिश करनी चाहिए तथा संबंधित बैंकों और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रमुख द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार की बड़ी इकाइयों की लघु इकाइयों में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। उस स्थिति में वे लघु इकाइयों को और अधिक व्यवहार्य बना सकेगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को औद्योगिक संगठनों से विपणन के लिए योजनाओं को मंजूरी देनी चाहिए। उन्हें औद्योगिक सहकारी संस्था तथा दूसरे विपणन संगठनों को सीधे धन देना चाहिए।

प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों को केन्द्रीय पूंजी निवेश पर राजसहायया प्रदान की जाती थी। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो दुर्भाग्य से सितम्बर 1980 में अचानक इस सहायता को बन्द कर दिया गया।

केवल केरल को ही 1988 से पहले 11 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए थे। यह राज सहायता लघु क्षेत्र के लिए एक वरदान थी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह राज सहायता देने से लघु उद्योगों की सहायता होगी।

लघु उद्योगों से सम्बन्धित नीति वक्तव्य में एक मुश्त सहायता देने का वायदा किया गया है। मैं केवल यह जानना चाहता था कि उस एक मुश्त सहायता का क्या था।

मुझे दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया गया था। मुझे अपने खाने सम्बन्धित मीनू की कुछ समस्या थी। मैंने अपने मित्र से खाने की वस्तुओं के बारे में पूछा। उसने कहा, कि यह तो बहुत साधारण खाना होगा। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण नमक नहीं खा सकता है और कोई चीनी नहीं खा सकता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी, जो कि मेरे मित्र हैं द्वारा दी गई एक मुश्त सहायता को ढूंढ़ रहा था। वह पैकेज आश्वासनों से पूर्ण था। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मैंने जो भी नए कार्यक्रम के रूप में सुझाव दिया है उसे पैकेज में शामिल कर लिया जाए। यदि वह पैकेज हमें दिया जाए तो मेरा विश्वास है कि हम समस्या का समाधान कर लेगें, हम रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू कर सकेंगे।

छोटे उद्योग हमारे उत्पादन का 40% तथा इस देश की कुल रोजगार क्षमता का 60% प्रदान करते हैं। यह राष्ट्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मेरा अनुरोध है कि काफी परिवर्तनों को देखते हुए लघु क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए, जो रुग्ण उद्योग हैं उन्हें पुनः चालू किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों और सभा के समक्ष रखे गए नीति वक्तव्य का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारा देश गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कोई व्यक्ति सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से सहमत होगा और कोई असहमत होगा। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार ने इस समय स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट बात कही है।

बजट प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने नई औद्योगिक नीति, नई आयात और निर्यात नीति, लघु क्षेत्र, कुटीर क्षेत्र और छोटे उद्योगों से सम्बन्धित नई नीति प्रस्तुत की। बजट में भी उन्होंने आंतरिक स्रोतों को एकत्र करने का प्रयास किया। जब हमारा देश गम्भीर चुनौतियां और समस्याओं का सामना कर रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि सरकार पर आप विश्व में हो रहे परिवर्तनों का काफी प्रभाव पड़ता है। आज विश्व का क्या रुख है ? आज पूंजीवाद, सफल हुआ है, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद बहु-राष्ट्रीय निगम पूंजीवाद राष्ट्र ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बनाने में सफल हो गए हैं जैसे भविष्य पूंजीवाद का ही है। समाजवाद चला गया है, 'समाजवाद' शब्द पुरानी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा है कि यह समाप्त हो गया है। मेरे विचार से उन्हें इस बारे में घोर निराशा होगी। समाजवाद समाप्त नहीं हुआ है। आज के विश्व में समाजवाद का बहुत योगदान है। यहां तक कि पूंजीवाद ने भी समाजवाद की बहुत सी बातें ली है। एक समय था जब पूंजीवाद शोषण का सशक्त औजार था। यहां तक कि यह धारणा आज भी है। लेकिन आज वे मजदूरों की दशा की ओर अधिक ध्यान देते हैं उनमें से कुछ मजदूरों को अपने तरीके से शामिल करने का प्रयास कर रहे है, उन्हें प्रबन्ध में भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि जर्मनी और जापान जैसे देश भी कारखाने को एक परिवार की तरह मानते हैं। जब एक मजदूर एक उद्योग में कार्य आरम्भ करता है तब वह यही सोचता है कि पूरी जिंदगी इसमें ही रहेगा। जब एक मजदूर एक कारखाना छोड़कर अधिक वेतन और लाभ के लिए दूसरी जगह जाता है तो वह उसे बाहरी व्यक्ति समझते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उसने एक परिवार को छोड़ दिया है। कारखाने भी उनकी देखभाल करने का प्रयास करते हैं।

क्या हम उनसे कुछ सीख रहे हैं ? मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा हैं कि 42 वर्षों के बाद भी हम प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी की कोई योजना नहीं बना पाए, यद्यपि इस बार ऐसा कोई विचार दिखाई देता है। इसे केवल विचार ही नहीं रहने देना चाहिए। प्रबन्ध में मजदूरों की की भागीदारी देने का मेरा अर्थ उन्हें केवल निचले स्तर से लेकर उच्चतम प्रबन्ध तक भागीदारी देने का है। उन्हें प्रत्येक स्तर पर भागीदारी देकर जब तक उन्हे यह महसूस नहीं कराया जाएगा कि वह उसमें शामिल हैं, उसमें उनकी भागीदारी है, वे भी अपनी बात कह सकते हैं, वे शेयरधारक है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर-सरकारी, सबमें ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। यहां तक कि गैर-सरकारी क्षेत्र भी मजदूरों को पर्याप्त वेतन देकर और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देकर ही ऐसा कर सकते हैं।

इसलिए, मेरा कहना है कि यह उचित समय है कि हम ऐसा करें। यह कहना बेवकूफी होगी कि हम इसकी अनदेखी करे या इससे आंख मूंद लें कि विश्व स्तर पर क्या हो रहा है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरूआत के बावजूद भी मनुष्य का योगदान बहुत अधिक है, यही अति आधुनिकी प्रबन्धन सत्य है और प्रबन्ध एक मुख्य मुद्दा बन गया है। यह एक नई प्रकार की पूंजी है, मानव शक्ति एक पूंजी है और आधुनिक देश इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम उस हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे मजदूरों की दशा अच्छी नहीं है। हमने उनकी उपेक्षा की है। हमने उनकी कुशलता को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में ऐसी बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां हस उनका मार्ग निदेश कर सकें, उन्हें सलाह दें सकें, उन्हें बढ़ावा दे सकें। अतः मेरा कहना है कि भारतीय उद्योग में यह सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। हमने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने नए उद्यमों के विकास पर जोर नहीं दिया।

हम पिछड़े क्षेत्रों में असफल क्यों रहे? कार्य करने की भावना की कमी नहीं थी। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में कुछ कार्य करने के लिए नीतियां भी बनाई। पिछड़े क्षेत्रों में अनेक रियायतें और प्रोत्साहन दिए गए। लेकिन अभी योजनाएं असफल हो गई। अधिकांश राज्यों में वे क्यों असफल हुई? मैं यह नहीं कहूंगा कि वह प्रत्येक राज्य में असफल रही। महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ हद तक सफल रहीं। लेकिन पूरे उत्तर भारत में उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में असफल रहीं। इन्हीं क्षेत्रों में हमारी अधिकांश जनसंख्या रहती है और यहां यह असफल हो गया।

इसके अनेक कारण थे। एक कारण आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। इन अधिकांश क्षेत्रों में आप पाएंगे कि परिवहन और संचार व्यवस्था अभी भी खराब है।

उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र में, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है जो कि राष्ट्रीय औसतन से ज्यादा है। लेकिन आज भी हम बड़ी रेल लाइन और सड़कें न होने से परेशान हैं। हमारे 80% गांवों और कस्बों में पक्की सड़कें नहीं हैं। वहां संचार और टेलीफोन सुविधाएं नहीं हैं। वहां कौन जाएगा? यदि उन्हें उचित परिवहन और संचार सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वे आधारभूत सुविधाओं की कमी का सामना करते रहेंगे। अतः मैं यह कहूंगा कि सरकार को इस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाकर उनकी आवश्यकताओं, पर्यावरण, कुशलता की उपलब्धि और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर विशेष योजनाएं बनानी चाहिएं। सरकार को पिछड़े क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए चाहे वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाके में हो। मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं और ऐसे तो अनेक क्षेत्र हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि योजना आयोग को राज्य सरकारों से परामर्श करके पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड गठित करने का प्रयास करना चाहिएं। वह प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता यह होनी चाहिए। इन पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए युवाओं के लिए उचित प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिए। उन क्षेत्रों में कुशलता बढ़ाने, वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, मार्ग निर्देश, परामर्श देने और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल देना

चाहिए ।

आपने लाइसेंस समाप्त कर दिए हैं। उस पर मैं आपसे कोई टकराव नहीं चाहता । अगर आप यह समझते हैं कि इससे आपको कोई सहायता मिल सकती है तो आप ऐसा अवश्य कीजिए । परन्तु आपको यह स्मरण रखना होगा कि हमने संविधान की प्रस्तावना में यह प्रण किया है कि हम धन को कुछ लोगों के हाथों में ही नहीं रहने देंगे ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्द केवल नारा मात्र नहीं थे। उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए विकास करना था । दूसरी पंचवर्षीय योजना तक सामाजिक न्याय के साथ विकास प्रमुख उद्देश्य रहा । मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 'सामाजिक न्याय' के शब्द को ही भुला दिया गया । इस उद्देश्य को प्राप्त करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था । पिछले तीन-चार वर्षों से तो इस शब्द को ही भुला दिया गया । कम से कम जनता दल को इतना श्रेय तो जाता है कि सामाजिक न्याय आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है ।

हमने अपने देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या की उपेक्षा की जोकि गरीब क्या गरीबी की रेखा के नीची रहती है । हमारी 55 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जिनकी मासिक आय 400 रुपए प्रति माह हैं । रुपए के अवमूल्यन के पश्चात् इस 400 रुपए की कीमत 325 रुपए रह गई है । इस प्रकार हमारे देश की 55 प्रतिशत आबादी की आज 325 रुपए प्रति माह मासिक आय है । क्या हम उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना नहीं चाहते ? क्या हम राष्ट्रीय विकास में उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे ? अगर हम ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो इससे बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो सकती है । पहले ही हम राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति का सामना कर रहे हैं । इसलिए जब तक हम इसे समझने के लिए संयुक्त प्रयास नहीं करते, सहयोग की भावना नहीं दिखाते, राष्ट्रीय आम सहमति के प्रयास नही करते, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने के प्रयास नहीं करते, मेरे विचार में तब तक हम स्थिति का सामना नहीं कर सकते ।

वर्ष 1991 में हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आज स्थिति क्या है ? आधारभूत क्षेत्रों की कार्यक्षमता के अनुसार, 5 प्रतिशत उत्पादन कम रहेगा । कोयला, रेलवे का कार्य निष्पादन, इस्पात, कच्चा तेल के क्षेत्रों में कुल मिलाकर पांच प्रतिशत उत्पादन कम रहेगा··· (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : और सीमेंट के क्षेत्र में।

श्री चन्द्रजीत यादव : सीमेंट भी इसी श्रेणी में आता है। अर्थव्यस्था के इन चार-पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 के दौरान उत्पादन में 5.1 की कमी होने की आशंका है। अगर आप इस कमी की ओर ध्यान देंगे तो हमारे सामने बहुत ही गम्भीर समस्या उत्पादन होने वाली है ।

5 00 म०प०

इन वर्षों में हमारी क्या समस्या रही है ? हमारी प्रमुख समस्याएं रही हैं—अधिक उत्पादन

[श्री चन्द्रजीत यादव]

लागत जिसके कारण हम विश्व के दूसरे उत्पादों के समक्ष ठहर नहीं सके, हमारे देश में बने सामान की निम्न गुणवत्ता जिसके कारण हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस स्थिति नहीं बना पाए तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अकुशलता। सार्वजनिक क्षेत्र के 2400 उपक्रमों में से केवल 42 ऋण से मुक्त हैं। हमारे 90 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अकुशलता, अधिक उत्पादन लागत तथा दूसरे कारणों से भारी ऋण के नीचे दबे हुए हैं।

मेरी यह गंभीर आशंका है कि वर्तमान औद्योगिक नीति के कारण देश में ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि जैसे सारी असफलाओं का कारण सार्वजनिक क्षेत्र है तथा सार्वजनिक क्षेत्र को एक अस्पृश्य क्षेत्र के रूप में प्रतिबिम्बित किया जा रहा है तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना एक अपराध थी। इस प्रकार का सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी वातावरण जो कि नई औद्योगिक नीति तथा संसद में प्रस्तुत पिछले बजट के कारण बना है, एक बहुत ही गम्भीर चेतावनी है। यह मत भूलिए कि निजी क्षेत्र इस्पात, भारी उद्योग, तेल निकालने तथा यहां तक कि फार्मेस्यूटिकल उद्योग तक में आने के लिए तैयार नहीं था। मुझे याद है जब भारत-चीन तथा भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश में ऐंटिबायोटिक उद्योग खोलना चाहते थे क्योंकि हम जानते थे कि हमारे दुश्मन स्थिति का लाभ उठाना चाहेंगे तथा संभावना थी कि वे हमारी सेनाओं के लिए आवश्यक दवाईयों की आपूर्ति नहीं करेंगे। उस समय कोई भी निजी क्षेत्र की कम्पनी इसके लिए आगे नहीं आई। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करके हम कोई अधिक प्रसन्न नहीं थे परन्तु हम ऐसा करने के लिए मजबूर थे क्योंकि हम अपने उद्योग का विकास करना चाहते थे। हमारी आत्म-निर्भरता की नीति थी तथा हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को दूसरों पर निर्भर नहीं करना चाहते थे। अब सार्वजनिक क्षेत्र को कोई भी श्रेय दिए बिना अगर आज हम सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी वातावरण बनाने में सहायता करें, तो यह बहुत ही गम्भीर बात होगी। आप सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ऊंचा उठाने के उद्देश्य को छोड़ सकते हैं परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा इस देश में रहेगा तथा इसका योगदान हमेशा रहेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार इस सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी वातावरण को समाप्त करने की चेष्टा करे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सरकारी नीतियां इस सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी वातावरण को बनाने में सहायक रही हैं।

5.03 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

मुझे नई नीति पर कोई आपत्ति नहीं है। इस गतिशील समाज अथवा विश्व में प्रत्येक पांच या दस वर्ष पश्चात् नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। परन्तु यह सब जल्दी में नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में आपने इस सम्बन्ध में जल्दबाजी से काम लिया और इसलिए यह वातावरण पैदा हुआ है कि अब हर चीज की स्वतन्त्रता है। मुझे यह कहते हुए बडा खेद हो रहा है कि हमारे वित्त मंत्री—वह एक विशेषज्ञ हैं··· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : एक भूतपूर्व समाजवादी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मैं नहीं जानता ।

श्री मुरली देवरा : आपकी तरह वह भी एक पूर्व समाजवादी हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं अब भी समाजवादी हूं। मैं भूतपूर्व समाजवादी नहीं हूं।

सभापति महोदय : मेरी तरह ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह कह रहा हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने लोगों की आकांक्षाओं तथा इसके राजनीतिक परिणामों को समझा नहीं । यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को भी वित्त मंत्री द्वारा की गई कुछ गलतियों को सुधारने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करना पड़ा । आज जब कि हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो गए हैं तथा हमारे किसान आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो सूखे तथा बाढ़ की स्थिति में खाद पर से राजसहायता वापस लेकर कालाबाजारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मैं सीधा अपने चुनाव क्षेत्र से आ रहा हूं । परसों मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में था । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से तथा जिले में लोगों का एक ही मत था कि हर जगह खाद की काला बाजारी हो रही है। खाद की कीमतें 40 से 60 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ गई हैं । हमने ऐसा क्यों किया ? क्योंकि वित्त मंत्री को स्थिति की जानकारी नहीं है । यह नई नीति जो कि छोटे तथा सीमांत किसानों में भेदभाव करती है, कदापि अव्यावहारिक है । दोहरी मूल्य नीति अव्यावहारिक है तथा मैं यह बताना चाहूंगा कि यह असफल हो रही है । इसके कारण भ्रष्टाचार तथा काला बाजारी हो रही है तथा इससे भी खराब बात है कि इसके कारण हमारे किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए, कृपया इस समस्या पर विचार कीजिए ।

दूसरे क्षेत्र जिनमें हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा वे हमारे औद्योगिक विकास के दो विशेष क्षेत्र हैं । एक है कृषि पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र । कृपया इस क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दीजिए तथा दो करोड़ तक निवेश के लिए प्रोत्साहन दीजिए ताकि लोगों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । इसके साथ उन्हें प्रशिक्षण, सलाह-माशविरा, उत्पादों के चयन तथा ऋण इत्यादि जैसी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएं । आप लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं परन्तु अगर कोई गरीब आदमी अथवा कोई युवा उद्यमी बैंक में ऋण लेने के लिए जाता है तो आपको पता है कि उसे कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? उसे यहां से वहां अनथक भाग दौड़ करनी पड़ती है । उसे कितना ही समय व्यर्थ गंवाना पड़ता है ? उसे अपना काम करवाने के लिए पैसा भी देना पड़ता है । उसे मिलने वाले ऋण का आधा हिस्सा रिश्वत देने में लग जाता है । भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह बैंकों में भी पहुंच गया है । इसके लिए मैं भी उत्तरदायी हूं । इस देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण में मैंने भी भूमिका निभाई थी और इसका मुझे गर्व है कि इसके परिणाम स्वरूप बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ । परन्तु लगभग पिछले दस वर्षों में इस प्रणाली में भ्रष्टाचार ने घर कर लिया है । आरम्भ में ऐसा नहीं था । परन्तु, मेरे विचार से पिछले दस वर्षों में सारा वातावरण बदल गया है तथा अब वहां पर भारी भ्रष्टाचार है । इसलिए, मेरा यह कहना है कि ऋण सुविधाओं में कुछ रियायत दी जानी चाहिये ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

एक और क्षेत्र इंजिनियरी सामान क्षेत्र है। भारत से इंजिनियरी सामान के निर्यात की काफी संभावना है। इंजिनियरी क्षेत्र को उपेक्षा की गई है। हमारे रसायन तथा दूसरे उद्योगों पर निवेश बढ़ाने के लिए काफी ध्यान दिया है परन्तु इंजीनियरी क्षेत्र की उपेक्षा की है जहां पर कि रोजगार की काफी संभावनायें हैं। आज क्या स्थिति हैं ? पांच करोड़ पढ़े-लिखे युवक-युवतियां बेकार हैं तथा अगर इनमें अनपढ़ बेरोजगारों को भी शामिल किया जाए तो यह संख्या 15 करोड़ हो जाती है। यह बहुत ही गंभीर मामला तथा हमारी प्रणाली के लिए गंभीर चेतावनी है। जब तक हम रोजगारोन्मुखी उद्योगी की ओर अधिक ध्यान नहीं देते, तब तक हमें गम्भीर संकट का सामना करना पड़ेगा तथा इस सम्बम्ध में लघु तथा कुटीर उद्योग काफी महत्वपूर्ण हैं।

भारत एक महान देश है जहां बहुत दक्षता है। हमारे लोगों के दास पारम्परिक निपुणता है। हमारे लोगों को यह निपुणता पीढ़ियां से विरासत में मिलती आ रही हैं। आज की दुनिया में हम इन हुनरों के लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना द्वारा जीवित रख सकते है जिस‌ाी कि इस क्षेत्र में काफी संभावना है।

अभी-अभी मैं वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से बातचीत कर रहा था। उन्होंने बताया कि हमारे लघु उद्योगों का निर्यात में 25 प्रतिशत योगदान है। यह कई छोटी बात नहीं कि हमारे लघु तथा कुटीर उद्योग का निर्यात में 25 प्रतिशत योगदान है। इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। हमारी वस्तुओं की गुणवत्ता काफी है। भारतीय डिजाईन भी काफी उत्तम होते हैं। आपको इतने अच्छे डिजाईन और कहीं नहीं मिलेंग।

आज हमारे बुनकरों की क्या स्थिति है ? बुनकर हमारी जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा हैं। आज वे हमारे समाज का सबसे पीड़ित वर्ग हैं क्योंकि धागे के भाव बढ़ रहे हैं। आर्थिक विषमताओं के कारण उनका बनाया माल बिकता नहीं है। विचौलिए अब भी उनका शोषण कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत कम है। इसलिए, कृपया लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करें ताकि वे हमारी अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान दे सकें।

मैं सभा का और समय लेना चाहया हूं क्योंकि हमारे दल के और सदस्यों को भी बोलना है। मैं कुछ सुझाव दूंगा। मेरे विचार से हमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं इस उद्देश्य के साथ प्रदान की जायें कि वे भी देश के अन्य क्षेत्रों के साथ अपना विकास कर सकें, लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सके और गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करना जो कि हमारा उद्देश्य है सम्भव हो सके।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। 47 मिनट आपने लिए और 49 मिनट आपकी पार्टी के लिए है, अब समाप्त करिए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र जीत यादव : फिर भी मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर दूंगा उसके बाद आप कुछ रियायत दे सकते हैं। तत्पश्चात् मैं यह मांग करूंगा कि पूर्व उत्तर प्रदेश—जिसके अन्तर्गत मेरा अपना जिला आजमगढ़ और अन्य जिले जैसे गाजीपुर और बलिया आते हैं—के लिए एक विकास बोर्ड गठित करने पर विचार किया जाए।

जब मेरे प्रिय मित्र, श्री पी० डी० धर योजना मंत्री थे तो वे मेरे जिले में गए और जब उन्होंने वहां की हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गये। विशेष तौर पर जब वह कुछ प्राइमरी, स्कूलों, जहां एक ही स्कूल में नहीं बल्कि अधिकांश स्कूलों में, बीमार बच्चे अध्ययन कर रहे थे। इस क्षेत्र का हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में बहु मूल्य योगदान है लेकिन फिर भी यह पिछड़ा हुआ है। जब गाजीपुर के एक सदस्य ने लोक सभा में आंसू बहाए तो तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग का गठन किया और उस आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की। तब से यह क्षेत्र उपेक्षित है। मऊ से होती हुई साहब गंज से बलिया तक की छोटी लाइन का कार्य भी अधूरा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार कम से कम इस क्षेत्र के विकास पर तो ध्यान देगी।

महोदय दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नए उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उद्योग में अधिक युवक उद्योग में आ सकें वे रोजगार के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने क्षेत्र में भी नहीं रह सकते हैं इस प्रकार देश पर भार बढ़ रहा है।

उन छोटे कुटीर उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो उपेक्षित रहते हैं। उदाहरणार्थ हथकरघा उद्योग, विद्युत करघा उद्योग और कुछ ऐसे उद्योग और भी है इनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : राज सहायता ?

श्री चन्द्र जीत यादव : जब मैं 'ध्यान' कहता हूं तो इसका तात्पर्य राजसहायता, संरक्षण और आरक्षण से है। महोदय, आप को बड़े उद्योग घरानों के कार्यों के बारे में जानकर आश्चर्य होगा। उदाहरणार्थ, बाटा के जूते गांवों अथवा छोटे-छोटे कस्बों में गरीब मोचियों द्वारा बनाये जाते हैं। बाटा कम्पनी उन जूतों को खरीदती है तथा उन पर अपनी मुहर लगाकर और अपना ब्रांड नाम देकर लागत मूल्य से चार-पांच गुणा अधिक मूल्य पर बेचती है। परन्तु गरीब मोचियों को अपनी रोटी और अन्य आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। ऐसा कल-पुर्जे वाले उद्योगों और दूसरे उद्योगों में भी हो रहा है। टूथपेस्ट उद्योग अथवा साबुन उद्योग अथवा टूथब्रश उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही अनेक उद्योग हैं जिन्हें छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित और संरक्षित रखा जाना चाहिए। आज बहुराष्ट्रीय नियम बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार होगा तथा मैं नहीं जानता कि स्थिति ऐसी है अथवा नहीं यह भी समझने योग्य बात है क्योंकि जब तक राजनैतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक कोई नहीं आएगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां केवल अपने लाभ कमाने के लिए आती हैं। हमें

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वे हमारी मदद करने, समाज सेवा करने, और भारत को आत्मनिर्भर तथा आधुनिक समाज के रूप में कायम रखने के लिए नहीं आती हैं। एक भावना पैदा की जा रही है कि यदि हम उनके लिए दरवाजे खोल देंगे तो हम विकसित और उच्च प्रौद्योगिकी के साथ एक आधूनिक भारत और आधुनिक समाज के रूप में विकसित होंगे। परन्तु औद्योगिक विश्व में वे शार्क के समान हैं वे जो उस देश में ही जाती हैं जहां उन्हें कुछ लाभ मिलता है। वे हमें निगल सकती हैं और हमारे देश के राष्ट्रीय उद्योगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज वे इस बात से खुश हो सकते हैं कि नई प्रौद्योगिकी आ रही है। परन्तु हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हमारे देश में राष्ट्रीय पूंजीवाद का विकास होता तो हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे महान लोग होते हुए जो प्रतिभावान होते और जो हमारे देश की आर्थिक विकास में मदद करते। परन्तु हमारे दिमाग में यह आशंका है इस बात का भी खतरा है। कृपया इस खतरे की ओर ध्यान दीजिए। (**व्यवधान**) इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज से सात साल पहले भी मैंने चन्द्रजीत यादव जी को सुना था। आपकी अधिकांश बातें उस वक्त कांग्रेस में रहकर भी और आज भी वहीं हैं। ऐसा लगा, कहीं आप अरण्य-रोदन तो नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरे विचारों में कोई फर्क नहीं है। मैं कांग्रेस में रहते हुए भी समाजवादी और प्रगतिशील बातें कहता था और आज भी मैं कह रहा हूं ···(**व्यवधान**)···

श्री दाऊ दयाल जोशी : कहीं यह अरण्य-रोदन तो नहीं है।···(**व्यवधान**)···

श्री चन्द्रजीत यादव : अरण्य-रोदन नहीं है, यह भविष्य के लिए रास्ता है, जो आप समझ नहीं पाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रफुल्ल पटेल बोलेंगे।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय मैंने भी अपना नाम दिया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जी हां, आपका भी नाम है। परन्तु आप तभी बोलेंगे जब आपको अवसर मिलेगा, अभी नहीं।

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा) : सभापति महोदय मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया गया है, मैं इन अनुदानों मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से इस सभा के समक्ष कुछ विचार, जो मेरे विचार से हमारे

देश के समग्र संतुलित औद्योगिक विकास को सुदृढ़ बनाएगी।

महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने पहली बार साहसपूर्ण औद्योगिक पहल की है। 1948 और 1956 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने औद्योगिक नीति संकल्प तैयार किये थे जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था जिसके अन्तर्गत समाजवाद के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा इस देश के दलितों को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था के प्रेरित किया जाएगा और इस देश में उपलब्ध प्रतिभावान उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ? शुरू के वर्षों में विशेषतः स्वतन्त्रता के बाद बड़ी परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी की कमी थी और इसी कारण सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उद्योग के लिए इसका सहारा लिया। उद्योगों जैसे इस्पात, ऊर्जा, खान, सीमेंट और ऐसे ही अन्य उद्योगों सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। वर्षों बाद हमारा सरकारी क्षेत्र का निवेश 1,30,000 करोड़ रुपया हो गया। हमने सरकारी क्षेत्र के परिणाम को भी देखा है। हमें अपने इस वादे पर कायम रहने का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम सरकारी क्षेत्र को सहारा दें। यह निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय उद्योग नई अर्थव्यवस्था, समाज के दलित और कमजोर वर्गों की आशा के अनुकूल हों तथा हमारे देश के दूर दराज के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें। वर्षों से सरकारी क्षेत्र के प्रशंसनीय परिणाम रहे हैं परन्तु साथ ही कुछ क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र बुरी तरह असफल रहा है। इस बात से हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि सार्वजनिक धन बर्बाद नहीं किया जा सकता। हम जनता के प्रति जवाब देह हैं, हमें उनकी आशाओं के अनुकूल होना चाहिए। जैसाकि हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने बताया था कि स्वतन्त्रता के बाद से आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। इसलिए हमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बनाना है और हम अपने सीमित संसाधनों को किस प्रकार व्यवस्थित करना है। सरकारी क्षेत्र में अनेक उद्योगों में बहुत बड़ा घाटा हुआ है।

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किराए की कारों, रोटी के उत्पादन अथवा रेंस्तराओं को चलाने अथवा ट्रैवल एजेंसी को चलाने के लिए कीमती सरकारी धन का उपयोग क्यों किया जाए। यह ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमने अपने सरकारी धन का निवेश किया है और उन्हें जनता के द्वारा बिना किसी कठिनाई के अथवा बिना किसी परेशानी के आसानी चलाया जा सकता है। हमें अपने निवेश को वापस लेने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन उद्यमियों को अवसर देने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें इस प्रकार के निवेश वापसी से लाभकारी रोजगार दिया जा सकता है। जब तक हमारे विकास की दर तेज नहीं होगी तब तक हम इस देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के अपने उद्देश्य को किसी प्रकार पूरा नहीं कर पाएंगे। हम पहले ही कि प्रत्येक वर्ष 15 मिलियन से 17 मिलियन लोगों का रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कुल मिलाकर बेरोजगार लोगों की संख्या कहीं अधिक है। इस देश में करोड़ों बेरोजगार पहले से ही हैं। इसीलिए जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसके अन्तर्गत हम मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित कर सकें। यह महत्वपूर्ण बात है कि

[श्री प्रफुल पटेल]

विगत कई वर्षों के दौरान बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और आबादी, जोकि आज 35 करोड़ से 85 करोड़ तक पहुंच गई में वृद्धि के साथ बेरोजगारों कि संख्या में भी बेहिसाब वृद्धि हुई है। मुझे यह भी पक्का विश्वास है कि सरकार के पास भी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने विभिन्न योजनाओं और व्यवसायिक मार्ग निर्देशों के द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए हैं, लेकिन साथ ही इन आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता भी है।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, हम इस्पात उद्योग का उदाहरण ले सकते हैं। हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक निवेश कर रहे हैं। इस्पात उत्पादों का हम बड़ी मात्रा में आयात भी कर रहे हैं ताकि हम अपने कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मैं उदाहरण स्वरूप टाटा स्टील का नाम ले रहा हूं। टाटा जिसका इतना उच्चा रिकार्ड रहा है उस कम्पनी को भी अपनी क्षमता को लाखों टन बढ़ाने की स्वीकृति लेने में पन्द्रह वर्ष लग गए, जबकि केवल इस्पात के क्षेत्र में हमें प्रतिवर्ष दो से तीन लाख टन मात्रा तक का आयात करना होता है और हमारे बहुमूल्य लौह-अयस्क को जापान और ताइवान जैसे देशों को निर्यात किया जा रहा है। वे इसी लौह-अयस्क से इस्पात उत्पाद तैयार कर रहे हैं और उत्पादित माल को वापिस तीसरी दुनिया के देशों या विकसित देशों को निर्यात कर रहे हैं। हम भी उन्हीं देशों में एक हो सकते हैं, जो अपने लौह-अयस्क से उत्पादित इस्पात के वस्तुओं का आयात कर रहे हैं।

विशिष्ट कारणों से हमें इस मामले को परखना चाहिए। इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग भी उत्पादन शुरू कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को इससे दूर होने या उस क्षेत्र में निवेश नहीं करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन संवर्धित नई क्षमता के साथ विश्व भर की कई कम्पनियां यह कार्य कर सकती हैं। टाटा स्टील सरीखी बहुत सी कम्पनियां हमारे देश में भी है, जिन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने का, नये परियोजना स्थापित करने का मौका दिया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के और अवसर प्राप्त होंगे, हमारे उद्योग के विकास को अधिक बल मिलेगा तथा साथ ही साथ हम अपने विदेशी मुद्रा को बचा सकेंगे।

जहां तक आटोमोबाइल क्षेत्र का संबंध है, मेरा यह कहना है कि हमें नई औद्योगिक नीति में भी कारों के उत्पादन या अन्य प्रकार के वाहनों के उत्पादन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस देश में आटोमोबाइल उद्योग की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहां तक कि तथाकथित शो-पीसमॉडल मारुति 1000 सी०सी० जिसका उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता हैं और जिसमें आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया गया हैं, उसमें ईंधन की खपत बहुत अधिक होती हैं। मुझे भी एक ऐसी ही कार लेने का अवसर मिल चुका है। मारुति 1000 सी०सी० की औसतन ईंधन खपत दस किलोमीटर प्रतिलीटर है। हम ईंधन क्षमता की बात करते हैं। हम अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने की बात करते हैं। हम पेट्रोल उत्पादों के उस आयात को कम करने की बात करते है जो कि प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का होता हैं। दो पहिया वाहनों और चार पहिया वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए

जाने वाले पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का खर्च कम किया जा सकता है। यदि आटोमोबाईल क्षेत्र की क्षमता बढ़ जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ईंधन के खर्च को कम कर सकते हैं या कम से कम 2000 से 3000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोक सकते हैं। हमारी फियेट, मारुति, अम्बेस्डर कारों में से, किसी में भी ईंधन दक्षता नहीं है। फिर हमारे सामने प्रदूषण की एक और समस्या है। आजकल दिल्ली, मुम्बई महानगरों के सामने प्रदूषण की भयंकर समस्या है।···(व्यवधान) मेरा यह मानना है कि जहां आटोमोबाईल उद्योग का संबंध है मारुति कार केवल एक शो-पीस ही है। यदि यही स्थिति है और यदि मारुति कार की भी यही हालत है तो हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि औरों की स्थिति क्या होगी। इसलिए यदि नई कम्पनियां और नए उद्यमी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और जहां तक प्रदूषण का संबंध हैं ईंधन के खपत को कम करने और गुणवत्ता को बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि नई कम्पनियों और नए उद्मियों को इस क्षेत्र में आने से रोकने या लाईसेंस देने के मानदण्ड उन पर लागू करने की क्या जरूरत है।

महोदय, हम नई औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं। आटोमोबाईल उद्योग पर दुनिया के सभी विकासशील देश में विशेष बल दिया जा रहा है। अमरीका जैसा देश, जिसकी जनसंख्या हमारे देश की एक तिहाई है, शायद उससे भी कम हो—प्रतिवर्ष 80-90 लाख कारों उत्पादन करता है। हमारे देश में दोपहिया वाहनों को छोड़कर, अन्य वाहनों का कुल उत्पादन 250,000 या 300,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। अब तथाकथित उत्साही मध्यम वर्गीय लोग भी इस क्षेत्र में भागीदार बन रहे हैं। वे भी कार या अन्य वाहन खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें बैंकों द्वारा ऋण आसानी से मिल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे नये सहयोगी उद्योग भी पनपेंगे। इसलिए इस क्षेत्र पर निश्चय ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब, मैं फार्मास्युटिकल उद्योग के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यद्यपि यह अलग मंत्रालय के अन्तर्गत है, फिर भी मैं एक तथ्य पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जहां तक इस उद्योग का संबंध है, लाईसेंस समाप्त नहीं किया गया है। आज ही सुबह जब यह मुद्दा एक माननीय सदस्य ने उठाया था कि दवाईयों की अत्यधिक कमी हो गई है, हमने इसकी चर्चा की है। यह एक ऐसा उद्योग है, जिसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसका हमारे देश के लाखों गरीब लोगों के लिए उपयोग हो सकता है। साथ ही इसकी क्षमता बढ़ जाने से रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे।

इन उद्योग को लाईसेंस प्रणाली से मुक्त करके इसके विकास के लिए उचित प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता? मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि रक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत से रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं। इस देश में रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने की काफी क्षमता है? हमारे यहां बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहां पर कि हथियार, गोला बारूद तथा कई प्रकार के रक्षा उपकरणों का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लघु क्षेत्र हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें संवेदनशील क्षेत्रों में उत्पादन आरम्भ करना चाहिए। परन्तु ऐसे बहुत से रक्षा उपकरण

[श्री प्रफुल पटेल]

हैं जिनका उत्पादन सहायक क्षेत्र तथा लघु क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के लिए यह काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। क्योंकि रक्षा मंत्रालय कई कारणों से काफी गोपनीय मंत्रालय है, इसलिए हम इन सब बातों की यहां पर विस्तार सहित चर्चा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से उद्योग मंत्रालय को इस पहलू का अध्ययन करना चाहिए।

इस देश में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षममा 60,000 मेगावाट है। परन्तु जब हम विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने तथा अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, तो मैं केवल एक तथ्य को उजागर करना चाहूंगा कि यदि हमारी संयंत्र क्षमता जो कि इस समय लगभग 50% से भी कम है, उसे बिना एक पैसा भी खर्च किए 10 से 15 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि हमें अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त हो सकेगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि विद्युत उत्पादन के पहलू पर उद्योग मंत्रालय सूक्ष्म रूप में विचार करेगा। इससे बहुत से मंत्रालय जुड़े हुए हैं जैसे कि कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय इत्यादि। अगर इनका आपस में उचित समन्वय स्थापित हो जाए, तो हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ सकता है।

जहां तक तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग तथा तेल के लिए खुदाई का सम्बन्ध है, तो हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि लाभ कमाने की दृष्टि से हम कई बार काफी सराहनीय कार्य करते हैं। सम्भवतः इस लाभ को और भी बढ़ाया जा सकता है। शायद वास्तविक क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जहां तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है, हमने इसे एक एकाधिकार प्राप्त इकाई का रूप दे दिया है। हम इस सम्बन्ध में उदार क्यों नहीं हो रहे हैं? इससे हम अपनी क्षमता बढ़ा पायेंगे। जहां तक लाभ कमाने का सम्बन्ध है, हम इसके द्वारा अपनी उत्पादन लागत भी कम कर पायेंगे।

जहां तक विदेशी पूंजी निवेश का सम्बन्ध है, इसके बारे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। हमारे ऊपर 72 बिलियन डालर का विदेशी कर्ज है तथा सम्भवतः पिछले 25 वर्षों में भारत में कुल विदेशी पूंजी निवेश दो बिलियन डालर से अधिक नहीं हुआ। इन्डोनेशिया जैसे देश में भी वार्षिक विदेशी पूंजी निवेश शायद डेढ़ बिलियन डॉलर के बराबर है। अपने उद्योगों को बचाने के साथ-साथ हम अधिक विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकते हैं। हम उचित सुरक्षा उपाय भी अपना सकते हैं। श्री यादव ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 'शार्क' की संज्ञा दी है। इस सम्बन्ध में मैं उनसे असहमत नहीं हूं। परन्तु हम अपनी वर्तमान प्रणाली में सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकते हैं, जिससे कि हम उन्हें पूंजी निवेश के लिए आमन्त्रित कर सकेंगे तथा निश्चित रूप से इससे हमें लाभ होगा।

श्री लोक नाथ चौधरी : वे इतने उदार नहीं हैं।

श्री प्रफुल पटेल : वे उदार न भी हों तब भी हम कुछ सुरक्षा उपाय अपना सकते हैं।

नए प्रस्ताव के अन्तर्गत हमने उन्हें 51 इक्विटि प्रदान की हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि हम ऐसा न कर पाएं। **(व्यवधान)**

श्री प्रफुल पटेल : जहां तक कृषि पर आधारित उद्योगों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जा सकता है।

एक बड़ी इस्पात फैक्टरी अथवा एक बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ रुपये तक का पूंजी निवेश करना पड़ता है जिसमें से 30 से 40 करोड़ रुपये तक शेयर बेच कर प्राप्त होता है तथा बाकी की पूंजी वित्तीय संस्थाओं से ऋण सावधि ऋण प्राप्त करके पूरी की जाती है। महाराष्ट्र में, जहां से कि मैं निर्वाचित होकर आया हूं, एक चीनी की फैक्टरी स्थापित करने के लिए 10 करोड़ के ऋण तथा दूसरी राजसहायता की आवश्यकता होती है। दो या तीन करोड़ रुपये शेयर बेचकर प्राप्त किए जा सकते हैं। एक चीनी फैक्टरी से 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। एक चीनी फैक्टरी स्थापित होने से 10,000 किसानों तथा उनके परिवारों को लाभ पहुंचता है। इसके अतिरिक्त, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों को लाभ पहुंचता है, बहुत से हमारे ऐसे बेरोजगार युवक जो कि ट्रेक्टर तथा ट्रक खरीदने के लिए ऋण लेते है, उन्हे भी इससे लाभ प्राप्त होता है जब उनके टैक्टर तथा ट्रक चीनी फैक्टरियों द्वारा किराये पर लिये जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जो 250 करोड़ रुपये, उन औद्योगिक इकाईयों को ऋण के रूप में दिया जाता है, उसे यदि 25 चीनी मिलों की स्थापना के लिये दिया जाये तो रोजगार अवसरों तथा लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या हजारों तथा लाखों में होगी।

आखरी बात मैं नई नीति में उदारीकरण के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा जो कि घोषित की गई है। मैं विशेष रूप से एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि अब लाइसेंस प्रणाली समाप्त होने के कारण किसी उद्योग को एक महानगर से 25 कि० मी० की दूरी पर भी स्थापित किया जा सकता है। उद्योगपतियों को अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिए गये हैं, जिस राज्य से कि हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं हैं। ग्रामीण अथवा दूरस्थ स्थानों पर उद्योग स्थापित करने के लिए भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिए गये हैं। इसलिए हमारी नई नीति के कारण पिछड़े हुए क्षेत्रों को काफी हानि उठानी पड़ेगी। मैं इस नई औद्योगिक नीति से कुछ लेने का प्रयास नहीं कर रहा। परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ और प्रोत्साहन प्रदान करने का मैं मंत्री जी से हार्दिक निवेदन करता हूं, ताकि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो सकें अन्यथा यहां पर औद्योगिकरण मुश्किल होगा।

इस देश की सचार प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। हम अपने देश के सभी भागों में समीपता तथा राष्ट्रीय अखण्डता की बात करते हैं। परन्तु आज अगर दिल्ली के किसी उद्योगपति को असम में कोई संयत्र लगाना पड़े तो वह कहेगा, अरे ! मुझे असम जाना पड़ेगा। उसे असम लन्दन से भी अधिक दूर लगता है।

इस दुःखद स्थिति के कारण, जहां देश के आधारभूत ढांचे और देश को औद्योगिकीकरण

[श्री प्रफुल पटेल]

को समीप लाने का सम्बन्ध है उद्योगपतियों का यही दृष्टिकोण है। श्री यादव ने भी यही बात कही है।

जहां तक भविष्य में औद्योगिकीकरण किए जाने विशेषकर देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रक्रिया में शामिल करने का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आधारभूत ढांचागत सुविधाओं, संचार सुविधा—चाहे वह रेल, सड़क, टेलीफोन या वह सुविधा कुछ भी हो—जोकि एक आधुनिक देश में इस समय उपलब्ध है, उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिये। अमरीका जैसे देश में औद्योगिकीकरण को लाने और पूरे देश में संतुलित विकास करने में सफलता का कारण यह है कि ज्यों ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उन्होंने सक्षम आधारभूत ढांचा विकसित करने पर बल दिया और यही कारण है कि अमरीका जैसे देश के लोग औद्योगिकीकरण के समीप पहुंच सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के परम प्रिय नेता श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपना भाषण कर रहा हूं। मैं सत्ताधारी पक्ष को इस बजट के बारे में बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि चालीस वर्ष से पण्डित नेहरू जी की, जो कांग्रेस की परम्परा चलती रही है। मंहगाई बढ़ाने की, उस मंहगाई बढ़ाई की परम्परा को इन्होने खंडित नहीं किया है। सभापति महोदय, यह सरकार सिर्फ नारा देना चाहती है लेकिन उस पर अमल नहीं करना जानती है। हमारे कांग्रेस के सदस्य ने भी यह बताया था कि यह सरकार कानून बनाती है लेकिन अमल नहीं करती है। यह सरकार गरीबों का दुःख नहीं जानती है और न ही मजदूरों का दुख जानती है। सामान्य जनता का दुख नहीं जानती है। इसलिए हमारे सिर पर 90 हजार करोड़ का विदेशी कर्ज है। यह सरकार विदेशों से पैसा लेती है और गर्व से कहती है कि हम देश चलाते हैं और उसी में खुशी मनाती है। यह सरकार हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। यह सरकार विलासिता की चीजों पर अनावश्यक खर्च करके इस देश के सामने मौजूदा संकट पैदा करती है। सरकार की गलत नीतियों के कारण सिर्फ चन्द लोग उन सुविधाओं को भोग रहे हैं लेकिन गरीब आदमी को मंहगाई से दबा-दबाकर उसके पास से कर के रूप में, मंहगाई के रूप में पैसा वसूल कर रही है।

सभापति महोदय, हमारे देश में संसद सदस्यों ने मारुति उद्योग लि० पर बहुत अच्छी तरह भाषण दिया और सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने ही उसकी बुरी हालत के बारे में बताया कि हमारे हिन्दुस्तान में दस हजार व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति मारुति—1000 प्रयोग करता है लेकिन मारुति के लिए अब तक इस सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का आयात किया है

जबकि उसके निर्यात में हमें केवल 40 करोड़ रुपया मिला है। यह कितनी शर्मनाक स्थिति है? यह सरकार जनता को दिशाहीन कर रही है। गरीब बेचारा बस, ट्रेन में धक्के खाता फिरता है और उन्ही लोगों से सरकार ज्यादा किराया वसूल करती है। इतना ही नहीं सरकार ने जो पैंप्सी उद्योग लगा दिया है, गरीब के लिये उसका कोई उपयोग नहीं है। इस उद्योग तथा कास्मेटिक और अन्य उद्योग पर सरकार अब तक करोड़ रुपया खर्च हो चुकी है और यह सरकार अप्रत्यक्ष रूप से गरीब जनता पर बोझ डाल रही है। सरकार ने पहले ही पेट्रोल और रेलवे के भाड़ें में वृद्धि कर दिया है जिसकी वजह से 90 प्रतिशत वस्तुओं के दाम और बढ़ गये हैं जिसमें रॉ-मैटिरियल भी शामिल है जोकि उद्योग में काम आता हैं और उद्योग सम्बन्धी अन्य सामान भी शामिल हैं। ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए सबकुछ उदार नीति बनाई है लेकिन मैं आपके माध्यम से सत्ताधारी पक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस मंहगाई में छोटे-छोटे उद्योगपति एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल मार्किट में किस प्रकार कम्पीटीटिव भाव पर अच्छी क्वालिटी का सामान को दे सकते हैं? यह सरकार को सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान से अपना चार हजार करोड़ फॉरेन करेंसी कर्जा में चला जाता है लेकिन सरकार सोलर एनर्जी के विकास के लिए राजी नहीं है। जो टेक्नालॉजी है, उसमें संशोधन करके नहीं लाती है जिसकी वजह से हमारी करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है। मैं गर्व से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक स्थान महाबलेश्वर में इलेक्ट्रीसिटी सोलर एनर्जी से पैदा की जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर सोलर एनर्जी का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारी काफी बचत हो सकती है और इसका उद्योग इंडस्ट्रियल कैंटीनों और घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार से विनती करता हूं कि इसके बारे में सोचे। भारत में ज्यादा से ज्यादा डाक्टर्स हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा साईंटिस्ट्स हैं और हमारा नाम अमरीका और रूस के बाद आता है।

हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स हैं लेकिन दुर्भाग्य को बात यह है कि यहां वे खाली येस मैन नहीं बनते इसलिए वे विदेशों में चले जाते हैं। बंगलौर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जहां के साइंटिस्ट सोलर एनर्जी के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं। वहां पर सरकार ने उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया और उनको ज्यादा बैंकिंग नहीं दिया, इसलिए अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक उसको छोड़कर चले गए। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और सोलर एनर्जी के अनुसंधान को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि काम तेजी से हो। मैं सरकार से विनती करता हूं कि ग्रामीण इलाकों में एग्रो इंडस्ट्री बढ़ानी चाहिये और एग्रो इंडस्ट्री में गांव वाले लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिये। अगर उनको वहां चांस मिल जाएंगे तो वहा उनका तो विकास होगा ही, बेरोजगारी भी दूर होगी, लेकिन साथ-साथ ग्रामों का भी समुचित विकास हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निरीक्षण इंस्पेक्टर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, वे बार-बार जाकर छोटी-छोटी फैक्टरी वालों को परेशान करते हैं। ग्रामीण इलाकों में उनके लिये निरीक्षण का एक ही दिन होना चाहिये और उसके ऊपर सरकार को निगरानी करनी चाहिये। हिन्दुस्तान में जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं विशेषकर महाराष्ट्र में जो कोआपरेटिव

[श्री मोहन विष्णु रावले]

बैंक्स हैं जो ग्रामीण जनता को लाभ देते हैं, सरकार की नीति ऐसी है कि पांच-पांच वर्ष बाद रिजर्व बैंक उनको लाइसेंस देता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि यह जो नीति है, उसमें सुधार करना चाहिये और उसमें जो एक-एक वर्ष की कंडीशन होती हैं, उस बैंक को बढ़ावा देने के लिये उस नीति में सुधार करना चाहिये और हर वर्ष कोआपरेटिव बैंक को खोलने की अनुमति देनी चाहिये।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी हटाने के लिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि वहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होने चाहिये जिसके आधार पर तीन सौ, चार सौ छोटे-छोटे उद्योग होने चाहिए जिससे वहां जो रॉ-मैट्रीरियल की चीजें होंगी तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको वे छोटे उद्योगपार्ट्स वह सप्लाई कर सकते हैं। सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र में लेदर इंडस्ट्री है। अगर हम उसको बढ़ावा देंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी ठीक तरह से मिल सकती है। खनिज तो हमारे लिए सोना है, लेकिन आज खनिज हिन्दुस्तान के बाहर जा रहा है। रॉ मैटीरियल बाहर जा रहा है। वही लोग इसका शुद्धीकरण करके हमारे पास भेजते हैं। मेरी आपसे बिनती है कि हम खनिज पदार्थ जैसे भारत में लौह अयस्क और जिंक बहुतायत में उपलब्ध है लौह अयस्क और सिलिका जैसी खनिज जो महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में उपलब्ध, उसका अगर हम आधुनिक टैक्नॉलॉजी मे शुद्धीकरण करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में स्टेंडर्ड में वृद्धि हो सकती है और निर्यात के द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। हमारे यहां मारबल और ग्रेनाइट भी काफी होता है। मारबल तो इटली के स्तर का होता है लेकिन उसका कुछ प्रयोग नहीं होता। हम निर्यात नहीं कर सकते, बाहर वाले सब यहां से लेकर जाते हैं और वर्ल्ड में उससे करोड़ों का फायदा कमाते हैं।

सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं सरकार से विनती करता हूं कि स्टील का विनियंत्रण करना चाहिए जिससे हमारे देश की उन्नति हो सके। सभापति महोदय, सत्ताधारी पक्ष ने अपने घोषणापत्र में वायदा किया कि एक करोड़ लोगों को एक वर्ष में रोजगार देंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मुम्बई में कई मिलें 1982 से बन्द हैं जिससे 70 हजार लोग मिल के बाहर हैं और बेरोजगार हैं।

सभापति महोदय, अगर सरकार ने ये मिल चलाई तो उनको रोजगार मिल सकता है। अगर सरकार यह नहीं करेगी तो जैसा हमारे बहुत बड़े संसद सदस्य यादव जी ने बताया कि कोओपरेटिव बेसिस के ऊपर अगर वह मिलें मजदूरों को चलाने दी जाएंगी तो उनको उसमें रोजगार मिल सकता है। इसमें मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को गारमेंट प्रोडक्शन भी शुरू करना चाहिए क्योंकि जो परदे होते है, करटेन्स लगते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, अगर एन०टी०सी० की जो मिल है उसको बढ़ावा देंगे और उसमें गारमेंट शुरू कर देंगे तो उससे अच्छा काम हो सकता है और सरकारी दफ्तरों को भी सस्ती दर पर कपड़ा मिल सकता है और अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

सभापति महोदय, इस बजट में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आयकर का भुगतान देरी

से करता है तो सरकार उससे 2 प्रतिशत दण्ड के रूप में वसूल करती है जबकि धन वापस करते समय, जहां पहले डेढ़ प्रतिशत ब्याज दिया जाता था, अब उसे घटा कर इस वर्ष एक प्रतिशत कर दिया गया है। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि धन वासस करते समय अब जो दर घटा कर एक प्रतिशत कर दी गई है, उसे भी दो प्रतिशत किया जाये।

सरकार की ओर से मजदूरों को और सामान्य कर्मचारियों को महंगाई सहने के लिए जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, वह पिछले 6 महीनों में बढ़ी महगाई के आधार पर दिया जाता है परन्तु सरकार उस महंगाई भत्ते के ऊपर भी टैक्स वसूल करती है जो कि इंकम नहीं होनी है। इससे सिद्ध होता है कि जहां सरकार एक हाथ से देती है वहीं दूसरे हाथ से छीन लेने का काम भी करती है। इसी प्रकार मजदूरों को दिए जाने वाले ओवरटाइम भत्ते पर भी सरकार आयकर वसूल करती है। विदेशों में स्थिति यह है कि जैसे ही महंगाई बढ़ जाती है तो उसके साथ-साथ आयकर की सीमा भी स्वयमेव बढ़ जाती है। दोनों के बीच एक तारतम्य रहता है। उसी आधार पर, मेरी सरकार से विनती है कि आयकर की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 36000 रू० कर देना चाहिए।

हमारे यहां हिन्दुस्तान लिवर नाम की एक कम्पनी है। उसका मुख्य उत्पादन साबुन, डिटर्जेंट, केमिकल और कृषि उत्पाद है लेकिन वह कम्पनी चाय, वनस्पति तेल, कमीजें, चावल, जूते और कालीन तक का निर्यात कर रही है। वैसे ही एक कम्पनी प्रोक्टर एण्ड गैम्बल है। उसका मुख्य उत्पादन डिटर्जेंट, खाद्य पदार्थ, कागज और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुएं हैं जबकि उसे 45 प्रतिशत आय सिगरेट उत्पादों के निर्यात से होती है। वैसे ही पौन्डस इण्डिया कॉस्मैटिक्स का सामान तैयार करने वाली कम्पनी है परन्तु वह भी 80 प्रतिशत चमड़े का निर्यात करती है। इसी प्रकार अन्य कई कम्पनियां हैं जो देश में व्यापारी के रूप में काम करती हैं और निर्यात संबंधी यानी एक्सपोर्ट इन्सैंटिव प्राप्त कर रही हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि अमेरिका की एन०बी०सी० टेलीविजन कम्पनी ने समाचार दिया है कि बड़े-बड़े भारतीय उद्योगपतियों और स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी के खास चहेतों ने बी०सी०सी०आई० के खातों में टैक्स की चोरी करके धन जमा कराया है। इस आरोप की जांच कराये जाने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

सभापति जी, हमारी ब्रॉड बेन्डिग इन्वैस्टमैंट पौलिसी बड़ी पेचीदा है क्योंकि इससे ब्यूरोक्रेसी को शोषण करने के अधिकार अपेक्षाकृत ज्यादा मिल गए हैं। यदि किसी का एक सैक्टर विशेष का बिजिनैस है और वह अपने बिजिनैस को किसी दूसरे बिजिनैस में कन्वर्ट करना चाहता है तो वह कन्वर्ट नहीं कर सकता। इस इंडस्ट्रियलिस्ट को अनुकति ही नहीं मिलती। मैं सरकार से विनतीं करता हूं कि इस स्थिति में सुधार लाया जाये और जैसा अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि एम०आर०टी०पी० और फेरा एक्ट में संशोधन करने के लिए सरकार को बिल लाना चाहिए, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ कन्ट्रोल और कैपिटल ईश्यू में भी संशोधन करने के लिए सरकार को कोई बिल सदन में लाना चाहिए, इसकी भी मैं मांग करता हूं।

[श्री मोहन विष्णु रावले]

हमारे देश में हर साल रेलवे डिब्बों से करोड़ों रूपयें का माल चोरी चला जाता है। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से भी करोड़ों रूपए का सामान चोरी हो जाता है। मैं समझता हूं कि चोरी में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। उसी तरह टेलीफोनों की चोरी से, उनका दुरूपयोग करके, सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये का नुकसान सहन करना पड़ता है। इसमें ज्यादातर कार्मिशयल उद्देश्य के लिए चोरी की जाती हैं। अतः सरकार को चाहिए कि रेलों में होने वाली चोरी को रोकने, टेलीफोनों के दुरूपयोग को रोकने और अनावश्यक खर्चे पर यदि नियंत्रण किया जाये तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। अन्यथा स्वतंत्र न रहकर हम परतंत्र होते चले जायेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा।

सभापति जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अन्त में, सरकार से एक ही विनती करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमारे जितने वैज्ञानिक डॉक्टर, इंजीनियर है उनमें अच्छे-अच्छे बाहर के देशों में जा रहे हैं। उनकी प्रतिभा का फायदा हमारे देश को न मिलकर विदेश के लोग उठा रहे हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे बाहर न जाने पाएं और आप उनके लिए कुछ सुविधाएं दीजिए और जो गए हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल प्रातः 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 21 अगस्त, 1991/30 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 1991